सत्यमेव जयते

वर्ष 2012-13 के लिए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है



संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2014 की प्रतिवेदन सं.1
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

वर्ष **2012-13** के लिए

संघ सरकार

संघ सरकार के लेखे

2014 की प्रतिवेदन सं.1

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैरा सं.	शीर्ष	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	**ix**
	विशिष्टताएं	**xi**
	अध्याय 1: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2012-13 का विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.1.2	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय मापदंडों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन	3
1.2	संसाधन का सृजन	4
1.2.1	राजस्व प्राप्तियाँ	4
1.2.2	मुख्य राजस्व संबंधित मापदंडों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल	5
1.2.3	कर राजस्व	5
1.2.4	गैर-कर राजस्व	6
1.2.5	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	8
1.3	व्यय विश्लेषण	9
1.3.1	भारतीय समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा (ई-लेखा डाटा)	10
1.3.2	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	12
1.3.3	राजस्व व्यय का विश्लेषण	13
(क)	राजस्व व्यय की अधिकता	13
(ख)	राजस्व व्यय के प्रमुख घटक	14
1.3.4	पूंजीगत व्यय का विश्लेषण	19
1.3.5	योजनागत व्यय का विश्लेषण	19
(क)	योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय	20
(ख)	योजनागत व्यय का संकुचन	20
1.3.6	सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम-पिछले चार वर्षों में वास्तविक व्यय	22
1.3.7	योजनागत व्यय के मुख्य घटक	24
1.3.8	मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात	26
1.3.9	राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की सुपुर्दगी की पद्धति	26
1.3.10	विगत पांच वर्षों के लिए व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण	28

1.4	व्यय का समय विश्लेषण	29
1.5	ऋण तथा घाटा सूचक	32
1.5.1	घाटे के प्रकार	35
(क)	राजस्व घाटा	35
(ख)	राजकोषीय घाटा	36
(ग)	प्राथमिक घाटा	37
1.5.2	बाह्य ऋणःअप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता	38
1.6	संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि	39
	अध्याय 2: लेखाओं पर टिप्पणियां	
2.1	पारदर्शिता के मुद्दे	42
2.1.1	संघ के वित्त लेखों में बारहवें तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना	42
2.1.2	सरकारी लेखों में अपारदर्शिता	43
2.1.3	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	44
(क)	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी नियामकों की निधियाँ	44
(ख)	प्र.वृ.नि.प्र.ओ.प्रा. निधि का सरकारी लेखे से बाहर रखना	46
(ग)	सरकारी धन को सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना	49
2.1.4	सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया जाना तथा राज्यों को कम आवंटन	51
2.2	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	52
2.2.1	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	52
	सा.से.दा. निधि का कम बताया जाना	53
2.2.2	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम-उपयोग	55
2.2.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियां तथा निरंतर प्रतिकूल शेष	57
2.2.4	नवीकरण आरक्षित निधि के अंतरण को गलत दर्शाया जाना	59
2.2.5	स्वच्छ ऊर्जा उपकर को निधि में जमा न करना	59
2.2.6	राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.)	60
2.2.7	आयकर कल्याण निधि का सृजन	62
2.2.8	चिन्हित निधियों के उपकर का लोक लेखा में कम अंतरण	63
2.3	सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे	64
2.3.1	कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में विसंगति	64
2.3.2	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति	65
2.3.3	लघु बचत, भविष्य निधियों आदि के कारण देयताओं का कम बताया जाना	66
	ब्याज प्राप्ति को न दर्शाया जाना	67
2.3.4	प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना	67

2.3.5	पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना	68
2.3.6	निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि	68
2.3.7	बाह्य ऋण के लेखांकन को कम बताना	69
2.3.8	बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना	70
2.3.9	संघ सरकार द्वारा दिये गये ऋणों को न दर्शाया जाना	71
2.3.10	बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन	71
2.3.11	विभिन्न निधि लेखाओं में अंतर एवं असंगति	72
2.3.12	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (हि.शि.लि.) के ऋणों का गलत दर्शाया जाना	73
2.3.13	संघ सरकार के वित्त विवरणी में लाभांश शेयरों का लेखाकरण न होना	74
2.3.14	अन्य विसंगतियां	75
(क)	विवरणी सं. 13 में आरक्षित निधि में प्राप्तियों/संवितरण के रूप में दर्ज राशि के संबंध में वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 एवं 10 में असंगति/विसंगति	75
(ख)	संघ सरकार वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में निवेश का अधूरा दर्शाया जाना	76
(ग)	ऋण अग्रिम के नियमों तथा शर्तों को अंतिम रूप न देना	78
2.4	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	78
2.4.1	मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष	79
	वे.ले.का. उचंत	81
	उचंत लेखा (सिविल)	82
	विदेशों में क्रय हेतु उचंत लेखा	83
	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (सा.क्षे.बैं. उचंत)	83
	रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (के.ले.का.)	84
2.4.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	85
2.4.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	85
2.4.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना	87
2.4.5	विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति	88
2.4.6	हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना	88
	अध्याय 3: विनियोग लेखेः 2012-13	
3.1	संवैधानिक प्रावधान	90
3.2	कुल प्रावधानों/वास्तविक संवितरणों का सारांश	91
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	93
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	94
3.5	अनुदानों में निरन्तर आधिक्य	97
3.6	लघु/उप शीर्ष-वार आधिक्य व्यय	99

3.7	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत (खण्ड-वार)	100
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	101
3.9	31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)	102
3.10	लघु/उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)	102
3.11	लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)	103
3.12	अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (40 प्रतिशत से अधिक)	103
3.13	अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान	105
3.14	उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त किए गए अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	106
3.15	निरन्तर बचत (उप-शीर्ष वार)	106
3.16	संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)	106
3.17	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	107
3.18	बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक की ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत (लघु/उप-शीर्ष वार)	109
3.19	मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय	109
3.20	रक्षा सेवाएं	112
3.20.1	निरंतर बचतें	112
3.20.2	रक्षा सेवाएं अनुदानों बचतों का अभ्यर्पण	113
3.20.3	रक्षा सेवाएं अनुदानों में उपलब्ध प्रावधान से अधिक निरंतर अतिरिक्त व्यय	114
	अध्याय 4: विनियोग लेखेः लेखाओं पर टिप्पणियां	
4.1	अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों में व्यय हेतु संसद से लगातार गलत प्राधिकरण प्राप्त किया जाना	116
4.2	के.प्र.क.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3)- करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय का लगातार उल्लंघन	116
4.3	के.उ.सी.शु.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) - करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय का लगातार उल्लंघन	118
4.4	बजट सीमा के बिना किया गया व्यय	118
4.5	संवर्धन प्रावधानों हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	119
4.5.1	विषय-शीर्ष 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	119
4.5.2	विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन	121
4.5.3	विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रावधान का संवर्धन	122
4.5.4	विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के प्रावधान का संवर्धन	123
4.5.5	विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रति प्रावधान का संवर्धन	124
4.6	पूंजी लेखे के बजाए तथा प्रतिक्रम में राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण	127

4.6.1	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	127
4.6.2	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	129
4.6.3	पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना	131
4.6.4	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	132
	गलत वर्गीकरण का प्रभाव	135
4.7	अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	135
4.7.1	भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना	135
4.7.2	विषय शीर्ष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों तथा सहायता अनुदान-वेतन का परिचालन न होना	136
4.7.3	अनुदान के समान प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में वर्गीकरण	138
4.7.4	'अन्य देशों को सहायता को दर्ज करने हेतु विषय शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन	145
4.7.5	लेखा के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का दर्ज किया जाना	147
4.7.6	अनुदानों की विस्तृत मांगों में गलत कोड शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान करना	148
4.7.7	लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग	148
4.7.8	गृह मंत्रालय में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गलत बुकिंग जारी रहना	149
4.7.9	लेखे के गलत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण	150
4.7.10	अनुपलब्ध विषय शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग	150
4.8	अंतरिक्ष विभाग द्वारा पूर्व-प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय	151
4.9	अंतरिक्ष विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश जारी करना	151
4.10	एकमुस्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	152
4.11	विषय शीर्षों के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति	157
4.12	निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना व्यय	158
4.13	डाक विभाग	162
4.13.1	बजट सीमा के बिना किया गया व्यय	162
4.13.2	पुनर्विनियोग आदेशों का जारी न किया जाना	162
4.14	रक्षा सेवाएं	163
4.14.1	बचतों/आधिक्य की राशियों को गलत दर्शाना	163
	अध्याय 5: सहायता अनुदान : एक विश्लेषण	**165**
5.1	प्रस्तावना	165
5.2	व्यय की प्रवृत्ति	165
5.2.1	प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान	166
5.2.2	योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान	167

5.3	योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति	168
5.3.1	कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) के लेखों में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष	170
5.3.2	सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन	171
5.4	योजनागत सहायता अनुदान पर व्यय डाटा; समग्रता एवं उपलब्धता के मामले	174
5.4.1	डाटा के अभाव एवं संस्वीकृतियों तथा निर्गमों के मध्य अंतर	175
5.4.2	सहायता अनुदान पर योजनागत व्यय से संबंधित डाटा के तीन स्रोतों में विभिन्नता	177
5.5	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)	178
5.6	उच्च शिक्षा विभाग एवं वस्त्र मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच	180
5.6.1	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	180
	अनुदान सं. 59-उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	**180**
5.6.2	प्रस्तावना	180
5.6.3	बजट एवं व्यय	181
5.6.4	सहायता अनुदानों पर व्यय का माह-वार प्रवाह	182
5.6.5	संस्थाओं - सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय, पंजीकृत समितियां आदि के संबंध में संस्वीकृत एवं जारी किये गये अनुदान	184
5.6.6	सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण	185
5.6.7	सहायता अनुदान रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण	186
5.6.8	अनुमोदन प्रक्रिया में कमिया	187
(क)	कार्यक्रम प्रभाग द्वारा अनुमोदन तथा वास्तव में जारी भुगतान के बीच अंतर	187
(ख)	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदान प्राप्त निकायों से संबंधित सूचना प्रदर्शित न करना	187
(ग)	संगठन के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना	188
(घ)	निर्गम, व्यय न किया जाना - अग्रिमों का गैर-प्रकटीकरण	189
5.6.9	जारी किए गए अनुदानों की निगरानी	189
(क)	स्वायत्त निकायों की बाह्य पीयर रिव्यू नहीं किया गया	189
(ख)	निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया	190
(ग)	त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण	191
(घ)	वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से संसद को ब्यौरों की सूचना न देना	192
(ङ)	बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)	193
5.6.10	वि.अ.आ. को अधिक अनुदान जारी किया जाना	194
	अनुदान सं. 93-वस्त्र मंत्रालय	**195**
5.6.11	प्रस्तावना	195
5.6.12	राजस्व लेखा पर प्रावधान एवं व्यय	195

5.6.13	अनुदानों पर वस्तु शीर्ष वार व्यय	196
5.6.14	अस्तित्वों के अनुसार व्यय - सा.क्षे.उ., स्था.नि., पंजीकृत सामितियां आदि	196
5.6.15	सहायता अनुदान पर माह वार व्यय का प्रवाह	198
5.6.16	मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा ₹750.56 करोड़ के मूल्य की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन का आश्वासन न देना	199
5.6.17	₹5 करोड़ से अधिक का सहायता अनुदान जारी किए जाने के मामले में समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) हस्ताक्षरित नहीं किया जाना	201
5.6.18	अनुदानग्राही से राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों की प्रमात्रा का पता लगाए बिना अनुदानों का निर्गम	201
5.6.19	अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब	202
5.6.20	₹259.87 करोड़ के अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना जारी अनुदान	203
5.6.21	उप.प्र. में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना	203
5.6.22	उपयोग प्रमाणपत्र (उप.प्र.)	204
5.6.23	निष्पादन सह उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	206
5.6.24	अनुदानग्राही निकायों से पर्याप्त प्रस्तावों के बिना बजटों की तैयारी	207
5.6.25	अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां	208
5.6.26	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का गैर-प्रकटीकरण	208
5.6.27	वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से संसद को विवरणों की सूचना न दिया जाना	209
5.6.28	स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई	209
5.6.29	त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण	210
5.6.30	निधियों की पार्किंग	211
5.6.31	रूचि के अन्य विषय	212
(क)	रा.फै.प्रौ.सं. से ब्याज की वसूली न होना	212
(ख)	'एकीकृत वस्त्र उद्यान' योजना कार्यान्वित करने वाले वि.उ.वा. से अनुदानों की मुख्य राशि तथा ब्याज की वसूली न होना	213
5.7	निष्कर्ष	215
	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	217
	अनुबंध 1.2	226
	अनुबंध 2.1	238
	अनुबंध 2.2	239
	अनुबंध 2.3	240
	अनुबंध 2.4	243

	अनुबंध 2.5	246
	अनुबंध 2.6	247
	अनुबंध 2.7	251
	अनुबंध 2.8	253
	अनुबंध 3.1	255
	अनुबंध 3.2	257
	अनुबंध 3.3	258
	अनुबंध 3.4	259
	अनुबंध 3.5	263
	अनुबंध 3.6	266
	अनुबंध 3.7	270
	अनुबंध 3.8	271
	अनुबंध 3.9	275
	अनुबंध 3.10	277
	अनुबंध 3.11	278
	अनुबंध 3.12	279
	अनुबंध 3.13	280
	अनुबंध 3.14	283
	अनुबंध 3.15	291
	अनुबंध 3.16	305
	अनुबंध 4.1	308
	अनुबंध 4.2	312
	अनुबंध 4.3	315
	अनुबंध 5.1	320
	अनुबंध 5.2	321
	अनुबंध 5.3	322
	अनुबंध 5.4	323
	अनुबंध 5.5	324
	अनुबंध 5.6	325
	शब्दावली	**326**

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत टिप्पणियां पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित है। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं - सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं - वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विशिष्टताएं

संघ सरकार के वित्त एवं लेखे: 2012-13

यह प्रतिवेदन संघ के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर चर्चा करता है तथा वर्ष 2012-13 के लिए संघ सरकार के वित्त का विश्लेषण करता है। इसमें विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा वर्ष 2012-13 के संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं।

विशिष्टताएं

संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियां

- 2012-13 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्राथमिक रूप से, पूर्वगामी वर्ष में गैर कर प्राप्तियों में धीमीवृद्धि के पश्चात, कर राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों दोंनों में पर्याप्त वृद्धि के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों में 15.59 प्रतिशत की वृद्धि के द्वारा वर्णित किया गया था।

  (पैरा 1.2.1,1.2.3 एवं 1.2.4)

- पूँजीगत व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय समेकन योजना में वर्ष के लिए निर्धारित 3.8 प्रतिशत के स्तर से बहुत नीचे, स.घ.उ. का 1.80 प्रतिशत था। कुल पूंजीगत व्यय में से 39 प्रतिशत रक्षा द्वारा दर्ज किया गया था।

  (पैरा 1.1.2 एवं 1.3.4)

- सिविल मंत्रालयों के योजनागत व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुल योजनागत व्यय का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान भुगतान के रूप में था। सबसे अधिक योजनागत व्यय कर रहे 10 मंत्रालयों/विभागों में से तीन में 99 प्रतिशत सहायता अनुदान के संवितरण के रूप में था।

  (पैरा 1.3.7 एवं 1.3.8)

- कर निर्धारितियों से ₹249.50 करोड़ की राशि के अग्रिम भुगतानों की प्राप्तियों का लोक लेखे से भारत की समेकित निधि (भा.स.नि) में अंतरण न होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 में इसके समकक्ष राशि से भारत सरकार की सीमा शुल्क प्राप्तियों को कम बताया गया। चूँकि सीमा शुल्क प्राप्तियां केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करों का विभाज्य संचय का भाग बनती है, इसलिए भा.स.नि. में राशि जमा न करने से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्यों को बांटे जाने वाले करों में अल्प अंतरण निहित रहता है।

  (पैरा 2.1.4)

- दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹6,735.47 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (सा.से.दा. निधि) को केवल ₹625 करोड़ का अंतरण एवं संवितरण किया। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष के ₹6,110.47 करोड़ तक कम कथन में हुआ। 2002-03 से 2012-13 के दौरान सा.से.दा.निधि के अंतशेष में ₹27,949.92 करोड़ का कम कथन था।

(पैरा 2.2.1)

- कुल ₹4,139.17 करोड़ के अनुसंधान तथा विकास उपकर का 1996-97 से 2012-13 की अवधि के दौरान संग्रहण किया गया था। इसमें से केवल ₹528.91 करोड़ (12.77 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उगाही के उद्देश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.2.2)

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से प्राप्तियों से काफी अधिक में व्यय होने के कारण वर्षों से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था जो 2007-08 में (-)₹24.56 करोड़ से 2012-13 में (-)₹200.46 करोड़ तक लगातार बढ़ा।

(पैरा 2.2.3)

- 2008-13 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) में पड़ी राशियों के निवेश से अर्जित तथा भारत की समेकित निधि में क्रेडिट की गई ₹905.23 करोड़ की कुल आय में से चयनित पहलों पर व्यय को पूरा करने के लिए, भारत की समेकित निधि में ₹398.11 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुए, लोक लेखे में केवल ₹507.12 करोड़ का अंतरण किया गया था।

(पैरा 2.2.6)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अलावा, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। तथापि, 2012-13 के दौरान भा.स.नि. से प्राधिकृत राशि से ₹6,591 करोड़ तक (सिविल मंत्रालयों के चार अनुदानों के पांच खंडों में ₹4,565 करोड़; रेल मंत्रालय की आठ अनुदानों/विनियोजनों के दस खंडों में ₹ 1,670 करोड़, डाक

विभाग की एक अनुदान के एक खण्ड में ₹160 करोड़, तथा रक्षा सेवाओं की तीन अनुदानों के तीन खंडों में ₹196 करोड़) के अधिक संवितरण किए गए थे जिसका संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत नियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.4)

- अनुदान अथवा विनियोग में बचत त्रूटिपूर्ण बजट बनाने तथा निष्पादन में कमी का सूचक है। 84 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाएं) के 104 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत थी जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 104 मामलों में कुल मिलाकर बचतें ₹5,86,099 करोड़ की थी।

(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.5)

- पिछले तीन वर्षों (2010-2013) के दौरान 42 अनुदानों/विनियोगों के 53 अनुभागो में ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी। तीन वर्षों की अवधि के दौरान कुछ अनुदान/विनियोगों में बड़ी निरन्तर बचतें, ऋण का पुनर्भुगतान (₹9,71,751 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹86,554 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (₹67,523 करोड़), आर्थिक मामले विभाग (₹69,807 करोड़), ऊर्जा मंत्रालय (₹23,202 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹13,917 करोड़) तथा पुलिस (₹8,449 करोड़) में थी।

(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.6)

- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयुध कारखानों के अनुदान में वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग अधिनियम के माध्यम से प्राप्त प्राधिकार ₹13,014.94 करोड़ की राशि के बजाए ₹1,801.68 करोड़ की राशि के लिए था जोकि सकल व्यय प्रावधान था। इसने ₹11,213.26 करोड़ के कम प्राधिकार को भारत की समेकित निधि से प्राप्त किया था।

(पैरा 4.1)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में यह व्यवस्था है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अलावा, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2012-13 के दौरान संसद के अनुमोदन के बिना ₹6,666 करोड़ राशि के प्रतिदायों के ब्याज पर व्यय किया। पिछले छः वर्षो से आवश्यक विनियोजनों के माध्यम से संसद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर ₹40,749 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार,

पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा करों की वापसी पर ब्याज पर ₹44.78 करोड़ को इसे राजस्व में कटौती के रूप में मानते हुए व्यय किया गया।

(पैरा 4.2 एवं 4.3)

- किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को 'सहायता अनुदान' में भारत की समेकित निधि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन केवल संसद की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। नौ अनुदानों/ विनियोगों के 19 मामलों में 2012-13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बिना संसदीय पूर्वानुमति प्राप्त किए विभिन्न निकायों/ प्राधिकरणों को '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करके ₹418.75 करोड़ का व्यय किया गया था।इसी प्रकार, दो अनुदानों के दो मामलों में, ₹80.78 करोड़ का वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में तथा बिना संसदीय पुर्वानुमति के विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' को आवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अनुदानों के पांच मामलों में कुल ₹55.84 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' को अवर्धन किया गया था। इन सभी अधिक व्ययों ने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया।

(पैरा 4.5.1, 4.5.2 तथा 4.5.3)

- विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोग में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमति आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। तीन अनुदानों के चार मामलों में 2012-13 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति लिए बगैर मंत्रालयों/ विभागों द्वारा ₹100.04 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। इस अधिक व्यय ने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया था।

(पैरा 4.5.4)

- विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी तथा उपकरण' में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोग में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमान आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹ 2.5 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। 12 अनुदानों में 2012-13 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति लिए बगैर मंत्रालयों/विभागों द्वारा ₹407.07 करोड़ का इन विषय शीर्षों

के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करने हेतु अधिक व्यय किया गया था। इस अधिक व्यय ने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया था।

(पैरा 4.5.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विपरीत में गलत वर्गीकरण किया। गलत वर्गीकरण का परिणाम ₹698.07 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के अतिकथन तथा ₹1,781.62 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के कम बताए जाने में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1,083.55 करोड़ के पूंजीगत व्यय का कम बताया जाना हुआ। संगत रूप से राजस्व घाटे को वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹1,083.55 करोड़ की समान राशि तक अधिक बताया गया था।

(पैरा 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 तथा 4.6.4)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 छठी श्रेणी अर्थात् विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता है। 23 अनुदानों/विनियोगों के 30 मामलों में ₹2,992.75 करोड़ को विनियोग की इन प्राथमिक इकाईयों में गलत वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.7.3)

- जहां आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु तुरन्त उपाय किये जाने हों अथवा ऐसी किसी परियोजना/योजना जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारम्भ किये जाने हेतु सैधान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी हो, पर प्रारम्भिक व्यय की पूर्ति की जानी हो, को छोड़कर किसी भी अन्य स्थिति में बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। पाँच अनुदानों में एक मुश्त अनुपूरक प्रावधान वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में प्राप्त किए गए थे तथा अतिरिक्तताओं को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजनाओं को, जिनके पास अनुदानों हेतु विस्तृत मांग में अलग बजट लाईन हैं, संवितरित किया गया था। तदनुसार, विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' तथा 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने' को एकमुश्त अनुपूरक के माध्यम से ₹2,55.42 करोड़ का आवर्धन किया गया था जोकि वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था, जिसमें सहायता अनुदान के प्रत्येक आवर्धन के लिए संसद से पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

(पैरा 4.10)

- लोक सेवा प्रदाय के स्थानांतरण प्रतिमान ने अनुदान सहायता, व्यय में लगातार वृद्धि का नेतृत्व किया है जिससे इसने ऋण पुनर्भुगतानों की छूट के अपवाद के साथ, अनुदान हेतु व्यय की सबसे बड़ी मद का गठन किया है। समितियों, गै.स.सं., ट्रस्टों को योजनागत सहायता अनुदान जारी करने की पर्याप्त राशि हेतु नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा छूट न तो उन्मुक्त और न ही अप्रतिबंधित है। पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने हेतु नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 का प्रस्तावित संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं।

(पैरा 1.3.10, 5.1 एवं 5.3.2)

- वर्ष 2012-13 के लिए, संघ सरकार ने, राज्य सरकार के बजट के बाहर, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹1,04,971 करोड़ की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखे के बाहर अनुरक्षित इनके लेखाओं में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिर्धारणीय थी। इसलिए, सरकारी व्यय, जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया था, को उस सीमा तक अधिक बताया गया।

(पैरा 5.3.1)

- वस्त्र मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायता अनुदान पर व्यय के विस्तृत परीक्षण से किए गए व्यय की गुणवत्ता से संबंधित अपर्याप्त आश्वासन तथा कमजोर नियंत्रण तंत्र की मौजूदगी के बारे में पता चला।

(पैरा 5.6)

1:संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2012-13 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में संघ सरकार के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए, जिसमें वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों की विवरणी को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे विधायिकाओं द्वारा प्राधिकृत राशियों के साथ मिलान करते हुए व्यय तथा प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत परिणामतः आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरण को दर्शाते हैं।

बाक्स 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	• संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्ष एक समेकित निधि बनाएंगे।
आकस्मिकता निधि	• संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। • ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात् आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	• समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविय निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। • इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।

1.1.1 वर्ष 2012-13 आर्थिक विकास में गिरावट के रूप में चिन्हित किया गया था जो कि सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि[1] द्वारा वर्ष 2011-12 में 6.6 प्रतिशत के प्रति 4.7 प्रतिशत मापी गई। 2012-13[2] के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आयात की तुलना में निर्यात में कम विकास और निवेश दर में कमी के कारण विकास दर में काफी गिरावट आई। सर्वेक्षण में आगे यह नोट किया गया कि 2012-13 में सेवा क्षेत्र की विकास दर भी 6.6 प्रतिशत तक गिर गई और निजी अंतिम उपभोग (भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, विद्युत, स्वास्थ्य सेवायें, परिवहन, शिक्षा आदि) व्यय जो कि बाजार मूल्य पर स.घ.उ. का तीन बटे पांचवा भाग बनाता है, भी 2012-13 में 4.1 प्रतिशत तक काफी धीमा हो गया है।

---

[1] 31 जनवरी 2014 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 2004-05 के बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुमान पिछले वर्ष से 4.7 प्रतिशत तक बढ़े जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह 12.2 प्रतिशत तक बढ़े। बाजार मूल्यों (वर्तमान मूल्यों) पर स.घ.उ. के अनुमानों को पिछले वर्ष के प्रतिवेदनों के साथ तुलना के उद्देश्य से अपनाया गया है।

[2] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (फरवरी 2013)

इस पृष्ठभूमि के विरूद्ध, यह अध्याय वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहंगावलोकन प्रदत करता है। **तालिका 1.1** वर्ष 2012-13 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा संघ सरकार के उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्तियां *	1055891 (910277)	**राजस्व घाटा 364582** (394918)	राजस्व व्यय	1420473 (1305195)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	25889 (18088)		पूंजीगत व्यय	150382 (139465)
कर्जो की वसूली	26624 (36818)		ऋण तथा अग्रिम	32063 (38404)
कुल गैस-ऋण प्राप्तियां	1108404 (965183)	**राजकोषीय घाटा 494514** (517881)	वास्तविक व्यय	1602918 (1483064)
लोक ऋण	3968038 (4063177)		लोक ऋण	3426893 (3495929)
भा.स.नि.में कुल प्राप्तियां	5076442 (5028360)	**भा.स.नि. में अधिशेष 46631** (49367)	भा.स.नि. में कुल व्यय	5029811 (4978993)
आकस्मिकता निधि				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
लोक लेखा				
लघु बचतें	381315 (372828)		लघु बचतें	375092 (358502)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	117117 (108076)		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	117529 (102402)
जमा	113974 (92993)		जमा	107536 (93552)
अग्रिम	33424 (35290)		अग्रिम	37140 (40209)
उचन्त लेखे	11832 (4894)		उचन्त लेखे	16275 (56477)
प्रेक्षण	3122 (6586)		प्रेक्षण	2831 (2901)
कुल लोक लेखे	660784 (620667)	**लोक लेखे में अधिशेष 4381** (घाटा33376)	कुल लोक लेखे	656403 (654043)
प्रारंभिक नकद	17439 (1449)	**नकद में वृद्धि 51012** (15991)	अन्तः नकद	68451 (17439)
लोक लेखा घाटा (मांग)		-4381	(भा.स.नि.) में अधिशेष–रोकड़ में वृद्धि	
वार्धिक देयताएं (आपूर्ति)		553394	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्धिक देयताएं (मांग)		553394	राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में वृद्धि (+) (अग्रिम+उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण	

**राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़ों को शामिल नहीं करता (2012-13 के लिए ₹2,91,547 करोड़)*

नोटः (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2011-12 के लिए अनुरूप आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2012-13 के लिए राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय को, करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय को व्यय की बजाय "कम किया राजस्व" के रूप में दर्शाने के कारण ₹ 6,682 करोड़ से कम बताया गया है। विवरण के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2 एवं 4.3 का संदर्भ लें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया, 2012-13 में भी, 2011-12 की तरह, भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) में अधिशेष था। पिछले वर्ष की तुलना में भा.स.नि. के अधिशेष में ₹2,736 (5.54 प्रतिशत) की गिरावट आई थी। संघ सरकार के गैर-ऋण प्राप्तियों में 14.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद भा.स.नि. के अधिशेष में कमी आई। लोक ऋण की प्राप्ति में 2.34 प्रतिशत की कमी तथा वास्तविक व्यय में 8.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी, भा.स.नि. के अधिशेष में कमी के मुख्य कारण है। लोक लेखे के मामले में, जहाँ सरकार एक बैंकर न्यासी के रूप में कार्य करती है, पिछले वर्ष के घाटे की तुलना में इस वर्ष अधिशेष हुआ था।

1.1.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय मापदंडों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन

सकल घरेलू उत्पाद (स.उ.घ.) की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकल तथा तेरहवें वित्त आयोग (13वें वि.आ.) की रिपोर्ट द्वारा तैयार रूपरेखा को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.2: केन्द्र हेतु राजकोषीय समेकन मार्ग का सारांश (तेरहवां वित्त आयोग)

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

मापदंड	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित					वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन		
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व घाटा	3.2	2.3	1.2	0.0	-0.5	3.26	4.38	3.60
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.67	0.61	0.52
पूंजीगत व्यय	3.0	3.1	3.8	3.9	4.5	2.33	1.97	1.80
राजकोषीय घाटा	5.7	4.8	4.2	3.0	3.0	4.92	5.75	4.89
ऋण (वर्ष के अंत की समायोजन देयताएं	53.9	52.5	50.5	47.5	44.8	45.38	46.08	46.54

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कोई भी मापदण्ड 13वें वि.आ. द्वारा 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वस्तुतः, वर्ष 2012-13 का राजस्व घाटा 13वें वि.आ. द्वारा रूपांकित लक्ष्य से तीन गुना से अधिक है। दिलचस्प रूप से, पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों में अपकर्ष स्पष्ट दिखता है। विशेषकर, वर्तमान वर्ष में पूंजीगत व्यय 13वें वि.आ. द्वारा 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्य से लगभग आधा है। यद्यपि, वर्तमान वर्ष में ऋण 46.54 पर रहा जोकि 50.5 के बेंचमार्क लक्ष्य से नीचे है, फिर भी लगातार पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 45.38, 46.08 और 46.54 की इसकी बढ़ती प्रवृत्ति को 13वें वि.आ. द्वारा 2014-15 के लिए 44.8 के निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है।

1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व की स्थिति (लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सकल प्रोद्भूत) का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:

1.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष को सकल राजस्व प्राप्तियों में 15.59 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि (2011-12 में 1.19 प्रतिशत के सीमांतवृद्धि की तुलना में) द्वारा विशेषीकृत किया गया है। 2012-13 हेतु सकल ऋण प्राप्ति से सकल प्राप्ति 65.82 प्रतिशत थी जो कि 2011-12 में 68.82 प्रतिशत थी, जो बजट को संतुलित करने हेतु ऋणों पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

तालिका 1.3: स.घ.उ. में प्राप्तियों का अंश

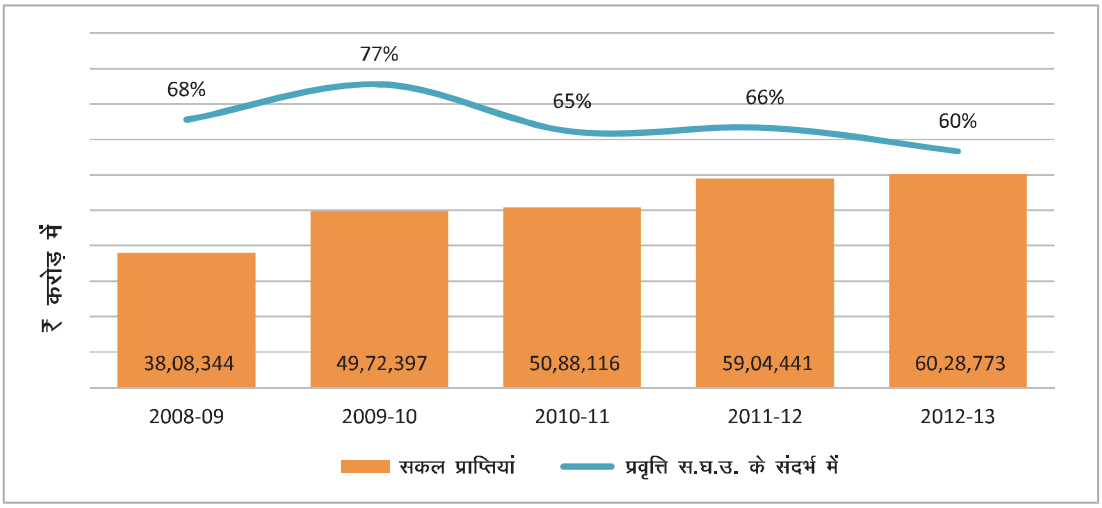
(₹ करोड़ में)

वर्ष	*सकल राजस्व प्राप्तियां** (1)	गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3+4)	स.घ.उ.@	सकल प्राप्तियां / स.घ.उ. (6)
2008-09	814026 (21%)	14075 (0%)	2395765 (63%)	584478 (15%)	3808344	5582623	68
2009-10	869355 (17%)	37314 (1%)	3405327 (68%)	660401 (13%)	4972397	6477827	77
2010-11	1151989 (23%)	52099 (1%)	3177106 (62%)	706922 (14%)	5088116	7784115	65
2011-12	1165691 (20%)	54906 (1%)	4063177 (69%)	620667 (11%)	5904441	9009722	66
2012-13	1347438 (22%)	52513 (1%)	3968038 (66%)	660784 (11%)	6028773	10113281	60

**राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं (2012-13 के लिए, 2,91,547 करोड़)। इस घटक का अपवर्जन ₹10,55,891 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्ति देता है जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है।*

@स्त्रोतःकेन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ब्यूरो मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2014 आंकडों का के.सां.सं. द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है तथा यह डाटा वृहत अर्थव्यवस्था निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की एक संकेतिक तुलना हेतु है।

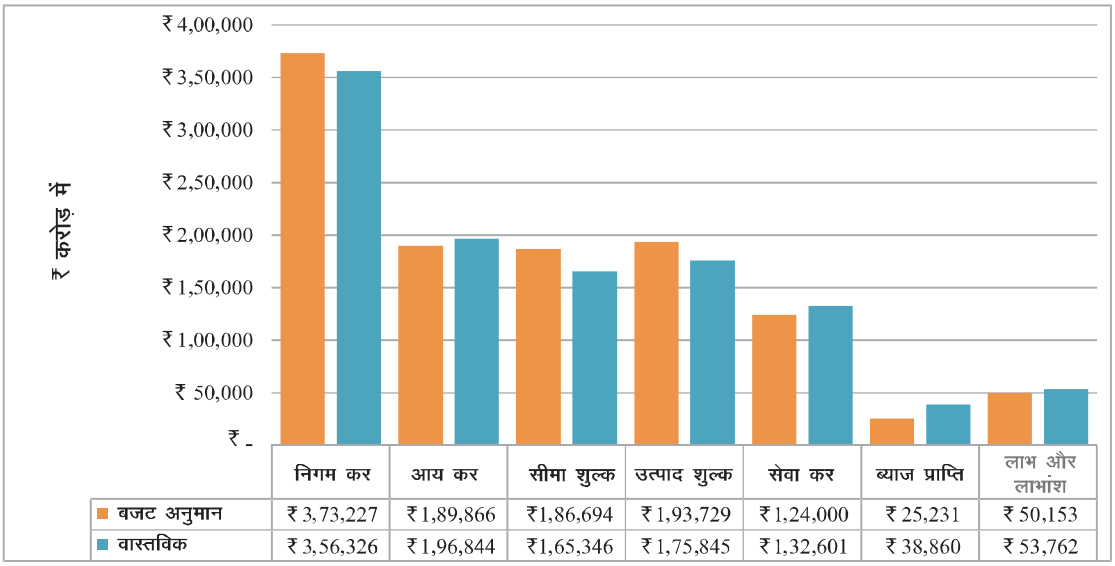
चार्ट 1.1: स.घ.उ. के संदर्भ में सकल प्राप्तियों एवं प्रवृत्ति में वृद्धि



1.2.2 मुख्य राजस्व संबंधित मापदंडों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का सूत्रीकरण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.2 दर्शाता है कि आयकर एवं सेवा कर के अलावा सभी करों से प्राप्ति अनुमानित स्तर से काफी कम थी। कर रहित राजस्व क्षेत्र में लाभांशों एवं लाभ से प्राप्तियाँ तथा ब्याज प्राप्तियाँ ब.अ. से क्रमशः 54 प्रतिशत और 7.20 प्रतिशत अधिक थीं।

चार्ट 1.2 बजट अनुमानों से सकल वास्तविक प्राप्तियों का विचलन



1.2.3 कर राजस्व

तालिका 1.4: कर राजस्व के घटक (सकल)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ.
XIवीं योजना (2007-12) औसत	**701080**	**254507**	**126956**	**114493**	**123563**	**67838**	**13723**	**6760429@**
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395	5582623
2009-10	624528	244725	122417	83324	102991	58422	12649	6477827
2010-11	793308	298688	139102	135813	137701	71016	10988	7784115
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	9009722
2012-13	1036461	356326	196844	165346	175845	132601	9499	10113281
वृद्धि की औसतन वार्षिक दर (*प्रतिशत*)								
XIवीं योजना (2007-12)	**11.41**	**14.64**	**12.91**	**10.83**	**5.71**	**15.46**	**(-)15.02**	16.55
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-)4.07	(-)12.13	18.79	(-)11.59	12.83
2009-10	3.18	14.68	15.41	(-)16.58	(-)5.18	(-)4.13	(-)22.85	16.04
2010-11	27.03	22.05	13.63	62.99	33.70	21.56	(-)13.13	20.17
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	15.74
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.73	21.36	35.99	(-)5.38	12.25

#राज्यों/सं.शा.क्षे.को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं.

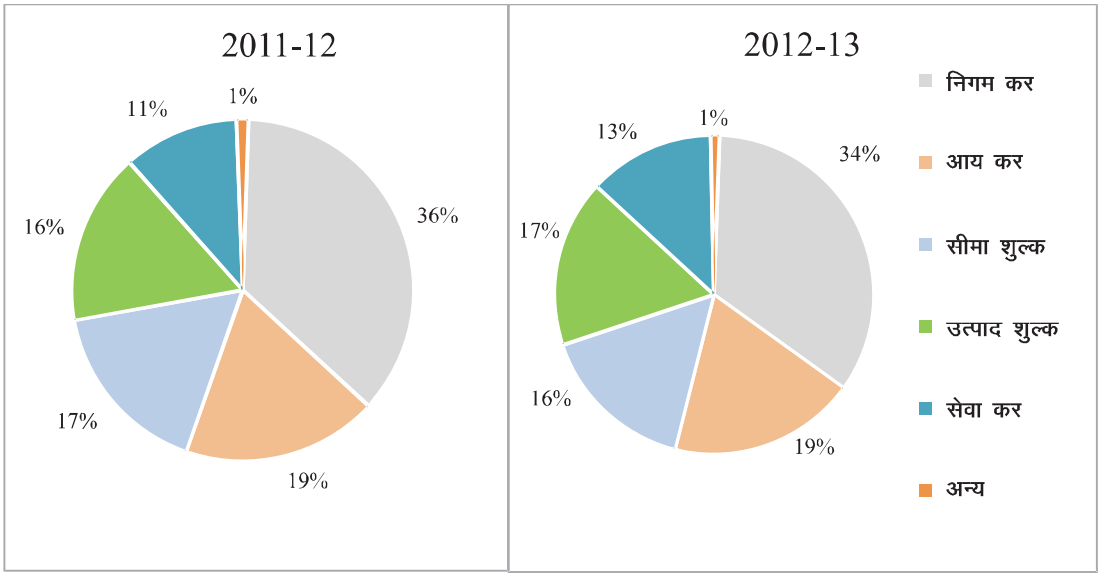
**अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पति कर, उपहार कर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।*

@2007-08 के लिए स.घ.उ. ₹ 49,47,857 करोड़ था।

जैसा कि **तालिका 1.4** से देखा जा सकता है जबकि चालू वर्ष में समग्र कर राजस्व 16.57प्रतिशत तक बढ़ा,फिर भी सेवा कर में सार्थक वृद्धि थी जो 35.99 प्रतिशत तक बढ़ा था। सकल करों की वृद्धि चालू वर्ष के स.घ.उ. से अधिक थी, जो पिछले वर्ष के प्रवृत्ति में उत्क्रमण का संकेत करती है। निगम कर जो कर राजस्व का तीसरे हिस्से से अधिक का योगदान करता है निरन्तर चिंताजनक प्रवृत्ति को दिखाता है। निगम कर की वृद्धि दर (10.38 प्रतिशत), कर राजस्व की कुल वृद्धि दर (16.57 प्रतिशत)और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान निगम कर की औसत वृद्धि दर (14.64 प्रतिशत) से भी कम थी।

चार्ट 1.3 में दिखाए गए 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कर राजस्वों के सापेक्ष अंशों की तुलना में सेवा कर के अंशों में बहुत कम वृद्धि दर्शाता है (दो प्रतिशत से) और दूसरी ओर निगम कर के अंश में कमी थी (दो प्रतिशत से); बाकी अंश लगभग वही हैं।

चार्ट1.3: कर राजस्व के घटक



1.2.4 गैर-कर राजस्व

तालिका 1.5 दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान,गैर-कर राजस्व (59 प्रतिशत) का सबसे बड़ा अंश विभिन्न विभागों द्वारा उद्ग्रहित उपभोक्ता प्रभारों से आता है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्याज प्राप्तियों ने गैर-कर राजस्व का 13प्रतिशत संघटित किया जबकि लाभांश तथा लाभ लगभग 17प्रतिशत तक दर्ज किए गए थे। पिछले वर्ष में 22.89% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्तमान वर्ष में 12.44 प्रतिशत के गैर-कर राजस्व में सकारात्मक वृद्धि थी। यह मुख्यतः सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों (387.75 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हुआ था जो कि पिछले वर्ष के समाज सेवाओं के लगभग सभी घटकों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व #	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	स्वायत्त तथा अन्य कार्य **
XIवीं योजना (2007-12) औसत	**259378**	**35332**	**44392**	**759**	**155743**	**23151**
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	**100**	**14**	**17**	**नगण्य**	**60**	**9**
2008-09	208728	30846	38608	540	118146	20588
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	100	15	19	**नगण्य**	57	10
2009-10	244827	35849	50250	713	133038	24977
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	100	15	21	**नगण्य**	54	10
2010-11	358681	35299	47993	814	248252	26323
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	100	10	14	**नगण्य**	69	7
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	100	15	18	**नगण्य**	57	10
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (*प्रतिशत*)	100	13	17	2	59	9
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
XI वीं योजना (2007-12)	**11.75**	**4.36**	**10.34**	**10.33**	**13.65**	**11.82**
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
2009-10	17.29	16.22	30.15	32.04	12.60	21.32
2010-11	46.50	(-)1.53	(-)4.49	14.17	86.60	5.39
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39

टिप्पणीः सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग हमेशा 100 नहीं भी हो सकता है। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत से कम है।

#अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है।

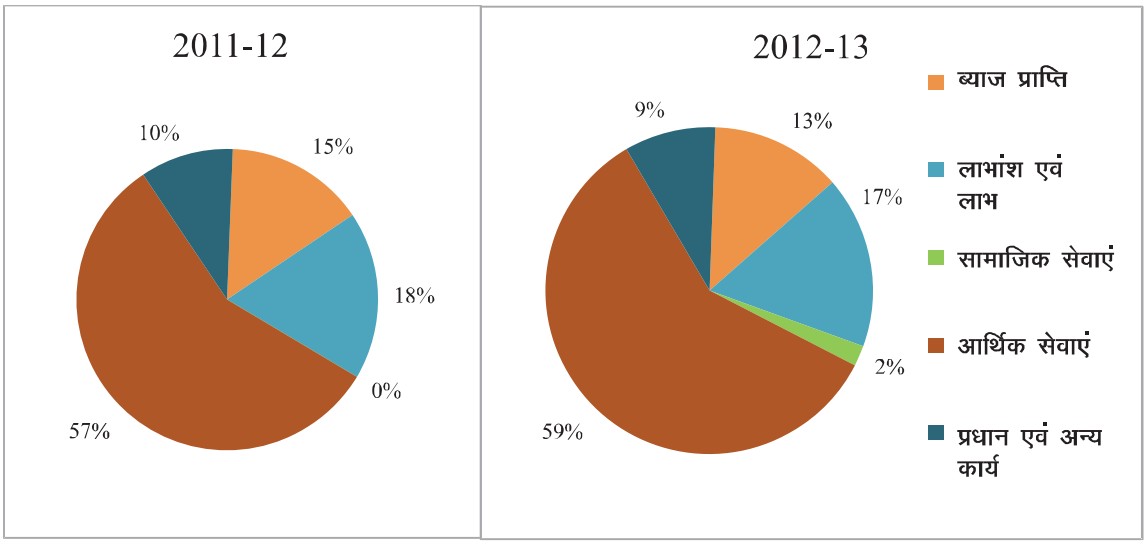
सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा सरकारी उपक्रमों जैसे रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

**राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)

गैर-कर राजस्व के घटकों के सापेक्ष अंश **चार्ट 1.4** में नीचे दर्शाए गये हैं। यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों ने गैर-कर राजस्व में मुख्य भाग बनाया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से राजस्व के अंशों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई। वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम थे जिनमें सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से प्राप्ति जो कि 2011-12 में ₹ 1.09 करोड़ से 2012-13 में ₹ 3594.14 करोड़ तक वृद्धि हुई ओर पेट्रोलियम-अन्य प्राप्ति जोकि 2011-12 में ₹260.39 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹637.04 करोड़ हो गई और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-अन्य प्राप्ति 2011-12 में ₹ 108 करोड़ से 2012-13 में ₹ 473.74 करोड़ हुई।

चार्ट 1.4: गैर-कर राजस्व के घटक



नोटः 2011-12 में 'सामाजिक सेवाओं' का अंश गैर-कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत से कम था।

1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस अंश, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। **तालिका 1.6** विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती हैं। 2012-13 के दौरान, विनिवेश प्राप्तियाँ पिछले दो वर्षों की तुलना में बजट अनुमानों के समीप थीं। ऋणों की वसूली, पिछले वर्षों के जैसे, बजट अनुमानों से काफी अधिक थी, जो कि अनुमानों के सूत्रीकरण में कमी को दर्शाता है।

तालिका 1.6: विनिवेश से प्राप्तियाँ तथा कर्जों की वसूली

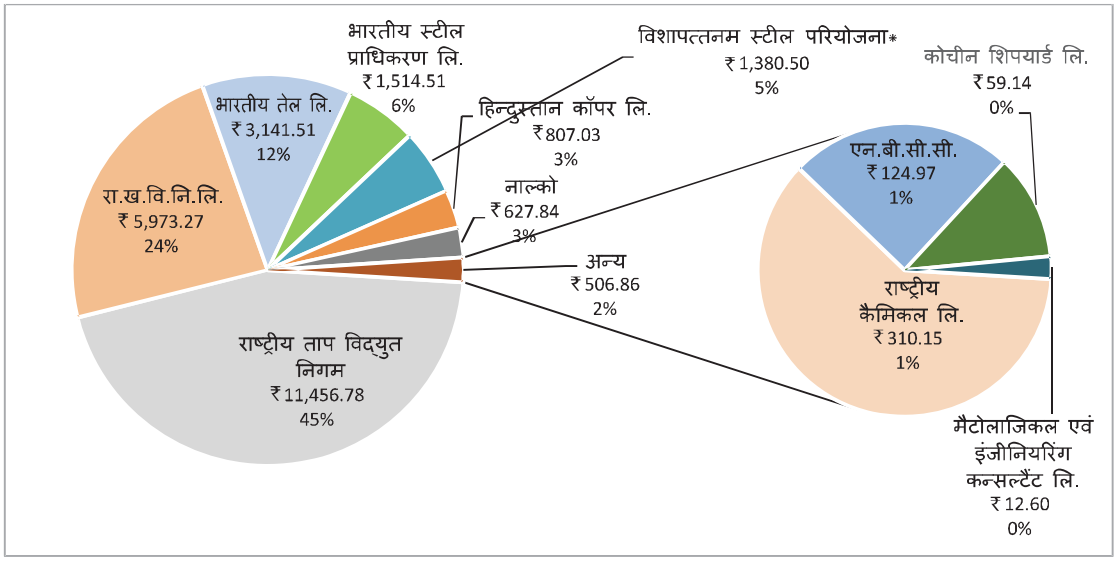
अवधि	विनिवेश			ऋणों की वसूली		
	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ* (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
2008-09	10165	22	0.22	5993	13509	225.41
2009-10	1120	23599	2107.05	5720	12733	222.60
2010-11	40000	22277	55.69	6624	29253	441.62
2011-12	40000	14027	35.07	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28

**बोनस अंश शामिल नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में चार सा.क्षे.उ. द्वारा भारत सरकार को जारी कुल ₹115.80 करोड़ के बोनस अंशों को 2012-13 के लिए वित्त लेखे में दर्ज नहीं किया गया है (पैरा सं. 2.3.13 के संदर्भ में)।*

वर्ष के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों का ब्यौरा **तालिका 1.5** में दिया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा.ख.वि.नि.) लिमि.नामक दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश लाभ का 69 प्रतिशत देखा जा सकता है।

चार्ट 1.5: विनिवेश लाभ के घटक

(₹ करोड़ में)

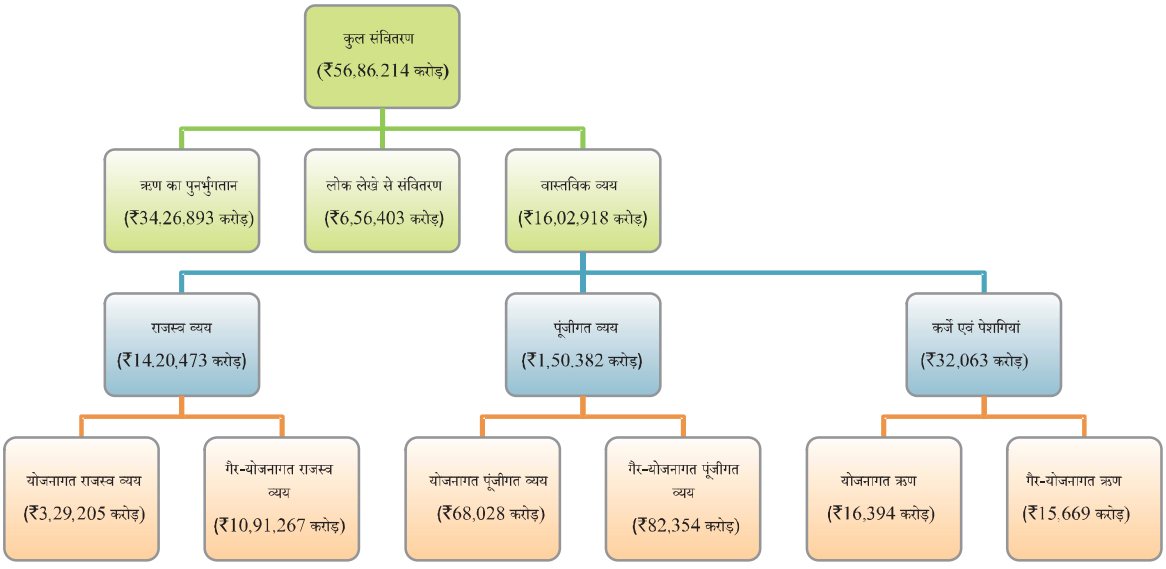


पूर्व में 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड' से जाना जाता था।

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत सरकार की समेकित निधि से तथा लोक लेखे से कुल संवितरण ₹ 56,86,214 करोड़ था। जैसा कि **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है कि कुल संवितरण के तीन मुख्य घटक हैं।

चार्ट 1.6: कुल संवितरणों के घटक



2012-13 में, सरकार के कुल संवितरणों में बहुत कम (एक प्रतिशत से कम) बढ़ोतरी हुई। कर्ज का पुनर्भुगतान संपूर्ण का सबसे बड़ा भाग था। संवितरण, कुल संवितरण का 60 प्रतिशत लेखा के लिए एवं 12 प्रतिशत लोक लेखा में भुगतान के लिए था। इस प्रकार, चालू कार्यों के लिए वास्तविक व्यय के प्रति केवल 28 प्रतिशत था।

1.3.1 भारतीय समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा (ई-लेखा डाटा)

चूंकि वित्त लेखा में घटक-वार व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है,आगामी पैराग्राफ में ई-लेखा का प्रयोग कुछ विश्लेषणों में पूरक के रूप में किया गया है।ई-लेखा, जो कि भुगतान एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य ऑफलाइन इंटरफेस पर कॉम्पेक्ट पर बनाया जाता है, मॉनीटरिंग तंत्र एवं मूल्य वद्धित रिपोर्टिंग के लिए दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के एकीकरण के साथ कोर लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करते हैं।

वित्त लेखा में व्यय आंकड़ों की निवल वसूलियां दर्शाई गई है और इस प्रकार, ई-लेखा से आंकड़े जहाँ भी लिए गए हैं, निवल वसूलियों के रूप में लिए गए हैं।

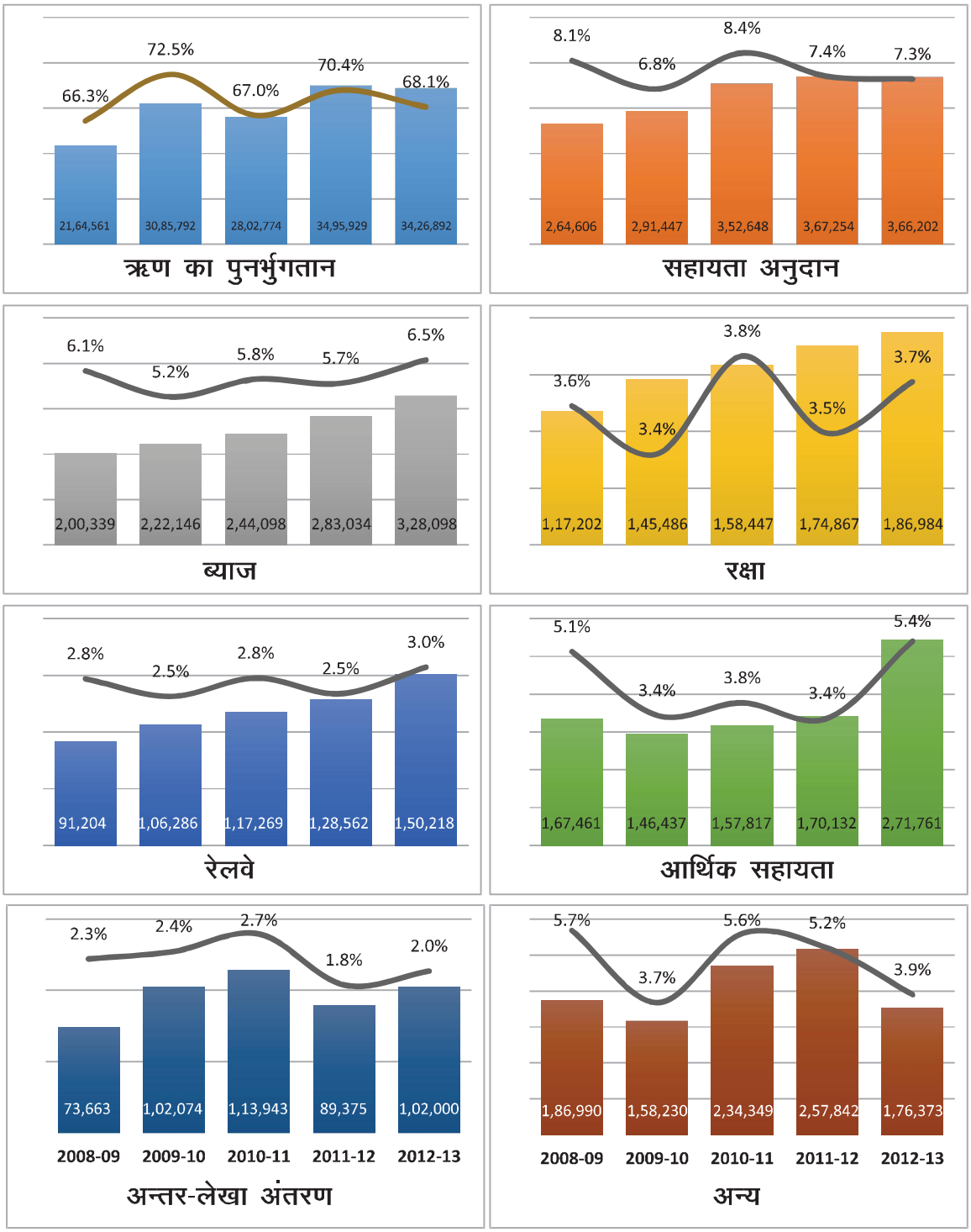
भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) से व्यय का सबसे बड़ा घटक सार्वजनिक ऋण के पुर्नभुगतान की ओर था। जैसा कि चार्ट.1.7 में देखा जा सकता है, भा.स.नि. से कुल व्यय में से सार्वजनिक ऋण के पुर्नभुगतान का अंश 2011-12 में 70 प्रतिशत से 2012-13 में 68 प्रतिशत तक बहुत कम घटा है।

यह भी देखा गया है कि रक्षा सेवाओं पर व्यय 2011-12 में ₹ 1,74,867 करोड़ से 2012-13 में ₹1,86,984 करोड़ तक बढ़ गया था। इस अवधि में कुल व्यय में इसके अंश में भी 3.5 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत तक की थोडी सी वृद्धि हुई थी। विभिन्न रक्षा सेवाओं के अंश भी **चार्ट 1.13** में दर्शाये गए हैं।

2011-12 में 'अन्य प्रभारों' में ₹ 65,000 करोड़ की 'सब्सिडियों' के गलत वर्गीकरण (जैसाकि 2013 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया है) के कारण वर्ष 2012-13 में सब्सिडियों पर व्यय तथा अंश में काफी वृद्धि देखी गई थी। यह 'अन्य' शेयरों में तीव्र गिरावट का प्रभाव था जो 2011-12 में 5.2 प्रतिशत से 2012-13 में 3.9 प्रतिशत हो गया।

रेलवे के मामले में,यद्यपि औसत व्यय में वर्ष 2008-09 से लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, कुल भा.स.नि. में इसका अंश 2.5 से 3.0 प्रतिशत पर लगभग समान था।

चार्ट 1.7: भारत की समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा



स्त्रोतः 26 जुलाई 2013 को प्रदत्त ई-लेखा डाटा डंप। इसमें जर्नल की प्रविष्टियाँ शामिल नहीं हैं।

टिप्पणीः ***चार्ट में दी गई राशि करोड़ में*** *है। प्रवृत्ति रेखा भा.स.नि. से कुल व्यय में प्रतिशत अंश को दर्शाती है। गलत वर्गीकरण के कारण, 2011-12 के दौरान 'सब्सिडी' के अंतर्गत ₹65,000 करोड़ की सब्सिडी की गणना ही नहीं की गई थी। 'ब्याज' पर व्यय हेतु, केवल मुख्य शीर्षों 2048 तथा 2049 के नीचे वस्तु शीर्ष 45 के अंतर्गत आंकड़ों को ही लिया गया है। रक्षा में रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदान शामिल नहीं है। 'अन्य' 'कम वसूलियां' का निवल है।*

नीचे **तालिका 1.7** सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के मुख्य घटकों के अंश को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2011-12 के दौरान 62.06 प्रतिशत से 2012-13 में 60.27 प्रतिशत तक घट गया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 11 प्रतिशत तक लोक लेखा संवितरण का अनुरक्षण करते हुए, वास्तविक व्यय का अंश 26.33 प्रतिशत से 28.19 प्रतिशत तक बढ़ गया। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 88.01 प्रतिशत से 88.62 प्रतिशत तक बढ़ा है। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात 2011-12 में 27.81 प्रतिशत से 2012-13 में 25.80 प्रतिशत तक घटा है।

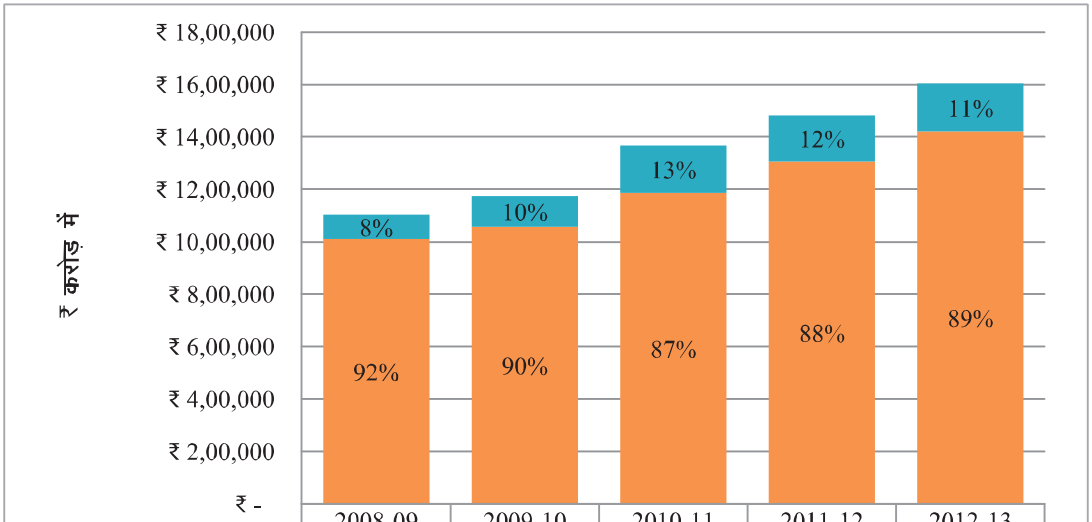
तालिका 1.7: 2011-12 एवं 2012-13 अवधि के दौरान कुल संवितरण के घटक

विवरण	2011-12	2012-13
कुल संवितरण (कु.सं.) (*प्रतिशत* में)	100.00	100.00
कु.सं. की प्रतिशतता के रूप में कु.सं. के घटक		
ऋण का पुर्नभुगतान	62.06	60.27
लोक लेखा से संवितरण	11.61	11.54
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	26.33	28.19
वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में वा.व्य. के घटक		
राजस्व व्यय (रा.व्य)	88.01	88.62
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	9.40	9.38
कर्जे एवं पेशगियाँ (क.पे.)	2.59	2.00
रा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्यय के घटक		
योजनागत राजस्व व्यय	25.57	23.18
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	74.43	76.82
पूं.व्य. की प्रतिशतता के रूप में व्यय के घटक		
योजनागत पूँजीगत व्यय	41.98	45.24
गैर-योजनागत पूँजीगत व्यय	58.02	54.76
क.पे. की प्रतितशतता के रूप में क.पे. के घटक		
योजनागत कर्जे	52.35	51.13
गैर-योजनागत कर्जे	47.65	48.87
वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय	27.81	25.80
वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में गैर योजनागत व्यय	72.19	74.20

1.3.2 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जो परिसम्पत्तियों के सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है जिसमें अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता तथा अन्तरण आदि शामिल होते हैं। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में भी माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत व्यय, गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय होने के बावजूद, 2010-11 से 2012-13 तक प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत से कम हुआ है। **चार्ट 1.8** पूंजीगत व्यय के ऊपर राजस्व व्यय की प्रभाविता को दर्शाता है।

चार्ट 1.8: पूँजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पुँजीगत व्यय*	₹ 92,141	₹ 1,16,801	₹ 1,81,312	₹ 1,77,869	₹ 1,82,445
राजस्व व्यय	₹ 10,10,224	₹ 10,57,479	₹ 11,86,115	₹ 13,05,195	₹ 14,20,473

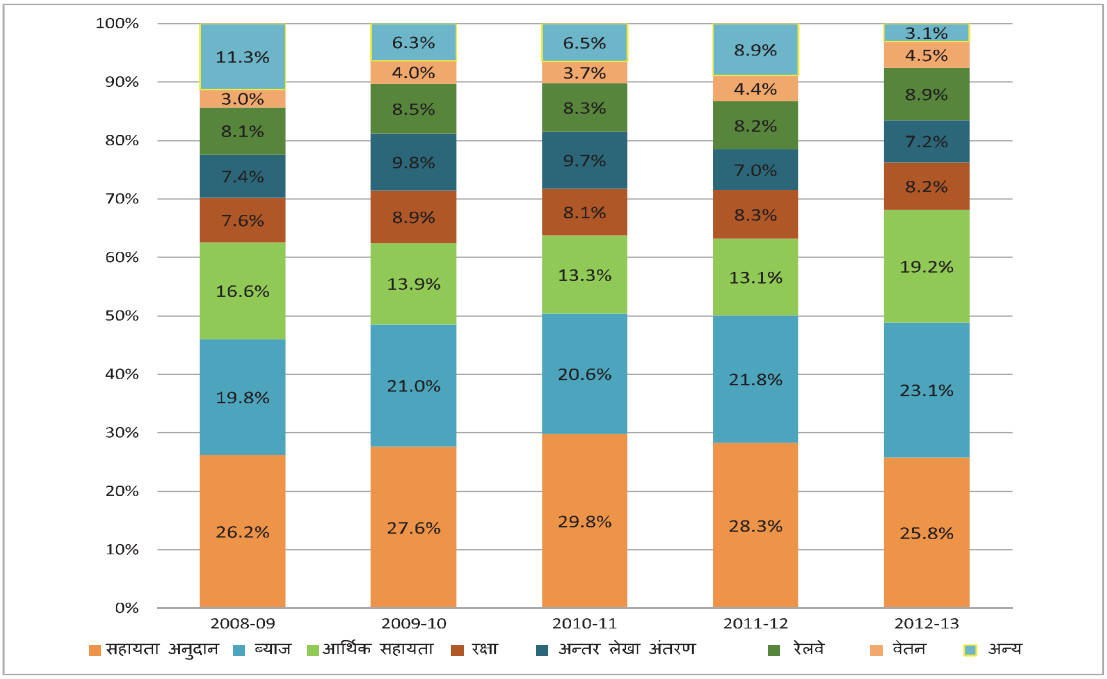
**ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं*

1.3.3 राजस्व व्यय का विश्लेषण

(क) राजस्व व्यय की अधिकता

शासकीय व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय की तरफ जाता है जिससे प्रायः सरकार की नई परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता तथा इससे सरकारी मशीनरी का नियमित परिचालन तथा रखरखाव किया जाता है। 2012-13 का कुल राजस्व व्यय ₹ 14,20,473 करोड़ था। जैसाकि नीचे **चार्ट 1.9** में दिखाया गया है, राजस्व व्यय का लगभग दो तिहाई तीन संघटकों अर्थात सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता की ओर था।

चार्ट 1.9: राजस्व व्यय के मुख्य घटक



स्रोतः 26 जुलाई 2013 को 'ई-लेखा' डाटा डम्प से प्राप्त किया गया है। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है।
नोटः 2011-12 के दौरान गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 65000 करोड़ की आर्थिक सहायता को आर्थिक सहायता में गिना नहीं गया। 'ब्याज' पर व्यय हेतु, केवल मुख्य शीर्षों '2048' तथा '2049' के नीचे वस्तु शीर्ष '45' के अंतर्गत आंकड़ों को ही लिया गया है। रक्षा में रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदान शामिल नहीं है। 'अन्य' 'कम वसूलियां' का निवल है।

2011-12 के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का अंश लगभग 88.01प्रतिशत था जो 2012-13 के दौरान लगभग 88.62 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2008-09 में राजस्व व्यय का अंश व्यय के लगभग 92 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 2010-11 में धीरे-धीरे घटकर लगभग 87 प्रतिशत तक हुआ तथा तब से प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई है।

राजस्व व्यय 2011-12 के दौरान 10.04 प्रतिशत के प्रति वर्तमान वर्ष के दौरान 8.83 प्रतिशत तक बढ़ गया। वचनबद्ध तथा अनिवार्य व्यय जैसे कि ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा संबंधित व्यय राजस्व व्यय का मुख्य अंश लेता है।

(ख) राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

सहायता अनुदानः सामान्य तथा पूंजी निर्माण दोनों के लिए सहायता अनुदान वे अनुदान होते हैं जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों, विदेशी सरकारों या भारत की समेकित निधि से बाहर निकायों/ प्राधिकरणों/हस्तियों को दिए जाते है। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। सार्वजनिक वितरण के नए मॉडलों के संदर्भ में,

सहायता अनुदान सिविल मंत्रालय के लिए राजस्व व्यय का अति महत्वपूर्ण घटक बन गया है जैसा कि **चार्ट 1.9** से स्पष्ट है। पिछले दो वर्षों से राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात 2011-12 में 28.3 प्रतिशत से 2012-13 में 25.8 प्रतिशत तक घट गया है।

ब्याज भुगतानः चार्ट 1.9 के अनुसार, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है। यह लोक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत उधारों पर ब्याज भुगतान शामिल हैं, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। **तालिका 1.8** के अनुसार राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2008-09 में 19.86 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में 23.24 प्रतिशत तक बढ़ गया। बढ़ते हुए ब्याज भुगतान, अन्य व्यय में से राजकोषीय क्राउडिंग को दर्शाता है। 2011-12 में 17.32 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2012-13 में ब्याज भुगतान की वृद्धि 15.05 प्रतिशत थी जैसा कि **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

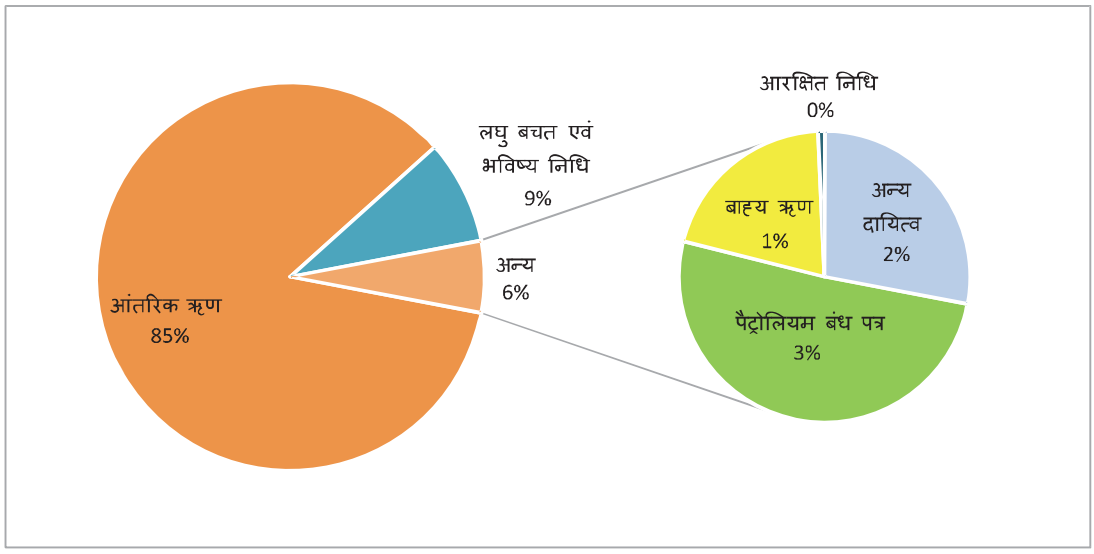
तालिका 1.8: संघ सरकार वित्त लेखे में राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान से मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज भुगतान	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान का राजस्व व्यय से अनुपात
XI वीं योजना (2007-12) औसत	**227175**	**1058775**	**21.62**
2008-09	200580	1010224	19.86
2009-10	223701	1057479	21.15
2010-11	244624	1186115	20.62
2011-12	286982	1305195	21.99
2012-13	330171	1420473	23.24

जैसाकि **चार्ट 1.10** में दर्शाया गया है, आन्तरिक ऋण (₹ 2,81,891 करोड़) के प्रति ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹3,30,171 करोड़) का 85 प्रतिशत बनता है।

चार्ट 1.10: वित्तीय वर्ष 2012-13 ब्याज व्यय के प्रमुख घटक



स्रोतः संघ सरकार वित्त लेखा 2012-13

कुल ब्याज भुगतानः ₹ 3,30,171 करोड़; आंतरिक ऋण पर ब्याजः ₹2,81,891 करोड़, बाह्य ऋण पर ब्याजः ₹4,019 करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ब्याजः ₹28,553 करोड़, पेट्रोलियम बंध पत्रों पर ब्याजः ₹10,051 करोड़, रिजर्व निधि पर ब्याजः ₹151 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ब्याजः ₹5,506 करोड़

आर्थिक सहायताः आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ (यथा कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (यथा नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत मूल्य से कम करने के लिए प्रदान की जाती हैं। **तालिका 1.9** आर्थिक सहायताओं, जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। जैसाकि तालिका से स्पष्ट है, सब्सिडी का अंश दोनों स.घ.उ. के अनुपात और राजस्व व्यय में प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बढ़ा हिस्सा भोजन एवं पेट्रोलियम सब्सिडी की ओर है।

तालिका 1.9: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पैट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य*	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (क)	आर्थिक सहायताएं (ख)
XI वीं योजना (2007-12) औसत	**54038**	**25610**	**35710**	**23095**	**6749**	**145202**	**2.15**	**13.71**
2008-09	43751	28048	48555	2852	6502	129708	2.32	12.84
2009-10	58443	22184	39452	2951	6692	129722	2.00	12.27
2010-11	63844	24337	41500	38371	9695	177747	2.28	14.99
2011-12	72822	33924	36108	68481	6567	217902	2.42	16.69
2012-13	85000	35132	30576	96880	9591	257179	2.54	18.11

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है

विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

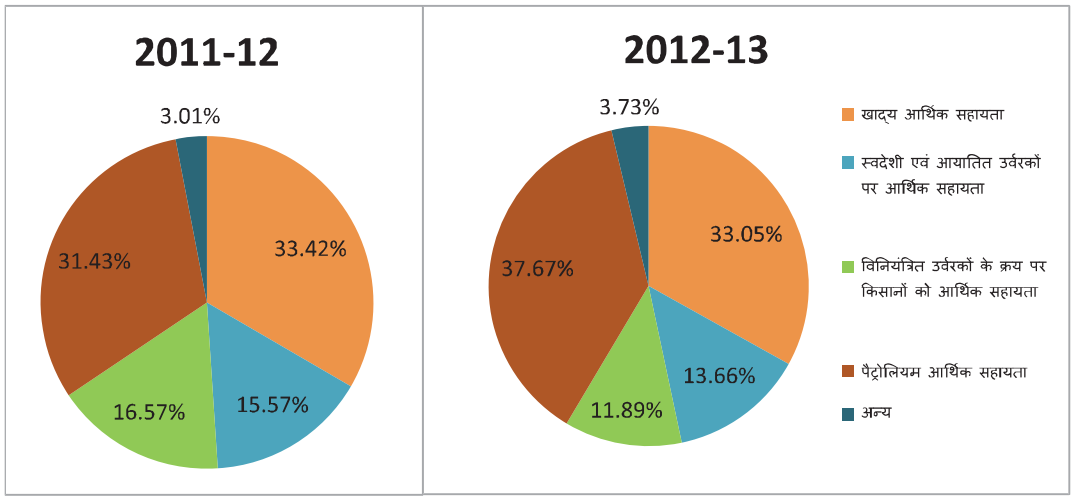
**अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, नेफेड को दिया गया अनुदान, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, हज अध्यायों के लिए आर्थिक सहायता आदि।*

(क) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में (ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

2012-13 में पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं (₹28,399 करोड़) में अधिक वृद्धि के कारण मुख्यतः कम-वसूलियों की क्षतिपूर्ति में तेज वृद्धि है जो कि घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री तथा मिट्टी के तेल (पी.डी.एस.) प्रचालनों के कारण हुआ।

2011-12 तथा 2012-13 में सरकार द्वारा दी गई स्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक नीचे **पाई चार्ट 1.11** में भी दर्शाए गए हैं। जैसा कि चार्ट तथा ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, आर्थिक सहायताओं में 2011-12 के दौरान स.घ.उ. के औसतन 2.42 प्रतिशत से 2012-13 में 2.54 प्रतिशत तक की आंशिक वृद्धि हुई। 2012-13 में, सरकार द्वारा प्रदत्त स्पष्ट सब्सिडी, स.घ.उ. का 2.57 प्रतिशत बनती है। भोजन सब्सिडी का अंश 2011-12 एवं 2012-13 में 33 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा। पेट्रोलियम सब्सिडी के अंश में 31 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई। हालांकि, दूसरी ओर उर्वरक (यूरिया) तथा उर्वरक (विनियंत्रित) का अंश क्रमशः 15.57 प्रतिशत से 13.66 प्रतिशत तथा 16.57 प्रतिशत से 11.89 प्रतिशत तक घटा है।

चार्ट 1.11: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक

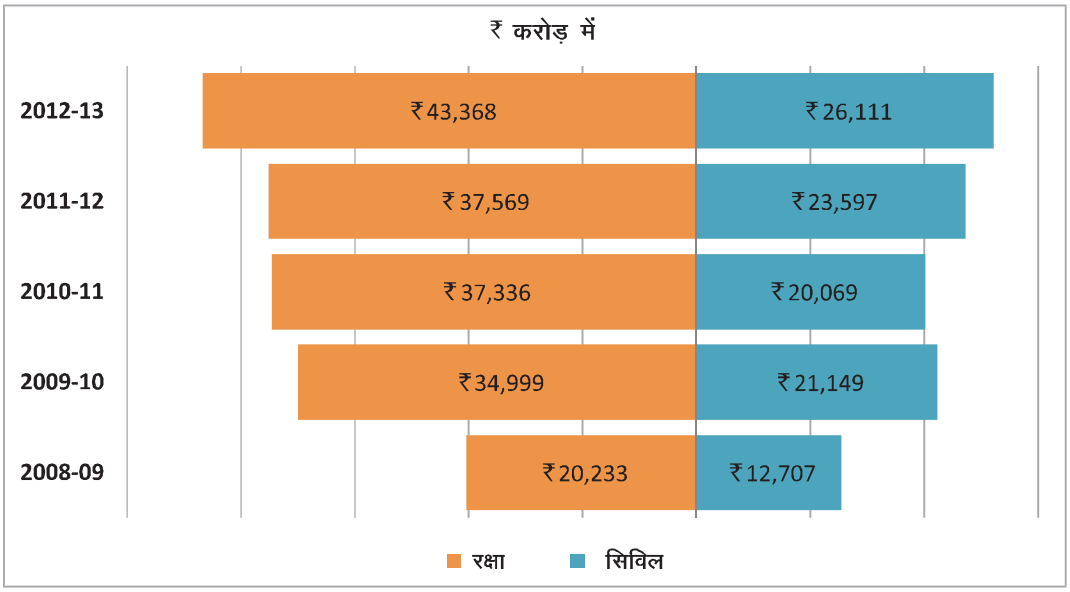


आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा प्रदान करके भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यतः अस्पष्ट आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अस्पष्ट आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। **तालिका 1.9** में प्रदर्शित आर्थिक सहायताएं केवल 'स्पष्ट आर्थिक सहायताएँ' से संबंधित है जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं।

पेंशन भुगतान - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2008-09 में ₹ 32,940 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 69,479 करोड़ हो गया जिसने 2008-13 में 111 प्रतिशत की वद्धि दर्ज की। **चार्ट 1.12** 2008-13 की अवधि की स्थिति को दर्शाता है। पिछले पाँच वर्षों (2008-13) के दौरान, विचाराधीन रक्षा पेंशनों के मामले में, पेंशन भुगतानों में 114 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा यह ₹ 43,368 करोड़ था जो संघ सरकार द्वारा किए गए कुल पेंशन भुगतान का 62.42 प्रतिशत था।

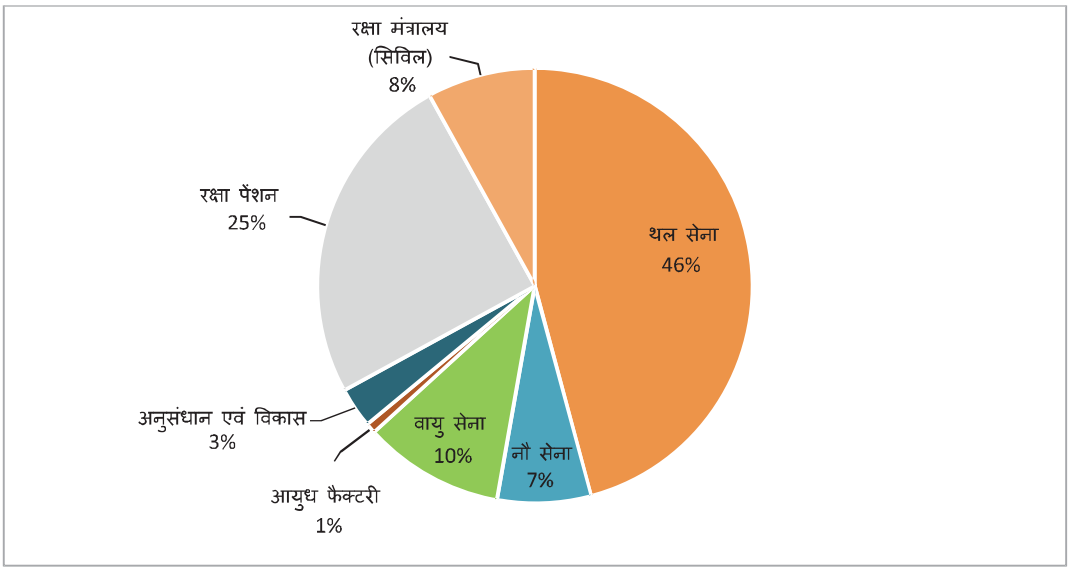
2008-09 में सिविल पेंशन ₹ 12,707 करोड़ रही जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 26,111 करोड़ हो गई और उसमें विचाराधीन अवधि (अर्थात 2008-13) में 105 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

चार्ट 1..12: 2007-13 की अवधि में पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय



रक्षा व्ययः जैसाकि **चार्ट 1.13** में दर्शाया गया है, रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय में, थल सेना (₹ 79,669 करोड़), नौसेना (₹ 12,119 करोड़), वायु सेना (₹ 18,138 करोड़), आयुध कारखानों (₹ 1,340 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹ 5,219 करोड़), रक्षा पेंशन (₹ 43,368 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹ 14,012 करोड़) के व्यय शामिल हैं। 2012-13 में, यह केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत था।

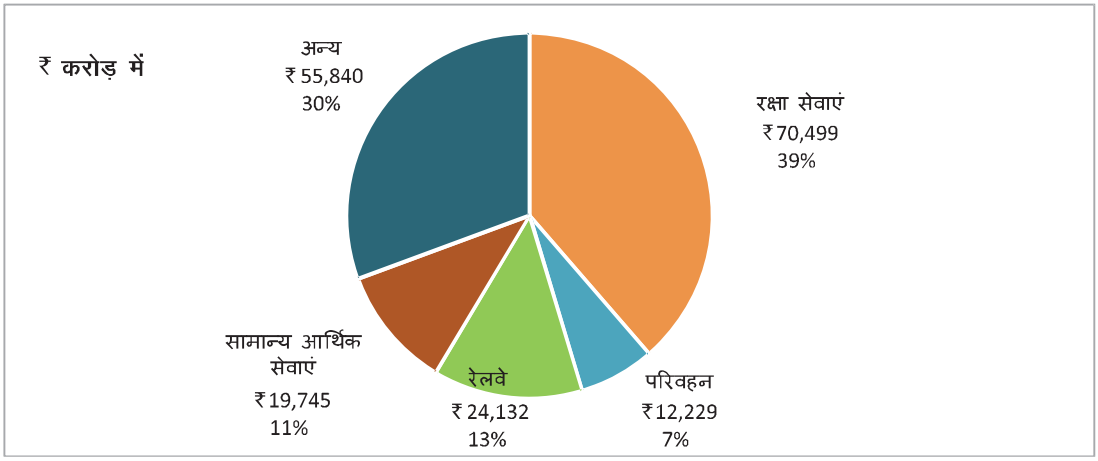
चार्ट 1.13: 2012-13 की अवधि में रक्षा पर व्यय



1.3.4 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) जो परिसम्पत्ति अर्जन पर किए गए व्यय का तथा मौजूदा परिसम्पत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने का सूचक है, पिछले वर्ष में ₹ 4,576 करोड़ (2.57 *प्रतिशत*) तक बढ़ा तथा 2012-13 में ₹ 1,82,445 करोड़ रहा। जैसाकि पहले ही पैरा 1.3.1 में नोट किया जा चुका है, हाल के वर्षों में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश धीरे-धीरे घट रहा है।

चार्ट 1.14 : वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूंजीगत व्यय का आवंटन - मुख्य क्षेत्र (प्रतिशत में)



चार्ट 1.14 दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं ने चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय का 70 प्रतिशत व्यय दर्ज किया।

- सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम' बैंक में निवेशित ₹ 12,618 करोड़ (अर्थात 64 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अभिदत्त ₹ 4,005 करोड़ (20 प्रतिशत) तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु प्रदान किए कर्जे के लिए ₹ 915 करोड़ (4.63 प्रतिशत) के कारण था।
- 'अन्य' के मामले में, व्यय का मुख्य खण्ड राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियों (₹10,661 करोड़), लक्षित/सार्वजनिक संवितरण प्रणाली 'खाद्य भण्डारण एवं गोदाम' के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के प्रापण कार्यों हेतु कर्जे (₹ 10,000 करोड़), 'पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय' (₹ 6,123 करोड़) तथा शहरी विकास के अंतर्गत स्थानीय निकायों, निगमों आदि हेतु कर्जे (₹ 2,578 करोड़) के कारण था।

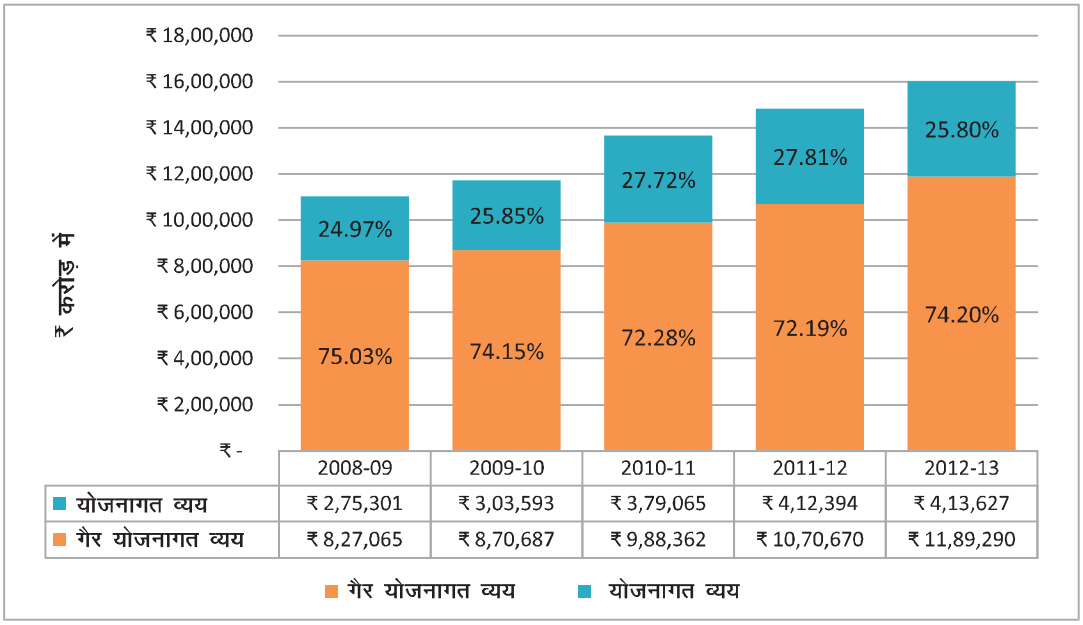
1.3.5 योजनागत व्यय का विश्लेषण

संघ का 2008-09 में कुल योजनागत व्यय ₹ 2,75,301 करोड़ था जो 2011-12 के दौरान बढ़कर ₹ 4,12,394 करोड़ हो गया। यह 2012-13 के दौरान आंशिक रूप से बढ़कर ₹ 4,13,627 करोड़ हो गया जो वास्तविक व्यय का 25.80 प्रतिशत था। ई-लेखा से लिए गए व्यय द्वारा प्रमुख 10 अनुदानों (**चार्ट 1.21**) ने 2012-13 में संघ सरकार के कुल योजनागत व्यय का 74.56 प्रतिशत दर्ज किया।

(क) योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और गैर-योजनागत में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है तथा इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर, गैर-योजनागत व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए समर्पित होता है। तथापि, योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय दोनों में, राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। **चार्ट 1.15** सरकार के योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का ब्यौरा दर्शाता है। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2010-12 से लगभग 28 प्रतिशत पर बना रहा पर 2012-13 में घटकर 26 प्रतिशत हो गया।

चार्ट.-1.15: योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय का विश्लेषण



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
योजनागत व्यय	₹ 2,75,301	₹ 3,03,593	₹ 3,79,065	₹ 4,12,394	₹ 4,13,627
गैर योजनागत व्यय	₹ 8,27,065	₹ 8,70,687	₹ 9,88,362	₹ 10,70,670	₹ 11,89,290

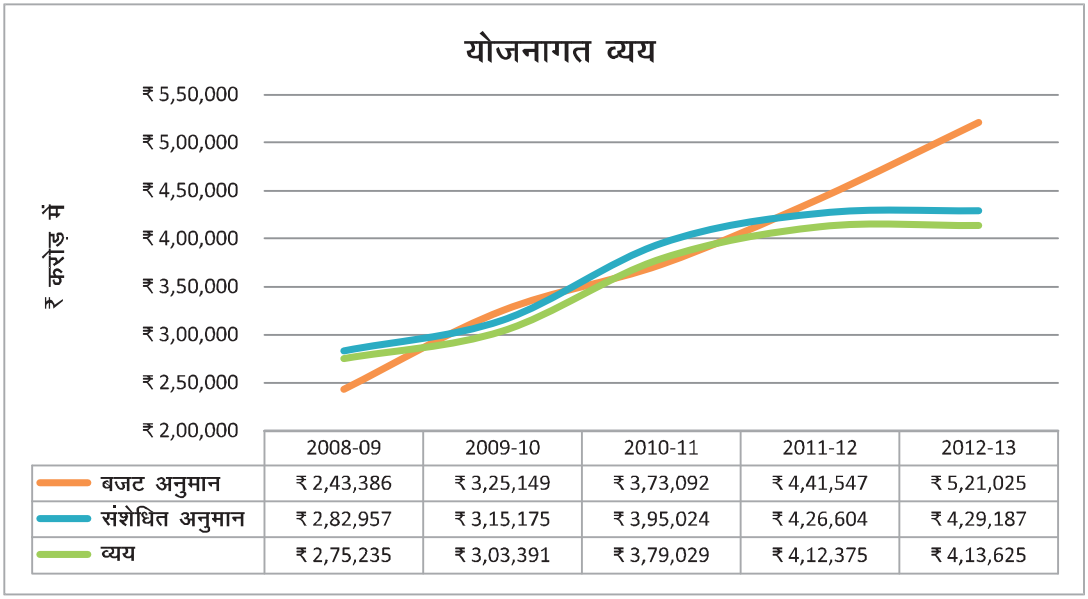
(ख) योजनागत व्यय का संकुचन

गैर-विकासात्मक व्यय को सीमित करने तथा प्राथमिकता योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करने के दृष्टांत से अतिरिक्त संसाधनों को जारी करने के लिए, समय-समय पर वित्त मंत्रालय सरकार में मितव्ययिता के उपायों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय को युक्तिसंगत करने तथा उपलब्ध संसाधनों में सुधार तथा व्यापक आर्थिक विकास के सुधार हेतु वित्त मंत्रालय ने राज्यों को वित्त आयोग अनुदान, पेंशन, वेतन, रक्षा पूंजी, ऋण के पुनर्भुगतान, ब्याज भुगतान को छोड़कर गैर-योजनागत व्यय में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती लगाई (मई 2012)।

बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान 2012-13 के विश्लेषण (जैसा 2013-14 के लिए अनुदानों के लिए मांग में उद्घाटित किया गया है) से पता चला कि संशोधित अनुमानों मे गैर योजनागत बजट प्रावधान[3] लगभग 10 प्रतिशत की कटौती के साथ ₹48,68,793.76 करोड़ से ₹44,03,227.08 करोड़ तक कम हुआ। योजनागत व्यय के मद में, संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान 17 प्रतिशत की कटौती के साथ ₹6,09,202.69 करोड़ से ₹5,03,690.33 करोड़ तक कम हुआ।

पाँच वर्ष की अवधि 2008-13 के लिए व्यय एवं संशोधित अनुमानों बनाम बजट अनुमानों के अंतर-अस्थायी विश्लेषण से पता चला कि योजना पक्ष पर राजकोषीय संकुचन केवल 2012-13 में अर्थपूर्ण रहा है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट है।

चार्ट 1.16: योजनागत व्यय में राजकोषीय संकुचन



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बजट अनुमान	₹ 2,43,386	₹ 3,25,149	₹ 3,73,092	₹ 4,41,547	₹ 5,21,025
संशेधित अनुमान	₹ 2,82,957	₹ 3,15,175	₹ 3,95,024	₹ 4,26,604	₹ 4,29,187
व्यय	₹ 2,75,235	₹ 3,03,391	₹ 3,79,029	₹ 4,12,375	₹ 4,13,625

डाटा स्रोतः वर्ष 2008-09 से 2014-15 (प्रावधानिक) व्यय बजट भाग-1

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 का अनुदानवार विवरण स्पष्ट करता है कि 61 अनुदानों में संशोधित अनुमान स्तर पर योजना बजट अनुमान 10 प्रतिशत से ज्यादा कम किए गए थे, जबकि गैर-योजना बजट अनुमान केवल 18 अनुदानों में ही 10 प्रतिशत से ज्यादा कम किए गए, जो कि आर्थिक मानदण्डों पर जारी किए गए निर्देशों के विरुद्ध है।

संशोधित अनुमान स्तर पर योजना व्यय मे समग्र कमी का मुख्य कारण कृषि, परमाणु ऊर्जा, रसायन एवं उर्वरक, दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पेय जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह मामले, मानव संसाधन विकास, अल्पसंख्यक मामले, विद्युत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, अंतरिक्ष, कपड़ा, शहरी विकास तथा महिला एवं

[3] 106 अनुदानें (99 सिविल अनुदानें, छः रक्षा अनुदानें और एक डाक अनुदान) रेलवे को छोड़कर

बाल विकास के योजना आबंटन मे कमी थी, जैसा कि वर्ष 2013-14 के बजट व्यय (खण्ड-I) में प्रदर्शित है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के वास्तविक व्यय बनिस्पत संशोधित अनुमान में कमी का तुलनात्मक अध्ययन, व्यय बजट (खण्ड-I) मे प्रदर्शित सूचनाओं के आधार पर, निम्नलिखित **तालिका 1.10** एवं **चार्ट 1.17** मे प्रदर्शित है।

तालिका 1.10: योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय अनुमानों में प्रवृत्तियाँ

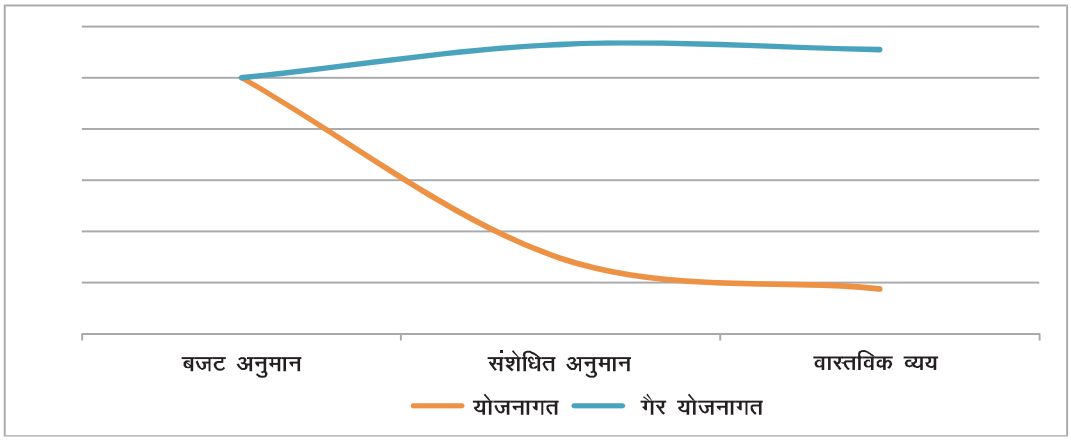
2012-13	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	सं.अ. स्तर पर कमी	बचतें बनाम सं.अ.	बचतें बनाम ब.अ.
		₹ करोड़ में		प्रतिशत		
योजनागत	521025	429187	413625	17.63	3.63	20.61
गैर-योजनागत	969900	1001638	996742	3.27@	0.49	2.77*
कुल	**1490925**	**1430825**	**1410367**			

स्रोतः वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए व्यय बजट भाग-I की विवरण संख्या 1

@ सं.अ. स्तर पर गैर-योजना व्यय में वृद्धि

* वास्तविक गैर-योजना व्यय ब.अ. से बढ़ गया।

चार्ट 1.17: योजनागत एवं गैर योजनागत अनुमानों और वास्तविक व्यय का प्रवाह

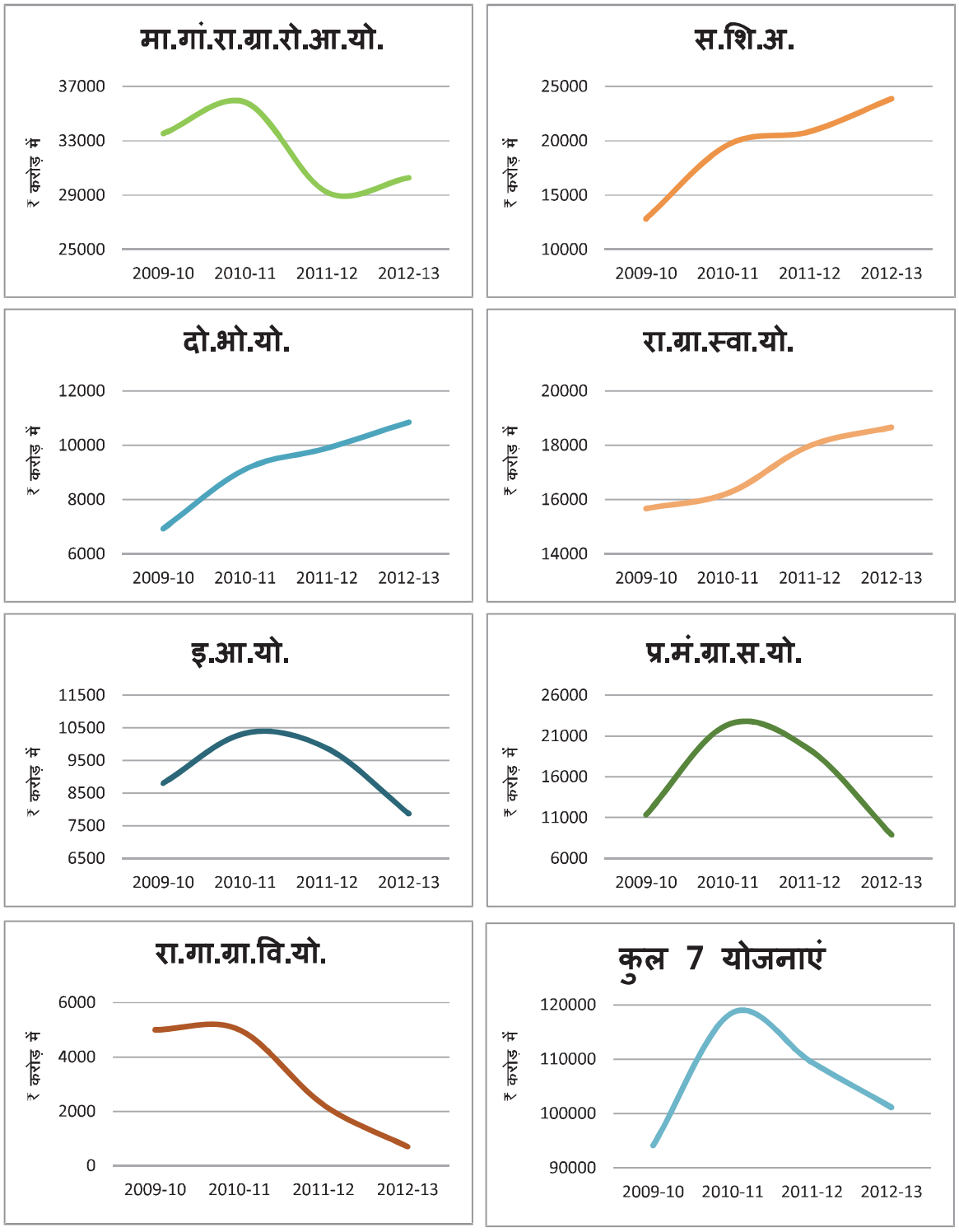


उपर्युक्त तालिका एवं चार्ट से यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश कि गैर योजना व्यय को बजट अनुमान की तुलना मे 10 प्रतिशत तक रखा जाए, ने इच्छित परिणाम नहीं दिया है। गैर-योजना संशोधित अनुमान तथा अंतिम व्यय में क्रमशः 3.27 प्रतिशत तथा 2.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, बजट अनुमान की तुलना मे योजना व्यय मे 20 प्रतिशत से अधिक की तीव्र कमी हुई।

1.3.6 सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम-पिछले चार वर्षों में वास्तविक व्यय

संघ सरकार प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। नीचे **चार्ट 1.18** 2009-13 की अवधि के दौरान इन मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 1.18: 2009-13 के दौरान मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय



स.शि.अ.=सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो.=दोपहर के भोजन की योजना, रा.ग्रा.रो.आ.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना, रा.गा.ग्रा.वि.यो.=राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इं.आ.यो.=इंदिरा आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो.=प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रा.ग्रा.स्वा.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

उपर दर्शाई गई सात प्रमुख योजनाओं पर कुल व्यय 2009-10 में ₹ 94,105 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1,18,571 करोड़ तक बढ़ गया तथा फिर 2011-12 में ₹ 1,09,379 करोड़ तथा चालू वर्ष में ₹ 101,008 करोड़ तक घट गया है। **चार्ट 1.18** तथा **तालिका 1.11** से यह देखा जा सकता है कि रा.गा.ग्रा.वि.यो., इं.आ.यो. तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. जैसी मुख्य योजनाओं ने, जब उनकी पिछले वर्ष से तुलना की गई, व्यय में कमी दर्ज की लेकिन बजट अनुमानों से तुलना में सभी सातों मुख्य योजनाओं के व्यय में गिरावट देखी गई।

तालिका 1.11: पिछले चार वर्षों में सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान (ब.अ.)

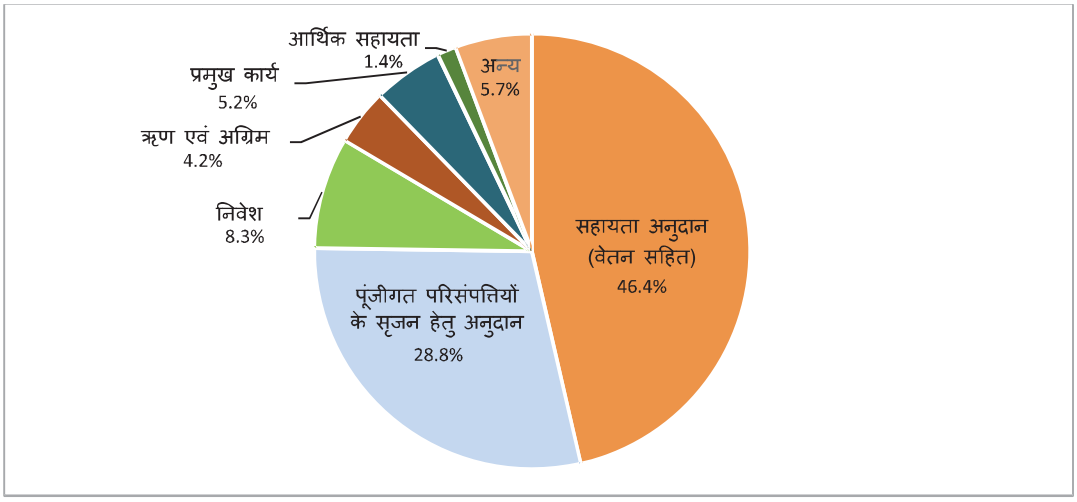
(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)
स.शि.अ.	13100	12825	(-)2.10	15000	19637	30.90	20413	20841	2.10	24243	23873	(-)1.53
दो.भो.यो.	8000	6932	(-)13.40	9440	9118	(-)3.40	10061	9891	(-)1.69	11643	10849	(-)6.82
रा.ग्रा.रो.आ.यो.	39100	33538	(-)14.20	40100	35841	(-)10.60	40000	29213	(-)26.97	33000	30274	(-)8.26
रा.गा.ग्रा.वि.यो.	6300	5000	(-)20.64	5500	5000	(-)9.10	6000	2237	(-)62.72	4900	698	(-)85.76
इं.आ.यो.	8800	8800	-	10000	10337	3.40	10000	9872	(-)1.28	11075	7869	(-)28.95
प्र.मं.ग्रा.स.यो.	12000	11340	(-)5.50	12000	22400	86.70	20000	19342	(-)3.29	24000	8884	(-)62.98
रा.ग्रा.स्वा.मि.	15534	15670	(-)0.90	17138	16238	(-) 5.30	19838	17983	(-)9.35	22799	18661	(-)18.15
कुल	**102834**	**94105**	**(-)8.49**	**109178**	**118571**	**8.60**	**126312**	**109379**	**(-)13.41**	**131660**	**101108**	**(-)23.20**

1.3.7 योजनागत व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि **चार्ट 1.19** से देखा जा सकता है कि अनुदान सहायता, निवेश, कर्जे एवं आर्थिक सहायता योजनागत व्यय का 89 प्रतिशत बनते है। सिविल मंत्रालयों के मामले में 2012-13 के दौरान 2011-12 की तुलना में, अनुदान सहायता (₹2,93,995) कुल योजनागत व्यय का लगभग 75 प्रतिशत पर बना रहा है। हालांकि, 2012-13 में पूंजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान का अंश 33 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक कम हुआ। योजनागत व्यय के मंत्रालय वार /अनुदान -वार घटक **अनुबंध 1-1** में दिखाए गए हैं।

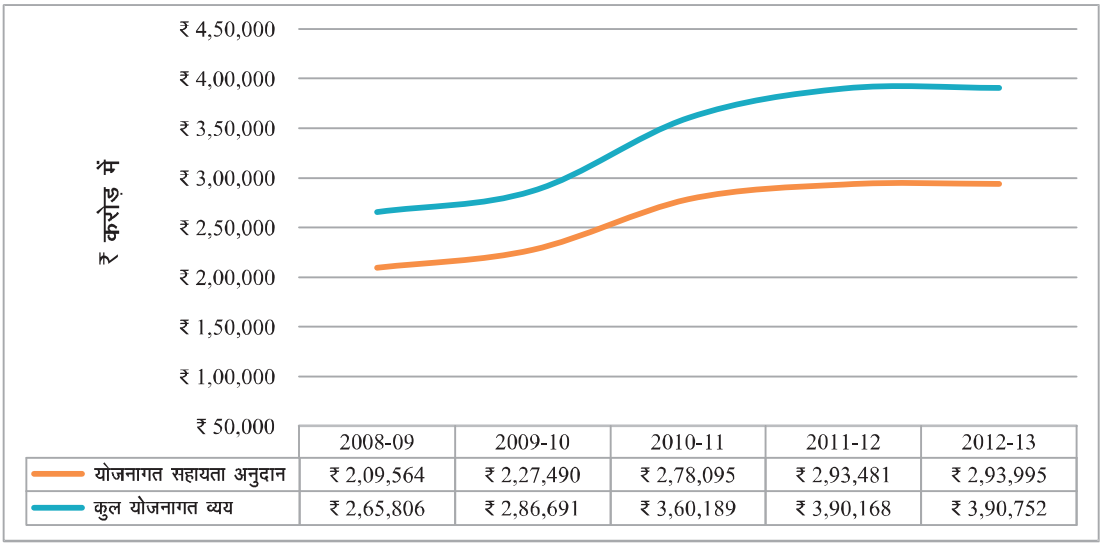
चार्ट 1.19: योजनागत व्यय के घटक



स्रोतः 26 जुलाई 2013 को ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा (संख्या 22 से 27), डाक (सं.13), रेलवे एवं विनियोग ऋण का पुर्नभुगतान (सं.37) से संबंधित अनुदानों को छोड़कर। जर्नल प्रविष्टियां, 'अंर्त-लेखा अंतरण' (व.शी.63) तथा 'कम वसूलियां' (व.शी.70) शामिल नहीं हैं।

चार्ट 1.20 2007-08 से 2012-13 के दौरान कुल योजनागत व्यय के भाग के रूप में योजनागत अनुदान सहायता (पूंजीगत निर्माण और वेतन हेतु अनुदान सहायता सहित) 75 प्रतिशत तथा 79 प्रतिशत के बीच होने को दर्शाता है।

चार्ट 1.20: कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत सहायता अनुदान (पूंजीगत निर्माण तथा वेतन हेतु सहायता अनुदान सहित)



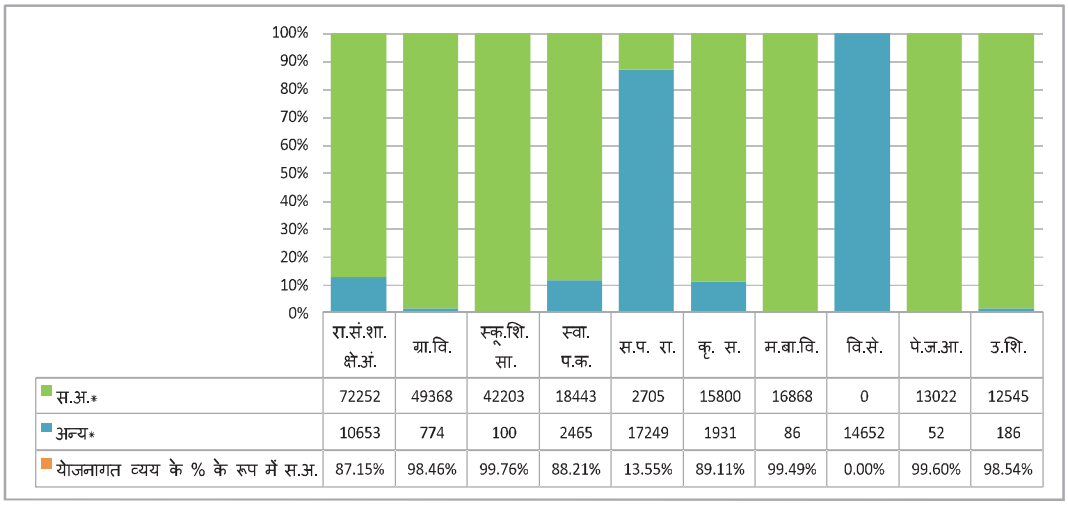
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
योजनागत सहायता अनुदान	₹ 2,09,564	₹ 2,27,490	₹ 2,78,095	₹ 2,93,481	₹ 2,93,995
कुल योजनागत व्यय	₹ 2,65,806	₹ 2,86,691	₹ 3,60,189	₹ 3,90,168	₹ 3,90,752

स्रोतः 26 जुलाई 2013 को ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा, डाक तथा रेलवे अनुदानों को छोड़कर)। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है।

1.3.8 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

नीचे **चार्ट 1.21** 2012-13 में वृहत योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.21: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूंजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान सहित)



	रा.सं.शा. क्षे.अं.	ग्रा.वि.	स्कू.शि. सा.	स्वा. प.क.	स.प. रा.	कृ. स.	म.बा.वि.	वि.से.	पे.ज.आ.	उ.शि.
स.अ.*	72252	49368	42203	18443	2705	15800	16868	0	13022	12545
अन्य*	10653	774	100	2465	17249	1931	86	14652	52	186
योजनागत व्यय के % के रूप में स.अ.	87.15%	98.46%	99.76%	88.21%	13.55%	89.11%	99.49%	0.00%	99.60%	98.54%

*राशि ₹करोड़ में

टिप्पणी: अ.स.=अनुदान सहायता, यो.व्य.=योजनागत व्यय, रा.सं.शा.क्षे.स.अ.=राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, ग्रा.वि.=ग्रामीण विकास, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, स.प.रा.=सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, वि.से.=वित्तीय सेवाएं, पे.ज.आ.=पेय जल आपूर्ति, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा

स्त्रोतः दिनांक 26 जुलाई 2013 को 'ई-लेखा' पोर्टल से लिया गया डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं। 'अंर्त-लेखा अंतरण' एवं 'कम वसूलियां' वस्तु शीर्षों को छोड़कर।

जैसाकि स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, पेय जलापूर्ति तथा उच्चतर शिक्षा मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय निकायों/अप्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण था।

1.3.9 राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की सुपुर्दगी की पद्धति

नीचे **तालिका 1.12** दर्शाती है कि कुल योजनागत व्यय का केन्द्रीय योजना सहायता के सीधे अंतरण का अनुपात, 2010-11 में 31.32 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचने के पश्चात्, 2007-08 में 26.71 प्रतिशत से 2012-13 में 25.38 प्रतिशत तक घटा।

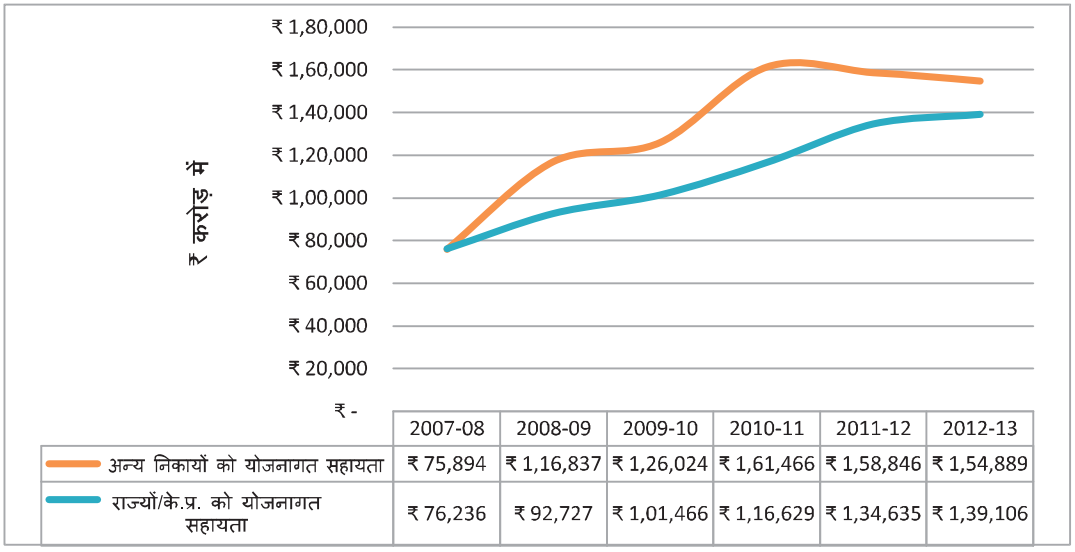
तालिका 1.12: राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा कि व्यय बजट, संस्करण-I, विवरणी सं. 18 में है)	कुल योजना व्यय	कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	54776	205082	26.71
2008-09	83224	275301	30.23
2009-10	90521	303593	29.82
2010-11	118740	379065	31.32
2011-12	109173	412394	26.47
2012-13	104971	413627	25. 38

निकायों/प्राधिकारियों को अंतरण की तुलना में राज्य सरकार के माध्यम से अंतरण: चार्ट 1.22 से यह स्पष्ट है कि सेवाओं के वितरण हेतु निकायों/प्राधिकरणों को अन्तरण राज्य सरकारों के द्वारा सेवाओं के वितरण की तुलना में प्रबल रहा है।

चार्ट 1.22: राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अन्तरण बनाम निकायों/प्राधिकारियों को अनुदानों के अन्तरण का अनुपात



	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अन्य निकायों को योजनागत सहायता	₹ 75,894	₹ 1,16,837	₹ 1,26,024	₹ 1,61,466	₹ 1,58,846	₹ 1,54,889
राज्यों/के.प्र. को योजनागत सहायता	₹ 76,236	₹ 92,727	₹ 1,01,466	₹ 1,16,629	₹ 1,34,635	₹ 1,39,106

स्रोतः दिनांक 26 जुलाई 2013 को 'ई-लेखा' डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि सहायता अनुदान में सीधे अंतरण का औसत अंश ग्यारहवीं योजना अवधि में (2007-12) 55 प्रतिशत था जो 2012-13 के दौरान कुल योजना सहायता अनुदान व्यय के 53 प्रतिशत तक घट गया। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा बार-बार प्रकट किया मुख्य चिंता का विषय यह है कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग की निधियों के लेखे शीघ्र ही उपलब्ध नहीं हैं तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इन अभिकरणों के

पास अप्रयुक्त निधियाँ पड़ी हैं। इस मुद्दे पर अध्याय-5 में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है।

1.3.10 विगत पांच वर्षों के लिए व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण

एक अनुदान अथवा विनियोजन मानक विषय के द्वारा वितरित की जाती है जिसके अंतर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक मानक विषय, जिसके प्रति व्यय हेतु प्रावधान प्रकट होता है, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई का गठन करता है। विनियोजन की यह प्राथमिक इकाई वस्तु शीर्ष कहलाती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान जिन पाँच वस्तु शीर्षों पर सर्वाधिक व्यय हुआ उन्हें नीचे **तालिका 1.13** में दिया गया है। उधारियों का पुनर्भुगतान और सहायता अनुदान वर्णित अवधि में वृहत वृद्धि दर्शाती है। इन वस्तु शीर्षों पर व्यय की प्रवृत्ति और भारत की समेकित निधि में उनके अंश की प्रवृत्ति को चार्ट सं. 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: 2008-13 के दौरान वृहत व्यय वाले पाँच विषय शीर्ष

(₹ करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
56-उधारियों के पुनर्भुगतान	21,64,561	30,85,792	28,02,774	34,95,929	34,26,892
सहायता अनुदान	2,64,606	2,91,447	3,52,648	3,67,254	3,66,202
45- ब्याज	2,00,973	2,22,777	2,45,701	2,89,288	3,29,263
33-आर्थिक सहायता	1,67,461	1,46,437	1,57,817	1,70,132*	2,71,761
63-अंतर खाता अंतरण	73,663	1,02,074	1,13,943	89,436	1,02,071

टिप्पणीः डाटा स्रोतः ले.म.नि. द्वारा प्रदत्त 'ई-लेखा' डाटा डम्प (रक्षा, डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

** यह आंकड़ा अन्य प्रभारों के रूप में ₹ 65000 करोड़ के गलत वर्गीकरण को शामिल नहीं करता।*

पिछले वर्षों से 2012-13 में व्यय के बुकिंग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले विषय शीर्ष निम्न तालिका में दिये गये हैः

तालिका 1.14: पिछले वर्षों से 2011-12 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले पाँच विषय शीर्ष

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष	2011-12 में व्यय	2012-13 में व्यय	प्रतिशत में वृद्धि
60-अन्य पूंजीगत व्यय	1,789	3,923	119%
33-आर्थिक सहायता	1,70,132	2,71,761	59%
42-एकमुश्त प्रावधान	313	464	47%
32-अंशदान	6,349	8,896	39%
23-राशन की लागत	1,692	2,116	24%

आगे विश्लेषण ने उजागर किया किः

- वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय (अ.पूं.व्य)' पर व्यय 119 प्रतिशत तक बढ़ गया अर्थात् वर्ष 2011-12 में ₹1,789 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 3,923 करोड़ हो गया।

मंत्रालय/अनुदानवार विश्लेषण से पता चला कि दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदान में, अ.पूं.व्य पर व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 50.00 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,517.18 करोड़ तक बढ़ गया, इस प्रकार इसका एक वर्ष में कुल वृद्धि में योगदान रहा। अंतरिक्ष विभाग ने भी इस वस्तु शीर्ष पर व्यय में वर्ष 2011-12 में ₹ 406.32 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 1,278.98 करोड़ तक वृद्धि कर दी थी।

- जैसाकि 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 65,000 करोड़ को, जो कि आर्थिक सहायता के रूप मे संवितरित किए गए थे, वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' मे गलत वर्गीकृत किया। हालांकि मंत्रालय ने 2011-12 के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में दर्ज ₹ 3481.00 करोड़ के प्रति 2012-13 में ₹96,879.87 करोड़ दर्ज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस वस्तु शीर्ष पर व्यय में तेज वृद्धि हुई।

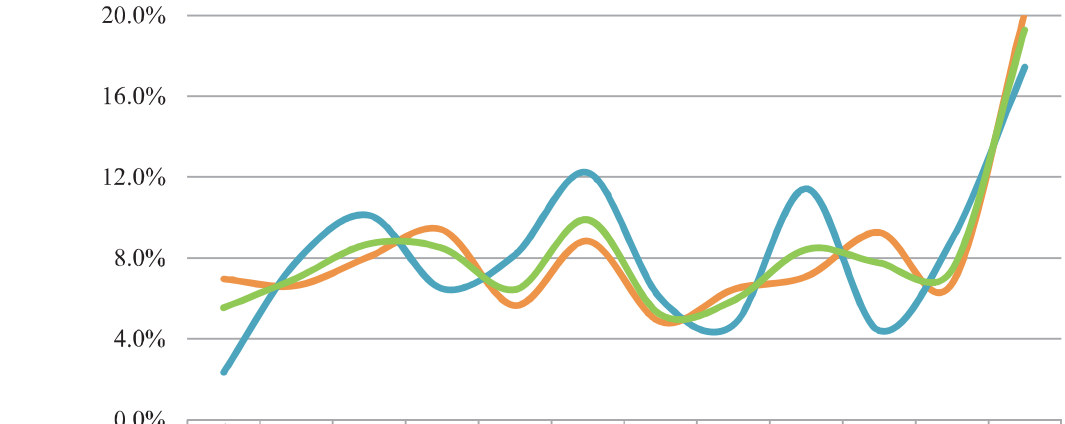
- यह भी नोट किया गया कि वस्तु शीर्ष 'एकमुश्त प्रावधान' पर व्यय वर्ष 2011-12 में ₹313 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 464 करोड़ तक बढ़ गया। इस वृद्धि का एकमात्र कारण आर्थिक कार्य विभाग द्वारा व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (व्य.अं.वि.पो.) से संबंधित ₹457.55 करोड़ को दर्ज किया जाना था। वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के अनुसार एकमुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य सभी मामलों में व्यय का ब्यौरा दिया जाना चाहिए **(पैरा सं. 4.11 के संदर्भ में)।** 2011-12 में इस वस्तु शीर्ष में भी 130 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

- विषयशीर्ष 'अंशदान' में व्यय में 39 प्रतिशत अर्थात् वर्ष 2011-12 में ₹6,349 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹8,896 करोड़ तक वृद्धि हुई। इस वृद्धि मे सर्वाधिक अंशदायक विदेश मंत्रालय एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय थे जहां 2011-12 से 2012-13 के दौरान 'अंशदान' पर व्यय में क्रमशः ₹2,646.12 करोड़ से ₹3,894.05 करोड़ एवं ₹1,373.35 करोड़ से ₹2,420.15 करोड़ वृद्धि हुई।

1.4 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय प्रबंधन का एक मुख्य पहलू वर्ष की समाप्ति की ओर व्यय के घनत्व से बचना है। वित्त मंत्रालय ने मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। नीचे **चार्ट 1.23** दर्शाता है कि कैसे कुल व्यय तथा इसमे योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार को छोड़कर अन्य मंत्रालय विभाग) का वित्तीय वर्ष में संवितरण हुआ।

चार्ट 1.23: व्यय का माह वार प्रवाह (प्रतिशत में)



	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
गैर-योजनागत	7.0%	6.6%	8.1%	9.4%	5.7%	8.8%	4.8%	6.4%	7.1%	9.3%	6.7%	20.1%
योजनागत	2.3%	7.8%	10.1%	6.5%	8.2%	12.2%	6.0%	4.7%	11.4%	4.4%	8.9%	17.4%
भा.सं.नि.#	5.5%	7.0%	8.7%	8.5%	6.4%	9.9%	5.2%	5.9%	8.4%	7.8%	7.4%	19.3%

#भा.स.नि.= भारत की समेकित निधि (इस चार्ट में 'अन्तर लेखा अन्तरण' को शामिल न किए जाने के कारण भा.स.नि. से माह-वार व्यय की प्रतिशतता अनुबंध I-ख के साथ मेल नहीं खा सकती है)

टिप्पणीः 26 जुलाई 2013 को प्रदत्त 'ई लेखा' डाटा डम्प (रक्षा (सं. 22 से 27), डाक (नं.13), रेलवे तथा विनियोजन-ऋण का पुनर्भुगतान (सं.37) से संबंधित अनुदान के अलावा) जर्नल प्रविष्टियां, 'अन्तः लेखा अन्तरण' (व.शी.-63) तथा 'कम वसूलियाँ' (व.शी.-70) शामिल नहीं है।

सिविल मंत्रालयों[4] हेतु भारत की समेकित निधि से सरकार के कुल व्यय का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल वार्षिक व्यय का 19 प्रतिशत मार्च 2013 में एवं 34 प्रतिशत वर्ष 2012-13 के अंतिम तिमाही में किया गया था। मार्च 2013 में योजनागत व्यय एवं गैर-योजनागत व्यय में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। योजनागत व्यय 2012 के जून, सितम्बर तथा दिसम्बर की तिमाही में उंचाई पर था तथा मार्च 2013 में कुल योजनागत व्यय के 17 प्रतिशत की सुस्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय जो वार्षिक व्यय का प्रत्येक माह औसत 5 से 9 प्रतिशत के बीच रहा, मार्च 2013 में, कुल गैर-योजनागत व्यय के 20 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

मंत्रालय/विभाग वार समय विश्लेषणः तालिका 1.15 में एक पृथक्कृत विश्लेषण दर्शाता है कि मार्च 2013 में 10 अनुदानों के मामले में कुल व्यय का 26 प्रतिशत से ऊपर व्यय किया गया था। वित्तीय सेवाएं विभाग के मामले में कुल व्यय का 59 प्रतिशत मार्च के अंतिम दिन किया गया था। मंत्रालय-वार /अनुदान-वार व्यय का समय विश्लेषण **अनुबंध 1.2** में दिया गया है:-

[4] डाक (अनुदान सं. 13), रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27) तथा ऋण पुनर्भुगतान (अनुदान सं. 37) को छोड़कर

तालिका 1.15: मार्च 2013 में किये गए व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	21292.76	15126.50	71.04	12519.87	58.80
075	विद्युत मंत्रालय	6302.90	3951.41	62.69	12.80	0.20
010	कोयला मंत्रालय	744.90	291.96	39.19	0.03	0.00
070	पंचायती राज मंत्रालय	3937.27	1250.50	31.76	518.71	13.17
005	नाभिकीय ऊर्जा	4061.14	1147.08	28.25	409.67	10.09
047	आयुष विभाग	755.19	208.68	27.63	147.26	19.50
053	मंत्रिमंडल	925.05	255.02	27.57	245.15	26.50
050	भारी उद्योग विभाग	768.98	209.08	27.19	81.25	10.57
073	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	97423.06	26248.10	26.94	13.20	0.01
020	रक्षा मंत्रालय	15609.71	4164.49	26.68	2675.78	17.14

टिप्पणीः ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

उन मंत्रालयों जहाँ वित्त वर्ष के अंतिम दिन को एक महत्वपूर्ण धन राशि खर्च की गयी थी, के संबंध में आगे एक विश्लेषण ने उदघाटित किया कि-

- कुल ₹ 12,519 करोड़* में से ₹ 12,517 करोड़ की राशि, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा मार्च 2013 के अंतिम दिन '54-निवेश' वस्तु शीर्ष के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुर्नपूंजीकरण पर व्यय की गयी जो कि कुल राशि का 99.98 प्रतिशत था। 2011-12 में भी, मार्च के अंतिम दिन पर विभाग ने अपने अनुदानों का 67 प्रतिशत व्यय किया था।

- इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित अनुदान के अंतर्गत कुल ₹ 245.15 करोड़ में से ₹ 218.93 करोड़ की राशि दो वस्तु शीर्षों अर्थात् विदेश यात्रा व्यय (₹ 184.75 करोड़) तथा मशीनरी एवं उपकरण (विशेष सुरक्षा समूह के लिए ₹ 34.18 करोड़) पर व्यय की गई जो कि 89.30 प्रतिशत बनती है।

विषय शीर्षवार समय विश्लेषणः संघ सरकार के लेखाओं के कोडिंग प्रतिमान के अनुसार एक उप-शीर्ष योजनाओं को प्रस्तुत करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को प्रस्तुत करता है तथा विषय शीर्ष अंतिम शीर्षों (अर्थात वेतन, दै.भ., म.कि.भ., पुरस्कार, उपदान आदि) को प्रस्तुत करता है जिन पर व्यय किया गया है। सिविल मंत्रालयों में विषय शीर्ष स्तर पर व्यय की जाँच ने प्रकट किया कि कई वस्तु शीर्षों में उल्लेखनीय व्यय घनत्व था। **तालिका 1.6** में मुख्य 10 मामले दर्शाए गए हैः

* अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों में प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 1.16 मार्च 2013 में हुए विषय शीर्ष व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

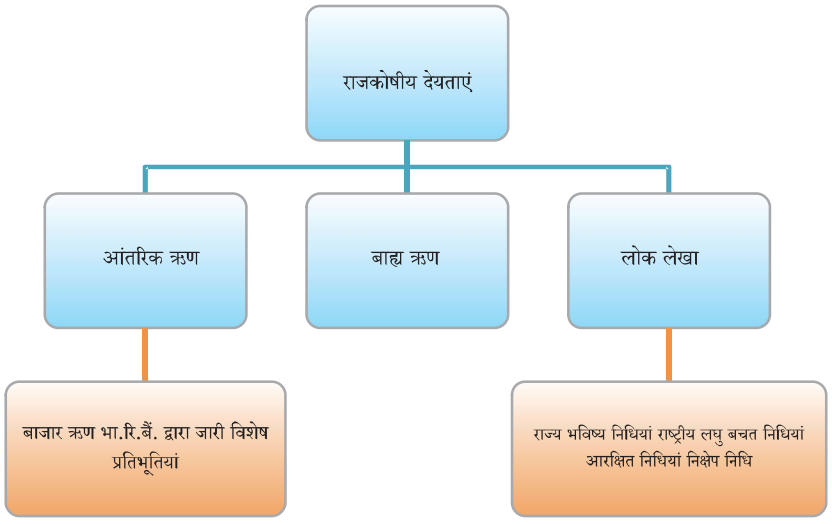
वस्तु शीर्ष	वस्तुशीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर कुल व्यय की प्रतिशतता
44	विनिमय विविधताएं	69.09	69.09	100.00	0.00	0.00
64	बट्टे खाते/हानियाँ	564.69	267.43	47.36	174.70	30.94
54	निवेश	38946.96	14780.29	37.95	12834.01	32.95
25	परिधान एवं खेमा	505.60	158.15	31.28	60.70	12.00
05	पुरस्कार	38.64	12.03	31.13	5.71	14.79
53	मुख्य कार्य	23854.33	7407.90	31.05	3138.47	13.16
26	विज्ञापन एवं प्रचार	1511.90	455.98	30.16	56.20	3.72
30	अन्य संविदात्मक सेवाएं	1721.73	519.00	30.14	353.14	20.51
52	मशीनरी एवं उपकरण	3049.06	882.39	28.94	401.86	13.18
50	अन्य प्रभार	10370.25	2996.48	28.90	1370.85	13.22

टिप्पणीः ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27), डाक (अनुदान सं.13) तथा रेलवे से संबंधित अनुदान शामिल नहीं है। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय को एक साथ करने के कारणों की जांच विशेष रूप से निवेश, विज्ञापन एवं प्रचार, प्रमुख कार्य तथा अन्य प्रभारों के मामले में करनी चाहिए।

1.5 ऋण तथा घाटा सूचक

बॉक्स-1.2 भारत सरकार की राजकोषीय देयताएँ



यद्यपि बजट के संतुलन हेतु ऋण पर भरोसा करने से नहीं बचा जा सकता, संघ सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्वों तथा बजट प्रबंधन (रा.उ.प्र.ब.) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों

पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार विधान के माध्यम से अपनी देयताओं पर सीमाएं निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया। रा.सु.ब.प्र. नियमावली निर्धारित करती हैं कि केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की अधिकता में अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) को ग्रहण नहीं करेगी और आने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. 9 प्रतिशत की सीमा को स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत को उत्तरोत्तर घटाया जाना था। 2012-13 में उजागर ₹5,55,302 करोड़ तक की राशि की अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. का 5.56 प्रतिशत थीं, जो कि राजकोषीय कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। राजकोषीय कानून के अनुसार 2012-13 में अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. का एक प्रतिशत होनी चाहिए थीं।

तालिका 1.17 दसवीं योजना औसत की तुलना में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल देयताओं में घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह मुख्यतः हाल के वर्षों में स.घ.उ. की वृद्धि कुल देयताओं में वृद्धि से काफी अधिक रहने के कारण थी। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि संघ सरकार को अपने ऋण स्टॉक को 2012-13 तक स.घ.उ. के 50.5 प्रतिशत और 2014-15 तक 44.8 प्रतिशत तक कम करना चाहिए।

तालिका 1.17: राजकोषीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार आन्तरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा* (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
X वीं योजना (2002-07) औसत	**1274620 (38.41)**	**72715 (2.19)**	**368973 (11.12)**	**1716307 (51.73)**	**193395 (5.83)**	**1836987 (55.36)**
XI वीं योजना (2007-12) औसत	**2409114 (35.64)**	**139377 (2.06)**	**558068 (8.25)**	**3106559 (45.95)**	**265049 (3.92)**	**3232230 (47.81)**
2008-09	2019841 (36.18)	123046 (2.20)	556235 (9.96)	2699122 (48.35)	264059 (4.73)	2840135 (50.87)
2009-10	2328339 (35.94)	134083 (2.07)	583279 (9.00)	3045701 (47.02)	249306 (3.85)	3160924 (48.80)
2010-11	2667115 (34.26)	157639 (2.03)	586458 (7.53)	3411212 (43.82)	278877 (3.58)	3532450 (45.38)
2011-12	3230622 (35.86)	170088 (1.89)	597765 (6.63)	3998475 (44.38)	322897 (3.58)	4151284 (46.08)
2012-13	3764566 (37.22)	177289 (1.75)	610016# (6.03)	4551871 (45.01)	332004 (3.28)	4706586 (46.54)

टिप्पणी: कोष्ठको में दर्शाए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

** 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

31.03.2013 तक लोक लेखा देयताएं ₹ 11,28,737 करोड़ पर रहीं, जिसमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में ₹ 5,17,221 करोड़ का निवेश तथा 2007-08 से भा.अ.वि.कं.लि. में ₹ 1,500 करोड़ का निवेश शामिल है।

उपरोक्त तालिका 1.17 दर्शाती है कि 2012-13 के लिए, आंतरिक ऋण (16.53 प्रतिशत) की वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि (12.25 प्रतिशत) से कहीं अधिक तेज थी जो कि 2012-13 में ऋण स्थिति के खराब होने को दर्शा रहा थी।

31 मार्च 2013 को, ₹ 37,64,566 करोड़ के आंतरिक ऋण का ₹ 39,41,855 करोड़ कुल लोक ऋण का लगभग 95.50 प्रतिशत संघटित किया। वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 2,81,891 करोड़ की राशि का भुगतान किया। आंतरिक ऋण पर अदा किए गए ब्याज में 80 प्रतिशत (₹ 2,25,520करोड़) से ज्यादा हिस्सा बाजार ऋण वाले ब्याज (विभिन्न दरों का) थे। 2012-13 के द्वारा भारत द्वारा अदा किए बाह्य ऋण (₹ 4,019 करोड़) के ब्याज पर किये गये भुगतान का लगभग 86 प्रतिशत (₹3,470.48 करोड़) अंश केवल चार संस्थाओं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (अं.वि.सं.), पुर्ननिर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (पु.वि.अं.बैं.), जापान सरकार एवं एशियाई विकास बैंक (ए.वि.बैं.) से ऋणों के प्रति था।

2012-13 के अंत में लघु बचतों, भविष्य निधियों, आदि के कारण केन्द्र सरकार की देयताओं को ₹ 9,88,832.95 करोड़ तक दर्शाया गया है। हालांकि, आई.आई.एफ.सी.एल. में ₹ 1,500 करोड़ एवं विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में ₹ 5,17,221.26 करोड़ के निवेशों को छोड़ने के पश्चात् निवल देयता ₹ 4,70,111.69 करोड़ तक दर्शाई गई थीं। संघ सरकार की कुल देयता की गणना करते समय राष्ट्रीय लघु बचत निधि के परिचालन को छोड़ देने के कारण 2012-13 के अंत में ₹69,476.57 करोड़ संचित घाटा हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए, लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के कारण 2012-13 के अंत में केन्द्र सरकार की देयता ₹10,58,309.52 करोड़ हो सकती थीं। परिणामस्वरूप, लोक लेखा के अंतर्गत देयता तथा संघ सरकार की कुल देयताओं को भी उस सीमा तक कम बताया गया था।

तालिका 1.18: गैर-ऋण प्राप्ति तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान

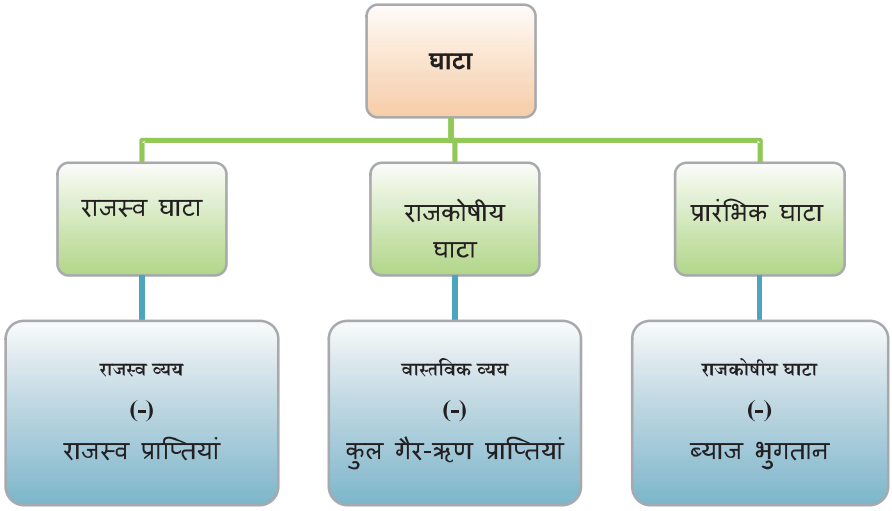
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	आंतरिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
2008-09	2154553	164164	10007	4195	2332919	667922
2009-10	3074652	180504	11139	3629	3269924	741837
2010-11	2802999	201841	11774	3156	3019770	984785
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	1108404

तालिका 1.18 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए सरकार के गैर-ऋण प्राप्तियों के समक्ष लोक ऋण के पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज) की मात्रा को दर्शाती है। 2008-09 के दौरान लोक ऋण का पुनर्भुगतान गैर-ऋण प्राप्तियों का 349 प्रतिशत था और 2012-13 में 335 प्रतिशत तक घट गया था। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान का अनुपात 357 प्रतिशत तक था, जो 2012-13 में 352 प्रतिशत तक घट गया है। जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में ऋण का कुल पुनर्भुगतान ₹ 29,196 करोड़ तक नीचे था और कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ ₹ 1,43,221 करोड़ तक बढ़ गई थीं।

1.5.1 घाटे के प्रकार

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार



(क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति बैक अप नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणतः कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य मापदंड **तालिका 1.19** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.19: राजस्व घाटा तथा उसके मापदण्ड

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	*प्रतिशतता* के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
	(₹ करोड़ में)					
XI वीं योजना (2007-12) औसत	**770152**	**1058775**	**288623**	**4.24**	**37.48**	**27.26**
2008-09	653847	1010224	356377	6.38	54.50	35.28
2009-10	704523	1057479	352956	5.45	50.10	33.38
2010-11	932686	1186115	253429	3.26	27.17	21.37
2011-12	910277	1305195	394918	4.38	43.38	30.26
2012-13	1055891	1420473	364582	3.60	34.53	25.67

तालिका 1.19 दर्शाती है कि 2011-12 में राजस्व घाटा बढ़ा लेकिन 2012-13 में ₹ 30,336 करोड़ तक कम हुआ। वर्ष 2012-13 में राजस्व घाटे में सुधार को राजस्व प्राप्तियों में 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की कारण से कहा जा सकता है।

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों के उपर वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यतः सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं या राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय मापदंडों के सापेक्ष घाटे की अधिशेष प्रवृति के साथ साथ राजकोषीय घाटा प्रवृति **तालिका 1.20** में इंगित की गई है।

तालिका 1.20: राजकोषीय घाटा तथा इसके मापदण्ड

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय
	(₹ करोड़ में)					
XIवीं योजना (2007-12) औसत	**811668**	**1198142**	**386474**	**5.69**	**47.61**	**32.26**
2008-09	667922	1102365	434444	7.78	65.04	39.41
2009-10	741837	1174280	432443	6.68	58.29	36.83
2010-11	984785	1367427	382642	4.92	38.86	27.98
2011-12	965183	1483064	517881	5.75	53.66	34.92
2012-13	1108404	1602918	494514	4.89	44.61	30.85

जैसाकि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे में चालू वर्ष में सुधार देखा गया।

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। **तालिका 1.21** ग्यारहवीं योजना अवधि तथा 2012-13 हेतु राजकोषीय घाटे के संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 1.21: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
XIवीं योजना (2007-12)औसत	**74.68**	**24.35**	**0.97**
2008-09	82.03	17.72	0.25
2009-10	81.62	17.60	0.78
2010-11	66.23	30.79	2.98
2011-12	76.26	23.44	0.31
2012-13	73.73	25.17	1.10

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति जाता है। 2012-13 में, राजकोषीय घाटे के घटक के रूप में निवल पूंजीगत व्यय के संबंधित अंश में सुधार था।

निम्न **तालिका 1.22** वर्ष 2012-13 में पूर्व वर्षों में बजटों के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय मापदंडों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है। वर्तमान वर्ष में, राजस्व घाटा बजट अनुमानों (ब.अ.) में दर्शाई गई निर्दिष्ट सीमा से सीमांत ऊपर था और राजकोषीय घाटा इस सीमा से नीचे था।

तालिका 1.22: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2010-11 में वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2011-12 में वर्ष 2012-13हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. में बजट अनुमान 2012-13	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	2.7	2.7	3.4	3.60
राजकोषीय घाटा	4.1	4.1	5.1	4.89

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता को छोड़ने के वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का उपाय है।

पिछले पाँच वर्षों के प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति **तालिका 1.23** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.23: प्राथमिक घाटा

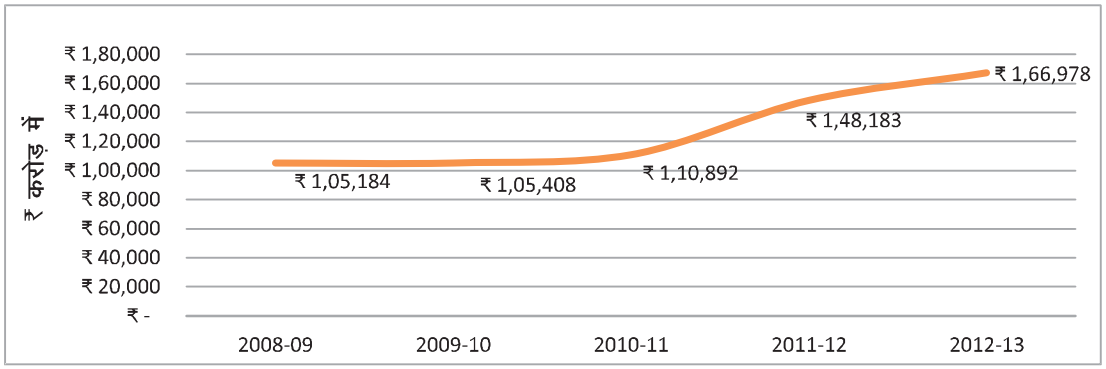
(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय भुगतान	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत में
2008-09	434444	200580	233864	4.19
2009-10	432443	223701	208742	3.22
2010-11	382642	224624	138018	1.77
2011-12	517881	286982	230899	2.56
2012-13	494514	330171	164343	1.63

1.5.2 बाह्य ऋण : अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2013 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता ₹ 1,66,978 करोड़ थी। **चार्ट 1.24** विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहरित शेष दर्शाता है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹ 29,406 करोड़), सड़कें (₹ 22,140 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹15,242 करोड़), विद्युत (₹ 14,171 करोड़), जल संसाधन प्रबंधन (₹ 11,567 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹11,462 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.24: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता



अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.24** ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए वचनबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.24: वचनबद्ध प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.पु.वि.बैं.	जोड़
2008-09	62.62	0.00	4.17	50.58*	117.37
2009-10	53.26	0.00	5.57	27.28	86.11
2010-11	40.15	23.23	26.78	18.63	108.79
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.29
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52

स्रोतः सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक

ए.वि.बैं.=एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं.=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

**अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सम्मिलित है।*

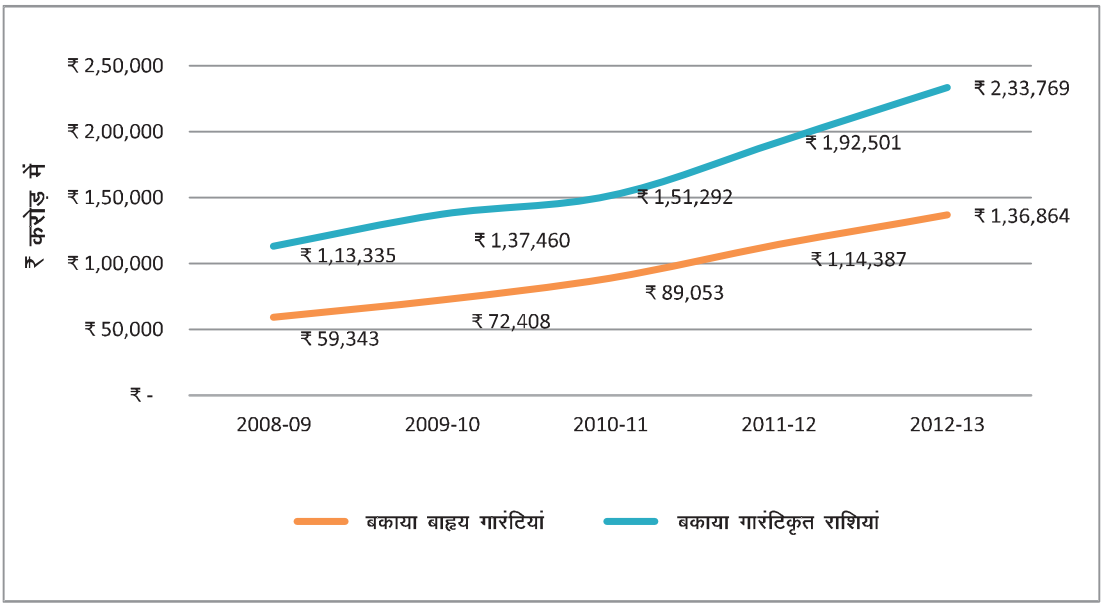
यह निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2012-13 में ₹ 92.52 करोड़ के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान, (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान, (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है। 31 मार्च 2013 को गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया तथा बकाया कुल गारंटियाँ क्रमशः ₹ 2,42,915 करोड़ तथा ₹ 2,33,769 करोड़ थीं।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, उसमें सरकार की ऋण स्थिति में तेजी लाने का सामर्थ्य होता है। अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और गारंटियों को आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में गारंटियों का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। **चार्ट 1.25** तथा **तालिका 1.23,** 2008-13 वित्तीय वर्षों के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि,बकाया गारंटीकृत राशियां तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट: 1.25 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ



तालिका 1.25: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	117659	113335	59343	52.36
2009-10	150437	137460	72408	52.76
2010-11	160611	151292	89053	58.86
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती है। 2012-13 में, 31 मार्च 2013 तक बकाया गारंटीकृत राशि (₹ 2,33,769 करोड़) में से 59 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गई, 33 प्रतिशत आर.बी.आई/बैंकों/औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष आठ प्रतिशत शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए गई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से उपभोक्ता मामलों, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील के मंत्रालय/विभाग थे। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारंटी रजिस्टरों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 नियम 3(3) में अनुबंधित है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार को 0.5 प्रतिशत स.घ.उ. की राशि से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए, यह प्रतिशतता गारंटियों के निवल संचयन के आधार पर निकाली गयी है। वर्ष 2012-13 में दी गई गारंटी ₹ 36,938 करोड़ की थी जो स.घ.उ. का 0.37 प्रतिशत थी। किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारंटी जो बकाया है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा क्योंकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारंटी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारंटी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2012-13 में, कुल बकाया गारंटियाँ (₹ 2,33,769 करोड़), स.घ.उ. का 2.31 प्रतिशत तथा 2012-13 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 22.14 प्रतिशत थीं।

2: लेखाओं पर टिप्पणियां

संघ वित्त लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियाँ अनुवर्ती पैरों में दी गई हैं। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4 तथा 5 में सम्मिलित किया गया है। सरकारी खर्च पर नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट कर संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

2.1 पारदर्शिता के मुद्दे

2.1.1 संघ के वित्त लेखों में बारहवें तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना

तेरहवें वित्त आयोग ने पाया था कि वित्त लेखे सभी परिशिष्टों को समावेशित नहीं करते तथा अनुशंसा की, कि (पैरा 7.134 में) वित्त लेखाओं के लिए परिशिष्टों की सूची का बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मानकीकरण किया जाए एवं इनका अनुपालन सभी राज्यों में किया जाए।

बारहवें वित्त आयोग ने, नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अधिक पारदर्शिता लाने एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु रोकड़ से लेखांकन को प्रोद्भूत आधार पर करने से संबंधित लम्बित परिवर्तन के चलते संघ सरकार के लेखाओं में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया था। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्न के संबंध में थीं:

(i) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की दी गई आर्थिक सहायता (ii) विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा वेतन पर व्यय (iii) पेंशनभोगियों पर व्यय का ब्यौरा एवं सरकारी पेंशन पर व्यय (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन को शामिल करते हुए सरकार के अधिकार में रखी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि या कमी (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव तथा (viii) वेतन तथा गैर वेतन भाग को अलग दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय ।

वर्ष 2012-13 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने उजागर किया कि बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों को संघ लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस बात का उल्लेख प्रासंगिक है कि (क) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं तथा (ख)

भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव पर दर्शाई गई विवरणियों को छोड़कर अधिकतर राज्यों ने अपने लेखाओं में उपरोक्त सभी विवरणियों को समाविष्ट कर लिया था।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 एवं 2011-12 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया था कि संघ सरकार के लेखाओं में कथित अतिरिक्त विवरणियाँ/सूचनाओं को शामिल करने संबंधी बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी, अनुपालन नहीं किया गया था। यह भी अनुशंसा की गई कि वित्त मंत्रालय संघ वित्त लेखाओं में उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने हेतु एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करे। मंत्रालय की कार्यवाही टिप्पणी अभी (फरवरी 2014) तक प्रतीक्षित थी।

जैसा कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ सरकार के वर्ष 2010-11 हेतु लेखे पर प्रतिवेदन में इंगित किया गया, राज्य सरकारों की वित्तीय विवरणियों में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति उत्साहजनक है। तथापि, संघ सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अनुपालना नहीं हुई है।

2.1.2 सरकारी लेखों में अपारदर्शिता

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में अधिक खुलापन एवं पारदर्शिता एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। यह पारदर्शी बजटीकरण तथा लेखांकन अभ्यास के उद्देश्य पर है जो यह सुनिश्चित करता है कि जिन सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु सरकार द्वारा निधियों की मांग की गई वे सरकार द्वारा किए गए वादे अनुसार व्यय की जाती है तथा व्यय से अधिकतम लाभ उठाया जाएगा। लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक यह है कि लेखा प्रपत्र, जिसमें सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को विधायिका को सूचित किया जाता है, उसकी निरन्तर समीक्षा तथा अद्यतन किया जाता है ताकि वे सही रूप में सभी महत्वपूर्ण भागीदारों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा कर सकें तथा एक पारदर्शी रूप में सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति तथा व्यय को प्रदर्शित कर सकें।

संघ सरकार वित्त लेखे 2012-13 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखों के 16 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के अंतर्गत कुल ₹10,814.62 करोड़ का कुल व्यय को लेखों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। यह लेखे में भारी अपारदर्शिता की मात्रा को दर्शाता है। उन कार्यकलापों का विवरण जिनमें व्यय में अपारदर्शिता विद्यमान हैं-अन्य सामाजिक सेवाएँ, कृषि वित्तीय संस्थान, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, नागरिक उड्डयन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,

अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, तथा विदेशी व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय आदि 16 मुख्य शीर्षों के विवरण **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण व्यय मदों जैसे किसानों को अल्प अवधि ऋण पर ब्याज से छूट (₹5,400 करोड़), मिशन लचीले कुण्ड (₹2,953 करोड़), रक्षा सेवाओं हेतु ओ.एफ.सी. आधारित तंत्र (₹1,517 करोड), असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता (₹1,552 करोड़), पुस्तक प्रोत्साहन हेतु संस्थान (₹1,001 करोड़), हज चार्टर के परिचालन हेतु सब्सिडी (₹908 करोड़), निर्यात अवसंरचना एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता की योजना (₹592 करोड़), राष्ट्रीय आरोग्य बिल (₹506 करोड़) को वित्त लेखों में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था बल्कि लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' में जोड़ा गया था।

इस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 को समाप्त संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदनों में इस अनुशंसा के साथ टिप्पणी की गई थी कि इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की संरचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए जिससे वित्तीय रिपोर्ट देने में अधिक पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। एक अंतरिम उपाय के रूप में, लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत आवृत्त महत्वपूर्ण व्यय के ब्यौरों को वित्त लेखे में फुट नोटों के माध्यम से दर्शाया है। सरकार के वर्तमान कार्यकलापों को दर्शाने के लिए लेखे की पुनर्संरचना की बजाए सरकार के भारी व्यय को स्पष्ट ढ़ंग से दर्ज करने के लिए कुछ नये लघु शीर्ष खोलने हेतु टुकड़ों में की गई कार्यवाही मदद नहीं कर सकती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यवाही टिप्पणी में इस संबंध में दिए गए आश्वासन (सितम्बर 2010) तथा ले.म.नि. द्वारा लेखानियंत्रकों को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय को दर्ज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने हेतु अनुदेशों को दोहराए (जनवरी-2012) जाने के बावजूद, स्थायी तौर पर समस्या का निदान करने हेतु लेखा शीर्ष में मुख्य पुनर्संरचना प्रतीक्षित है।

2.1.3 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

(क) सरकारी लेखे से बाहर पड़ी नियामकों की निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005[1] में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया जाए।

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.ज्ञा.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.) /2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

14 नियामक निकायों एवं स्वायत्त निकायों, जो अपने क्षेत्र विशेष में नियामक के रूप में कार्य करते हैं, के वार्षिक लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जनवरी 2005 में जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2013 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति, कोष निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹4782.06 करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे। इन मामलों को **अनुबंध 2.2** में दर्शाया गया है।

नियामक निकायों, नामतः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) तथा पेंशन निधि निकाय विकास प्राधिकरण (पें.नि.नि.वि.प्रा.), के संबंध में इस मुद्दे पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष समाप्ति 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 हेतु संघ सरकार के लेखों पर प्रतिवेदनों में टिप्पणियाँ की गई थीं।

वित्त मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया (सितम्बर 2011) कि सरकारी लेखे में निधि को प्रचालित करने हेतु भारतीय लोक लेखे के ब्याज वहन न करने वाले वर्ग में मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत क्रमशः 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) निधि' तथा 'बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) निधि' के नाम से अलग निधियाँ खोली जाएंगी। मंत्रालय के बजट प्रभाग ने भी कार्यालय मुख्य नियंत्रक लेखा से कथित लेखांकन दिशानिर्देश/प्रक्रिया पर आधारित विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया तैयार करने हेतु अनुरोध किया।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया (फरवरी 2014) कि 'बी.नि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार', प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी शुल्क एवं प्रभार, केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किये एसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां बी.नि.वि.प्रा. निधि का भाग होगी। इस मामले की विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जांच की जा चुकी है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्राप्त धन, इसके द्वारा भारत सरकार के लिए और उसकी ओर से लिया गया धन है इसलिए इसे लोक लेखे में जमा कराना आवश्यक है।

वित्त मंत्रालय ने आगे बताया कि भा.प्र.वि.बो. के पास भा.प्र.वि.बो अधिनियम धारा 15 जे ए के अंतर्गत एक प्रावधान है जो जुर्माने के माध्यम से प्राप्त सारी धन राशियों को भारत की संचित निधि में जमा करने की व्यवस्था करता है, लेकिन बी.नि.वि.प्रा. अधिनियम 1999 के अंतर्गत ऐसी राशियों को भारत की संचित निधि में जमा करने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था। अतः बी.नि.वि.प्रा. अधिनियम 1999 के प्रावधान एवं विधि तथा न्याय मंत्रालय द्वारा दी गयी कानूनी राय में कोई अंतर्विरोध नहीं था। इसके

अतिरिक्त उपर्युक्त के परिचालन हेतु कार्रवाई, एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी, मंत्रालय द्वारा नहीं की गयी थी।

उपभोक्ता मामलों मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण, उपभोक्ता मामले विभाग ने बताया (मार्च 2014) कि भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) संसद के अधिनियम द्वारा (अर्थात भा.मा.ब्यू. अधिनियम, 1986) निर्मित एक वैधानिक निकाय है। अधिनियम की धारा 3 (2) में स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि ब्यूरो एक निगमित निकाय है। अधिनियम में कहीं भी इसे वैधानिक निकाय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। उसने आगे बताया कि धारा 10 (1) के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी कार्य को नियामक कार्य नहीं समझा जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.मा.ब्यू. सरकार के संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी नियमन के कार्यों को अनिवार्य रूप से करता है, इस प्रकार, इसे एक नियामक निकाय माना जाना चाहिए और इसलिए दिनांक 7 जनवरी 2005 के वित्त मंत्रालय का का.ज्ञा. इस पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त भा.मा.ब्यू. अधिनियम, 1986 की धाराएं 10 (1) और 15 में परिकल्पित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में नियामक के रूप में ही कार्य करता है।

पशु पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (भा.प.चि.प.) के सदस्यों, अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु अनुदानों का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह राज्य की परिभाषा में नहीं आता।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भा.प.चि.प. एक नियामक का कार्य कर रहा है। तदनुसार, इसकी 'निधि' को यह ध्यान दिए बिना कि क्या वह वेतन के भुगतान हेतु सरकार से अनुदाने प्राप्त करता है या नहीं, सरकारी लेखाओं का भाग होना चाहिए।

(ख) प्र.वृ.नि.प्र.ओ.प्रा. निधि का सरकारी लेखे से बाहर रखना

प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबंधन एवं आयोजन प्राधिकरण (प्र.व.नि.प्र.आ.प्रा.) को सभी उपभोक्ता अभिकरणों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर-वन प्रयोजन हेतु विपथन को अनुमेय करते समय संग्रहित प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधियों (प्र.वृ.नि.) तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से इस तरह विपथित वन-भूमि के निवल वर्तमान मूल्य के प्रति प्राप्त राशियों का भी संरक्षक होना था। संग्रहित धन को प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. हेतु प्र.वृ.नि.प्र.प्र.आ.प्रा. द्वारा न्यास में रखा जाना था और परिचालित अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार पर संबंधित राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी किया जाना था। एकत्रित निधियों को अंतरिम में निवेशित रखा जाता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अक्तूबर 2002 में निर्देश दिया था कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निधियाँ संघ, राज्य के सामान्य राजस्वों अथवा भारत की आकस्मिकता निधि का भाग नहीं होगी। इस प्रकार प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. निधियाँ वर्तमान समय में भारत की आकस्मिकता निधि अथवा भारतीय लोक लेखे के बाहर रखी गयी हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.व.मं.) की दिनांक 13 मार्च 2007 की अधिसूचना के अनुसार, प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (सितम्बर 2005) के अनुसार दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित कॉर्पोरेट लेखांकन अपनाने का निर्देश दिया गया था। राज्य प्र.वृ.नि.प्र.आ. के दिशानिर्देश के अनुरूप राज्य प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. समुचित लेखे एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में लेखे के वार्षिक विवरण को तैयार करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय एवं प.व.मं. द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों को नीचे संक्षिप्त में वर्णित किया गया है।

दिनांक	निर्देश
23 अप्रैल 2004	अन्य बातों के साथ प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. को शामिल करने वाली प.व.मं. की अधिसूचना निर्धारित करती थीः • कार्यकारी निकाय, प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. की शक्तियों एवं कार्यों में 'निधियों का निवेश' शामिल था। • प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंको, डाकघर सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी बंधपत्रों एवं जमाओं में निवेश किया जाएगा।
6 मई 2006	सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. को सृजित करने वाले अपने आदेश के माध्यम से प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. की ओर से उपभोक्ता अभिकरणों से प्राप्त समस्त धनराशियों एवं विभिन्न राज्य सरकार पदाधिकारियों द्वारा उस पर अर्जित आय की लेखापरीक्षा कराई जानी थी, जिसके लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नि.म.ले.प. के द्वारा की जानी थी। लेखापरीक्षा को जांच करनी थी कि क्या निधियों को निवेशित करते समय समुचित वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

2006 एवं 2013 की अवधि के दौरान, तदर्थ प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. के साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि ₹1,324.22 करोड़ से बढ़कर ₹26,384.73 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2013 तक, एकत्रित निधियों में ₹20,417.51 करोड़ की राशि का मूलधन एवं ₹5,967.22 करोड़ के ब्याज संघटक शामिल थे।

उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्र.व.नि. के प्रति देय धनराशि के संग्रहण का मौजूदा स्वरूप, इसका लेखाकरण, प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. प्राधिकरणों द्वारा संघ/राज्य/सं.शा.क्षे. स्तर पर किये गये व्यय, इस निधि के प्रदर्शन से संबंधित प्रबंध तथा सरकारी वित्तीय विवरण में इससे प्राप्ति एवं व्यय, संसद एवं राज्य विधानसभा में इसका प्रतिवेदन उल्लेखनीय मुद्दें उत्पन्न करते हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः-

- केन्द्रीय प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. के पास मौजूदा धन राशि काफी अधिक है। 31 मार्च 2013 तक वे ₹26,384.73 करोड़ तक थे।

- राज्य/सं.शा.क्षे. प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. प्राधिकरणों को 31 मार्च 2013 तक कुल निर्गम ₹3,831.26 करोड़ था और उनके द्वारा मार्च 2012 तक सूचित व्यय ₹1,775.84 करोड़ था।

- जबकि प्राप्ति एवं व्यय काफी अधिक थे, मंत्रालय द्वारा प्र.वृ.नि. से संबंधित आय एवं व्यय को संसद या राज्य विधानसभाओ को सूचित करने के लिए कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

- संग्रहित एवं व्यय की गयी धन राशि न केवल संसद एवं राज्य विधानसभाओं की जानकारी में नहीं थी, बल्कि विधायिका प्राधिकारों द्वारा व्यय करने के प्राधिकरण हेतु कोई प्रणाली भी विद्यमान नहीं थी।

- इस तथ्य के आलोक में कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के प्रति प्राप्त राशि काफी अधिक थी, यह देखना भी उतना ही चिंताजनक था कि केन्द्र और राज्य दोनों में ही ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी जिससे मंत्रालय में या राज्यों में मंत्रालय शीर्ष स्तर पर स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर सकें कि संग्रहित की जा रही राशि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं अन्य अधिनियमों, नियमों एवं उपयोग को विनियमित करने वाले आदेशों तथा प्र.वि.नि. के उपयोग एवं संग्रहण को विनियमित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप थे।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत संग्रहित की जा रही निधियों की राशि उससे होने वाले व्यय, प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. से संबंधित कार्य में निहित स्पष्ट लोक हित को देखते हुए, मंत्रालय को प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. के मौजूदा स्वरूप की समीक्षा करनी चाहिए यथावश्यकतानुसार सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना चाहिए। इसे इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हो, प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. को संसद एवं राज्य विधानसभाओं दोनों के वृहतर केन्द्र-बिन्दु में एवं व्यापक लोक दृष्टि में लाया जा सके ताकि अधिकतम संभव पणधारियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इस लक्ष्य के लिए यह उचित होगा यदि तदर्थ प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. में पड़ी राशि को भारतीय लोक लेखा में हस्तांतरित कर दिया जाए, जैसाकि प्रतिपूरक वृक्षारोपण निधि बिल 2008 में परिकलित था, जो 2009 में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और बाद में सभा के भंग होने के परिणामस्वरूप व्यपगत हो गया था। प्रत्येक राज्य को किए जाने वाले हस्तांतरणों को पारदर्शी बनाया जा सकता है ताकि सभी पणधारियों को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. पर बजटीय वित्तीय तथा निष्पादन संबंधी सूचना/जानकारी की लोक प्रलेखों में, पूर्णतः प्रदर्शित हो, प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. से आय एवं बहिर्गमनों को केन्द्र एवं राज्य स्तर पर दर्शाया गया हो, जिससे मौजूदा प्रबंधन में बृहतर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को प्रभावी किया जा सके।

प.व.मं. ने बताया (दिसम्बर 2013) कि प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. निधियों के सक्षम एवं पारदर्शी तरीके से परिरक्षा एवं सुरक्षा तथा उपयोग को सुनिश्चित करने और दिनांक 23 अप्रैल 2004 के मूल प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. अधिसूचना एवं राज्य प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. दिशानिर्देश 2009 के साथ पठित सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10 जुलाई 2009 के आदेश की संशति में सामंजस्य को भी सुनिश्चित करने तथा राज्य प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए वि.मं. ने नियमित प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. को द्विस्तरीय संरचना यथा एक राष्ट्रीय प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. केन्द्रीय सरकार स्तर पर एवं प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. में राज्य प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. के साथ गठित करने के लिए एक मसौदा आदेश (सर्वोच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद) तैयार किया था। कथित मसौदा आदेश की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संघ मंत्रीमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक मसौदा टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा चुका था। तथ्य यह था कि ₹26,384.73 करोड़ की प्र.वृ.नि.प्र.आ.प्रा. निधि सरकारी लेखे के बाहर रखी गयी थी।

(ग) सरकारी धन को सरकारी लेखे से बाहर रखा जाना

संविधान का अनुच्छेद 114 एवं 115, संबंधित वित्त वर्ष हेतु सेवाओं पर व्यय करने के लिए भारत की समेकित निधि निर्दिष्ट धनराशियों के लिए आहरण को प्राधिकृत करता है।

केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 11 के अनुसार, सरकारी खाते से किसी लेखा अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में खुले किसी खाते पर जारी चैकों के प्रति, अथवा आ.सं.अ. के लिए खुली एक समनुदेशन लेखा से एक मान्यता प्राप्त शाखा से चैक के आहरण, के अलावा धन की निकासी नहीं की जानी चाहिए। ऐसे खाते विभाग के वित्तीय सलाहकार के आदेश द्वारा लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) के परामर्श से खोले जाने चाहिए। सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय नियमावली में लोक निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) और इसकी इकाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और अंतरिक्ष उपकरणों के देश के सर्वांगीण विकास हेतु सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाने का प्राथमिक दायित्व है, जिसके लिए विभिन्न विकासमूलक परियोजनाएं समय-समय पर शुरू की जाती है। अधिकांश परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष मिशन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अंतरिक्ष उपभोग्य वस्तुओं के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना एवं कमीशन हेतु विकास मूलक संविदाओं एवं क्रय-आदेश शामिल हैं।

तथापि, अंतरिक्ष विभाग ने अपनी दो इकाईयों, नामतः विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अ.के.) एवं तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (त.प्र.प्र.के.) को 19 संविदाओं/क्रय

आदेशों के निष्पादन हेतु भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में निलंब[2] खाते खोलने की संस्वीकृति प्रदान की थी। इन केन्द्रों ने भा.स्टे.बै. एवं ठेकेदारों के साथ इन परियोजनाओं को चलाने के लिए निलंब खाते परिचालित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। अंतरिक्ष विभाग ने परिचालित निलंब खातों के विवरण को दर्शाने वाली एक सूची **अनुबंध 2.3** में दी गयी है।

निलंब खातों के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

- वि.सा.अ.के. एवं व.प्र.प्र.के., द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 के आरंभ से भारत की आकस्मिता निधि से भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में विभिन्न शाखाओं पर बड़ी धन राशियों का हस्तांतरण किया गया था। इन इकाईयों ने 19 निलंब खातों में ₹831.11 करोड़ की राशि हस्तांतरित की थी।

- 19 खातों में से, तीन खाते बंद हो चुके थे और 16 निलंब खाते चालू थे तथा बैंकिंग प्रणाली में 31 मार्च 2013 तक उपलब्ध शेष ₹139.90 करोड़ था और शेष पर कमाया गया ब्याज ₹100.16 करोड़ था।

- अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान, अ.वि. इकाइयों द्वारा ₹186.16 करोड़, सरकारी खाते से बैंकिंग प्रणाली में हस्तांतरित किया जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.1 एवं तालिका 2.2** में दिया गया है:-

तालिका 2.1: सरकारी निधियों का निलंब खाते में अंतरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	निलंब खातों की संख्या	वित्तीय स्वीकृति	अर्जित ब्याज	2008-13 के दौरान व्यय	2008-13 के दौरान निलंब खाते में अंतरण	31 मार्च 2013 तक शेष
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र	15	686.01	76.42	163.04	186.16	132.50
तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र	4	145.10	23.74	0	0	7.40
कुल	**19**	**831.11**	**100.16**	**163.04**	**186.16**	**139.90**

तालिका 2.2: सरकारी निधियों का निलंब खाते में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
मार्च की समाप्ति पर शेष	181.82	218.67	184.17	216.44	139.90	139.90
वर्ष के दौरान व्यय	39.13	49.95	73.96	0.00	0.00	163.04
निलंब खाते में अंतरण	63.50	78.11	32.81	9.44	2.30	186.16

[2] निलंब खाता किसी बैंक में सम्पत्ति कर, बीमा प्रीमियम इत्यादि देयताओं के भुगतान हेतु गृहीता के नाम पर एक न्यास खाता है, जहाँ भुगतान जारी करने के पूर्व, धन को बैंक में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाना होता है और बैंक ठेकेदार को विभिन्न संविदागत दायित्वों की पूर्णता के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर यथानुपात आधार पर धन का संवितरण करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय समेकित निधि से निलंब खाते खोलकर लंबी समयावधि में व्यय करने के लिए धन का आहरण और बैंकों में अंतरण, संसदीय प्राधिकरण का गंभीर उल्लंघन है।

चूंकि सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय नियमावली में लोक निधियों का सरकारी खातों से बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है, मार्च 2013 तक ₹139.90 करोड़ के लोक निधि का सरकारी खाते से बाहर रखना अनियमित है।

अंतरिक्ष विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि 19 निलंब खातों में से, 14 खाते पहले से ही बंद कर दिए गए हैं और 20 मार्च 2014 तक सरकारी प्राप्तियों को क्रेडिट किए गए अव्ययित शेष/अर्जित ब्याज तथा शेष ₹94.09 करोड़ तक कम हो गया था। अं.वि. ने आगे बताया कि एक खाते को अप्रैल 2014 में बंद कर दिया जाएगा और शेष चार खातों को 2014-15 में सीमित अवधि के लिए जारी रखा जाएगा। अं.वि. का उत्तर को इस तथ्य के प्रसंग में देखा जाना चाहिए कि विभाग के वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अव्ययित शेष बजट अनुमानों 18 से 42 प्रतिशत के बीच थे तथा इनका औसत 25 प्रतिशत से अधिक[3] था। इसलिए, जब वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाओं पर व्यय के लिए निधियाँ उपलब्ध थी तो इनको अपनी परियोजनाओं के लिए अलग से निलम्ब खाते के परिचालन की आवश्यकता नहीं थी।

2.1.4 सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया जाना तथा राज्यों को कम आवंटन

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उद्ग्रहित अग्रिम सीमाशुल्क प्राप्ति, जो आगामी अवधि से संबंधित हो, को लोक लेखे के अंतर्गत प्रतीक्षारत उचंत शीर्ष[4] में रखा जाता है। राशि को भारत की समेकित निधि (स.नि.) में उस वर्ष क्रेडिट किया जाता है जिस वर्ष से संग्रहित अग्रिम कर संबंधित होता है।

वित्त लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भिक शेष के रूप में प्रतीक्षारत उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 249.50 करोड़ उपलब्ध था। इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारत की समेकित निधि में सीमा शुल्क प्राप्ति के रूप में लेखांकित किया जाना था। तथापि, यह राशि उचंत लेखे में लेखांकित हुई। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012-13 में भारत सरकार की सीमाशुल्क प्राप्तियों को ₹ 249.50 करोड़ से कम बताया गया। सीमाशुल्क प्राप्तियों के रूप में संग्रहित राशि वितरणीय कर संग्रह का हिस्सा है जिसका वितरण केन्द्र तथा राज्य के बीच किया जाता है। इस राशि का भारत की समेकित निधि में क्रेडिट न होने का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्त आयोग द्वारा निदेशित राज्यों को कर आवंटन में कमी होना है।

---

[3] 2008-09: 18 प्रतिशत, 2009-10: 16.5 प्रतिशत, 2010-11: 22.43 प्रतिशत 2011-12: 42 प्रतिशत 2012-13: 27.68 प्रतिशत औसत 25.23 प्रतिशत

[4] 8658-136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमाशुल्क प्राप्ति

इस मामले पर 2010-11 एवं 2011-12 के समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी, परंतु वर्ष 2012-13 के दौरान कोई सुधारत्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।

के.सी.उ.शु. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि ₹170.39 करोड़ की राशि प्रतीक्षारत उचंत के अंतर्गत ऋणात्मक जमा के रूप में दर्ज की गई तथा भारत की समेकित निधि में 2012-13 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्ति के रूप में लेखांकन किया गया था। यह भी बताया गया कि कथित शीर्ष के अंतर्गत बचे हुए शेष के निपटान हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

2.2 लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ

2.2.1 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, लघु शीर्ष-118) को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नी.) 1999 में सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों को दिए गए महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 ने सा.से.दा. निधि को सांविधिक महत्व दिया तथा निर्धारित किया कि निधि का उपयोग केवल आधारभूत टेलीग्राफ सेवाओं को पहुँच प्रदान करते हुए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने हेतु किया जाना है, यथा, सार्वजनिक दूरसंचार एवं सूचना सेवाएं तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन का प्रावधान जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। इसमें ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, चरणबद्ध रूप से गाँवों में ब्रॉडबैंड जुड़ाव का प्रावधान ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रवर्तन को प्रोत्साहन आदि की अवसंरचनाओं के विकास पर बल देना आदि विचारित थे। सा.से.दा. निधि को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" (सा.प.उ.) के माध्यम से एकत्र किया जाना था। सा.से.दा. से संबंधित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन पात्र सेवादाताओं द्वारा किया जाना था, जिन्हें नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होनी थी।

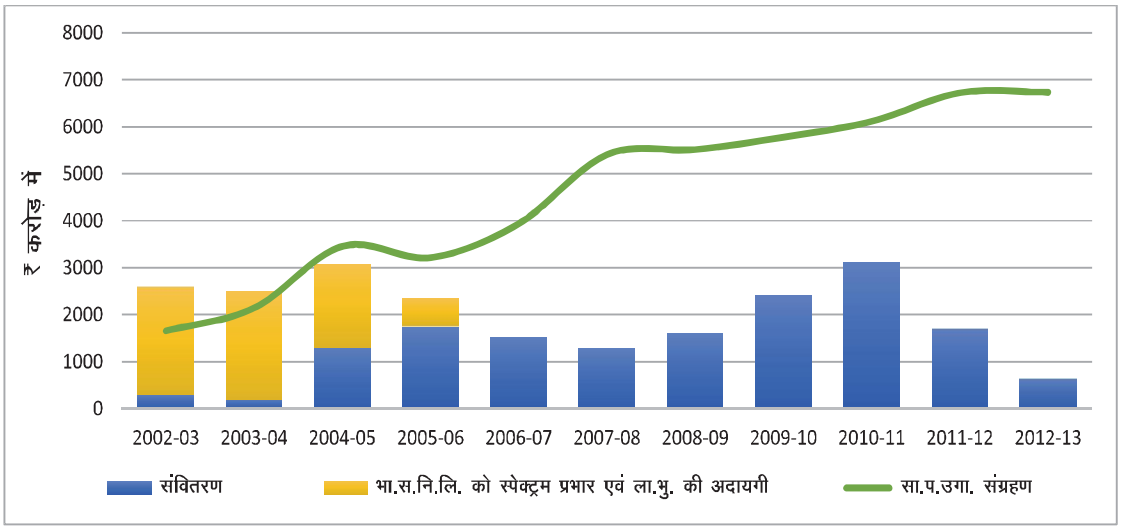
इस निधि का प्रबंधन दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर सा.से.दा. को पूरा करने हेतु विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में सा.से.दा. निधि की प्राप्तियां जमा करती है तथा यह एक गैर-व्यपगत निधि है।

सा.से.दा. निधि के कम बताए जाने के मामले पर वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने भी वित्त मंत्रालय द्वारा निधियाँ, जो

केवल सा.से.दा. क्रियाकलापों के लिए है, से अन्य कार्यक्रमों के लिए विपथन को अस्वीकृत किया था।

दू.वि. ने 2011-12 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा सं. 2.2.1 में सा.से.दा. निधि पर की गयी अभ्युक्तियों पर का.टि. प्रस्तुत करते हुए सा.से.दा. की विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं हेतु 31.03.12 तक ₹22,108.04 करोड़ को संवितरित राशि के रूप में पुष्टि की। इसमें बी.एस.एन.एल. को लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभारों के प्रति अदा ₹6,948.64 करोड़ की राशि शामिल थी। यह बताया गया था कि वित्त मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण देयताओं को पूरा करने के लिए बी.एस.एन.एल. की ₹6,948.64 करोड़ की राशि के लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभारों की अदायगी को, उपलब्ध शेष पर पहुंच हेतु लेखे में लेना आवश्यक है। 'सा.प.उ.' का वर्ष-वार संग्रहण एवं किये गये संवितरण निम्न चार्ट में दर्शाये गये हैः

चार्ट 2.1: सार्वभौमिक सेवाएं देयता निधि



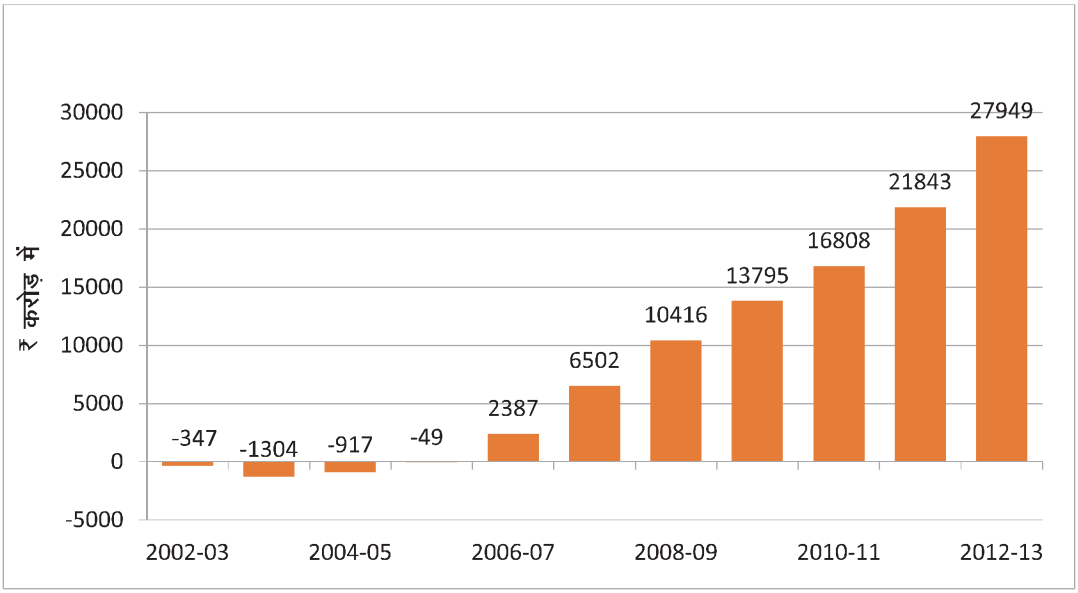
सा.से.दा. निधि का कम बताया जाना

सा.से.दा. निधि पर नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बावजूद, दू.वि. ने वर्ष 2012-13 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹6,735.47 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से लोक लेखे में सा.से.दा. निधि को केवल ₹625.00 करोड़ का अंतरण किया तथा सा.से.दा. निधि के अंतर्गत अंत शेष को 'शून्य' के रूप में दर्शाया था। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष को ₹6,110.47 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2002-03 से 2012-13 के दौरान ₹50,682.96 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति इन अवधियों के दौरान निधि से केवल ₹22,733.04 करोड़ (ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु 2002-03 से 2005-06 की अवधि में भा.सं.नि.लि. को

कुल ₹6,948.64 करोड़ के लाइसेंस शुल्क एवं स्पैक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए जैसा दर्शाया गया है) का संवितरण किया गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2013 को ₹27,949.92 करोड़ की सा.से.क्ष. निधि के अंत शेष का समग्र रूप से कम कथन था जो कि वर्ष दर वर्ष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जैसा नीचे बार में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: सा.से.दे. निधि ने वर्ष की समाप्ति पर संचयी शेष



दू.वि. ने पैरा में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों से सहमत होते हुए अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से प्राप्त राशि सा.से.दा.निधि को क्रेडिट किया जाता था। उसने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से प्राप्त ₹625 करोड़ को कथित वर्ष में सा.से.दा. निधि में अंतरित कर दिया गया था तथा सा.से.दा. निधि में किए गए अंतरण और किए गए पूरे आवंटन को उसी वित्तीय वर्ष 2012-13 में बेहतर उपयोग किया गया था और वित्तीय वर्ष में अंत में 'शून्य' शेष था। दू.वि. ने यह भी बताया कि निधि को क्रेडिट किया गया शेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होनी चाहिए।

लोक लेखा समिति ने अपने चौदहवे प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अपनी अनुशंसाओं में पाया कि सरकार को यू.ए.एल. के रूप में एकत्रित पूरी राशि को सा.से.दा.निधि में क्रेडिट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी जबकि मुख्य रूप से निधि का उपयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए होना चाहिए था।

इस प्रकार, वर्ष 2012-13 हेतु वित्त लेखा में सा.से.दा. निधि के अंतर्गत 'शून्य' शेष दर्शाना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के उल्लंघन में था जो कि यह निर्धारित करता है कि सा.से.दा.नि. एक व्यपगतरहित निधि है।

2.2.2 अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम-उपयोग

1986 में अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम को विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने तथा उसके साथ संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु किए गए सभी भुगतानों पर उपकर की उगाही तथा संग्रहण के प्रावधान हेतु लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति किए गए सभी भुगतानों पर उद्ग्रहित तथा संग्रहित किए जाने वाले उपकर के संग्रहण की ऐसी दरों जो 5 प्रतिशत से अधिक न हों, जैसा कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, का प्रावधान करती है।

अधिनियम ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (प्रौ.वि.बो.) द्वारा संचालित की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु एक निधि के सृजन को समर्थ किया। प्रौ.वि.बो. निधि का अनुरक्षण सरकारी लेखे से बाहर किया जाता है। निधि को अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनयम 1986 जैसा कि 1995 में संशोधित किया गया, के अंतर्गत औद्योगिक मामलों द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर सरकार द्वारा संग्रहित उपकर से, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों से क्रेडिट किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास उपकर संग्रहण का प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 उदग्रहित तथा संग्रहित उपकर की प्राप्ति को भारत की निधि में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित करती है तथा सरकार, संसद की स्वीकृति से विकास बैंक (इस मामले में पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) को निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी राशि अदा करेगी।

नीचे दी गई **तालिका 2.3** में दिए गए आंकड़ों में यह पाया गया है कि 1996-97 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान उपकर के माध्यम से ₹4,139.17 करोड़ की सीमा तक की निधियां संग्रहित की गई थीं। इसमें से, उसी अवधि के दौरान प्रौ.वि.बो. को सहायता अनुदान के रूप में ₹528.91 करोड़ (12.77 प्रतिशत) मात्र संवितरित किए गए थे। प्रौ.वि.बो. ने, इसके बदले सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे अथवा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित औद्योगिक मामलों हेतु ₹1,118.67 करोड़ की वित्तीय सहायता तथा ऋण संवितरित किए।

तालिका 2.3: अनुसंधान एवं विकास उपकर का संग्रहण तथा इसका उपयोग

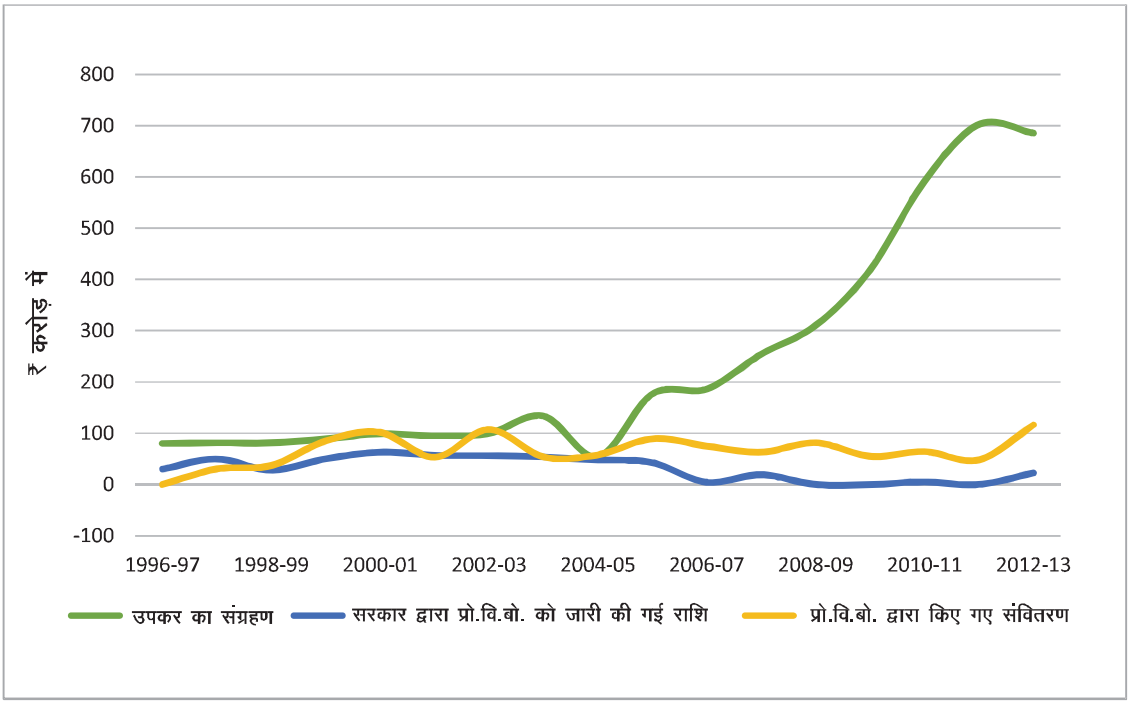
(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित उपकर	प्रौ.वि.बो., को जारी अनुदान	प्रो.वि.बो. द्वारा तकनीकी विकास के लिए संवितरण
1996-97	80.13	29.97	शून्य
1997-98	81.42	49.93	30.14
1998-99	81.10	27.99	36.99
1999-00	88.93	50.00	85.23
2000-01	98.91	62.79	101.73

वर्ष	संग्रहित उपकर	प्रौ.वि.बो., को जारी अनुदान	प्रो.वि.बो. द्वारा तकनीकी विकास के लिए संवितरण
2001-02	95.30	57.00	53.44
2002-03	99.47	56.00	107.11
2003-04	133.74	53.65	53.86
2004-05	53.98	48.10	57.91
2005-06	176.61	42.66	89.23
2006-07	186.56	4.32	74.98
2007-08	254.09	19.00	63.01
2008-09	310.33	-	81.60
2009-10	418.22	-	55.04
2010-11	592.22	5.00	64.19
2011-12	702.54	-	48.00
2012-13	685.62	22.50	116.21
कुल	**4139.17**	**528.91**	**1118.67**

वर्षों से उपकर के संग्रहण तथा इसके उपयोग का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार **(चार्ट 2.3)** दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3 : अ. एवं वि. उपकर का संग्रहण तथा इसका उपयोग



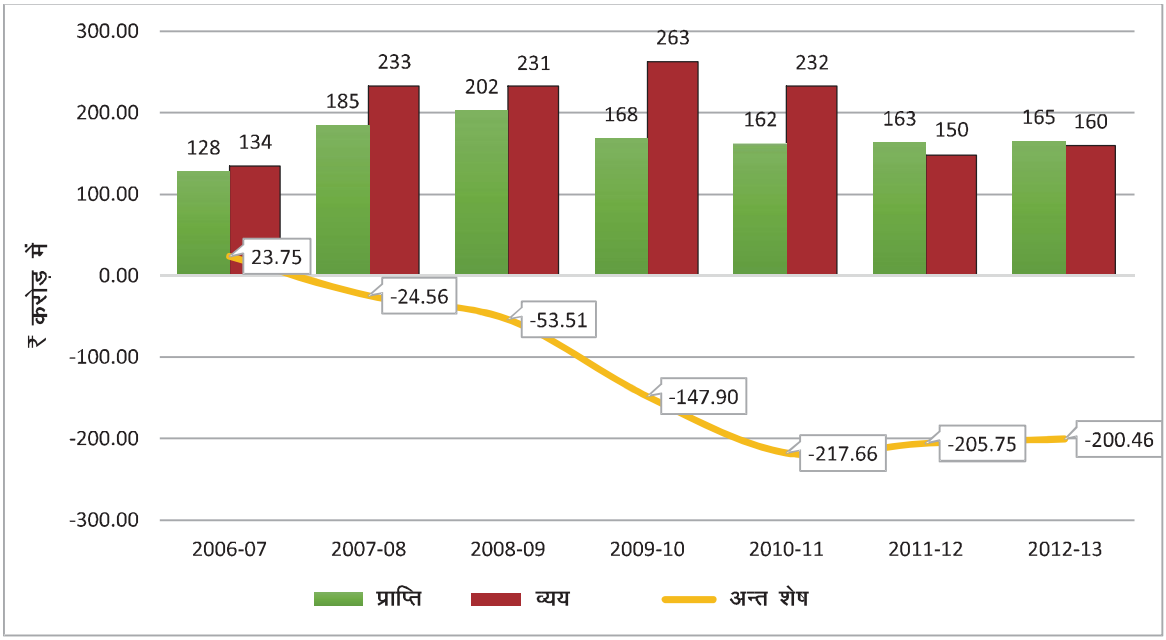
उपरोक्त चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत उपकर का संग्रहण पर्याप्त है। तथापि, प्रत्याशित उद्देश्यों हेतु उपकर प्राप्ति का उपयोग इष्टतम नहीं है। इस प्रकार उपकर प्राप्ति का वर्षों से सरकार के राजस्व घाटे का वित्तपोषण करने हेतु आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अपेक्षित उद्देश्यों हेतु प्राप्ति के कम उपयोग के कारण उपकर की उगाही की दर को पिछले वर्ष भी बढ़ाया गया था तथापि प्रवृत्ति वैसी ही बनी हुई थी।

2.2.3 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियां तथा निरंतर प्रतिकूल शेष

लोक लेखे[5] के अंतर्गत बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को बीड़ी स्थापनाओं में लगे व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 सृजित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, सरकार ने उत्पादित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में एक उपकर को प्रारम्भ किया। इस उपकर के माध्यम से संग्रहण को लोक लेखे में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में क्रेडिट किया जाना था।

2006-07 से 2012-13 की अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में व्यय, प्राप्तियों तथा अंत शेष के संबंध में समग्र स्थिति को नीचे **चार्ट** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.4: बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियां एवं निरंतर प्रतिकूल शेष



ऊपर चार्ट दर्शाता है कि निधियों में से प्राप्तियों से काफी अधिक व्यय होने के कारण वर्षों से बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में प्रतिकूल शेष हुआ था। 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था, जो कि 2007-08 में ₹(-)24.56 करोड़ से 2011-12 में ₹(-)205.75 करोड़ तक लगातार बढ़ा है। 2012-13 में यह ₹(-)200.46 करोड़ पर आकर थोड़ा कम हुआ था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 से 2012-13 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखाओं की जाँच ने प्रकट किया कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को अंतरित राशियों

[5] मु.शीर्ष 8229.200

तथा उससे पूरे किए गए व्यय में विसंगतियां थीं। इसका विवरण नीचे **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: उपकर प्राप्ति एवं बीडी श्रमिक कल्याण निधि का परिचालन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत की समेकित निधि में उपकर प्राप्ति	लोक लेखे में बीड़ी निधि को अंतरण		लोक लेखे में बीड़ी निधि से व्यय	
		अंतरण (विनियोग लेखे के अनुसार)	अंतरण (शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार)	निधि से पूरा किया गया व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	निधि से पूरा किया गया व्यय (वसूली विवरणी के अनुसार)
2006-07	175.33	127.51	126.37	134.48	133.97
2007-08	169.59	184.62	183.67	232.94	214.25
2008-09	183.60	202.42	201.45	231.37	231.37
2009-10	169.08	168.23	166.83	262.62	262.62
2010-11	166.37	162.27	160.92	232.03	233.62
2011-12	164.48	163.14	150.63	149.64	149.64
2012-13	155.21	164.94	160.00	159.65	159.65

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जाएगा कि विनियोग लेखे के अनुसार निधि को अंतरित राशि के आंकड़े शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार अंतरित राशि के आंकड़ों से ज्यादा थे।

इसी प्रकार, विनियोग लेखे के अनुसार व्यय के आंकड़े भी तीन वर्षों की वसूली विवरणी के आंकड़ों से भिन्न हैं। जबकि विनियोग लेखे शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं के आधार पर ले.म.नि. द्वारा तैयार किए गए हैं। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि इन लेखाओं में आंकड़ों के अलग सेट क्यों प्रकट हो रहे थे।

इस मामले पर वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक द्वारा संघ सरकार के लेखे पर प्रतिवेदन में टिप्पणी भी की गयी थी।

मंत्रालय का उत्तर फरवरी 2014 तक प्रतीक्षित था।

2.2.4 नवीकरण आरक्षित निधि के अंतरण को गलत दर्शाया जाना

अनुदान सं. 25-आयुध फैक्ट्री में, भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) '2079.00.787-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन (न.प्र.) निधि में अंतरण'से शीर्ष के माध्यम से, लोक लेखे में शीर्ष '8226.102' में संघ वित्त लेखे के विवरण सं. 13 में ₹350 करोड़ की राशि अंतरित की गयी थी। इसके अतिरिक्त, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन पर शीर्ष 2079.00.106-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के अंतर्गत ₹415.85 करोड़ का व्यय किया गया था तथा लोक लेखा में नवीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से राशि पूर्ण की गई थी।

तथापि, वि.व. 2012-13 हेतु संघ लेखे के विवरण सं.9 में ₹(-)64.69[6] करोड़ की राशि भा.स.नि. से लोक लेखे में शीर्ष 2079.00.797-न.प्र. निधि में अंतरण के अंतर्गत अंतरित राशि के साथ व्यय की निवल राशि द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अंतरित करना दिखाया गया था। रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय अंतरण विवरण (के.अं.वि.) में भी, इस अंतरण को त्रुटिपूर्ण रूप से दर्शाया गया था। लोक लेखा में अंतरण की निवल राशि दिखाने के बजाय, के.अं.वि. और विवरणी सं. 9 में इन अंतरणों को सही दर्शाया गया है (i) ₹350 करोड़ की पूरी राशि का लोक लेखा में अंतरण कर देना, (ii) मुख्य शीर्ष 2079 के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष को नवीकरण एवं प्रतिस्थापन पर वास्तविक व्यय को दर्ज एवं खर्च करना, और (iii) मुख्य शीर्ष 2079 के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष 'घटायी हुई राशि को रिजर्व निधि से पूर्ण करने' का परिचालन करना।

न.प्र. निधि में अंतरण को गलत रूप से दर्शाये जाने को नि.म.ले.प. के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं.-1 के पैरा 2.3.9 और नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 2.2.4 में भी इंगित किया जा चुका था हांलाकि, सी.जी.डी.ए. और रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.2.5 स्वच्छ ऊर्जा उपकर को निधि में जमा न करना

औद्योगिकरण और शहरीकरण से संबंधित बढ़े हुए प्रदूषण स्तरों एवं नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों को सुधारने के लिए, बजट 2010-11 में कई सक्रिय कदम प्रस्तावित किए गए थे। ऐसा ही एक कदम आयात किए गए कोयले तथा भारत में उत्पादन किए गए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाए जाने के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के निधिकरण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (रा.स्व.ऊ.नि.) को स्थापित करना था।

[6] न.प्र. निधि में लोक लेखा को अंतरित राशि और न.प्र. निधि से नवीकरण और प्रतिस्थापन पर हुए व्यय के बीच ₹1.16 करोड़ का अंतर है।

वर्ष 2010-13 के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपकर[7] संग्रहण, कुल ₹6,699.20 करोड़ इकट्ठा किया गया था। इसके विपरीत, लोक लेखा में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि[8] को केवल ₹2,566.46 करोड़ का ही अंतरण हुआ था। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु चिन्हित निधि से ₹4,132.74 करोड़ के उपकर का कम अंतरण हुआ, जैसाकि नीचे विवरण में दिया गया है।

तालिका 2.5: स्वच्छ ऊर्जा उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित स्वच्छ ऊर्जा उपकर (0038.03.112)	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण (2810.797)	उपकर का कम अंतरण
2010-11	1066.46	--	1066.46
2011-12	2579.55	1066.46	1513.09
2012-13	3053.19	1500.00	1553.19
कुल	**6699.20**	**2566.46**	**4132.74**

म.नि.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 2.2.5 में इंगित किये जाने के बावजूद, ₹4,132.74 करोड़ तक कम अंतरण हुआ था।

म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि आर्थिक कार्य विभाग के समग्र उपकर राशि को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरित नहीं करने के कारण के लिए संदर्भित किया जा चुका था।

2.2.6 राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.)

(i) 2005 में सरकार ने 'राष्ट्रीय निवेश निधि' (रा.नि.नि.)[9] का सृजन किया जिसमें लाभकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) में सरकार की कम हिस्सेदारी की बिक्री स्वरूप प्राप्त राशि को जमा किया जाना था। चयनित परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनियों को निधि संग्रह के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया। निधि का अनुरक्षण लोक लेखे (मु.शी. 8452-रा.नि.नि.) में किया जाना था। निधि से प्राप्त आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र, परियोजनाओं में निवेश तथा चयनित लाभकारी तथा पुर्नजीवित करने योग्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश किया जाना था। इसके आरंभ से लेकर 31 मार्च 2013 तक सरकार द्वारा ₹ 1,814[10] करोड़ का अन्तरण आगे के निवेश के लिए रा.नि.नि. में किया गया था।

रा.नि.नि. की निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार निधि प्रबंधकों के पास निवेशित पोर्टफोलियो से प्राप्त वार्षिक आय को भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)[11] में प्राप्ति

---

7 मु.शी. 0038.03.112- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

8 मु.शी. 8235.129-राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

9 मु.शी. '8452-रा.नि.नि.'

10 वर्ष 2007-08 में ₹1,651 करोड़ तथा 2008-09 में ₹163 करोड़ अंतरित किए गए।

11 विवरणी सं. 8 में लघु शीर्ष 1475.110

के रूप में दर्ज किया जाना था तथा 3:1 के अनुपात में लोक लेखे[12] में दो निर्धारित शीर्षों को अंतरित किया जाना था।

2008-13 की अवधि के दौरान आय के रूप में अर्जित ₹905.23 करोड़ की राशि के प्रति, लोक लेखा में, भारतीय संचित निधि में ₹398.11 करोड़ की शेष राशि छोड़ते हुए, केवल ₹507.12 करोड़ अंतरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ₹507.12 करोड़ की राशि, अन्य शीर्ष[13] को बंद रखते हुए, लोक लेखा में केवल एक लघु शीर्ष[14] में पूरी तरह अंतरित किया गया था। यह लघु शीर्षों एवं लोक लेखा के मध्य 3:1 के अनुपात को निर्धारित करने वाली नीति के उल्लंघन में था।

नि.म.ले.प. की 2011-12 के प्रतिवेदन सं.-1 में इंगित किये जाने के बावजूद तथा वित्त मंत्रालय द्वारा (नवम्बर 2011) यह आश्वासन दिये जाने कि रा.नि.नि. के अंतर्गत शेषों का मिलान हो रहा है एवं शेष राशि को तृतीय अनुपूरक में उपयुक्त प्रावधान करके अंतरित कर दिया जाएगा, के बावजूद मुख्य शीर्ष 8453 के अंतर्गत, शेषों का पूरी तरह मिलान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर-2013) कि सरकार द्वारा रा.नि.नि. निधि प्रबंधक से प्राप्त आय ₹801.01 करोड़ थी न कि ₹905.23 करोड़ जैसाकि पैरे में उल्लेख किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। संघ सरकार वित्त लेखे के विवरणी सं. 8 के अनुसार, सरकार द्वारा 2008-13 की अवधि में ₹905.23 करोड़ की आय प्राप्त की गयी थी।

(ii) रा.नि.नि. की संशोधित लेखांकन प्रक्रिया, जो वित्तीय वर्ष की अवधि 2009-12 के लिए लागू थी, जिसे आगे 2012-13 तक विस्तारित किया गया के अंतर्गत आर्थिक कार्य हेतु मंत्रीमंडलीय समिति (आ.का.मं.स.) द्वारा दिनांक 11.03.2012 को अनुमोदित 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2013 की अवधि के दौरान संग्रहित विनिवेश प्रक्रियाओं की लोक लेखा में 01.04.2009 से 31.03.2013 की अवधि हेतु रा.नि.नि. में निर्धारित लघु शीर्ष[15] के अंतर्गत अंतरित किया जाना था।

2012-13 के लिए वित्त लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कथित लघु शीर्ष (8452.102) नहीं खोला गया और रा.नि.नि. में से ₹23,933.73 करोड़ का अंतरण लघु शीर्ष 8452.102 के स्थान पर गलत लघु शीर्ष 8452.101 में दर्ज किया गया था।

---

[12] मु.शी. 8453.101 तथा 8453.102
[13] शीर्ष 8453.101
[14] शीर्ष 8453.102
[15] शीर्ष 8452.102

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि नया लघु शीर्ष अभी भी नि.म.ले.प. द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, तथा इसके कोड अनुभाग को इस संदर्भ की सूचना दी जा रही थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नए लघु शीर्ष को खोलने पर नि.म.ले.प. की सहमति अगस्त 2011 में ले.म.नि. को सूचित कर दी गई थी।

2.2.7 आयकर कल्याण निधि का सृजन

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों में निधि में ₹100 करोड़ का अंतरण किया। निधि को (i) आयकर विभाग के कर्मचारियों के कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii) चोट अथवा दुर्घटना जैसी आकस्मिकताओं के दौरान कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) कर्मचारियों को आपातकालीन एवं गम्भीर संकट हेतु, जो कि के.स.स्वा.यो. प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है, जोखिम बीमा सहित चिकित्सा अनुरक्षण के विभिन्न प्रकारों को प्रदान करने, (v) कर्मचारियों के उपयोग हेतु अवकाश गृहों का निर्माण करने/किराए पर लेने/पट्टे पर लेने/साज-सज्जा/अनुरक्षण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सृजित किया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निधि के सृजन इस निधि द्वारा आच्छादित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल करने तथा सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित करने के आधार पर सहमत नहीं थे। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि का सृजन, ब्याज की आवर्ती देयताओं के रूप में होगा जो कि सामान्य संसदीय वित्तीय नियंत्रण के अधीन नहीं होगी। निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि व्यय मान्यता प्राप्त नीति या प्रथा के अनुसरण में नहीं हो। इसके अतिरिक्त, यदि उद्देश्य कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, जिन्होंने अन्वेषण/गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान क्षति/मृत्यु का सामना किया हो, को आवृत करने तथा कर्मचारियों के लिए उच्च जोखिम बीमे के प्रावधान को शामिल करने हेतु भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है या ऐसे उद्देश्यों हेतु वर्तमान निधियों के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों में सम्मिलित किया जा सकता है। उल्लेखित अन्य उद्देश्यों को मंत्रालय की अनुदानों हेतु माँग में मानक विषय शीर्षों 'पुरस्कार', 'चिकित्सा उपचार', 'कार्यालय व्यय', 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

इस मामले पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2008-09, 2010-11 एवं 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-1 में टिप्पणी की गई थी। सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में

मंत्रालय ने बताया कि निधि का सृजन जनवरी 1998 में विस्तृत जाँच के पश्चात किया गया था। इसने यह भी बताया कि निधि के सृजन की उत्पत्ति स्वैच्छिक प्रकटीकरण आय योजना-97, जिसमें सामान्य कर संग्रहण से अधिक, लगभग ₹10,700 करोड़ के अतिरिक्त कर का संग्रहण किया गया था, के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में निहित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 100 करोड़ के संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा प्रारम्भ से ही इस निधि में कोई ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया गया था।

सामान्य वित्तीय नियमावली किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय को अनुमत नहीं करती। इसके अतिरिक्त, निधि का उपयोग संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगो की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा तथा इस तरह संसद को दी गई वित्तीय रिपोर्ट को माना जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आ.क.नि. को बंद किया जा सकता है और शेष को भारत की समेकित निधि को क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए।

2.2.8 चिन्हित निधियों के उपकर का लोक लेखा में कम अंतरण

सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन में उपयोग हेतु उपकर लगाये जाते हैं। पारदर्शिता हेतु, उपकर प्राप्तियों को एक चिन्हित विकास/कल्याण निधि में अंतरित कर दिया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं.) पेट्रोल/एच.एस.डी. तेल पर उपकर संग्रहित करता है तथा श्रम मंत्रालय लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं फ़ीचर फिल्मों पर उपकर वसूलता है। केन्द्रीय सड़क निधि (स.प.रा.मं.) तथा खदान कल्याण निधि (अभ्रक खदान श्रम कल्याण निधि, लौह अयस्क मेंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खदान श्रम कल्याण निधि एवं चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खदान श्रम कल्याण निधि सहित), सिने श्रमिक कल्याण निधि जैसा लोक लेखा (विवरण-13) में निधि का अनुरक्षण भी करते हैं। जिसमें[16] उपकर प्राप्तियां अंतरित होनी होती हैं।

तथापि, वित्त वर्ष 2012-13 हेतु मसौदा संघ सरकार वित्त लेखे के ब्यौर की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि उपकर प्राप्तियों को समर्पित निधियों में पूरी तरह अंतरित नहीं किया जा रहा था, जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है।

[16] विवरण-13- प्राप्तियों का विवरण संवितरण तथा ऋण, जमा, प्रेषणों एवं आकस्मिकता निधि के अंतर्गत शेष

तालिका 2.6: लोक लेखा में चिन्हित निधियों में उपकर का कम अंतरण

(₹ हजार में)

	उपकर की प्राप्ति		लोक लेखा में अंतरण		उपकर का कम अंतरण
	उपकर का नाम/प्राप्ति शीर्ष	राशि	लोक लेखा में चिन्हित निधि का नाम एवं शीर्ष	राशि	
1.	पेट्रोल/एच.एस.डी. तेल पर उपकर (0038.03.106/107)	**199792860**	केन्द्रीय सड़क निधि (8224.101)	**194337300**	**5455560**
2.	फीचर फिल्मों पर उपकर (0038.04.130)	**22354**	सिने श्रमिक कल्याण निधियां (8229.115)	**16338**	**6016**
3.	लौहे अयस्क पर उपकर (0038.04.110)	164410	खदान कल्याण निधि (8229.114)	261204	215152
4.	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट पर उपकर (0038.04.112)	311933			
5.	अभ्रक पर उपकर (0038.04.111)	13			
	कुल (3+4+5)	**476356**			
	कुल कम अंतरण				**5676728**

स्रोतः संघ सरकार के वित्त लेखे 2012-13

जैसा कि उपर्युक्त से प्रमाणित है, उपकर प्राप्तियों के ₹567.67 करोड़ की राशि का चिन्हित निधियों में कम अंतरण हुआ था, अन्य उद्देश्य हेतु निधियों के संभावित विपथन में परणित हुआ।

इस मामले पर श्रम मंत्रालय द्वारा परिचालित निधियों के संदर्भ में नि.म.ले.प. के 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-1 में भी टिप्पणी की गयी थी।

महालेखा नियंत्रक ने बताया (अक्तूबर 2013) कि श्रम रोजगार मंत्रालय को संदर्भित किया जा चुका है और कम अंतरण के कारण बताने के लिए कहा गया है। स.प.रा.मं. से उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2014)।

2.3 सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे

2.3.1 कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में विसंगति

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि में केन्द्र सरकार के अंशदान को भारत सरकार के लोक लेखे में रखा जाना होता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संघ सरकार के लेखाओं में भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा आवश्यक समायोजनों हेतु अंशदान (तथा उस पर ब्याज) को सरकार के अंश के संबंध में संस्वीकृतियां जारी करता है। संस्वीकृतियों की प्रतियाँ इसके वार्षिक लेखे में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने हेतु केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) (क.भ.नि.सं.) को भी प्रेषित की जाती हैं। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को

पेंशन अंशदान का सरकारी अंश का शेष, जैसा कि लोक लेखे में दर्शाया जाता है तथा क.भ.नि.सं. के लेखे में अंकित अंशदान से मिलना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे में अंकित ₹36,939.04 करोड़ के प्रति पेंशन निधि को केन्द्र सरकार का अंशदान (ब्याज सहित) ₹36,809.06 करोड़ था। अतः दोनों वित्तीय दस्तावेजों में ₹129.98 करोड़ का अंतर था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में, संघ सरकार वित्त लेखे में दर्शाया गया शेष ₹63,723.42 करोड़ था तथा क.म.नि.सं. के तुलन-पत्र के अनुसार शेष ₹63,593.44 करोड़ था। अतः ₹129.98 करोड़ का वही अंतर वर्तमान वर्ष तक जारी था।

इस मामले को इंगित किए जाने पर श्रम मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2011) कि मंत्रालय की संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक को 1971 से हो रहे लेखांकन का ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया है तथा जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक से ब्यौरा मिल जाएगा संघ सरकार के वित्त लेखे एवं क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखाओं में समाधान कर लिया जाएगा।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि दोनो वित्तीय दस्तावेजों में ₹129.98 करोड़ के अंतर को ठीक इंगित किया गया था।

तथापि, इस विषय पर वित्त वर्ष 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में टिप्पणी किए जाने के बावजूद इस कमी को दूर करने हेतु कोई विवेकपूर्ण प्रगति नहीं की गई है।

2.3.2 कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति

वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के विवरणी सं. 14[17] लोक लेखे में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना[18] के विशेष जमा के अंतर्गत ₹ 1,438.78 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) द्वारा अनुरक्षित कर्मचारी बीमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 (क.ज.स.बी.यो.) के तुलन-पत्र में 31 मार्च 2013 तक ₹ 6,380.59 करोड़ का अंत शेष लोक लेखे में दर्शाया गया था। इस प्रकार दोनों आंकड़ों में ₹ 4,941.81 करोड़ (₹6,380.59-₹1,438.78) का अंतर है।

इस मामले को नि.म.ले.प. वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था और तब इन दोनों लेखाओं में ₹4,586.52 करोड़ का अंतर था। प्रधान

[17] विवरणी 14: विवरणी सरकार के ऋण तथा अन्य ब्याज वहनीय दायित्व

[18] मुख्य शीर्ष 8012.124-कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा

लेखा कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2012) कि दो लघु शीर्ष[19] इस प्रयोजन हेतु चलाये जा रहे थे। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों शीर्षों का योग ₹8,250.16 करोड़ (₹6,811.38 + ₹1,438.78) बन जाता है। मंत्रालय ने सरकारी बहियों तथा क.भ.नि.सं. में दिखने वाले अंतर के बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि 31 मार्च 2013 को क.ज.स.बी.यो. के विशेष जमाओं के शेष, क.भ.नि.सं. के तुलन पत्र के अनुसार क.ज.स.बी.यो. में विशेष जमा खाता में शेष में ₹1,810.60 करोड़ की असंगति थी जबकि सरकारी वित्त लेखे के अनुसार यह शेष ₹1,808.27 करोड़ था और इस प्रकार, केवल ₹2.33 करोड़ का अंतर था जिसे भा.रि.बै. के परामर्श से मिलान कर लिया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी बहियों में दर्शाये गये आंकड़े और क.भ.नि.स. के आंकड़े सही हैं और वहाँ ₹4,941.81 करोड़ का अंतर है।

लगभग दो वर्ष बीत जाने के बावजूद, मामले पर आगे की प्रगति नहीं की गई।

2.3.3 लघु बचत, भविष्य निधियों आदि के कारण देयताओं का कम बताया जाना

वर्ष 2012-13 के लिए संघ सरकार लेखे के विवरण सं. 2 में, लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के शेष ₹4,70,111.69 करोड़ के रूप में दिखाये गये थे। यह उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार की लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि पर कुल देयताएं 31 मार्च 2013 तक ₹9,88,832.95 करोड़ थीं। इसमें से ₹5,17,221.26 करोड़ का विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में एवं ₹1,500 करोड़ आई.आई.एफ.सी.एल. में लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के अंतर्गत ₹4,70,111.69 करोड़ के निवल बकाया देयता छोड़ते हुए, निवेश किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घटित किया कि भारत सरकार की कुल लघु देयताओं को परिकलित करते हुए लघु बचत, भविष्य निधि आदि, समग्र कमी (उपभोक्ताओं को अदा ब्याज, अभिकरण प्रभारों एवं अन्य प्रबंधन लागतों पर व्यय एवं निवेश पर अर्जित ब्याज के मध्य अंतर) मार्च 2013 के अंत तक ₹69,476.57 करोड़ थी जिसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि खाते पर कुल देयताओं में से समायोजित किया गया था। रा.ल.ब.नि. के संबंध में कुल देयता ₹10,58,309.52 करोड़ होना चाहिए था पर जिसे वित्त लेखे में ₹9,88,832.95 करोड़ गलत रूप से प्रदर्शित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की देयता को कम बताया गया।

[19] मु.शी. 8342.00.120- विवरणी सं. 13 में विविध जमा, तथा मु.शी. 8012.00.124- विवरणी सं. 14 में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा

ले.म.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि प्राप्ति बजट में दिखायी गयी देयता विवरण सं.2 में दर्शायी गयी देयता की राशि से भी मेल खा रहा है, इस प्रकार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के आय एवं व्यय के निपटान की वर्तमान प्रणाली नियमानुसार है तथा निधि की वास्तविक देयताओं को दर्शाती है।

ले.म.नि. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संघ सरकार की देयता को रा.ल.ब.नि. को संचित निधि के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है।

ब्याज प्राप्ति को न दर्शाया जाना

राष्ट्रीय लघु बचत निधि (परिशिष्ट सं.1 से विवरण 16) में 2008-09 से 2010-11 (अर्थात लगातार तीन वर्षों के लिए) तक '8008.01.104-रा.ल.ब.नि. में विशेष प्रतिभूतियों के विमोचन पर राशियों के पुनर्निवेश के प्रति जारी विशेष केन्द्रीय/राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश' पर ब्याज के अंतर्गत किसी प्रकार का ब्याज नहीं दर्शाया गया था, जबकि '8007.104-विशेष केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों में विशेष केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूतियों के विमोचन पर रा.ल.ब.नि. में प्राप्त, राशि का निवेश' (विवरणी सं. 6) के अंतर्गत वह निवेश 2008-09 के दौरान ₹98,296.34 करोड़ तथा 2009-11 के दौरान ₹1,10,354.34 करोड़ रहा था।

ले.म.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि चिन्हित वित्त वर्ष से संबंधित ब्याज का गलत वर्गीकरण हुआ था तथा प्रमुख शीर्ष "8008.01.102-विशेष 01.04.1999 से संग्रहण के प्रति विशेष केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज" के अंतर्गत जमा किया गया था तथा इसे वित्त वर्ष 2013-14 में पूर्वावधि समायोजन (पू.अ.स.) के माध्यम से सुधारा जाएगा।

2.3.4 प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना

संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) के राइट्स निर्गम में ₹9,996 करोड़ का निवेश किया था। नकद निर्गम की बजाय सरकार ने विशेष प्रतिभूतियाँ[20] जारी करते हुए लोक लेखे में देयता का सृजन कर दिया। इन प्रतिभूतियों का विमोचन एक भावी तिथि पर भारत की समेकित निधि[21] से लोक लेखे में निधियों के अन्तरण द्वारा 'प्रतिभूति विमोचन निधि' के सृजन के माध्यम से करना था।

लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान, प्रत्येक वर्ष में ₹ 625 करोड़ प्रतिभूति विमोचन निधि के अंश के कारण व्यय का लेखांकन हुआ था। ₹3,125 करोड़ की राशि को लोक लेखे में प्रतिभूति विमोचन निधि के रूप में इस

[20] मु.शी. 8012.120 राष्ट्रीय बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

[21] मु.शी. 3465.01.190.04-प्रतिभूति विमोचन निधि

एकमात्र उद्देश्य से क्रेडिट करना चाहिए था, कि भविष्य में कभी भा.स्टे.बैं. को विशेष प्रतिभूतियों के ₹9,996 करोड़ क्रेडिट किए जा सके।

आर्थिक कार्य विभाग के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि कथित निधि वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में मामले को इंगित किये जाने के बावजूद सृजित नहीं की गई थी परिणामस्वरूप ₹3,125 करोड़ एक उचंत शीर्ष में अभी तक पड़े थे।

2.3.5 पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना

पोत परिवहन विकास निधि समिति (पो.प.वि.नि.स.) को 1986 से समाप्त कर दिया गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों एवं देयताएं पो.प.वि.नि.स. (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अनुसार केन्द्र सरकार को हस्तांतिरत हो गयीं। आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के वित्त लेखे के विवरण सं. 15 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹(-)231.70 करोड़ (डेबिट) का कुल ऋण, जैसाकि निम्न **तालिका 2.7** में ब्यौरा दिया गया है, अभी तक पो.प.वि.नि.स. के प्रति बकाये के रूप में दिखाया जा रहा था, जबकि पो.प.वि.नि.स. की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं केन्द्र सरकार को पहले ही हस्तांतरित हो गयी थी।

तालिका 2.7: गलत चित्रण

शीर्ष का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
7052-01-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	58.83 डे.
7052-60-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	8.59 डे.
7052-02-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	(-)294.12 डे.
कुल	**(-)231.70 डे.**

इस मामले को वर्ष 2011-12 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया था, परंतु विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

उपर्युक्त मामले को मंत्रालय के साथ-साथ लेखा नियंत्रक के कार्यालय, वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया था लेकिन उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2014)।

2.3.6 निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि

आरक्षित निधियां तथा जमा, लोक लेखे का एक हिस्सा होते हैं जिसमें उस संबंध में लेन-देनों को दर्ज किया जाता है जिसमें सरकार प्राप्त धन को वापस करने की देयता तथा उसमें से पुर्नभुगतान करती है। निष्क्रिय निधियां/जमा ऐसी निधियाँ अथवा जमाओं को संघटित करते हैं जो लम्बी समय अवधि से संचालन में नही हैं। चूंकि आरक्षित निधि के गठन में आमतौर पर लोक लेखे में भारत की समेकित निधि से अंतरण शामिल होता

है इसलिए लोक लेखे में निष्क्रिय निधियों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा उसमें अंत शेष को भारत की समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने आरक्षित निधियों/जमाओं के 48 मामले प्रकट किए जो चार से 24 वर्षों के बीच की अवधि तक निष्क्रिय पड़े थे। इन मामलों को **अनुबंध 2.4** में दर्शाया गया है।

अनुबंध 2.4 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश मामले छोटी राशियों वाले थे अतः उन्हें जारी रखना किसी तार्किक उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। इन मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा भारतीय समेकित निधि के शेषों का सृजन कर बन्द करना चाहिए।

मामले पर नि.म.ले.प. के 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में टिप्पणी की गयी थी, परंतु कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी।

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि निष्क्रिय आरक्षित निधियों को विभिन्न विभागीय लेखाओं संगठनों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है और इन निधियों के ब्यौरे संबंधित कार्यालयों के पास स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किये जा चुके है।

2.3.7 बाह्य ऋण के लेखांकन को कम बताना

ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य ऋणों को विनिमय की ऐतिहासिक दर, जो कि लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर है, पर सरकारी लेखे में दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण पुनर्भुगतान, लेखे के आधार पर परिकलित देय राशि से काफी अधिक है। इस अधिक भुगतान को प्रत्येक वर्ष नकारात्मक अंत शेष के रूप में लेखे में दर्शाया गया है। शेष ऋण, जिसे अभी तक पूरी तरह वापस नहीं किया गया है, सकारात्मक शेषों के साथ लेखे में दर्शाया गया । बाद में, जब बाह्य ऋण जोड़े जाते हैं नकारात्मक तथा सकारात्मक शेषों को निवल करने के कारण यह वास्तविक राशि से कम बताया जाता है।

इसी प्रकार, किसी विशेष देश से प्राप्त ऋण के शेष भी ऋण के सही आंकड़े नहीं दर्शाते क्योंकि एक विशेष देश कई परियोजनाओं हेतु ऋण देता है जिन्हें अलग से लेखांकित किया जाता है। इनमें से, कुछ परियोजनाओं पर ऋणों को पहले ही अदा किया जा चुका है परन्तु विनिमय परिवर्तनों के कारण भुगतान अभी भी किए जा रहे हैं जिन्हें नकारात्मक शेष के रूप में दर्ज किया गया है। यह नकारात्मक शेष, जोड़े जाने पर, उस विशेष देश से बकाया ऋण के शेषों को कम दर्शाता है।

इस प्रकार, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ₹ 1,77,288.81 करोड़ के बाह्य ऋण की राशि, बकाया बाह्य ऋण के वास्तविक आयाम को प्रदर्शित नहीं करती है। विवरणी सं. 14 के

नीचे दिये गये नोट के अनुसार, मार्च 2013 के अंत में वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹3,32,003.70 करोड़ था। इस प्रकार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर लेखे में बाह्य ऋण को अंकित करना देयता का सही प्रतिबिंब नहीं है।

2013 के प्रतिवेदन सं. 1 में यह इंगित किया गया था कि ले.म.नि. द्वारा बकाया बाह्य ऋण के ऐतिहासिक विनियम दर पर वास्तविक आयाम दर्शाने हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। तथापि इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं दिखायी गयी है।

आर्थिक कार्य विभाग, नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालय (नि.स.ले.ले.प.) ने बताया (जनवरी 2014) कि प्रत्येक ऋण को अलग-अलग परिकलित किया जाता है तथा ऋण मुद्रा में पुनर्भुगतान किया जाता है, ऋणों की लंबी अवधि के दौरान विनिमय दर भिन्नता, पुनर्भुगतान (भारतीय मुद्रा में) के प्राप्ति (भारतीय मुद्रा में) से अधिक होने में परिणत होती है। पुनर्भुगतान आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदान हेतु वार्षिक मांग में दर्शाये गये थे जिसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

नि.स.ले.ले.प. ने इसके अतिरिक्त बताया कि भा.रि.बैं. द्वारा विदेशी विनिमय में बाह्य सहायता प्राप्तियों को भारतीय समेकित निधि में भारतीय मुद्रा के रूप में प्रेषित कर दी गयी हैं। इसी प्रकार, भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय में पुनर्भुगतानों को भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) में भारतीय मुद्रा में दर्ज कर दिया गया है। अतः बकाया ऋण का भारतीय मुद्रा में जोड़ने/हटाने का विवरण 14 में अभिलेखन मूल्य तिथियों पर आवश्यक है और लेखांकन आवश्कताओं की संगति में है। तथापि, सिविल लेखा नियमपुस्तिका 16.6.2(2) के अनुसार विदेशी मुद्राओं/करोड़ में रूपए तथा अपनायी गयी विनिमय दर (वर्ष के 31 मार्च को) दर्शाने वाला एक ब्यौरा (नि.स.ले.ले.प. द्वारा) भी विवरण सं. 14 के साथ जोड़ा है। बकाया ऋण के ऐतिहासिक एवं वर्तमान दोनों मूल्यों का चित्रण स्थापित लेखांकन पद्धति के अनुसार है और इस प्रकार गलत या असंगत नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखे में दिखाये गये बाह्य ऋण सरकार के सही देयता को प्रतिबिंबित नहीं करते। आ.का.वि. बाह्य ऋण को वित्त वर्ष के अंतिम तिथि पर वर्तमान विनिमय दर के आधार पर परिवर्तित करने अथवा किसी अन्य लेखांकन विधि को, यह तय करने के लिए कि बकाया बाह्य ऋण सरकार की सही देयता को प्रतिबिंबित करे, अपनाने का विचार कर सकता है।

2.3.8 बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना

लघु शीर्षों 6002-218 और 6002-233 के अंतर्गत ₹79.46 करोड़ एवं ₹119.50 करोड़ के ऋण कुवैत निधि एवं स्वीडन के प्रति 31 मार्च 2013 को बकाया दिखाये गये

थे। वर्तमान दर पर दिये गये इन ऋणों की संवीक्षा, इन संस्थाओं के प्रति ऋण की राशि को नहीं दर्शाती हैं। बल्कि, 2010-11 में स्वीडन पर प्रश्न भी उठाया गया था उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि मामले को 2011-12 में निपटा लिया जाएगा। तथापि, अभी तक कोई प्रगति होती हुई दिखायी नहीं दी।

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि कुवैत निधि एवं स्वीडन के प्रति ऋण बकाये (प्रतिकूल शेष) का प्रतिकूल शेष के परिसमापन का कार्य चल रहा था और इसे 2013-14 के दौरान निपटा लिया जाएगा।

2.3.9 संघ सरकार द्वारा दिये गये ऋणों को न दर्शाया जाना

वित्त लेखे 2011-12 और पहले के वर्षों के में, निम्न उल्लेखित संस्थाओं के भुगतान किए गए ऋण और उनके प्रति शेष को दर्शाया गया था। तथापि, ऋण राशि के ब्यौरे वर्ष 2012-13 हेतु मसौदा विवरण सं. 3 से हटा दिए गए थे, यह संकेत दिये बिना इन इकाइयों से ऋण बकाये वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त किए गये/बट्टे खाते में डाले गये।

तालिका 2.8: संघ सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों को न दर्शाया जाना

क्र.स.	इकाई का नाम	31 मार्च 2012 को इकाई के प्रति बकाया कुल ऋण (₹ लाख में)
1.	सहकारी समितियां एवं विभागीय कैंटीन	46.00
2.	भारतीय दूरसंचार उद्योगों के ऋण	706.54
3.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि.	554.03
4.	टाटा संचार लि. (पूर्व में वी.एस.एन.एल.)	1705.00
5.	अन्य दूरसंचार सेवाओं के लिए ऋण	77175.55

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि अपेक्षित स्पष्टीकरण दूरसंचार विभाग से मांगा गया है।

2.3.10 बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन

मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखा' के अंतर्गत लघु शीर्ष '111-विभागीय समायोजन लेखा', विभागीय लेखांकन प्राधिकारियों के बहियों में वर्ष 1982-83 के लेखाओं से निष्क्रिय हो गया था। विभिन्न लेखे भेजने वाले प्राधिकरणों को लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, 2008-09 की समाप्ति तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद ₹ 49.03 करोड़ के बकाया डेबिट शेष सहित लघु शीर्ष वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 में दिखाई देना जारी रहा।

ले.म.नि. ने जवाब दिया (अक्तूबर 2013) कि ₹49.03 करोड़ का बकाया डेबिट शेष, म.ले. सहित विभिन्न विभागीय लेखा प्राधिकारों से संबंधित शेषों की समेकित राशि थी, और उनके संबंधित शेषों को बट्टे खाते में डालने का कार्य शुरू करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है।

2.3.11 विभिन्न निधि लेखाओं में अंतर एवं असंगति

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ब्याज रहित लोक लेखा में पाँच निधियों, नामतः (i) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (ii) अभ्रक खदान श्रमिक कल्याण निधि, (iii) लौह अयस्क खदान, मैगंनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खदान श्रमिक कल्याण निधि (iv) चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खदान श्रमिक कल्याण निधि, (v) लोक लेखे के गैर ब्याज खण्ड में सिने श्रमिक कल्याण निधि का अनुरक्षण कर रहा है।

विनियोग लेखे (अर्थात धनीभूत लेखे) एवं 2012-13 हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शीर्ष-वार विनियोग लेखे की संविक्षा से इन निधियों को अंतरित एवं उनमें वास्तव में जमा की गई धनराशि में विभिन्नता का पता चला। नीचे की तालिका से, यह देखा जा सकता है कि धनीभूत लेखा में दिखायी गयी कुल प्राप्ति ₹193.21 करोड़ शीर्ष-वार विनियोग लेखे में शीर्ष 2230.01.797 के द्वारा किया गया अंतरण ₹188.24 करोड़ था।

तालिका 2.9: विभिन्न निधि लेखाओं में असंगतियाँ एवं विसंगतियों

(₹ हजार में)

निधि का नाम	निधि में अंतरण (शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार प्रमुख शीर्ष 2230.01.797 के माध्यम से)	निधि लेखा में दिखायी गयी प्राप्ति (धनीभूत लेखा में)	निधि लेखा में दिखायी गयी अतिरिक्त प्राप्ति (धनीभूत लेखा में)
बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि	1600000	1649371	49371
लौह अस्यक, मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क खदान श्रमिक कल्याण निधि	135600	135804	204
चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खदान श्रमिक कल्याण निधि	130500	130580	80
सिने श्रमिक कल्याण निधि	16300	16338	38
कुल	**1882400**	**1932093**	**49693**

चार निधि लेखे में प्राप्त दर्शाई गई राशि शीर्षवार विनियोग लेखें में इन निधियों को अंतरित की गई राशि से अधिक थी। चूंकि विनियोग लेखे ले.म.नि. द्वारा अधिक विस्तृत

शीर्ष-वार विनियोग लेखे के आधार पर तैयार किये जाते हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि इन लेखाओं में भिन्न आंकड़े क्यों दिख रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2014) कि चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत सीधे ही बैंक में ₹4.97 करोड का प्रेषण किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय समेकित निधि से अंतरण तथा निधि लेखा में प्राप्त राशि एक समान होनी चाहिए।

2.3.12 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (हि.शि.लि.) के ऋणों का गलत दर्शाया जाना

वर्ष 2009-10 हेतु संघ वित्त लेखे की विवरणी सं. 3 के अनुसार, 31 मार्च 2010 को जहाजरानी मंत्रालय का हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापटनम के पास ₹ 318.01 करोड़ कुल ऋण बकाया था। कुल ऋण में से, 31 मार्च 2010 को ₹ 47.53 करोड़ का ब्याज और ₹ 145.04 करोड़ मूलधन बकाया थे तथा पूर्व अवधि 1995-96 से बकाया देय राशियों में है।

हालांकि, वर्ष 2010-11 हेतु वित्तीय विवरणों मे, हि.शि.लि. से शेष ऋण नहीं दर्शाया गया था, परंतु एक फुटनोट द्वारा दर्शाया गया था कि सा.क्षे.उ. को रक्षा मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था। फुटनोट में आगे स्पष्टीकरण दिया गया था कि सरकारी ऋणों के पुनर्गठन के अंतर्गत, ₹149.87 करोड की मूलधन राशि एवं ₹157.37 करोड के ब्याज को बिना ब्याज के शाश्वत ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 2010-11 में कोई वसूली बकाया नहीं थी।

हि.शि.लि. को वित्तीय पुनर्गठन को अनुमोदित करते हुए, रक्षा मंत्रालय का दिनांक 23 मार्च 2011 के संस्वीकृत पत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.10: हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (हि.शि.लि.) को दिया गया ऋण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
सहायता अनुदान	452.68	वैधानिक देयताओं को समाप्त करने के लिए
शाश्वत ऋण	372.22	₹149.87 करोड़ के शेष सरकारी ऋण की वर्तमान मूलधन राशि, ₹157.37 करोड़ का शेष ब्याज और भा.स्टे.बै. ऋण के प्रति ₹64.98 करोड़ के शेष गारंटी शुल्क, को बिना ब्याज के शाश्वत ऋणों में परिवर्तित करना
कुल वित्तीय पैकेज	**824.90**	

वित्तीय वर्ष 2010-11 और उसके बाद में, संघ वित्तीय लेखे में हि.शि.लि. के प्रति कोई शेष और ऋण अनुमोदन नहीं दर्शाया जा रहा है। तदनुसार, लेखे से यह स्पष्ट नहीं है यदि हि.शि.लि. द्वारा ₹168.14 करोड़ (₹318.01 करोड़ - ₹149.87 करोड़) की शेष

राशि का पुनर्भुगतान किया गया है। यदि नहीं, पूर्व-पुनर्निर्माण अवधि हि.शि.लि. से ₹168.14 करोड़ अभी भी वसूली योग्य था, जिस कि सरकारी लेखे में शेष नहीं दर्शाया गया था ।

2.3.13 संघ सरकार के वित्त विवरणी में लाभांश शेयरों का लेखाकरण न होना

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी सरकार के पक्ष में लाभांश शेयरों की प्राप्तियों को प्राप्ति मुख्य शीर्ष '4000-विविध पूंजीगत प्राप्तियां' के अंतर्गत सरकारी लेखाओं में वर्गीकृत किया गया था। प्राप्ति आंकड़े उपरोक्त व्यय में संगत मुख्य/लघु शीर्ष के अंतर्गत निवेश हेतु विधि द्वारा प्राधिकृत पूंजीगत व्यय के प्राक्कलनों की संगति में होना चाहिए। लाभांश शेयरों की प्राप्ति का प्रकटीकरण संघ वित्त लेखे के विवरणी सं. 11 में भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों (के.सा.क्षे.उ.) की संगति में दर्शाया गया है।

संघ वित्त लेखा 2012-13 के परीक्षण से पता चला कि के.सा.क्षे.उ. ने वित्त वर्ष 2012-13 में सरकार के पक्ष में लाभांश शेयर जारी किये है लेकिन इन्हें वित्त लेखा में लेखाबद्व नहीं किया गया है। जिसका विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है -

तालिका 2.11: लाभांश शेयरों का लेखाकरण न होना

क्र.सं.	के.सा.क्षे.उ. के नाम	मंत्रालय	लाभांश शेयरों की संख्या	लाभांश शेयरों का कुल वास्तविक मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	राइटस लि.	रेलवे	60,00,000	60.00
2.	इरकोन	रेलवे	98,71,200	9.87
3.	भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लि. (पी.ई.सी.लि.)	वाणिज्य	40,00,000	40.00
4.	मैटल स्कैप ट्रेड निगम लि. (एम.एस.टी.सी.लि.)	इस्पात एवं खदान	59,29,800	5.93
कुल				**115.80**

उपरोक्त के.सा.क्षे.उ. द्वारा जारी लाभांश शेयरों का उल्लेख संघ वित्त लेखे के विवरणी सं. 8, 10 एवं 11 में नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के निवेश से संबंधित अपूर्णता हुई।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामलों में पूंजीगत व्यय करने हेतु कोई अनुपूरक प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया था वि.मं. के का.ज्ञा.स.एफ. 1(23)- बी (एसी)/2005 दिनांक 25 मई 2006, के नियमानुसार हैं।

ले.म.नि. ने पुष्टि की (दिसम्बर 2013) लाभांश शेयर उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा विवरणी सं. 10 एवं 11 में नहीं दर्शाया गया, और इस प्रकार इसे 2012-13 हेतु संघ सरकार वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जा सकता।

2.3.14 अन्य विसंगतियां

(क) विवरणी सं. 13 में आरक्षित निधि में प्राप्तियों/संवितरण के रूप में दर्ज राशि के संबंध में वित्त लेखे की विवरणी सं. 9 एवं 10 में असंगति/विसंगति

कुछ मामलों में राशि को भारत की समेकित निधि से लोक लेखे में आरक्षित निधियों में अंतरित किया गया था। तथापि, लोक लेखे में प्राप्त की गई राशि अंतरित राशि से भिन्न है। कुछ अन्य मामलों में योजनाओं पर व्यय, जो कि आरक्षित निधियों से वित्तपोषित किया गया था, तथा योजना पर किया गया वास्तविक व्यय भिन्न है। ऐसे मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

तालिका 2.12: वित्त लेखाओं में असंगतियों/विसंगतियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि का नाम एवं शीर्ष	विवरणी सं. 9 एवं 10 में लेखा शीर्ष	भा.स.नि. में योजना पर व्यय	लोक लेखा में निधि से वित्तपोषित व्यय	अंतर	टिप्पणी
1.	रेलवे पेंशन निधि (8121.103/104)	3001. 00. 901	61.26	21021.33	20960.07	ले.म.नि. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि ₹20650.48 करोड़ की राशि शीर्ष 3002.11.901 के अंतर्गत व्यय को भी पूरा करने के लिए उपयोग में लायी गयी थी। अतः ₹309.59 करोड़ का अंतर है जिसके लिए रेलवे मंत्रालय के पास संदर्भित किया गया है।
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधियां 8232.00.101	2505.02.101	30273.60	30274.72	1.12	रा.ग्रा.रो.गा.यो. शीर्ष पर भारत की समेकित निधि में दर्ज व्यय की तुलना में ₹1.12 करोड़ के अधिक व्यय को लोक लेखे से पूरा किया गया था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि शीर्ष 2505.02.101 के अंतर्गत ₹1.12 करोड़ का अंतर कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विभिन्न संगठनों के प्रति कम व्यय करने के कारण था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यय हमेशा प्रतिपूर्ति के पूर्व होता है।

3.	केन्द्रीय सड़क निधि (8224.101)	3054-80-903 3601-02-903 3601-04-903 3602-02-903 3602-04-903 5054-01-903	21115.22	21119.73	4.51	ले.म.नि. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास संदर्भित किया गया है।
भा.स.नि. से अंतरित तथा लोक लेखा में प्राप्त राशि में भिन्नता						
			भा.स.नि. से अंतरित राशि	लोक लेखा में दर्शायी प्राप्ति		
4.	रेलवे पूंजीगत निधि (8118.00.106)	3006.00.103	451.25	0	451.25	ले.म.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि राशि लोक लेखा के 8118.00.101 में अंतरित की गयी है न कि 8118.00.106 में ले.म.नि. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि शीर्ष 8118.00.101 'पूंजीगत आरक्षित निधि-डाक एवं टेलीग्राफ' से संबंध रखता है।

(ख) संघ सरकार वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में निवेश का अधूरा दर्शाया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 स्वायत्त निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में संघ सरकार के निवेश का ब्यौरा प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु विवरणी की संवीक्षा ने प्रकटीकरण के संबंध में कुछ विसंगतियों को प्रकट किया जिसका नीचे तालिका 2.14 में सार प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.13: सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के प्रकटीकरण में विसंगतियां

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	विसंगतियां	ले.म.नि./मंत्रालय का उत्तर
1.	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा टक्साल निगम लिमिटेड (भा.प्र.मु.ट.नि.लि.)	2005-06 से 2011-12 के दौरान ₹ 5 लाख के निवेश को सा.क्षे.उ. में दर्शाया गया है। इस निवेश को पूर्व वर्षों के लिए विवरणी सं.11 में नहीं दर्शाया गया था।	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि निवेश उसके ध्यान में 2012-13 में ही आया है तथा संघ सरकार वित्त लेखे 2012-13 के विवरणी सं. 11 में लिया गया है।
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्तीय तथा विकास निगम	सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश की प्रतिशतता अंकित नहीं की गई है।	ले.म.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि यह वित्त मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया है।
3.	राष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रक कम्पनी लिमिटेड	2012-13 में ₹100 लाख का निवेश दर्शाया गया था जबकि अन्य सूचनाएं अर्थात् शेयरों की संख्या, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य, सरकारी अंश की प्रतिशतता आदि प्रस्तुत नहीं की गई थी।	ले.म.नि. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वित्त मंत्रालय के पास मामले को संदर्भित किया जा चुका है।

4.	कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड	2012-13 में सा.क्षे.उ. में शेयरों के विनिवेश के बावजूद सरकारी निवेश अंश को 100% के रूप में दर्शाया गया है।	मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि सरकारी अंश की प्रतिशतता 72 प्रतिशत तक गिरी है इसे 2013-14 में सुधार लिया जाएगा।
5.	कोलकाता मैट्रो रेल लिमिटेड तथा चैन्नई मैट्रो रेल लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन दो सा.क्षे.उ. में नये निवेश के बावजूद को.मै.रे.लि. में सरकारी निवेश की प्रतिशतता 26 प्रतिशत तक कम हो गई है तथा चै.मै.रे.लि. की प्रतिशता निवेश के पश्चात भी 50 प्रतिशत पर स्थिर है।	ले.म.नि. ने शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणियों को उद्धृत किया (अक्तूबर 2013) कि पूर्व पश्चिम मैट्रो परियोजना, कोलकाता (का.मै.रे.लि.) की रेलवे मंत्रालय को हस्तांतरण के समय, रेलवे मंत्रालय को 24 प्रतिशत इक्विटी अंतरित किये गये।
6.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2012-13 में ₹ 923 करोड़ के निवेश के विवरणों को ई-लेखा तथा वित्त लेखे की विवरणी स. 10 में नहीं दर्शाया गया था।	ले.म.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि वित्त मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया है।
7.	रिपैट्रिएट्स सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लि., चैन्नई	2012-13 में ₹13.18 करोड़ का निवेश किया गया था परंतु निवेश के विवरणों को ई-लेखा तथा वित्त लेखे की विवरणी सं. 10 में नहीं दर्शाया गया था।	ले.म.नि. ने मंत्रालय के उत्तर को उद्धृत किया (फरवरी 2014) कि निवेश वित्त वर्ष 2011-12 में किया गया था परन्तु निवेश के ब्यौरे एफ.एफ.आर. प्रभाग से 2012-13 में प्राप्त हुए थे, अतः यह विवरण सं. 11 में 2012-13 में दर्शाया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निवेश का विलंबित प्रकटीकरण का यह अर्थ नहीं है कि निवेश का वर्ष परिवर्तित कर दिया जाए।
8.	बर्न स्टैन्डर्ड लि. तथा ब्रैथवैट लि.	इन दोनों अस्तित्वों को पहले ही समाप्त कर दिया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत भारी उद्योग लि. के साथ मिला दिया गया था। तथापि, 2011-12 से नये निवेशों को विवरणी सं. 11 में इन दोनो अस्तित्वों में दर्शाया गया है। इस मामले पर नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा सं. 2.3.10 में भी टिप्पणी की गई थी।	पिछले वर्षों के कथनों के अनुसार ही ले.म.नि. ने फिर से उत्तर दिया है (अक्तूबर 2013) कि इसे रेल मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया है।

9.	उ.पू. क्षेत्र में 50 सीटों वाले वायुयान हेतु सहायता	2012-13 में ₹2,152.50 लाख का निवेश किया गया था परन्तु इस निवेश के प्रभाव को वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में नहीं दर्शाया गया है। इस मामले पर नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा सं. 2.3.10 में टिप्पणी की गई थी।	पिछले वर्षों के कथनों के अनुसार ही ले.म.नि. ने फिर से उत्तर दिया है (अक्तूबर 2013) कि उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को सदंर्भित कर दिया गया है।

उपरोक्त विसंगतियां दर्शाती है कि फार्म सी.ए.एम.-60 में 'निवेश पंजिका', जो निवेश हेतु निधियों के निर्गम के लिए उत्तरदायी प्रधान लेखा कार्यालय अथवा वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है, का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जो संघ सरकार के लेखाओं में त्रुटिपूर्ण/लंबित प्रकटीकरण का कारण बना।

(ग) ऋण अग्रिम के नियमों तथा शर्तों को अंतिम रूप न देना

'राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली', स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1994-95 के पूर्व अवधि से संबंधित ₹ 2,929.00 लाख के अग्रिम ऋणों के नियमों एवं शर्तों, को 2012-13 के दौरान अतिरिक्त विवरणी सं.15 के प्रकटीकरण में दर्शाया गया था।

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि मंत्रालय से कई बार राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को ऋणों के नियमों एवं शर्तों के लंबे समय से लंबित निपटान को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है।

इस मामले को 2000 के प्रतिवेदन सं.-1 में ही उजागर किया गया था और उस समय ले.म.नि. का उत्तर वही था। ऋण देने के 18 वर्षों के अंतराल के बाद भी, ऋणों के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह प्रशासनिक मंत्रालय का अग्रिम ऋणों की वसूली एवं अन्य पहलुओं पर गंभीरता से न लिए गए दृष्टिकोण को दर्शाता है।

2.4 लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

संघ सरकार वित्त लेखे 2012-13 की परिशुद्धता पर कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत ऐसे लेन-देनों की बड़ी संख्या का होना, जिनका अंतिम वर्गीकरण बाकी है, (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषित धन (ऋ.ज.प्रे.) लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल बकाया की बढ़ती संख्या तथा मात्रा, तथा (iii) समय पर उपचारी कार्रवाई न करने के कारण बकाया शेषों की निरन्तर उपस्थिति।

लेखापरीक्षा ने ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत एक सामान्य समीक्षा की तथा कार्यालय ले.म.नि. तथा छः प्रधान लेखा कार्यालयों (प्र.ले.का.) अर्थात केन्द्रीय

प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आपूर्ति विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.) तथा विदेश मंत्रालय (वि.मं.), से संबंधित पिछले पांच वर्षों की विस्तृत जांच भी की थी। इन प्र.ले.का. को शेषों की सघनता और वर्ष-दर-वर्ष इनके जमा होते जाने के आधार पर चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गयी है :

2.4.1 मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

'उचंत शीर्ष' नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब लेखे के अन्तिम शीर्षों से संबंधित राशि उनमें दर्ज की जाती है। यदि ये राशियाँ समाशोधित नहीं होती हैं तो उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को यह सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

उचंत शेषों हेतु बहीखाता भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा उप/विस्तृत वर्गीकृत शीर्षवार के अंतर्गत, जैसा कि आवश्यक है तथा मु.ले.प. द्वारा भु.ले.का. से आवधिक रूप में प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर अनुरक्षित किया जाता है संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को उचंत शेषों की समीक्षा करना तथा मॉनीटरिंग के उद्देश्य हेतु महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2013 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹ 22038.21 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के संबंध में ₹ 3508.21 करोड़ (डेबिट), रक्षा के लिए ₹11520.44 करोड़ (डेबिट), रेलवे से संबंधित ₹ 2281.02 करोड़ (डेबिट), डाक के लिए ₹ 3005.09 करोड़ (डेबिट), दूरसंचार के लिए ₹ 589.77 करोड़ (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र, 2001 के संबंध में ₹1133.68 करोड़ (डेबिट) शामिल है। वित्त लेखे उचंत शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता, संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं हो पाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल

करने से वित्त लेखे में उचंत शेषों की अत्यधिक न्यूनोक्ति होती है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले पांच वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.14: सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वे.ले.का. उचंत	2512.92	524.57	2880.09	1172.22	3374.13	1131.37	3213.12	740.00	3348.71	331.95
कुल	**(-) 1988.35**		**(-) 1707.87**		**(-) 2242.76**		**(-) 2473.12**		**(-) 3016.76**	
102-उचंत लेखा (सिविल)	1608.78	1443.21	1942.11	1447.74	1943.09	9781.95	2050.60	3409.87	1200.82	4039.04
कुल	**(-) 165.57**		**(-) 494.37**		**7838.86**		**1359.27**		**2838.22**	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा	349.49	16.57	371.03	16.57	374.62	19.81	363.32	36.10	404.99	36.34
कुल	**(-) 332.92**		**(-) 354.46**		**(-) 354.81**		**(-) 327.22**		**(-) 368.65**	
108-सा.क्षे.बैं. उचंत	3526.51	1942.36	2435.52	1775.10	3091.85	1052.85	2881.34	1292.70	4352.63	1104.38
कुल	**(-) 1584.16**		**(-) 660.42**		**(-) 2039.00**		**(-) 1588.64**		**(-) 3248.25**	
109-रिर्जव बैंक उचंत (मु.)	11.37	190.04	11.37	185.26	11.67	185.14	11.37	185.80	11.37	188.73
कुल	**178.67**		**173.89**		**173.47**		**174.43**		**177.36**	
110- रिर्जव बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	339.41	47.09	92.02	128.83	28.52	193.74	45.50	65.52	59.07	114.38
कुल	**(-) 292.32**		**36.81**		**165.22**		**20.02**		**55.31**	
115- विदेश में क्रय इत्यादि हेतु उचंत लेखा	877.79	-	1894.85	-	940.82	-	661.19	-	504.63	52.00
कुल	**(-) 877.79**		**(-) 1894.85**		**(-) 940.82**		**(-) 661.19**		**(-) 452.63**	
129- सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखा	167.82	115.88	195.25	143.11	202.22	102.16	208.56	86.30	213.35	87.01
कुल	**(-) 51.94**		**(-) 52.14**		**(-) 100.06**		**(-) 122.26**		**(-) 126.34**	
136- प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियाँ	-	152.15	-	145.47	--	252.28	-	249.50	-	222.56
कुल	**152.15**		**145.47**		**252.28**		**249.50**		**222.56**	
138-अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक)	1.55	40.38	2.88	100.70	36.28	294.80	5.82	243.39	1.38	481.96
कुल	**38.83**		**97.82**		**258.52**		**237.57**		**480.58**	

यह देखा जा सकता है कि वे.ले.का. का उचंत, रोकड़ निपटान उचंत लेखा, सा.क्षे.बैं. उचंत, रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय तथा सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखे

के अंतर्गत डेबिट शेषों में पिछले वर्षों से 2012-13 में ₹1666.91 करोड़ तक बढ़े हैं। इसी प्रकार, उचंत लेखा सिविल, रोकड़ निपटान उचंत लेखा, रिर्जव बैंक (मु.), रिर्जव बैंक सी.ए.ओ.,विदेश में खरीद इत्यादि हेतु उचंत लेखा, सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा एवं अन्य नामित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक) शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट शेष पिछले वर्षों से 2012-13 में ₹972.46 करोड़ तक बढ़े हैं। ले.म.नि. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन के निरोधक प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

वे.ले.का. उचंत

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत वे.ले.का., संघ शासित क्षेत्रों के वे.ले.का. तथा महालेखाकार के खातों में हो रहे अन्तः विभागीय तथा अन्तः सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के अधीन लघु शीर्ष 'वे.ले.का. उचन्त' परिचालित किया जा रहा हो की ओर से किसी अन्य लेखा अधिकारी द्वारा की गई वसूलियों का अथवा भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा किया जाता है जब लेखा अधिकारी जिसकी बही में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, के द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'वे.ले.का. उचंत' के अन्तर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी, जिसके ओर से भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ होगा कि किसी वे.ले.का. द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से भुगतान किए गए, जिनकी वसूली की जानी है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि किसी वे.ले.का. द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से भुगतान प्राप्त किए गए हैं, जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2013 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष ₹3348.71 करोड़ तथा क्रेडिट शेष ₹331.95 करोड़ था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग ₹2349.71 करोड़ (डेबिट), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (व्यय) ₹242.92 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹421.90 करोड़ (डेबिट), आर्थिक कार्य विभाग ₹0.37 करोड़ (क्रेडिट) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹105.23 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे, जिसने प्रदर्शित किया कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को उनके द्वारा अभी 31 मार्च 2013 तक वसूली/भुगतान किया जाना था। वे.ले.का. उचंत के अन्तर्गत भारी डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उनका निरन्तर संचयन महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित करता था।

प्र.ले.का. के लेखाओं की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1986-87 से पहले की अवधि से 2012-13 की अवधि तक के.प्र.क.बो. से संबंधित ₹(-)0.02 करोड़ (डेबिट) तथा (-)₹2.51 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें ₹358.32 करोड़ (क्रेडिट) तथा

(-)₹758.41 करोड़ (क्रेडिट) शामिल थे जो पांच वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु लम्बित थे। वर्ष 2012-13 के अंत तक आर्थिक कार्य विभाग,वित्त मंत्रालय में ₹3.39 करोड़ (डेबिट) तथा ₹(-)11.68 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे। विदेश मंत्रालय में वर्ष 2012-13 की समाप्ति तक ₹437.66 करोड़ (डेबिट) तथा ₹14.70 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिसमें ₹11.45 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.19 करोड़ (क्रेडिट) पांच वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु लंबित थे। वे.ले.का. उचंत के ब्यौरे आपूर्ति विभाग एवं सड़क तथा राजमार्ग मंत्रालय से अभी भी प्रतीक्षित हैं।

उचंत लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देन के लेखांकन, निश्चित सूचना/दस्तावेजों अर्थात् वाऊचर, चालान आदि की मांग हेतु संचालित किया जाता है जिसे व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को 'ऋणात्मक' डेबिट या 'ऋणात्मक' क्रेडिट द्वारा लेखे से वांछित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष से तात्पर्य ऐसे भुगतान से है जिसे वाऊचर आदि जैसे विवरण के अभाव में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष से तात्पर्य प्राप्त की गई ऐसी राशि से है जिसे विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2013 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष ₹ 4,039.04 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹1,200.82 करोड़ (डेबिट) था, जो कि ₹ 5,239.86 करोड़ की प्राप्तियां तथा व्यय को दर्शाता है , जिन्हें समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था, को उनके लेखा के अंतिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग ₹3,334.79 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹597.56 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹ 598.14 करोड़ (क्रेडिट), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ₹3.83 करोड़ (डेबिट) तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ₹5.64 करोड़ (डेबिट) से संबंधित है।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि के.प्र.क.बो. में वर्ष 2012-13 की समाप्ति तक ₹ 5.76 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 0.12 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे, जिसमें ₹ 8.96 करोड़ (डेबिट) का डेबिट शेष तथा ₹ 0.19 करोड़ (क्रेडिट) का क्रेडिट शेष शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु लंबित थे। प्र.ले.का. ने बकाया शेषों का निपटान करने के लिए किए गए प्रयासों पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

विदेशों में क्रय हेतु उचंत लेखा

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय हेतु उचंत लेखा' नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/ आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह देती है। यद्यपि सरकार द्वारा इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिया गया है फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल किया जाना है।

2012-13 में, विदेशों में क्रय हेतु उचंत लेखा शेष ₹ 452.63 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2013 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹ 67.24 करोड़); पवन हंस लि. (₹ 57.44 करोड़); पाइराइटस, फॉसफेट्स एवं रसायन लि. (₹ 24.95 करोड़); कोल इंडिया लि. (प.ब.) (₹ 23.18 करोड़) थे। यह भी पाया गया कि 2003 से विभिन्न संगठनों से ₹ 210.46 करोड़ बकाया थे। 2003 से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची **अनुबंध-2.5** में दी गई है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह पाया गया था कि तदन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (सा.क्षे.बैं. उचंत)

सरकारी लेखा प्रणाली में निर्दिष्ट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह पहले अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति का दावा करता है। इसी प्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो इन प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय अंतराल होता है इसलिए प्रतीक्षारत अस्थाई समायोजन हेतु लेखे की सरकारी बही में लघु शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत परिचालित किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखे की प्राप्ति पर सा.क्षे.बैं. उचंत के अन्तर्गत मूल दर्ज ऋणात्मक क्रेडिट/ऋणात्मक डेबिट, जैसा भी

मामला हो, द्वारा समाशोधित किया जाता है तथा राशियां सरकार के रोकड़ शेष में दर्शाई जाती है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल ₹ 4,352.63 करोड़ (डेबिट) तथा ₹ 1104.38 करोड़ (क्रेडिट) था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे आपूर्ति मण्डल विभाग ₹ 276.82 करोड़ (डेबिट); के.प्र.क.बो. (व्यय) ₹ 472.66 करोड़ (डेबिट), सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ₹1,493.03 करोड़ (डेबिट), आर्थिक कार्य विभाग ₹4.62 करोड़ (डेबिट) तथा विदेश मंत्रालय ₹452.94 करोड़ (क्रेडिट) थे।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जाँच से उजागर हुआ कि के.प्र.क.बो. शेष में ₹(-)40.29 करोड़ (डेबिट) तथा ₹(-)44.93 करोड़ (क्रेडिट) का शेष वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर बकाया थे, जिसमें 5 से 24 वर्षों तक लंबित निपटान के ₹1,930.79 करोड़ का डेबिट शेष तथा ₹(-)509.42 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹(-)99.93 करोड़ (डेबिट), तथा ₹(-)1,671.41 करोड़ (क्रेडिट) के शेष वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर बकाया थे। आपूर्ति विभाग में, ₹0.30 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.31 करोड़ (क्रेडिट) वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर बकाया थे। विदेश मंत्रालय में ₹153.29 करोड़ (डेबिट) तथा ₹606.28 करोड़ (क्रेडिट) वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर बकाया थे। ले.स.नि., आपूर्ति प्रभाग विभाग ने बताया कि सी.सी.ए. (आपूर्ति प्रभाग) के अंतर्गत सभी वे.ले.का. के बकाया शेषों का मिलान करने और उनके निपटान का निर्देश कर दिया गया था तथा के.प्र.क.बो. के ले.अ. ने बताया कि सभी क्षे.ले.का. को उनके बकाया शेषों का मासिक आधार पर निपटान करने का निर्देश किया गया है।

रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (के.ले.का.)

संघ सरकार के लेखाओं में कर्जों का भुगतान, सहायता अनुदान, आयकर भाग, और राज्य सरकारों को संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान हेतु इस लघु शीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है तो संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा इस शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं से लेखे के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को '8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट करते हुए ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर ऋण/ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके इस शीर्ष को डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.) नागपुर से लेखे के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष '8675-भा.रि.बैं के पास जमा-101-केन्द्रीय सिविल' के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है। 31 मार्च 2013 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹59.07 करोड़ (डेबिट) तथा ₹114.38 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का) उचंत शेष मुख्य रूप से सड़क परिवहन एवं

राजमार्ग मंत्रालय ₹7.77 करोड़ (डेबिट), आपूर्ति विभाग ₹25.54 करोड़ (डेबिट), शहरी विकास मंत्रालय ₹8.16 करोड़ (क्रेडिट), पोत परिवहन मंत्रालय ₹3.40 करोड़ (डेबिट) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विभाग ₹7.68 करोड़ (क्रेडिट) के प्रति थे।

प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आपूर्ति विभाग में वर्ष 2012-13 के अंत में ₹ 25.54 करोड़ (डेबिट) का निवल डेबिट शेष बकाया था। बकाया शेषों की प्रभावी वर्ष-वार डेबिट तथा क्रेडिट ब्यौरा मांगा गया था, परंतु प्र.ले.का. ने इसे प्रस्तुत नहीं किया था। इस प्रकार वर्ष-वार ब्यौरे के अभाव में बकाया शेषों के निपटान की प्रभावशाली मॉनीटरिंग की जा रही है को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, के.प्र.क.बो. के संबंध में विवरणी सं. 13 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 'शून्य' अथ शेष के प्रति ₹(-)0.16 करोड़ के संवितरण को दर्शाया गया था जिसका परिणाम शीर्ष '8658.110-रि.बैं. उचंत' के अंतर्गत ₹(-)0.16 करोड़ के डेबिट शेष में हुआ। विभाग ने बताया कि यह राशि इस शीर्ष के अंतर्गत गलती से दर्ज हो गयी थी तथा जनवरी 2014 में एक अतंरण प्रविष्टि के माध्यम से इसका निपटान किया गया था।

2.4.2 ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वे ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ एक ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए। उदाहणस्वरूप, किसी भी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2012-13 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 81 मामले हैं जिन्हें **अनुबंध-2.6** में दिया गया है। इनमें से, तीन शेष वर्ष 2012-13 के दौरान 33 शेष प्रतिकूल हो गए तथा शेष 48 मामले पहले के वर्षों में बकाया थे। इनमें 22 मामले 5 वर्षों से अधिक, 8 मामले 10 वर्षों से अधिक, तथा 4 मामले 20 वर्षों से अधिक पुराने थे। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि ये जांचाधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसी जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.4.3 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों, जो अन्ततः समाशोधित होते हैं, को आरम्भ में दर्ज करने के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष है। लेखाओं के विभागीकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे वे.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष '8670-चैक एवं बिल में माह के दौरान वितरित चैकों की कुल राशि को क्रेडिट तथा संबंधित व्यय शीर्ष को डेबिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/भा.रि.बैं (के.ले.अ.) नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण (ति.मा.वि.)/शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो, 'शीर्ष 8670- चैक एवं बिल' को ऋणात्मक क्रेडिट तथा '8658-108-सा.क्षे.बैं उचंत/8675-101-भा.रि.बैं. जमा-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

2012-13 के वित्त लेखे में भारी शेष 'चैक एवं बिल' के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए थे जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 2.15: 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

पूर्व लेखापरीक्षा चैक	डेबिट	1668.20
वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	11547.30
विभागीय चैक	क्रेडिट	539.03
खजाना चैक	क्रेडिट	1673.26
इरला चैक	क्रेडिट	0.59
दूर संचार लेखा चैक	क्रेडिट	1367.85
डाक चैक	क्रेडिट	11324.20
रेलवे चैक	क्रेडिट	2581.21
रक्षा चैक	क्रेडिट	1211.43
इलैक्ट्रॉनिक सलाह	क्रेडिट	13.10
वेतन एवं लेखा कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	796.85

केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि चैक जारी करने की तिथि से तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त नियम 47(2) मे विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के माह से छः माह की अवधि तक अदत्त शेष चैकों का भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों के मामलों में, उन्हें '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है, तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय जिसमें से वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुनः लिखा जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी

नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए।

छः प्र.ले.का की नमूना जांच ने प्रकट किया कि विदेश मंत्रालय में ₹189.71 करोड़ की राशि के 6423 चैक, आपूर्ति विभाग में ₹7.19 करोड़ की राशि के 894 चैक, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹109.96 करोड़ की राशि के 886 चैक, तथा के.प्र.क.बो. में ₹173.18 करोड़ की राशि के 20307 चैक छः माह से अधिक समय तक बिना भुगतान किए रहे परंतु इन्हें प्र.ले.का. द्वारा निरस्त नहीं किया गया था।

2.4.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना

सिविल लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में,वे.ले.का. विभिन्न ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करने हेतु कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय हैं और गैस-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले ब्यौरे एवं मामले जहाँ शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रधान लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा पूरे मंत्रालय/विभाग की समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के शेषों की समीक्षा कुल 72 प्र.ले.का. में से क्रमशः केवल 36, 38, 22, 16, 08 एवं 14 विभागों में पूर्ण की गई थी।

प्र.ले.का. द्वारा शेषों की समीक्षा करने के विफलता तथा समय पर कार्रवाई की कमी ने कई वर्षों से बकाया पड़े अधिक मामलों के प्रतिकूल शेषों को दर्शाया है, जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में प्रतिबिम्बित किया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सरकारी लेखे की यथातथ्यता एवं गुणवत्ता का सुधार करने के लिए ऋ.ज.प्रे. एवं उचंत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों के समाशोधन/ निपटान हेतु निरन्तर समीक्षा एवं सामयिक कार्रवाई हेतु एक अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र को स्थापित करे।

2.4.5 विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 84 यह प्रावधान करता है कि विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के सरकारी उपक्रम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित अनुषंगी लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करेंगे।

मार्च 2013 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 41 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों को प्रोफॉर्मा लेखे, जिसमें सामान्यतः व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रेस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करती है, प्रकाशन विभाग केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। उनके नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति को **अनुबंध-2.7** में दिया गया है।

अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि उपक्रमों के संबंध में प्रोफॉर्मा लेखे एक से तेरह वर्षों के बीच की अवधि से बकाया थे जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.16: अवधि जिसके लिए प्रोफॉर्मा लेखे बकाया पड़े थे

वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1	2012-13	12
2-5	2008-09 से 2011-12	16
6-9	2004-05 से 2007-08	04
10-13	2000-01 से 2003-04	01
	कुल	**33**

प्रोफार्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.4.6 हानियाँ तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 33 विचार करता है कि हानि के कारण तथा पहचान के ढंग का ध्यान किए बिना लोक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, रसीदी टिकटें, अफ़ीम, भण्डार अथवा सरकार द्वारा अथवा ओर से नियंत्रित अन्य सम्पत्ति की किसी भी हानि अथवा कमी को संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा चाहे ऐसी हानि की उत्तरदायी पक्ष द्वारा पूर्ति

कर दी गई है। रूपये दो हजार से कम मूल्य वाली छोटी हानियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई वर्ष 2012-13 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/स्थगित की गई हानियों तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को **अनुबंध-2.8** में दिया गया है। अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि 2012-13 के दौरान, 237 मामलों में, ₹ 320.80 लाख बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष के दौरान, 202 मामलों में छोड़ी गई वसूलियाँ तथा किए गए अनुग्रह भुगतान कुल ₹ 114.82 लाख तक थे।

3: विनियोग लेखेः 2012-13

3.1 संवैधानिक प्रावधान

लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान हेतु मांगों के पारित होने के तुरन्त बाद, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ अनुच्छेद 293(2) के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के तुलनात्मक विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 99 अनुदानों और विनियोजनों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा तथा रेल मंत्रालय, और डाक विभाग अपने स्वयं के अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2012-13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार थाः

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	99
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग	**122**

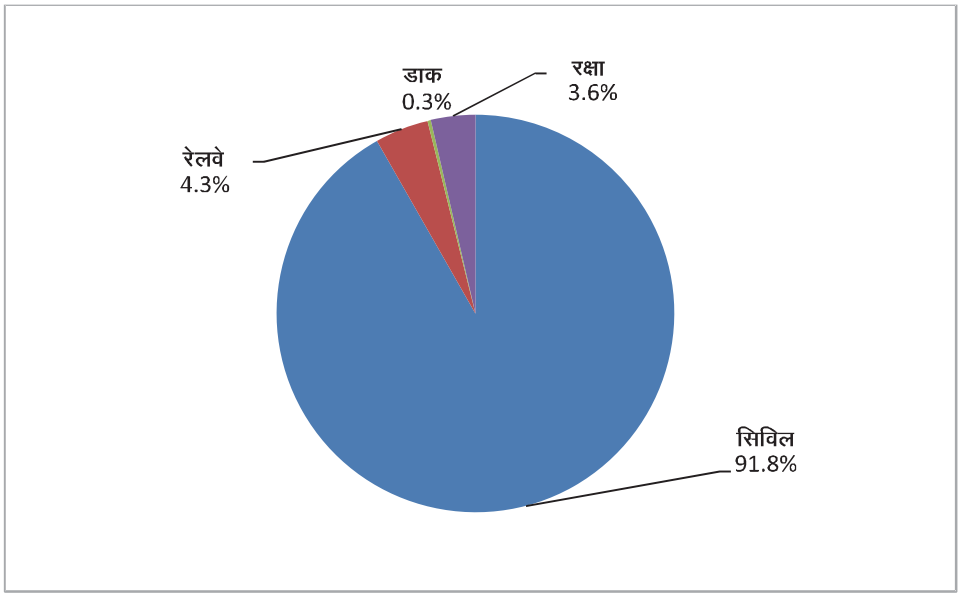
इस प्रतिवेदन में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाएं), पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निहित होती हैं जिनमें आबंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना

किए गए अनुपूरक प्रावधान, अव्यवहारिक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों के विश्लेषण शामिल होते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर विवेचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी सभी अनुदानों/विनियोगों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रेलवे विनियोगों के हवाले दिये गये हैं। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2012-13 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पृथक रूप से उपलब्ध है।

3.2 कुल प्रावधानों/वास्तविक संवितरणों का सारांश

नीचे दिया गया **चार्ट 3.1** सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय के वितरण को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 92 प्रतिशत तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा, रेलवे द्वारा चार प्रतिशत, रक्षा सेवाओं द्वारा चार प्रतिशत किया गया था जबकि कुल सकल व्यय का 0.3 प्रतिशत डाक विभाग द्वारा किया गया।

चार्ट 3.1: वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय का विघटन



वर्ष 2012-13 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा		कुल	
47,93,466		2,26,339		15,627		1,87,469		52,22,901	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	**दत्तमत**	**प्रभारित**
977071	3816395	226055	284	15626	1	187191	278	**1405943**	**3816958**
20.38%	79.62%	99.87%	0.13%	99.99%	0.01%	99.85%	0.15%	**26.92%**	**73.08%**

नीचे **तालिका 3.1** वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार के कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **अनुबंध-3.1** में सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.1: 2012-13 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	5345368	4793466	(-) 551902	10.32
डाक	15938	15627	(-) 311	1.95
रक्षा सेवाएं	198526	187469	(-) 11057	5.57
रेलवे	244889	226339	(-) 18550	7.57
कुल योग	5804721	5222901	(-) 581820	10

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹5,51,902 करोड़ की निवल बचत सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबधित 97 विनियोगों/अनुदानों में ₹5,56,467 करोड़ की बचत तथा चार विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹4,565 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

₹5,56,467 करोड़ के समग्र बचत में से अनुदान सं. 37-विनियोग-ऋणों का पुनर्भुगतान के अंतर्गत पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड में ₹3,59,181 करोड़, अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत दो खण्डों (राजस्व दत्तमत एवं पूंजी दत्तमत) में ₹53,697 करोड़ था, अनुदान सं. 35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत/प्रभारित) तथा पूंजीगत (प्रभारित) खण्डों में ₹35,928 करोड़., अनुदान सं.82- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड में ₹26,267 करोड़ था, अनुदान सं. 75-विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹9,436 करोड़, अनुदान संख्या 81-सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹8,447 करोड़ था तथा अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत) खण्डों में ₹6,108 करोड़ था। मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि ₹4,565 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से अनुदान सं. 21-रक्षा पेंशन के दत्तमत राजस्व तथा प्रभारित राजस्व खण्डों के अंतर्गत प्रत्येक पद पर समान पेंशन योजना के कार्यान्वयन, बैंक से लंबित पेंशन स्क्रोलों की प्राप्ति, न्यायालय डिक्री के कार्यान्वयन, संशोधित आश्वासित कैरियर उन्नयन योजना (सं.आ.कै.उ.यो.), स्थानीय डिस्चार्ज, पूर्व-मुक्ति प्रकरणों, मृत्यु प्रकरणों तथा अवकाश नकदीकरण के अधिक प्रकरण प्राप्त होने के कारण ₹ 3,868 करोड़ का व्यय था।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 204 अनुभागों में बचतें और पांच अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के तीन अनुभागों में बचतें और एक अनुभाग में आधिक्य; रेलवे के 19 अनुभागों में बचतें और 10 अनुभागों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के नौ अनुभागों में बचतें तथा तीन अनुभागों में आधिक्य थे। **अनुबंध-3.2** विवरणों के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

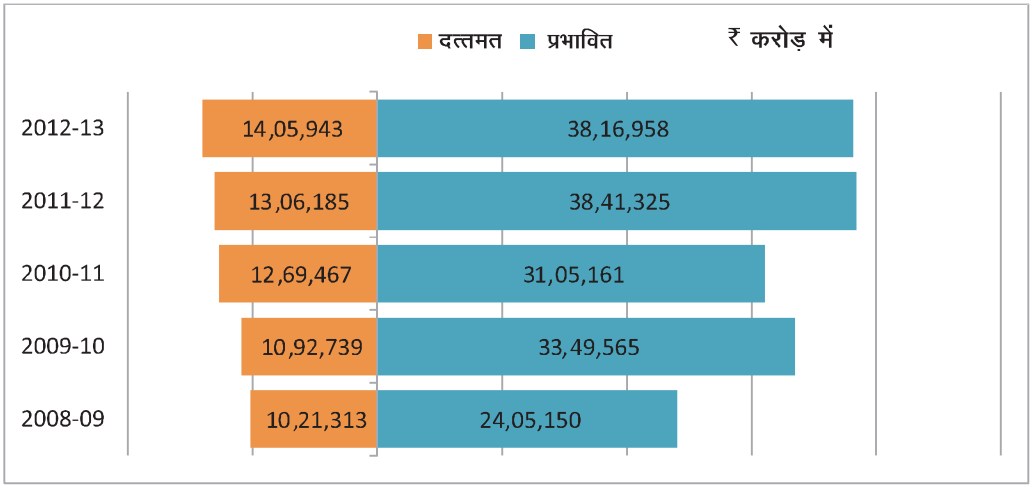
संविधान के अनुच्छेद 112 (2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय वह व्यय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 112 (3) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113 (1) में निर्धारित है परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध-3.3** में 2000-2013 के वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण दिखाया गया है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरणों के 70 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

2012-13 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹47,93,466 करोड़ के कुल संवितरण 2011-12 के दौरान किए गए ₹ 47,62,240 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹31,226 करोड़ अधिक थे। यह 2000-01 के ₹5,66,042 करोड़ से 747 प्रतिशत अधिक था। प्रभारित संवितरण 2000-01 के ₹4,05,289 करोड़ से 842 प्रतिशत बढ़ कर 2012-13 में ₹38,16,395 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत्त संवितरण ₹1,60,753 करोड़ से 508 प्रतिशत बढ़ कर ₹9,77,071 करोड़ तक हो गए थे। 2012-13 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 प्रतिशत थे।

मुख्य प्रभारित संवितरणों में, ₹34,26,893 करोड़ के ऋण पुनर्भुगतान, ₹3,30,183 करोड़ ब्याज भुगतान तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों, ब्लॉक अनुदानों, राज्य योजनागत योजनाओं हेतु ऋणों इत्यादि पर राज्य तथा संघ शासित सरकारों को ₹55,906 करोड़ के अंतरण सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण संसद के मतदान के अधीन नही हैं, इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार के कुल संवितरण के केवल 20 प्रतिशत तक ही सीमित होती है।

चार्ट 3.2, 2008-09 से 2012-13 के दौरान पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार में दत्तमत व्यय से प्रभारित व्यय की अधिकता को प्रकट करता है। सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भा.स.नि. से ₹52,22,901 करोड़ के कुल संवितरणों के प्रति प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 73 प्रतिशत (₹38,16,958 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत अनुभागों के अन्तर्गत व्यय



विनियोग लेखे 2012-13: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि से, आहरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा

संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य हो जाए। नीचे दी गयी **तालिका 3.2** में 2012-13 के दौरान भा.स.नि. में से प्राधिकृत संवितरण से ₹6591,30,34,331 (₹6591.30 करोड़) के आधिक्य का सारांश दिखाया गया है। सिविल मंत्रालयों/विभागों में चार अनुदानों/विनियोगों के पांच खण्डों में ₹4565,39,25,407 (₹4,565.39 करोड़), रेलवे के आठ अनुदानों/विनियोगों के 10 खण्डों में ₹16702406859 (₹1,670.24 करोड़), रक्षा सेवा के तीन अनुदानों के तीन खण्डों में ₹195,53,44,892 (₹195.53 करोड़) तथा डाक विभाग के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹160.13,57,173 (₹160.14 करोड़) का अधिक संवितरण था। अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के ब्यौरे **तालिका 3.3** में दिये गये हैं।

तालिका 3.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(राशि ₹ में)

		सिविल	रक्षा	डाक	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	3865,77,23,294	--	160,13,57,173	1668,94,67,521
	पूंजीगत	--	--	--	
प्रभारित	राजस्व	699,62,02,113	195,53,44,892	--	1,29,39,338
	पूंजीगत	--	--	--	
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		4	4	1	8
खंड		5	3	1	10
कुल आधिक्य		**4565,39,25,407**	**195,53,44,892**	**160,13,57,173**	**1670,24,06,859**
कुल योग		**6591,30,34,331**			

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों के अनुसार अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल				
राजस्व (दत्तमत्त)				
1.	21-रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	39499,18,00,000 43362,89,24,944 3863,71,24,944	प्रत्येक पद पर एक समान पेंशन योजना के कार्यान्वयन, बैंक से लंबित पेंशन स्क्रोलों की प्राप्ति तथा न्यायालय डिक्री के कार्यान्वयन के कारण।
2.	40- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	2561,55,00,000 2563,60,98,350 2,05,98,305	क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रति अतिरिक्त आवश्यकता, संशोधित आश्वासित कैरियर उन्नयन योजना (सं.आ.कै.उ.यो.), बकायों का भुगतान, अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति तथा रिक्त पदों को भरना।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
राजस्व (प्रभारित)				
3.	21-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य	*82,00,000* *4,81,60,400* *3,99,60,400*	संशोधित आश्वासित कैरियर उन्नयन योजना के अधिक मामलों की प्राप्ति, वेतन का पुनर्निधारण, स्थानीय निपटान, पूर्व-मुक्ति प्रकरण, मृत्यु प्रकरण तथा सेवानिवृत्त होने वालों के क्रेडिट में अधिक अवकाश।
4.	34 - ब्याज भुगतान	विनियोग व्यय आधिक्य	*329487,43,00,000* *330182,67,86,901* *695,24,86,901*	आधिक्य टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई गई
5.	101- शहरी विकास विभाग रेलवे	विनियोग व्यय आधिक्य	*44,23,00,000* *44,60,54,812* *37,54,812*	आधिक्य टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई गई
राजस्व (दत्तमत्त)				
6.	8- परिचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य	7860,77,94,000 7888,94,97,579 28,17,03,579	अधिक संविदा संबंधी भुगतान, स्टाफ लागत के प्रति अधिक व्यय करना।
7.	10- परिचालन व्यय-ईंधन	अनुदान व्यय आधिक्य	21729,34,02,000 22388,16,45,046 658,82,43,046	एच.एस.डी. तेल की मूल लागत में वृद्धि तथा एच.एस.डी. तेल के अधिक उपयोग, बाहर से खरीदी गई ऊर्जा की दर में वृद्धि।
8.	13-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य	20576,72,00,000 21558,67,20,896 98195,20,896	सं.आ.कै.उ.यो. तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि के कार्यान्वयन के कारण पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अधिक डेबिट की प्राप्ति, अधिक अनुग्रह पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के अधिक मामले, पेंशन का चयन करने वालों के लिए अवकाश नकदीकरण तथा नई पेंशन योजना हेतु अधिक सरकारी योगदान।
राजस्व (प्रभारित)				
9.	03-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*91,000* *42,73,995* *41,82,995*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
10.	04-स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं निर्माण	विनियोग व्यय आधिक्य	*51,22,000* *97,41,936* *46,19,936*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
11.	05-चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	*0* *4,12,746* *4,12,746*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
12.	07-संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*17,000* *2,28,968* *2,11,968*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
13.	08-परिचालन व्यय-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण	विनियोग व्यय आधिक्य	*0* *4,96,123* *4,96,123*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
14.	11-स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएँ	विनियोग व्यय आधिक्य	*469000* *1921241* *1452241*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
15.	13-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	*58,20,000* *73,83,329* *15,63,329*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किए जाने के कारण।
डाक सेवाएं राजस्व (दत्तमत्त)				
16.	13-डाक विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	15320,49,00,000 15480,62,57,173 160,13,57,173	मंहगाई भत्ता में सामान्य वृद्धि, वेतन में वृद्धि, सं.आ.कै.उ.यो., आदि के कारण।
रक्षा सेवाएं राजस्व (प्रभारित)				
17.	22.-रक्षा सेवाएं -थल सेना	वनियोग व्यय आधिक्य	*45,27,00,000* *221,87,35,739* *176,60,35,739*	धनपालन मामले में न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।
18.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	वनियोग व्यय आधिक्य	*13,20,00,000* *22,76,80,239* *9,56,80,239*	धनपालन मामले में न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।
19.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	वनियोग व्यय आधिक्य	*6,18,00,000* *15,54,28,914* *9,36,28,914*	धनपालन मामले में न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन।

अनुदान/विनियोग आंकड़ों में यदि कोई अनुपूरक अनुदान/विनियोग हो तो वो शामिल है।

अनुदान सं. 25 - रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने राजस्व (दत्तमत) में ₹1,796.48 करोड़ निवल राशि की प्राधिकृति प्राप्त की गयी तथा उसकी तुलना में ₹1,754.03 करोड़ का निवल व्यय वहन किया गया। तथापि, ₹11,934.94 करोड़ का सकल व्यय किया गया। अतः इस अनुदान में रक्षा मंत्रालय ने संसद की प्राधिकृति से ₹10,138.46 करोड़ की राशि का अधिक व्यय वहन किया। इस अनुदान में संसद द्वारा गलत रूप से किए गए प्राधिकरण का विवरण प्रतिवेदन के पैरा 4.1 में दिया गया है। लेखापरीक्षा के मतानुसार संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत इस अधिक व्यय को नियमित किये जाने की भी आवश्यकता होगी।

रेलवे अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के लिए संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए हैं।

3.5 अनुदानों में निरन्तर आधिक्य

संवीक्षा में 2008-09 से 2012-13 तक की पांच वर्ष की अवधि हेतु लगातार आधिक्य के पंजीबद्ध अनुदानों को लिया गया था। संवीक्षा से पता चला कि विश्लेषण के पांच वर्ष की अवधि में से कम से कम तीन वर्षों में नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत निरन्तर

आधिक्य हुए थे। आबंटनों की तुलना में निरन्तर आधिक्यों का अनुदान-वार तथा वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों में लगातार आधिक्य

(₹ में राशि)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सिविल अनुदान						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	21- रक्षा पेंशन					
	आधिक्य-	**13,32,985**	**8999,54,01,305**	**3336,30,72,983**	**3568,81,46,182**	**3863,71,24,944**
	व्यय-	20233,08,32,985	34999,29,01,305	37336,05,72,983	37568,56,46,182	43362,89,24,944
	अनुदान-	20232,95,00,000	25999,75,00,000	33999,75,00,000	33999,75,00,000	39499,18,00,000
डाक सेवाएं						
राजस्व (दत्तमत)						
2.	13- डाक विभाग					
	आधिक्य-	-	**818,12,99,976**	**366,63,29,167**	**400,03,82,246**	**160,13,57,173**
	व्यय-		13344,82,99,976	13793,26,29,167	14162,36,82,246	15480,62,57,173
	अनुदान-		12522,67,00,000	13426,63,00,000	13762,33,00,000	15320,49,00,000
रेलवे						
राजस्व (दत्तमत)						
3.	04- स्थायी मार्गों की मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं निर्माण					
	आधिक्य-	**104,05,87,825**	**55,50,24,359**	**7,75,52,784**	-	-
	व्यय-	5944,26,92,825	7496,25,82,359	7386,56,17,784		
	अनुदान-	5840,21,05,000	7440,75,58,000	7378,80,65,000		
4.	05- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण					
	आधिक्य-	**95,24,56,565**	**90,87,30,288**	**75,06,60,832**	-	-
	व्यय-	2924,36,28,565	3479,19,71,288	3423,60,13,832		
	अनुदान-	2829,11,72,000	3388,32,41,000	3348,53,53,000		
5.	06- माल डिब्बों एवं यात्री डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण					
	आधिक्य-	**149,69,22,039**	**164,57,39,230**	**221,08,77,978**	-	-
	व्यय-	6430,23,89,039	7857,06,14,230	7799,58,75,978		
	अनुदान-	6280,54,67,000	7692,48,75,000	7578,49,98,000		

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
6.	08- परिवालन व्यय - रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण				-	
	आधिक्य-	**131,05,69,735**	**36,30,60,599**	**189,88,89,127**		**28,17,03,579**
	व्यय-	4711,59,77,735	5983,59,00,599	6156,81,96,127		7888,94,97,579
	अनुदान-	4580,54,08,000	5947,28,40,000	5966,93,07,000		7860,77,94,000
7.	12- विविध संचालन व्यय					-
	आधिक्य-	-	**19,58,54,173**	**648,43,86,934**	**278,20,93,415**	
	व्यय-		3177,23,12,173	4002,49,56,934	4388,08,15,415	
	अनुदान-		3157,64,58,000	3354,05,70,000	4109,87,22,000	
8.	13- भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	-				
	आधिक्य-		**1512,38,96,979**	**1403,97,51,918**	**769,61,68,663**	**981,95,20,896**
	व्यय-		16911,20,69,979	16352,71,21,918	18326,96,73,663	21558,67,20,896
	अनुदान-		15398,81,73,000	14948,73,70,000	17557,35,05,000	20576,72,00,000
रेलवे राजस्व (प्रभारित)						
9.	03- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं					
	आधिक्य-	**1,04,322**	**24,21,286**	**20,97,842**	**27,29,201**	**41,82,995**
	व्यय-	9,52,322	34,79,286	36,49,842	30,34,201	42,73,995
	विनियोग-	8,48,000	10,58,000	15,52,000	3,05,000	91,000

अनेक अनुदानों में वर्ष-दर वर्ष आधिक्य होना चिंता का विषय है। रक्षा पेंशन के मामले में बड़ी राशि की अबाधित अधिकता निरपेक्ष हो गयी है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिशों के बावजूद इन अनुदानों में लगातार आधिक्य देखे गये हैं। मंत्रालयों/विभागों ने ठोस प्रयास नहीं किये तथा अधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र नहीं विकसित किये गये।

3.6 लघु/उप शीर्ष-वार आधिक्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(1) के अनुसार व्यय वहन करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गये आबंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आबंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि, वर्ष 2012-13 के शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 15 लघु अनुदानों के 60 लघु/उप-शीर्षों में उपलब्ध प्रावधान से ₹पांच करोड़ तथा अधिक का व्यय था। यद्यपि इन लघु/उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से ₹11,860.38 करोड़ का कुल अधिक व्यय किया गया था, जो इन लधु/उप-शीर्षों के अंतर्गत मौजूद प्रावधानों से अधिक था, परंतु संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाते हैं। अधिक व्यय वाले लघु उप-शीर्ष **अनुबंध 3.4** में सूचीबद्ध हैं।

3.7 ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत (खण्ड-वार)

लोक लेखा समिति ने अपनी 60 वीं रिपोर्ट (10वीं लोक सभा) में इच्छा जाहिर की थी कि समिति को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुदान के किसी भी अनुभाग में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचत के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक विस्तृत व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचत त्रुटिपूर्ण बजटीकरण के साथ-साथ निष्पादन में कमी को दर्शाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 84 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाएं सहित) के 104 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिसके लिए लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दिए जाने की आवश्यकता है। अधिक बचतें अनेक अनुदानों में देखी गयीं जैसे विनियोग-ऋण का पुर्नभुगतान (₹3,59,181 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹53,697 करोड़), ग्रामीण विकास (₹26,267 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (₹35,928 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹9,436 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹9044 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹8,447 करोड़), परिसंपत्ति-अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन-रेलवे निधि (₹8218 करोड़), निधियों के प्रति विनियोग-(रेलवे) (₹7731 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹6,108 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग (₹4869 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹4691 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹3985 करोड़), वस्त्र विभाग (₹3514 करोड़), पुलिस (₹2999 करोड़), वित्त सेवाएं विभाग (₹2,520 करोड़), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (₹1547 करोड़), आदि। **अनुबंध 3.5** विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत बचतों के ब्यौरे दर्शाता है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के कारण 'कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में विफलता', 'प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब', 'कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा व्यय की धीमी गति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित राशियां पड़े रहना तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति आदि बताये गये थे।

इसके अतिरिक्त, पूंजीगत खण्डों सहित 42 अनुदानों/विनियोगों के 53 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2010-2013) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी जैसा **अनुबंध-3.6** में दिखाया गया है। बड़ी निरन्तर बचतों वाले कुछ अनुदान थे सं. 32- आर्थिक मामले विभाग, 33- वित्तीय सेवा विभाग, 35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण, 37- ऋणों का पुनर्भुगतान, 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 59- उच्च शिक्षा विभाग, 75- विद्युत मंत्रालय तथा 82- ग्रामीण विकास विभाग तथा 14-निधियों के प्रति विनियोग (रेलवे)।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/ विभागों के 97 अनुदानों/विनियोगों के 204 खण्डों के अंतर्गत ₹5,56,467 करोड़ की बचतें हुईं। इसे चार अनुदानों के पाँच खण्डों के अंतर्गत ₹4565 करोड़ के अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹5,51,902 करोड़ के निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित की गई राशियां **तालिका 3.5** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों तथा अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि	अव्ययित प्रावधानों को 31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	111167.63	104934.50	92193.35	83	6233.13
प्रभारित	14044.47	14020.45	14009.73	100	24.02
कुल: राजस्व	125212.10	118954.95	106203.08	85	6257.15
पूंजीगत					
दत्तमत	70690.19	67816.07	58704.91	83	2874.12
प्रभारित	360565.01	343022.06	343004.94	95	17542.95
कुल: पूंजीगत	431255.20	410838.13	401709.85	93	20417.07
कुल योग	**556467.30**	**529793.08**	**507912.93**	**91**	**26674.22**

औषधि विभाग, विदेश मंत्रालय, पेंशन, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, दादरा एवं नगर हवेली, खनन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा सेवाएं-थल सेना, नौ-सेना, वायु सेना, रक्षा आयुध कारखाने और रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी। **अनुबंध 3.7** विवरण प्रदान करता है। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का सूचक है।

3.9 31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)

76 मामलों में, एक अनुदान/विनियोग में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें पाई गई थीं जिन्हें 30/31 मार्च 2013 अर्थात वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अन्ततः[1] अभ्यर्पित किया गया था। अभ्यर्पित न की गई एवं व्यपगत को अनुमत राशियों सहित बचतों, अभ्यर्पणों के ब्यौरे **अनुबंध 3.8** में दर्शाए गये हैं।

3.10 लघु/उप-शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा डाक सेवाओं के सात अनुदानों/विनियोगों के 20 मामलों में, कुल ₹ 827.30 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था, क्योंकि जिन लघु/उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा बढ़ाई गई थी उनमें मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः इन लघु/शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें

[1] वित्त मंत्रालयों द्वारा जारी लेखापरीक्षा आदेश की तिथि के संबंध में माना गया है

इनमें पुनर्विनियोजित की गई राशियों से अधिक थीं। 20 मामले, जहां पांच करोड़ तथा अधिक के पुनर्विनियोग किए गए हैं, का ब्यौरा **अनुबंध 3.9** में दिया गया है।

3.11 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)

इसी प्रकार, लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि रक्षा सेवाओं एवं सिविल मंत्रालयों/विभागों के छह अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 12 मामलों में, इन शीर्षों से कुल ₹ 2060.47 करोड़ के निधि के पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण थे, क्योंकि इनमें प्रत्येक लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले के मूल प्रावधान से भी अधिक थे। इनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोग के पश्चात उपलब्ध अंतिम प्रावधान से अधिक व्यय पुनर्विनियोजित राशि से भी अधिक थे। यह 12 मामले, जिनमें ₹ पांच करोड़ और अधिक के पुनर्विनियोजन किए गए हैं, **अनुबंध-3.10** में दिए गए हैं।

3.12 अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (40 प्रतिशत से अधिक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत, संसद, सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत कर सकती है। व्ययों के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने हेतु आवश्यक सावधानी बरतना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप देता है।

वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों में से अधिकांश ने मूल प्रावधानों से बहुत अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे। कुछ अनुदानों के विभिन्न खण्डों में अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान के 933 प्रतिशत तक थे। अनुदान सं. 73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पूंजीगत दत्तमत खंड में, ₹1.00 करोड़ के मूल प्रावधान के प्रति 480.50 करोड़ का तकनीकी अनुपूरक लिया गया जो मूल प्रावधान का 48,050 प्रतिशत था। मूल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक अनुपूरक मांग वाले मामलों का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: अवास्तविक बजटीय अनुमानों के कारण प्राप्त भारी अनुपूरक अनुदानों के ब्यौरे दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	43758.85	53273.77	122
2.	92-इस्पात मंत्रालय	121.89	125.68	103
राजस्व (प्रभारित)				
3.	21-रक्षा पेंशन	0.26	0.56	215
4.	53-मंत्रिमंडल	0.10	0.28	280
5.	54-पुलिस	5.67	8.15	144
पूंजीगत (दत्तमत)				
6.	9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	4155.82	2000.00	48
7.	10-कोयला मंत्रालय	30.00	279.95	933
8.	66-खनन मंत्रालय	69.58	79.47	114
9.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1.00	480.50	48050
10.	93-वस्त्र मंत्रालय	60.78	66.33	109
पूंजीगत (प्रभारित)				
11.	04-परमाणु ऊर्जा	1.00	8.00	800
12.	81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	7.50	23.00	307

बड़े अनुपूरक दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने यथार्थवादी आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा यथार्थवादी बजटीय अनुमान सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा 2013-14) में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किये गये व्यय को नियमित करते हुए, पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरूआत करनी चाहिए। राजस्व-वर्ष के दौरान मूल बजट के अतिरिक्त तीन अनुपूरकों का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करती है। बहुधा अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट

में अनुवर्ती अनुपूरकों द्वारा करने के लिए दबा दिया जाता है। अनुपूरक बजट सामानयः अपरिहार्य लोकहित के लिए किये गये व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजानाओं के लिए होना चाहिए। अन्य राजस्व संघीय मॉडलों के आधार पर वित्त मंत्रालय को साधनों एवं एक ऐसे ढाँचे का विकास करना चाहिए जो विनियोग खर्चों पर संसद की पहुँच एवं देख-रेख को सुनिश्चित करते हुए बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को बनाएगा।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा वर्ष 2005-06 से आगे के मूल प्रावधानों के प्रति अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति **अनुबंध 3.11** में दी गई है।

3.13 अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान

चार अनुदानों/विनियोगों में जिनके ब्यौरे **तालिका 3.7** में दिए गए हैं, 2012-13 के दौरान यद्यपि ₹ 463.14 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये थे, परंतु चार में से तीन मामलों में अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ। अतः प्राप्त किया गया समग्र नकद अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का द्योतक था।

'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालयों/विभागों को अनुदान में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की सम्भावना तलाशनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक अनुदान' लेना चाहिए जिससे वर्ष के अन्त में होने वाली बचतों से बचा जा सके।

तालिका 3.7: नकद अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	कुल प्राप्त अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक संवितरण	बचतें
सिविल अनुदान						
1.	19-संस्कृति मंत्रालय	1447.00	3.20	3.15	1390.93	59.27
2.	31-विदेश मंत्रालय	9661.97	1030.02	400.00	10120.70	571.29
3.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	1700.00	59.56	59.56	1316.07	443.49
4.	71-संसदीय कार्य मंत्रालय	11.72	0.43	0.43	10.51	1.64
कुल			**1093.21**	**463.14**		**1075.69**

वित्त मंत्रालय को मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस विषय में सभी मंत्रालयों और विभागों को उचित मार्गदर्शन जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.14 उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त किए गए अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालयों/विभागों ने संसद को कई योजनाओं/कार्यकलापों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बहुत अधिक अतिरिक्त आवश्यकता सूचित की थीं किन्तु वे अन्ततः न केवल सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग को खर्च करने में असफल रहे बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च न कर सके। ऐसे तीन अनुदानों/विनियोगों में स्थिति तीन लघु/उप-शीर्षों जिनमें सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदान के साथ मूल बजट प्रावधान भी अव्ययित रहे, इनके ब्यौरे **अनुबंध 3.12** में दिए गए हैं।

3.15 निरन्तर बचत (उप-शीर्ष वार)

विनियोग लेखाओं की विस्तृत जाँच से पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान 18 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई थी, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती है। 22 उप-शीर्षों के अनुदानवार ब्यौरे **अनुबंध 3.13** में दिए गए हैं।

3.16 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)

मंत्रालयों/विभागों द्वारा 47 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 134 उप-शीर्षों में संसद द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,61,185.18 करोड़ की राशि के सम्पूर्ण प्रावधान (₹10 करोड़ एवं अधिक) अव्ययित रहे। सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें इस तथ्य को इंगित करती है कि अनुमानों को परियोजनाओं/कार्यक्रमों की पर्याप्त समीक्षा के पश्चात तैयार नहीं किया गया था। मुख्य योजनाएं जो सम्पूर्ण प्रावधानों के उपयोग न करने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुईं, वे हैं:

- परमाणु ऊर्जा विभागः 'भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड' (₹216 करोड़); 'तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा (₹580 करोड़);
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालयः 'हरित भारत मिशन' (₹221 करोड़);
- वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) : 'लम्बी अवधि के सहकारी ऋण संरचना का पुनरूत्थान (₹500 करोड़);
- पुलिस (गृह मंत्रालय): 'उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील अवसंरचना' (₹155 करोड़);

- अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (गृह मंत्रालय के माध्यम से): 'अं.एवं नि. द्वीप समूहों तथा मुख्य भूमि क्षेत्र के बीच समुद्र के अंदर ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने के लिए' (₹200 करोड़);

- जल संसाधन मंत्रालयः 'राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन' (₹195 करोड़)

उप-शीर्ष जहाँ ₹10 करोड़ एवं अधिक के पूरे प्रावधान अव्ययित रहे, के ब्यौरे **अनुबंध 3.14** में दिये गये हैं।

3.17 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹ 100 करोड़ या अधिक की बचतें थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनो को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि कम संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.15,** एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की ₹ 100 करोड़ या अधिक की 163 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचतें हुईः

- **दूरसंचार विभागः** ₹2,064.10 करोड़ - 'सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति' (2,689.10 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत बेतार ब्राडबैंड योजना के गैर-कार्यान्वयन एवं अनावृत्त ग्राम सार्वजनिक दूरभाष (ग्रा.सा.दू.) चरण-II हेतु दावों को अनुमति न देने, सौर-प्रकाश वॉल्टेइक (सौ.प्र.वा.) मॉडल्यूलों एवं चार्ज संकेतकों का प्रावधान न होने एवं रॉल आउट में कमी के कारण;

- **राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरणः** ₹7738.42 करोड़; - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम (₹14242 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण; ₹7234.23 करोड़ 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (₹12,522 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य

सरकार द्वारा समान शेयरों को जारी न किए जाने के कारण, योजनाओं की शुरूआत में विलम्ब तथा परियोजनाओं को वापस लेने के कारण।

- **उच्च शिक्षा विभागः** ₹2151.78 करोड़ - 'विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतन मान में सुधार' (₹2250 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति के कारण।

- **विद्युत मंत्रालयः** ₹4086.15 करोड़ - 'राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण' (₹ 4761 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के कारण; ₹3162.27 करोड़ -'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम' (₹3810 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता, चरण II परियोजना की सुपूर्दगी में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से समाप्ति प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयः** ₹ 1777.03 करोड़ - 'राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि के प्रति अंतरण' (₹ 3627.17 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत परियोजनाओं के शेल्फ एवं संबंधित अभिकरणों से वैधानिक मंजूरी/पर्यावरण मंजूरी की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 4720.08 करोड़ - 'सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य' (₹5613.80 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) विश्व बैंक से ऋण को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य की धीमी प्रगति एवं राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।

- **ग्रामीण विकास विभागः** ₹ 12644.35 करोड़ - 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों आदि को सहायता' (₹ 16042.11 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों की कम समावेश क्षमता तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण, ₹2097.23 करोड़ - 'इंदिरा आवास योजना' (तीन घटकों के अंतर्गत) (₹ 9966 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण, ₹921.93 करोड़, - 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' (तीन घटकों के अंतर्गत) (₹1672.60 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ।

3.18 बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक की ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत (लघु/उप-शीर्ष वार)

प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय, पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के चरण, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिये जाने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बाद के चरण में परिहार्य अभ्यर्पणों की गुंजाइश को कम करना है। इसके अतिरिक्त, सामान्यतः परियोजनाओं/योजनाओं की बजट-पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले तथा संसद द्वारा बजट पारित करने तक ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए।

शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न लघु/उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसके परिणामस्वरूप अंततः वर्ष के अन्त में भारी बचतें तथा अभ्यर्पण करने पड़े। **अनुबंध 3.16** बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक के ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचत के ऐसे 48 मामलों का विवरण दर्शाता है।

3.19 मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने व्यय सीमाओं के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने दोहराया (जनवरी 2013) कि संशोधित अनुमान सीमाओं को योजनावार तथा एक संपूर्ण विषय के रूप में मांग-वार इन सीमाओं पर प्रतिबंध को अंतिम तिमाही/माह में लागू किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु व्यय की प्रवृत्ति से संबंधित सूचना मांगी गई थी।

तालिका 3.8 में दिए गए मामलों में यह पाया गया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2013 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.8: मार्च 2013 और/अथवा 2012-13 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं लेखापरीक्षा खंडन
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
सिविल							
1.	पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग	2361.37 (2244.66)	580.55	25 (26)	912.32	39 (41)	मंत्रालय ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक छूट वित्त मंत्रालय द्वारा छः योजनाओं हेतु प्रदान की गयी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वित्त मंत्रालय ने छः योजनाओं के लिए छूट प्रदान की थी न कि संपूर्ण भाग के लिए।
2.	9-नागरिक विमानन मंत्रालय	5238.84 (7208.76)	335.92	--	2349.93	45 (33)	--
3.	33-वित्तीय सेवाएँ विभाग	24437.24 (22112.42)	15861.79	65 (72)	15901.17	65 (72)	--
4.	31-विदेश मंत्रालय	9661.97 (10062.00)	2208.45	23 (22)	3551.82	37 (35)	मंत्रालय ने बताया कि अतिरिक्ता को 'बांग्लादेश को सहायता' के रूप में खर्च किया गया था जो मार्च के महीने में अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग पारित करने के पश्चात संवितरित किया गया था एवं विदेश स्थिति परियोजनाओं के निर्माण के निष्पादन पर प्रदत्त वापसी योग्य मू.व.क. वित्त वर्ष के अंदर प्राप्त नहीं हुआ था।
5.	50 – भारी उद्योग विभाग	1009.67 (789.97)	209.06	21 (26)	211.63	--	--
6.	53-मंत्रीमंडल	741.87 (797.13)	254.97	34 (32)	338.42	46 (42)	मंत्रालय ने तेजी हेतु प्र.मं. की यात्राओं के बिलों की एयर इण्डिया से एवं अन्य मंत्रालयों से विलंबित प्राप्ति को दोषी ठहराया। इसके अतिरिक्त बताया गया कि कई चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भी देर से प्राप्त हुए थे।

क्र. सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता #	मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं लेखापरीक्षा खंडन
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
7.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2737.39 (2693.47)	654.21	24 (24)	1214.35	44 (45)	मंत्रालय ने व्यय में तेजी हेतु मार्च माह में अनुपूरक मांगों के दूसरे खेप के अनुमोदन की दोषी ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि व्यय ने संशोधित अनुमान सीमाओं से संबंधित निर्धारित सीमा को भी पार कर दिया।
8.	70-पंचायती राज मंत्रालय	5350.74 (4000.66)	1249.88	23 (31)	1892.07	35 (47)	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि इन सीमाओं से अधिक व्यय की छूट वित्त मंत्रालय से प्राप्त की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छूट कुछ विशेष योजनाओं के लिए ही था और और वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सीमा पूरे मांग कर लागू होगी।
9.	73- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	43759.85 (97514.10)	26240.31	60 (27)	56856.38	130 (58)	--
10.	75-ऊर्जा मंत्रालय	15291.60 (12339.88)	3932.54	26 (32)	4030.01	26 (33)	--
11.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3484.00 (2956.00)	2945.74	85 (100)	2945.74	85 (100)	--
12.	92-इस्पात मंत्रालय	121.89 (247.07)	9.38	--	177.44	146 (72)	--

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित प्रतिशत दर्शाता है।

--निर्धारित सीमा के अंदर व्यय

नोटः कॉलम में दी गई प्रतिशतता अनुबंध 1.2 के साथ मेल नहीं खाती है क्योंकि इन प्रतिशतताओं को बजट अनुमानों के संबंध में परिकलित किया गया है (संशोधित अनुमानों के अनुसार)। दूसरी ओर, अनुबंध 1.2 में दी गई प्रतिशतताएं, कुल व्यय से संबंधित प्रतिशतताएं हैं।

चूंकि निधियां विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई थी वर्ष के दौरान प्रलक्षित रूप से खर्च नहीं हो सकी, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होनी थी इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी उद्देश्य के लिए अनुप्रयुक्त की गई जिसके लिए प्राधिकृत की गई थी।

3.20 रक्षा सेवाएं

3.20.1 निरंतर बचतें

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की जांच में छः अनुदानों के प्रभारित/दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति देखी गई जिसका विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2010-13 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
22- रक्षा सेवाएं - थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)			
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत)	234.10	244.63	286.33
800-अन्य व्यय (प्रभारित)	6.86	8.90	2.13
800-अन्य व्यय (दत्तमत)	142.83	246.90	490.67
23- रक्षा सेवाएं- नौ सेना(मुख्य शीर्ष 2077)			
101-नौ सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	17.52	40.15	303.47
104- नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	0.84	7.18	2.00
104 नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	20.09	658.17	295.87
111- निर्माण कार्य (प्रभारित)	3.05	2.56	0.71
800- अन्य व्यय (प्रभारित)	0.08	1.23	1.42
24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना (मुख्य शीर्ष-2078)			
105-परिवहन (प्रभारित)	0.01	0.01	0.05
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.90	2.00	0.77
800- अन्य व्यय (प्रभारित)	0.13	0.54	2.02
800-अन्य व्यय (दत्तमत)	64.47	52.06	118.49
25-रक्षा आयुध कारखाने (मुख्य शीर्ष 2079)			
001-निर्देशन एवं प्रशासन (प्रभारित)	0.06	0.21	0.46
004- अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत्त)	0.05	4.29	21.96
053- अनुरक्षण-मशीनरी एवं उपकरण (दत्तमत्त)	5.14	6.22	2.69
106-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन (दत्तमत्त)	117.18	14.75	84.15
110 - भण्डार (प्रभारित)	0.04	1.72	1.60
110 - भण्डार (दत्तमत्त)	1336.20	246.03	781.41
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.04	0.10	0.10
111-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	25.25	34.07	22.68

अनुदान सं. उप मुख्य/लघु शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13
26-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास (मुख्य शीर्ष-2080)			
003-प्रशिक्षण (दत्तमत्त)	6.34	3.94	0.42
004-अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत्त)	22.44	132.09	632.89
102- नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	0.11	0.10	0.06
105-परिवहन (दत्तमत्त)	1.81	12.19	26.74
110 – भंडार (प्रभारित)	0.15	0.20	0.20
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष-4076)			
01-थल सेना			
050-भूमि (प्रभारित)	16.71	17.26	16.35
050-भूमि (दत्तमत्त)	307.82	131.31	14.89
101-विमान एवं वायु इंजन (दत्तमत्त)	524.74	686.66	745.58
103-अन्य उपकरण (दत्तमत्त)	875.89	3895.78	1591.85
105-सैन्य फार्म (दत्तमत्त)	1.92	2.17	6.64
107-भूतपूर्व-सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (दत्तमत्त)	34.18	34.04	33.17
113-राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत्त)	25.67	22.35	49.31
202-निर्माण कार्य (दत्तमत्त)	906.55	656.88	1350.22
02 - नौ सेना			
050-भूमि (दत्तमत्त)	16.93	5.87	9.20
102-भारी एवं मध्यम वाहन (दत्तमत्त)	7.90	12.88	12.55
03 - वायु सेना			
050-भूमि (दत्तमत्त)	10.44	17.45	70.22
04 - रक्षा आयुध कारखाना			
111-निर्माण कार्य (प्रभारित)	0.11	0.74	2.00

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्तियाँ, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने या आपूर्ति प्राप्तियों एवं परियोजनाओं हेतु खराब योजना, अपर्याप्त निविदा प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारम्भ करने की विफलता की संकेतक हैं।

3.20.2 रक्षा सेवाएं अनुदानों बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय नियमावली के अनुसार बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2012-13 के दौरान, दो अनुदानों के प्रभारित खण्ड़ों के अंतर्गत ₹ 9.72 करोड़ के अभ्यर्पण की तुलना में ₹39.81 करोड़ की बचत पायी गई। रक्षा सेवाओं के छः अनुदानों के दत्तमत्त खण्डों के अन्तर्गत ₹14,910.47 करोड़ अभ्यर्पित किए जाने पर भी ₹11,212.59 करोड़ की बचत थी। अतः दत्तमत्त खण्ड में छः अनुदानों के अंतर्गत ₹14910.47 करोड़ तथा प्रभारित

खण्ड में दो अनुदानों के अंतर्गत ₹9.72 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि नियमों के प्रतिकूल था जैसा नीचे **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: बचतें एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	बचत (-)		अन्तिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22-थल सेना	-	463.60		1926.79	--	--
23-नौ सेना	-	645.87	--	1153.11	--	--
24-वायु सेना	-	200.37	--	620.07	--	--
25-रक्षा आयुध कारखाने	3.96	42.45	0.45	426.00	3.51	--
26-अनुसंधान एवं विकास	0.05	816.63	--	793.76	0.05	22.87
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	35.85	9043.67	9.27	9990.74	26.58	--
कुल	**39.86**	**11212.59**	**9.72**	**14910.47**	**30.14**	**22.87**

अनुदान सं. 22-थल सेना, 23-नौ सेना, 24-वायु सेना 25-रक्षा आयुध कारखाने, 26-अनुसंधान एवं विकास और 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के मामले में रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में ₹14,910.47 करोड़ की उपलब्ध बचतों के प्रति ₹11,212.59 करोड़ अभ्यर्पित किए। यह मंत्रालय में त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र दर्शाता है।

3.20.3 रक्षा सेवाएं अनुदानों में उपलब्ध प्रावधान से अधिक निरंतर अतिरिक्त व्यय

पिछले तीन वर्षों में रक्षा सेवाओं से संबंधित कुछ अनुदानों में वित्तीय बजटीय नियंत्रण की विफलता की लगातार प्रवृत्ति पर विश्लेषणात्मक तालिका नीचे वर्णित है:

तालिका 3.11: 2010-13 वर्षों के दौरान निरंतर अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	2010-11 के दौरान अंतिम अधिक व्यय	2011-12 के दौरान अंतिम अधिक व्यय	2012-13 के दौरान अंतिम अधिक व्यय
मुख्य शीर्ष– 2077 अनुदान सं. 23- रक्षा सेवाएं- नौ सेना				
1.	800-अन्य व्यय	35.09	21.11	35.65
मुख्य शीर्ष – 4076 अनुदान सं. 27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय				
01 - थल सेना				
2.	050-भूमि	25.25	4.94	8.10
3.	103-अन्य उपकरण	363.44	42.32	146.87
02 – नौ सेना				
7	103-अन्य उपकरण	67.65	130.26	328.97

मंत्रालय यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखे/नियंत्रक रक्षा लेखे ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय प्राधिकृत कैसे किया।

***

4: विनियोग लेखेः लेखाओं पर टिप्पणियां

4.1 अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों में व्यय हेतु संसद से लगातार गलत प्राधिकरण प्राप्त किया जाना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114 बताता है कि, लोक सभा द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों हेतु समेकित निधि से सभी अपेक्षित धनराशि प्रदान करने तथा भारत की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय जो किसी भी अवस्था में संसद के समक्ष पूर्व प्रस्तुत विवरण में दर्शायी गई राशि से अधिक नहीं हो, के विनियोग हेतु प्रावधान के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। इस प्रकार पेश किया गया विधेयक, अनुदानों हेतु प्रत्येक मांग पर आधारित होगा। संसद द्वारा पारित विनियोजन अधिनियम, भारत की समेकित निधि से भुगतान/आहरण का प्रावधान करता है।

अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों की वित्तीय वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि बजट अनुमानों पर ₹13,014.94 करोड़ के सकल व्यय प्रावधान को दर्शाते हुए, संबंधित अनुदान हेतु अनुदानों की मांग में केवल वसूली के प्रावधानों को निवल करते हुए विनियोग विधेयक के प्रयोजन हेतु ₹1801.68 करोड़ की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान सं. 25 - रक्षा आयुध कारखानों के अंतर्गत संसद से व्यय का प्राधिकरण प्राप्त किया जोकि ₹11,213.26 करोड़ तक कम था।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में गलत प्राधिकरण प्राप्त किए जाने के मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया था। रक्षा मंत्रालय से संदर्भ के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के दावों के प्रति सहमति जाहिर करते (जुलाई 2013) हुए, आश्वासन दिया कि तीन सेवाओं पर आपूर्तियों की लागत हेतु प्रावधान को शामिल करते हुए सकल आधार पर विनियोजन की मांग की प्रक्रिया को बदलने के मामले तथा वसूलियों को सीमा से अधिक दर्शाने की वर्तमान प्रणाली के प्रति वसूलियों को सीमा से नीचे दर्शाने की प्रणाली का अनुपालन 2014-15 के बजट से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 के संबंध में वित्त मंत्रालय ने पाया कि वर्तमान राजकोषीय वर्ष में किसी बदलाव हेतु अधिक अनुपूरक की आवश्यकता होगी, जो शायद पूरा न किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु संघ बजट में, रक्षा मंत्रालय ने अनुदान सं. 25 रक्षा आयुध कारखानों में संसद से ₹13,820.65 करोड़ के सकल प्रावधान की मांग की है।

4.2 के.प्र.क.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3)- करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय का लगातार उल्लंघन

संविधान का अनुच्छेद 114(3) अनुबंधित करता है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि द्वारा किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 'ब्याज' को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में वर्णित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में पाया कि ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी जिसके कारणवश विभाग, पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान को नहीं लगा पाया। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसियों पर 'ब्याज' को वापस लेने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। आगे, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया कि संविधान के अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधान द्वारा किए गए 'विनियोग' के अलावा भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालना रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में लो.ले.स. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया कि मंत्रालय सांविधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमावली के अनुसार एक प्रक्रिया स्थापित करे, जिससे कि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांग में कर वापसियों पर बयाज भुगतानों को दर्शाया जा सके तथा संसदीय स्वीकृति प्राप्त करे जैसाकि संविधान द्वारा आदेश दिया गया है।

पिछले छः वर्षों के लिए के.प्र.क.बो. द्वारा करों की वापसियों पर ब्याज पर किया गया व्यय निम्नानुसार हैः

तालिका 4.1: करों की वापसियों पर दिए गए ब्याज पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2007-08	4444
2008-09	5778
2009-10	6876*
2010-11	10499
2011-12	6486
2012-13	6666
योग	**40,749**

** आरंभ में, विभाग द्वारा ₹12,951 करोड़ के आंकड़े को सूचित किया गया। तदनंतर, रिपोर्ट के संसद में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विभाग द्वारा ₹6,876 करोड़ के आंकड़े को सूचित किया।*

अतीत की तरह वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹6,666 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किये बिना पिछले छः वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹40,749 करोड़ का व्यय किया गया था।

4.3 के.उ.सी.शु.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) - करों की वापसी पर ब्याज पर किया गया व्यय का लगातार उल्लंघन

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वापसियों पर ब्याज के भुगतान के मामले में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.) द्वारा भी इसी तरह की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क द्वारा वर्ष 2012-13 तथा चार वर्षों 2009-13 की अवधि में ब्याज को राजस्व में कमी के रूप में मानते हुए, करों की वापसी पर ब्याज पर क्रमशः ₹15.59 करोड़ तथा ₹44.78 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2 : करों की वापसियों पर दिए गए ब्याज पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसी पर दिए गए ब्याज पर व्यय		
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	कुल
2009-10	4.47	नगण्य	4.47
2010-11	16.51	0.70	17.21
2011-12	6.91	0.60	7.51
2012-13	15.47	0.12	15.59
कुल	**43.36**	**1.42**	**44.78**

चूंकि करों की वापसी पर ब्याज का भुगतान एक व्यय की मद है, जैसा कि पैरा संख्या 4.2 में वर्णित है तथा लोक लेखा समिति द्वारा कहा गया, इस तरह की मद हेतु बजट के प्रावधान को विभाग की संबंधित मांग के अनुसार प्राप्त करना चाहिए और लेखाओं में लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

इस गलत प्रक्रिया पर नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 में टिप्पणी की गई थी परंतु विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

4.4 बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

शीर्षवार विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि संसदीय प्राधिकरण के माध्यम से बिना किसी प्रदान बजट प्रावधान के चार अनुदानों में ₹ 1,501.00 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.3 : बजट सीमा के बिना व्यय

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियां
	20- रक्षा मंत्रालय (सिविल)			
1.	2075.00.108.01.01.31 सहायता अनुदान सामान्य	134.99	उत्तर प्रतिक्षित	का.ज्ञा. सं. एफ. 1 (23)-बी (ए.सी.)/2005 दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार संसद की पूर्व अनुमति प्राप्त कए बिना सहायता अनुदान पर प्राधिकृत प्रावधान के परे कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। परंतु इस मामले में सहायता अनुदान पर व्यय उस सेवा पर किया गया है जिसके लिए कोई संसदीय प्राधिकरण विद्यमान नहीं था।
2.	4047.00.037.01.05.52 मशीनरी एवं उपकरण	1363.57	मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि वर्गीकरण चूक को सही करने हेतु जहाज, वायुयान तथा फ्लीट का अधिग्रहण हेतु विषय शीर्ष 54 (निवेश) को 52- मशीनरी एवं उपकरण, में संशोधित किया गया था। इनका तदनुसार मार्च 2013 में पुनर्विनियोग आदेश जारी किया गया था।	वर्तमान मामले में गलत वर्गीकरण को सही करने हेतु विषय शीर्ष मशीनरी एवं उपकरण के अंतर्गत अनुपूरक मांगों में बजटीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।
	26- रक्षा (अ. एवं वि.)			
3.	युद्ध सामग्री अनुसंधान बोर्ड (ए.आर.एम.आर.ई.बी.) बुकिंग शीर्ष 852/04 सहायता अनुदान	2.35	उत्तर प्रतिक्षित	
	34-विनियोग ब्याज भुगतान			
4.	*2049.01.111.00.00.45* ब्याज *2049.60.101.25.00.45* ब्याज *2049.60.101.29.00.45* ब्याज (*सभी प्रभारित*)	0.09	कार्यालय मुख्य नियंत्रक लेखा ने बताया (अक्तूबर 2013) कि व्यय भुगतानों के अधिक होने के कारण था तथा यह भविष्य में प्रकट नहीं होंगे। ऐसी बुकिंग से बचने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि व्यय भले ही कम हो किन्तु संसद द्वारा बजट प्रावधान की उचित रूप से स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता।
	योग	**1501.00**		

4.5 संवर्धन प्रावधानों हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.5.1 विषय-शीर्ष 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

विनियोग लेखों के साथ-साथ ई-लेखा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग नौ अनुदानों/विनियोगों में 19 मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को '31- सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान के ₹ 418.75 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप से.नि.सा. की सीमाओं को आकर्षित किया। नीचे दी गई तालिका उन शीर्षों का ब्यौरा देती है जिनमें संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था।

तालिका 4.4: सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	अधिक व्यय
		₹ करोड़ में					
अनुदान सं.1 कृषि एवं सहकारिता विभाग							
1.	2435.01.101.09.00.31 लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ	44.70	-	-	44.70	45.95	1.25
मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि निधियां वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मुख्य शीर्ष '2552', के अंतर्गत प्रावधान में से पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गैस-क्रियात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान जिसे इस शीर्ष हेतु पुनर्विनियोजित किया गया था उसी योजना हेतु नहीं था तथा इसलिए सही नहीं था।						
अनुदान सं.20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
2.	2052.00.092.03.01.31-सहायता अनुदान-सामान्य	117.22	-	58.16	175.38	194.24	18.86
अनुदान सं.26-रक्षा (अ.एवं वि.)							
3.	बाहरी अनुसंधान शीर्ष 852/06	3.22	-	-	3.22	49.83	46.61
4.	जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (जी.वि.अ.बो.) शीर्ष 852/05	0.41	-	-	0.41	3.45	3.04
5.	नौसेना अनुसंधान तथा विकास बोर्ड (नो.अ.बो.) शीर्ष 852/03	1.17	-	-	1.17	11.57	10.40
अनुदान सं.46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग							
6.	2210.06.796.08.02.31 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.56	-	-	4.56	5.14	0.58
7.	2210.06.796.13.00.31 नर्सिंग सेवाओं का उन्नयन/ सशक्तिकरण	4.60	-	-	4.60	8.40	3.80
8.	2211.00.796.04.01.31 राज्य पी.आई.पी. आर.सी.एच. फ्लैक्सीबल पूल	109.50	-	-	109.50	154.89	45.39
9.	2211.00.796.04.02.31 राज्य पी.आई.पी. आर.सी.एच. फ्लैक्सीबल पूल	419.26	-	-	419.26	697.77	278.51
10.	2210.06.101.08.05.31 विधानमण्डल रहित सं.शा.क्षे. में व्यय	0.05	-	-	0.05	4.70	4.65
11.	2210.06.800.27.04.31 विभिन्न संघटकों हेतु राज्य समितियों को अनुदान (जी.सी.)	22.75	-	-	22.75	23.22	0.47

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	अधिक व्यय
		₹ करोड़ में					
अनुदान सं.59-उच्चतर शिक्षा विभाग							
12.	2202.80.800.37.00.31 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग	1.09	-	-	1.09	1.34	0.25
मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।							
अनुदान सं.63-विधि एवं न्याय मंत्रालय							
13.	2052.00.090.06.00.31 कानूनी कार्य विभाग	1.58	--	--	1.58	1.62	0.04
अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग							
14.	3451.00.090.18.00.31 अं.वि. सचिवालय	0.30	-	-	0.30	0.51	0.21
अनुदान सं.99-दमन एवं दीव							
15.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2235.02.196.02.00.31 पंचायतें	2.33	-	-	2.33	6.06	3.73
16.	ग्रामीण विकास मंत्रालय 2515.00.196.02.00.31 पंचायतें	8.21	-	-	8.21	8.66	0.45
अनुदान सं.100-लक्षद्वीप							
17.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 3435.60.198.01.00.31 पंचायतें	0.75	-	-	0.75	0.85	0.10
18.	शहरी विकास मंत्रालय 2215.02.198.01.00.31 पंचायतें	0.25	-	-	0.25	0.59	0.34
19.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2235.02.198.01.00.31 पंचायतें	1.48	-	-	1.48	1.55	0.07
	योग						**418.75**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.5.2 विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्घन

नई सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 में जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल ससंद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता हैं।

लेखा परीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹ 80.78 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद की पूर्व-स्वीकृति लिये बगैर विषय शीर्ष

'35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन' हेतु अनुदान के लिए संवर्धित की गयी थीं जिसने सेवा के नए साधन को सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.5: विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ. *	उ.पू. *	अ.प्रा. *	कु.प्रा. *	कु.व्य. *	राशि
		₹ करोड़ में					
अनुदान सं.2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग							
1.	2415.01.150.07.00.35 कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	164.60	4.00	62.70 +6.00#	237.30	317.89	80.59
अनुदान सं.93-वस्त्र मंत्रालय							
2.	2851.00.789.27.00.35 महा समूह का विकास	1.92	--	--	1.92	2.11	0.19
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि अधिक व्यय के नियमन हेतु वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।							
	योग						**80.78**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

मु.शी. 2552 के अंतर्गत अनुपूरक

4.5.3 विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' से निधियों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा या तो '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन' के लिए अनुदान या फिर '36-सहायता अनुदान वेतन' में पुनर्विनियोजन, संसद की पूर्व-स्वीकृति से अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगो के माध्यम से किया जाना अपेक्षित होता है। यह प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा 8 जून 2010 को जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन के आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनायी जानी थी, जब 12 फरवरी 2010 को विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियो के सृजन' के लिए अनुदान वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 के नीचे भारत सरकार के निर्णय 1 के नीचे दर्शाये गये विषय शीर्षो की सूची की इंगित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के पांच मामलों में कुल ₹55.84 करोड़ की निधियों के वर्तमान प्रावधान के उल्लंघन में संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' हेतु संवर्धित की गई थी जिसने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.6: विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ. *	उ.पू. *	अ.प्रा. *	कु.प्रा. *	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
1.	2221.80.102.01.00.36 प्रसार भारती	1280.10	--	187.65	1467.75	1520.00	52.25
मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि संसद की स्वीकृति मुख्य-शीर्ष वार प्राप्त की गई है तथा मु.शी. के अंतर्गत कोई निवल संवर्धन नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि न.से./से.न.उ. की सीमाओं को विनियोग की प्राथमिक इकाई अर्थात् विषय शीर्ष के साथ देखा जाना चाहिए।							
अनुदान सं.100-लक्षद्वीप							
2.	कृषि मंत्रालय 2403.00.198.01.00.36 पंचायतें	2.70		1.45	4.15	4.49	0.34
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2210.06.198.01.00.36 पंचायतें	13.33		2.00	15.33	16.35	1.02
4.	कृषि मंत्रालय 2401.00.198.01.00.36 पंचायतें	4.59		0.50	5.09	5.73	0.64
5.	कृषि मंत्रालय 2405.00.198.01.00.36 पंचायतें	2.22		0.48	2.70	4.29	1.59
	योग						**55.84**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा ढेर के अनुसार)*

4.5.4 विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, संसद द्वारा पहले ही दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं तथा ई-लेखा डाटा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि चार मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना मौजूदा प्रावधान के उल्लंघन में विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग तीन अनुदानों/विनियोगों में कुल ₹100.04 करोड़ की निधियाँ व्यय की गई थीं जिन्होंने नई सेवा/सेवा के नए उपकरण की सीमाओं को आकर्षित किया। निम्न तालिका उप-शीर्षों का ब्यौरा देती हैं जहाँ संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था जिसने सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.7: 'आर्थिक सहायता' पर संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.12-औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग							
1.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता योजना	शून्य	शून्य#	शून्य	शून्य	13.70	13.70
2.	2885.02.101.10.00.33 पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	86.12	86.12
विभाग ने बताया (जून 2013) कि 'एन.ई.आई.आई.पी.पी. 2007 के अंतर्गत' विभिन्न योजनाओं के बीच निधियों का विभाजन वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकता के अनुसार किया जाता है परंतु इसका विस्तृत ब्यौरा गैर-क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत अ.वि.मां. में नहीं दर्शाया गया है। विभाग ने आगे बताया (नवम्बर 2013) कि गैर-क्रियात्मक शीर्ष में एक-मुश्त प्रावधान एन.ई.आई.आई.पी.पी. के विभिन्न योजनाओं हेतु मांग के अनुसार आर्थिक सहायता के निर्गम में अधिक उत्तोलन को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था जो वर्ष के दौरान परिपक्व हो सकते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु अ.वि.मां. में क्रियात्मक शीर्ष के अनुसार पृथक रूप से गैर-क्रियात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि 'आर्थिक सहायता' के अंतर्गत संवर्धन में संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है इसलिए योजना-वार ब्यौरे को व्यक्त करना आवश्यक है।						
अनुदान सं.64-भारत का सर्वोच्च न्यायालय							
3.	2014.00.101.01.00.33 न्यायिक प्रशासन	0.50	-	-	0.50	0.57	0.07
अनुदान सं.99-दमन एवं दीव							
4.	गृह मंत्रालय 2225.02.283.02.00.33 अन्य आवास	0.06	-	-	0.06	0.21	0.15
	योग						**100.04**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.5.5 विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रति प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशानिर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012 तथा 5 अक्तूबर 2012) कि विषय शीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर न.स./स.न.स. के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक जो भी कम हो, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो या मौजूदा निर्माणों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि निम्न 131 मामलों में कुल ₹407.07 करोड़ की निधियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान

यद्यपि ₹99.82 करोड़ का एक प्रावधान 2552.00.238.00.33-उत्तर पूर्वी औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (उ.पू.औ.नि.प्रो.नी.) 2007 के अंतर्गत किया गया था।

संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना संवर्धन किया था जिसके कारण नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाएं आकर्षित हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.8 : विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान की वृद्धि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.1-कृषि एवं सहकारिता विभाग							
1.	4401.00.113.13.00.53 खेती मशीनरी प्रशिक्षण एवं निरीक्षण संस्थान	2.50	-	-	2.50	3.42	0.92
मंत्रालय नं बताया (जनवरी 2014) कि वर्तमान में चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय किया गया था तथा इसलिए संवर्धन अनुमत था। उत्तर, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 21 मई 2012 की दृष्टि में तर्कसंगत नहीं है।							
अनुदान सं.4-परमाणु उर्जा विभाग							
2.	68 मामले अनुबंध 4.1						218.06
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।							
अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजनाएं							
3.	4801.03.104.04.00.52 फास्ट ब्रीडर रियेक्टर	4.45	-	-	4.45	5.92	1.47
4.	4801.03.104.04.00.53 फास्ट ब्रीडर रियेक्टर	0.03	-	-	0.03	0.33	0.30
अनुदान सं.19-संस्कृति मंत्रालय							
5.	4202.04.104.01.00.53 भवन	3.00	-	-	3.00	5.16	2.16
मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि चालू कार्यों के अंतर्गत निधियों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु संवर्धन को मुख्य शीर्ष से बचतों से पूरा किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस संवर्धन को संसद की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जाना चाहिए था।							
अनुदान सं.28 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय							
6.	4552.00.800.03.00.53 एन.ई.सी. स्टाफ हेतु आवास स्थान/एन.ई.सी अतिथि गृह	0.50	-	-	0.50	1.17	0.67
मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2014) कि अनभिप्रेत चूक वर्तमान अनुदेशों की गलत व्याख्या करने के कारण हुई।							
अनुदान सं.54-पुलिस							
7.	4055.00.203.02.02.53 भा.ति.सी.पु. हेतु आवासीय भवन (मुख्य निर्माण कार्य)	30.92	-	-	30.92	36.80	5.88
8.	4055.00.203.01.01.53 महानिदेशक सी.सु.ब.-सीमा चौकी	117.24	-	-	117.24	120.08	2.84
9.	4055.00.203.01.02.53 कार्यालय भवन सी.सु.ब.	334.93	-	6.00	340.93	347.09	6.16
10.	4055.00.216.07.01.52 राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	0.20	-	-	0.20	0.42	0.22
11.	4055.00.216.13.01.52 राष्ट्रीय जांच अभिकरण	0.20	-	-	0.20	0.37	0.17
गृह मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि दो मामलें में जहाँ संवर्धन ₹50 लाख से अधिक नहीं था, वित्त मंत्रालय के अनुदेश उपयुक्त नहीं थे तथा उसे अनुदान में से उपयुक्त बचतों से संवर्धन हेतु अधिकार दिया गया था। मंत्रालय का उत्तर 21 मई 2012 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं था। अन्य मामलों के लिए, उत्तर फिर भी उन कारणों को संदर्भ नहीं करता जो संसद की पूर्वानुमति के बिना संवर्धन का कारण बने।							
अनुदान सं.61-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय							
12.	4250.00.800.03.03.52 महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम-मशीनरी तथा उपकरण	0.34	-	-	0.34	0.46	0.12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग							
13.	12 मामले (अनुबंध 4.1)		-	-			29.15
अनुदान सं.96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह							
14.	21 मामले (अनुबंध 4.1)		-	-			27.27
अनुदान सं.98-दादरा एवं नागर हवेली							
15.	गृह मंत्रालय 4055.00.207.01.00.53 जिला पुलिस	1.00	-	-	1.00	1.92	0.92
16.	4055.00.211.01.00.53 भवन	0.51	-	-	0.51	1.00	0.49
17.	उच्चतर शिक्षा विभाग 4202.01.202.05.00.53 भवन	5.25	-	-	5.25	8.25	3.00
18.	कृषि मंत्रालय 4403.00.101.10.00.53 निर्माण	0.91	-	-	0.91	1.16	0.25
19.	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 4406.01.070.06.00.53 निर्माण	1.04	-	-	1.04	3.91	2.87
20.	जल संसाधन मंत्रालय 4711.02.103.01.00.53 गुजरात सरकार को देय शेयर पूंजीगत परिव्यय	1.75	-	-	1.75	3.64	1.89
21.	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम मंत्रालय 4851.00.101.02.00.53 नई औद्योगिक सम्पदा का विकास	3.00	-	-	3.00	3.43	0.43
22.	जल संसाधन मंत्रालय 4705.00.201.00.00.53 अन्य मदें	0.00	-	-	0.00	55.20	55.20
23.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 4210.03.105.04.00.53 अन्य मदें	10.42	-	-	10.42	12.17	1.75
24.	विद्युत मंत्रालय 4801.05.101.09.00.53 अवसंरचना विकास	52.00	-	-	52.00	83.07	31.07
अनुदान सं. 99-दमन एवं दीव							
25.	शहरी विकास मंत्रालय 4055.00.211.01.0053 भवन	1.40	-	-	1.40	2.18	0.78
26.	4059.80.052.02.00.52 क्रय	0.20	-	-	0.20	0.23	0.03
27.	4215.01.800.01.00.53 अन्य मदें	3.00	-	-	3.00	3.70	0.70
28.	4801.05.095.01.00.53 दमन एवं दीव	1.00	-	-	1.00	1.25	0.25
29.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 4406.02.110.01.00.53 वनों का विकास	0.95	-	-	0.95	2.32	1.37

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.100-लक्षद्वीप							
30.	शहरी विकास मंत्रालय 4711.02.103.03.00.53 तटीय क्षेत्रों की रक्षा	4.75	-	-	4.75	8.36	3.61
31.	शहरी विकास मंत्रालय 5452.01.800.03.00.53 भवन	3.10	-	-	3.10	3.80	0.70
32.	शहरी विकास मंत्रालय 4059.60.051.26.00.53 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.50	-	-	0.50	0.58	0.08
33.	शहरी विकास मंत्रालय 4059.80.051.26.00.53 भवन	1.00	-	-	1.00	7.29	6.29
	योग						**407.07**

** ब.अ. = बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. 2552/4552/6552 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)*

4.6 पूंजी लेखे के बजाए तथा प्रतिक्रम में राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वित्तीय वार्षिक विवरणियां, अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग रखेंगी। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धांतों की अनुपालना की जानी चाहिए।

पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा प्रतिक्रम में राजस्व प्रकृति के व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किए गए थे। फिर भी कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत ससंदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती लेखापरीक्षा पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय का अधिग्रहण), जहाँ विषय शीर्ष यथा 51 से 56 तथा 60 से संबंधित है, को वर्गीकृत करता है। ये विषय शीर्ष[1] पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही उपयोग किया जाना चाहिए।

[1] संदर्भ अनुबंध-4.2

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं के साथ-साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा में वे मामले उजागर हुए जहाँ से विषय शीर्ष, राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ प्रयुक्त हुए थे जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जिसके कारण पूंजीगत व्यय को ₹1,331.39 करोड़ से कम बताया गया।

तालिका 4.9: पूंजीगत प्रकृत्ति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	2070	52	0.02	विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि ऐसे व्यय हेतु प्रावधान अनुदानों हेतु विस्तृत मांग 2014-15 में पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। विभाग ने यह भी बताया (फरवरी 2014) कि मु.शी. 2070 तथा 2435 के अंतर्गत व्यय मशीनरी तथा उपकरण को चलाने हेतु अपेक्षित उपभोज्यों पर किया गया था तथा उन्हें राजस्व वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मशीनरी तथा उपकरण को चलाने हेतु अपेक्षित उपभोज्यों पर व्यय को विषय श्रेणी प्रशासनिक व्यय अथवा संविदात्मक व्यय तथा आपूर्तियों में वर्गीकृत उपयुक्त विषय शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
2.		2401	51	0.47		
3.		2401	52	0.94		
4.		2435	52	0.05		
5.	3-पशुपालन, विभाग तथा डेरी विकास	2403	52	0.93	वे.ले.का. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि व्यय को विषय अनुदानों हेतु विस्तृत मांग में बजट प्रावधान के अनुसार दर्ज किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन विषय शीर्षों पर व्यय प्रवृत्ति में पूंजीगत है तथा इनका न तो प्रावधान किया जा सकता है और न अंतिम रूप से अनुदान के राजस्व वर्ग के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है।
6.		2403	53	0.15		
7.		2404	53	0.59		
8.		2405	51	0.10		
9.		2405	52	2.10		
10.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2037	52	46.96	सी.जी.डी.ए. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि शीर्ष के अंतर्गत प्रारम्भिक आवंटन ₹89.40 करोड़ था तथा इस शीर्ष से बचतों का उपयोग अन्य राजस्व विषय शीर्ष के अंतर्गत किया गया था न कि पूंजीगत मुख्य शीर्ष को।	उत्तर इस तथ्य को धुंधला करता है कि ₹46.96 करोड़ के पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय को गलत प्रकार से राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
11.		2075	53	7.10	उत्तर प्रतीक्षित	
12.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	3403/ 3451	52	0.22	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2014)।	

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष कोड	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
13.	32-आर्थिक कार्य विभाग	3054	53	1102.45	विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि राजस्व वर्ग के अंतर्गत व्यय को दर्ज करने के मामले की बजट प्रभाग के साथ जांच की जाएगी।	
14.	41-राजस्व विभाग	2070	52	0.04	उत्तर प्रतिक्षित	
15.	43-अप्रत्यक्ष कर	2037	52	13.06	उत्तर प्रतिक्षित	
16.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210	51	2.02	उत्तर प्रतिक्षित	
17.			52	8.99		
18.	52-गृह मंत्रालय	2052	52	0.53	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगति को वर्ष 2013-14 हेतु जारी शुद्धिपत्र के माध्यम सुधार दिया गया है।	अभ्युक्ति वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुद्धि करने हेतु गलत प्रकार से प्राप्त प्रावधान का अभ्यपर्ण करके सही विषय शीर्ष के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया जाना चाहिए था।
19.		3454	52	15.00		
20.	90-अंतरिक्ष विभाग	3402 एवं 3252	52	40.04	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि इसके द्वारा अगस्त 2013 में यह बताते हुए एक परिपत्र जारी कर दिया गया था कि राजस्व शीर्ष के अंतर्गत विषय शीर्ष '52' केवल कार्यालय उपकरण की खरीद तक सीमित है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय उपकरण पर व्यय को अनुदान के राजस्व वर्ग में विषय शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
21.	93-कपड़ा मंत्रालय	2851	52	0.01	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2013)	
22.	104-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51, 52 एवं 53	19.61	उत्तर प्रतिक्षित	
23.		2702	51, 52 एवं 53	65. 20	उत्तर प्रतिक्षित	
24.		2711	51 एवं 52	4.51	उत्तर प्रतिक्षित	
25.		3075	52	0.30	उत्तर प्रतिक्षित	
योग				**1331.39**		

व्यय आंकड़े स्रोतःई-लेखा/समेकित सारांश

4.6.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, श्रेणी 6 के अलावा अन्य से संबंधित विषय शीर्षों को राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकृत करता है।

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखे के साथ-साथ ई-लेखा लेखा परीक्षा संवीक्षा ने कई मामलों को प्रकट किया जहाँ राजस्व प्रकृत्ति के विषय शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। इन गलत वर्गीकरण का परिणाम संघ सरकार के राजस्व व्यय को ₹101.25 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.10: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र.स	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4-परमाणु ऊर्जा विभाग	4861 एवं 5401	27	2.82	उत्तर प्रतिक्षित	
2.	52- गृह मंत्रालय	4216	27	0.06	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि राजस्व वर्ग के अंतर्गत वर्तमान शीर्ष को बदलने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं।	
3.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	5051	01	6.22	कार्यालय प्र.मु.ले.नि. ने बताया (नवम्बर 2013) कि ब.अ. 2013-14 में पूंजीगत के अंतर्गत किए गए प्रावधान को राजस्व शीर्ष में अंतरित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।	यह अभ्युक्ति वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है।
4.		5051	50	0.69	कार्यालय प्र.मु.ले.नि. ने बताया (नवम्बर 2013) कि 'अन्य प्रभार' उपयुक्त शीर्ष है क्योंकि सू.प्रौ. पर व्यय कार्यालय चलाने के व्ययों से संबंधित नहीं है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' विषय श्रेणी 6 के अंतर्गत नहीं आता है जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के, अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के लिए है।
5.		5052	50	0.76		
6.	94-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	2.00	मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वह शीर्ष 'व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक सलाहकार पर व्यय को दर्ज करने के मामले को वित्त मंत्रालय के साथ नए अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पहले उठायेगा।	
7.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4059/ 4401/ 4406/ 4801/ 5052/ 5452	28/21/ 50/43/ 30	26.26	उत्तर प्रतिक्षित	
8.	100-लक्षद्वीप	4851	27	0.03	उत्तर प्रतिक्षित	
9.	101-शहरी विकास विभाग	4217	32	55.00	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2013) कि 2011-12 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुपालन करते हुए तथा एन.सी.आर. योजना बोर्ड के साथ सलाह से विषय शीर्ष 'निवेश' को 2013-14 हेतु अ.वि.मां. में जगह दी गई है।	मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर सही नहीं है। अनुदान के राजस्व वर्ग में उपयुक्त विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' है।

क्र.स	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियाँ
10.	104-जल संसाधन मंत्रालय	5075	01 03 06 11 13 20 43 50	7.41	उत्तर प्रतिक्षित	
योग				**101.25**		

4.6.3 पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली 1990 का नियम 31, अनुबंधित करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित संपत्ति का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

इसके अतरिक्त सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48 में संदर्भित परिशिष्ट 3 का पैरा 4 अनुबंधित करता है कि बजट में कोई एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जहां आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु तुरंत उपाय प्रदान किए जाने हैं अथवा ऐसी परियोजना/योजना जिस पर प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने हेतु एवं वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किए जाने हेतु मूल में स्वीकार किया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली का नियम 8 भी अनुबंधित करता है कि विषय शीर्ष '42 एक मुश्त प्रावधान' का उपयोग, योजनाओं, जिसके प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हों, के संबंध में व्यय को दर्ज करने हेतु किया जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में अवसरंचना परियोजनाओं के लिए दी गयी सहायता को दर्शाने वाले ₹457.55 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसरंचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के रूप में सहायता अनुदान के रूप में, एक समय या आस्थगित, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के प्रति शीर्ष 5475 अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय,12-अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण हेतु सहायता के तहत दर्ज करना उल्लेखित नियमावली के विपरीत था। इस व्यय को उपयुक्त रूप के अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत व्यय हेतु प्राप्त ₹457.55 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो अनुबंधित करते हैं कि एकमुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों के अनुसार विवरण दिया जाना चाहिए।

मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2014-15 के दौरान व्य.अं.वि. के अंतर्गत व्यय को विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया जाएगा। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' पूंजीगत प्रभाग के विषय श्रेणी 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय) के अंतर्गत आता है न कि राजस्व प्रभाग में।

वित्त मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि लेखापरीक्षा का निष्कर्ष गलत है क्योंकि निर्गम पूंजीगत व्यय के लिए था। उसने यह भी बताया कि विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' के अंतर्गत जारी व्यय के मामले में सृजित पूंजी का स्वामित्व सरकार के पास नहीं रहता है क्योंकि इस मामले में अनुदान अवधि की समाप्ति पर स्वामित्व प्रयोजककर्ता को हंस्तारित किया जाएगा।

उत्तर सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 215(3)(1) के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रायोजित परियोजनाओं तथा योजनाओं के वित्तपोषण का व्यवहार करते हुए, जहाँ यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रालय/विभाग परियोजनाओं का वित्तपोषण करते समय एक अनुबंध प्रदान करेगा कि ऐसी निधियों में सृजित अथवा अर्जित भौतिक तथा प्रज्ञात्मक परिसम्पत्तियों में स्वामित्व प्रायोजक का रहेगा।

4.6.4 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है और संगठन के दिन प्रति दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे के साथ-साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने ऐसे कई मामले उद्घटित किये जहाँ राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जो राजस्व व्यय के अधिक बताए जाने/कम बताए जाने तथा ₹310.96 करोड़ तक संघ सरकार के राजस्व घाटे पर भी प्रभाव होने में परिणत हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के बीच गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर
	पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण			
1.	11-वाणिज्य विभाग	29.90	गुना, मध्य प्रदेश, 'फुटवियर डिजाईन एवं विकास संस्थान की शाखा की स्थापना' हेतु फुटवियर डिजाईन एवं विकास संस्थान को जारी राशि को विषय शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत पूंजीगत प्रभाग में प्रावधान/दर्ज किया गया था। इस मामले में सही विषय शीर्ष अनुदान के राजस्व प्रभाग में '35-परिसम्पति सृजन हेतु अनुदान' होना चाहिए था।	वाणिज्य विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है तथा संबंधित प्रशासनिक प्रभाग को 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में आवश्यक सुधार करने हेतु अनुरोध किया जा रहा था।
2.	28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	21.53	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत वायु संयोजकता के प्रति व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण/आर्थिक सहायता को पूरा करने हेतु व्यय को उपयुक्त विषय शीर्ष 33-आर्थिक सहायता के बजाए शीर्ष 4552.00.202.03.00.54 के अंतर्गत प्रावधान/दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2013) बताया कि वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में एक नए लेखा शीर्ष खोला जा रहा था। मंत्रालय ने गलत वर्गीकरण को जानकारी की कमी को आरोपित किया (फरवरी 2014)।
3.	32-आर्थिक कार्य विभाग	24.22	अफ्रीका में 33 उच्च कर्जदार गरीब देशों हेतु बहुपक्षीय ऋण राहत पहलकदमियों (एम.डी.आर.आई.) के प्रति अफ्रीकी विकास निधि (अ.वि.नि.) को भा.स. द्वारा किए गए कुल ₹2.11 करोड़ के अंशदान तथा अ.वि.नि. के प्रति भा.स. द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाले ₹22.11 करोड़ का राजस्व प्रभाग में सही विषय शीर्ष '32-अंशदान' का संचालन करने के बजाए विषय शीर्ष '54-निवेश' के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज/प्रावधान किया गया था। मामला नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1. में भी इंगित किया गया था।	आर्थिक कार्य विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2013-14 हेतु अ.वि.नि. के एम.डी.आर.आई. के प्रति अंशदान के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नया विषय शीर्ष 3466.00.104.01.00.32 स्वीकृत कर दिया गया है। अ.वि.नि. को अंशदान के कारण 2012-13 के दौरान ₹22.11 के संबंध में इसने बताया कि मु.शी. 3466 के अंतर्गत नया विषय शीर्ष खोले जाने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
4.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	59.18	भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय (एक स्वायत्त निकाय) को इसके परिसर के विकास हेतु जारी राशि को अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' में दर्ज करने के बजाए इसे विषय शीर्ष '50- अन्य प्रभारों' के अंतर्गत अनुदान (मुख्य शीर्ष 5052) के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि 2013-14 के दौरान, विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' को मुख्य शीर्ष 3052 के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया गया है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	विभाग का उत्तर
5.	90-अंतरिक्ष विभाग	4.44	अंतरिक्ष विभाग द्वारा कुल ₹4.44 करोड़ के विनिमय परिवर्तन को 'राजस्व प्रभाग' के बजाए 'पूंजीगत प्रभाग' (मु.शी. 5252 विषय शीर्ष 60) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि नई परियोजनाओं को तैयार करने तथा अ.वि.मां. में उपयुक्त प्रावधान करने हेतु, विनिमय दर सहित आयातित मद के प्रापण पर किए गए व्यय पर विचार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनिमय परिवर्तन को राजस्व प्रभाग में अलग से दर्ज किया जाना होता है तथा विनिमय परिवर्तन को शामिल न करते हुए परियोजना पर व्यय को परियोजना शीर्ष के 'पूंजीगत प्रभाग' के अंतर्गत दर्ज किया जाना है।
राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति		**139. 27**		
राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण				
6.	90-अंतरिक्ष विभाग	444.69	अंतरिक्ष विभाग ने अपने आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2007 में स्पष्ट किया कि एक वर्ष से अधिक के जीवन वाले उपग्रहों (ऐसे उपग्रहों हेतु लांच सेवाओं सहित) के मामले में 'आपूर्तियों तथा सामग्रियों' तथा 'अन्य प्रभारों' पर व्यय को 'अन्य पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया जाए। ₹444.69 के व्यय की 'राजस्व प्रभाग' के अंतर्गत विषय शीर्ष '21 आपूर्तियां एवं सामग्रियां' तथा '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था जिसे वर्तमान आदेशों के अनुसार 'पूंजीगत प्रभाग' के अंतर्गत '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए था।	अं.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि इसने अगस्त 2013 में यह बताते हुए एक परिपत्र जारी किया था कि एक वर्ष से अधिक के जीवन वाले वाहनों तथा उपग्रहों के लांच के संबंध में सामग्रियों/संघटकों/बाहरी संरचना पर किए गए व्यय तथा उपग्रहों को लांच करने हेतु बाहरी अभिकरण से प्राप्त लांच सेवाओं पर व्यय को भी '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतगत दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। अं.वि. ने यह भी बताया कि भविष्य में इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
7.		5.54	मशीनरी तथा उपकरण (चार मामले[2]) के अधिग्रहण पर व्यय को पूंजीगत प्रभाग में सही मुख्य शीर्ष तथा विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' में संचालित करने के बजाए विषय शीर्ष '21' के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में वर्गीकृत किया गया था।	अं.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि इसने अगस्त 2013 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' केवल कार्यालय उपकरण के प्रापण तक सीमित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मशीनरी एवं उपकरण के अधिग्रहण पर व्यय को अनुदान के पूंजीगत वर्ग में विषय शीर्ष कोड '52' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
राजस्व व्यय का अधिकथन		**450.23**		
समग्र प्रभावः राजस्व व्यय का ₹310.96 करोड़ तक का अधिकथन				

इस प्रकार का गलत वर्गीकरण जवाबदेही को अप्रभावी कर देता है, और लेखांकन में पारदर्शिता, पूर्णता, समग्रता, स्थिरता तथा तुलनीयता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को

[2] 3402.00.101.01.00.21, 3402.00.101.10.00.21, 3402.00.101.19.00.21, 3402.00.101.09.00.21

विफल कर देता है और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोबारा न हो के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 (2) में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के सिद्धांतों के अनुपालन में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचलन का प्रभाव सरकार के राजस्व घाटे के न्यूनोक्ति अथवा अधिकथन पर होता है।

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹ 698.07 करोड़ तक अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹1781.62 करोड़ तक की न्यूनोक्ति के रूप में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹ 1,083.55 करोड़ के पूंजीगत व्यय न्यूनोक्ति में हुआ। इसी प्रकार वित्त वर्ष के दौरान ₹ 1083.55 करोड़ के बराबर राशि अधिकथन में हुआ।

4.7 अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.7.1 भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे " भारत की समेकित निधि " कहा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) इसके अतिरिक्त प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धनराशियों को भारतीय लोक लेखा में जमा किया जाएगा। इस प्रकार, इसके द्वारा प्राप्त की गई सभी अन्य सार्वजनिक धनराशियों के संबंध में, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार प्राप्त सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है तथा इसमें से संबंधित संवितरण भी किए जाते हैं।

कोयला मंत्रालय की वर्ष 2012-13 हेतु अनुदान सं.10 के संबंध में विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इ.लि.) द्वारा उनकी ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु जमा राशियों को जमा कार्य के रूप में लोक लेखे के माध्यम से लेन-देनों को पारित किए जाने के बजाए कोयला समृद्ध क्षेत्रों के भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के प्रति भारत की समेकित निधि से किए गए पूंजीगत व्यय में कटौती के रूप में माना जा रहा था।

कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 4803.00.800.01.00.54 में ₹309.82 करोड़ का व्यय किया गया था तथा व्यय को को.इ.लि. से प्राप्तियों के साथ पूरा किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को

को.इ.लि. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति प्राप्त किया गया था इसलिए लेन-देनों को भारत की समेकित निधि के माध्यम से पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

आगे यह पाया गया था कि किया गया व्यय ₹309.82 करोड़ था जबकि व्यय की कटौती में लेखे में समायोजित वसूलियां ₹309.85 करोड़ की थी इसलिए ₹0.03 करोड़ का अव्याख्यात अंतर है।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि कोयला समृद्ध क्षेत्रों के संबंध में व्यय को लघु शीर्ष "117-सार्वजनिक निकायों अथवा निजी व्यक्तियों हेतु किए गए कार्यों के लिए जमा" के साथ मु.शी. 8443 सिविल जमा के अंतर्गत दर्ज किए जाने हेतु पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

4.7.2 विषय शीर्ष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों तथा सहायता अनुदान-वेतन का परिचालन न होना

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रभावी '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' तथा 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी 36-सहायता अनुदान वेतन नए शीर्षों का वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के नीचे विषय श्रेणी-4 के अंतर्गत विषय शीर्षों की सूची में प्रारंभ किया।

वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि इन विषय-शीर्षों को कुछ नमूना परीक्षित मंत्रालयों में परिचालित नहीं किया गया था, जबकि वेतन संघटकों के प्रति स्वायत्त निकायों आदि को अनुदान जारी किए गए है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.12: विस्तृत शीर्ष 'सहायता-अनुदान-वेतन' का परिचालन न होना

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
1.	9-नागरिक विमानन मंत्रालय	भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एक स्वायत्त निकाय) को ₹1.88 करोड़ की राशि उनके कर्मचारियों के वेतन हेतु जारी की गई जिसे '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि वर्ष 2013-14 हेतु अ.वि.मां. में संशोधन हेतु आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
2.	12- औद्योगिक नीति एवं प्रौन्नति विभाग	राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (एन.एम.सी.सी.) दिनाँक 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। एन.एम.सी.सी. के स्थापना व्ययों अर्थात् वेतन, समयोपरि भत्ता, चिकित्सा उपचार आदि के प्रति किए गए ₹2.12 करोड़ के व्यय को अनुदान के राजस्व वर्ग में उप-शीर्ष 2852.80.800.19- राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के अंतर्गत विषय श्रेणी 1 (कार्मिक सेवाए तथा लाभ) तथा विषय श्रेणी 2 (प्रशासनिक व्यय) से संबंधित विभिन्न विषय शीर्षों में दर्ज किया गया था। एन.एम.सी.सी. के संबंध में आवंटन/व्यय को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' तथा '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि एन.एम.सी.सी. समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अभी भी स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत नहीं की गई है तथा जैसे ही यह पंजीकृत होती है इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत बजटीय आवंटन प्रदान किया जाएगा। उत्तर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तर्कसंगत नहीं है कि एन.एम.सी.सी. को डी.आई.पी.पी. के आदेश दिनाँक 6 अक्तूबर 2004 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय घोषित किया गया था।

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
3.	18-कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान (भा.का.का.सं.) के वेतनों तथा अन्य स्थापना व्ययों के रूप में संवितरित ₹8 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' तथा '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत व्ययों को अलग-अलग दर्ज करने के बजाए विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान (सामान्य)' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में भा.का.का.सं. के संबंध में विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' खोला जाएगा।
4.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन, भत्तों आदि के भुगतान के प्रति खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.आ.) मुंबई को ₹25.96 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए विषय शीर्ष '20- अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2012-13 हेतु खा.ग्रा.उ.आ. को जारी निधियों में से ₹50.11 करोड़ के कुल व्यय में पेंशन के भुगतान के प्रति ₹38.13 करोड़ तथा या.भ. एवं आकस्मिकताओं के भुगतान के प्रति ₹11.98 करोड़ शामिल थे। 2012-13 के दौरान, पेंशन के भुगतान पर व्यय को दर्ज करने हेतु कोई अलग शीर्ष नहीं था तथा व्यय को "36-सहायता अनुदान वेतन" के बजाए विषय शीर्ष 2851.00.105.05.01.20-अन्य प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत दर्ज किया गया। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मई 2012 के संस्वीकृति आदेश के अनुसार वेतन एवं भत्तों के भुगतानों हेतु ₹25.96 करोड़ की राशि जारी की गई थी जिसे सही प्रकार से विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।
5.		वेतन एवं भत्ते के प्रति महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (म.गां.ग्रा.औ.सं.), वर्धा को ₹1.55 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया था। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि व्यय को योजनागत तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया गया था क्योंकि वर्ष 2012-13 हेतु अ.वि.मां. में 'सहायता अनुदान वेतन' हेतु कोई अलग शीर्ष उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वेतन पर व्यय के प्रति अनुदानों के भुगतानों हेतु प्रावधानों को शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत प्राप्त किया जाना चाहिए था जो अप्रैल 2011 से प्रचालन में है।
6.		मंत्रालय ने वेतन/सी.ई.ए./अ.या.रि./अवकाश नकदीकरण एवं चिकित्सा पूतिपूर्ति आदि के प्रति कॉयर बोर्ड, कोच्चि को ₹1.55 करोड़ की राशि जारी की तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों के संबंध में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी व्यय तथा गैर-वेतन व्यय को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था तथा नियमित कर्मचारियों के वेतन से संबंधित व्यय को विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। यह नियमित कर्मचारियों के वेतनों पर किए गए व्यय तथा सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों पर व्यय के बीच अंतर दर्शाने हेतु किया गया है। मंत्रालय का उत्तर मई 2012 में जारी संस्वीकृति आदेश जिसने विशेष रूप से विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत अनुदान संस्वीकृत की थी, के विपरीत है तथा इसलिए स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि गलत वर्गीकरण को नवंबर 2012 में ठीक कर दिया गया था। फिर भी मंत्रालय का उत्तर ई-लेखा में प्रविष्टियों के विपरीत था ।
7.	88-पोतपरिवहन मंत्रालय	राष्ट्रीय जहाज डिजाईन एवं अनुसंधान केन्द्र (रा.ज.डि.अ.के.) को सहायता के प्रति ₹2.32 करोड़ के व्यय को शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था जिसमें वेतन उद्देश्य हेतु अनुदान भी शामिल था। भा.स.वि. अधिनियम 2008, के प्रावधानों के अनुसार रा.ज.डि.अ.के. को इसकी सभी परिसम्पत्तियों तथा कर्मचारियों सहित भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय में समाहित हो गया था। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2013) कि विश्वविद्यालय को सहायता को बजट अनुमान 2013-14 में 'सहायता अनुदान सामान्य' तथा 'सहायता अनुदान वेतन' में बाँट दिया गया है तथा तदनुसार दर्ज किया गया है।

क्र.स	अनुदान सं. एवं नाम	अभ्युक्तियाँ एवं मंत्रालय के उत्तर
8.	90-अंतरिक्ष विभाग	वर्ष 2012-13 के दौरान '31 सहायता अनुदान सामान्य' एवं '36-सहायता अनुदान' शीर्षों के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग ने अपने स्वायत्त निकायों अर्थात् -राष्ट्रीय वायमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (रा.वा.अ.प्र.), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (पू.अ.अ.के.), भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.अं.प्रौ.सं.) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (भा.अ.प्रो.), अर्ध-चालक प्रयोगशाला (अ.च.प्र.) के प्रति प्रावधान प्राप्त किए तथा अनुदान जारी किए। इन स्वायत्त निकायों ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों को सृजन के प्रति कुल ₹76.73 करोड़ (रा.वा.अ.प्र. ₹5.39 करोड़; भा.अं.प्रौ.सं. ₹60.21 करोड़ तथा अ.च.प्र. ₹11.13 करोड़) का व्यय किया, अंतरिक्ष विभाग ने विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत बजट प्रावधान प्राप्त नहीं किया और तदनुसार वर्ष 2012-13 के लिए विनियोग लेखे में व्यय दर्ज किया। आ.वि. ने उत्तर दिया (जुलाई 2013 कि वर्ष 2013-14 के लिए अ.वि.मां. में प्रावधान कर लिया गया है।
9.	93-कपड़ा मंत्रालय	मंत्रालय ने राज्य सरकारों की प्रवर्तन मशीनरी हेतु वेतन के भुगतान के प्रति किए गए ₹1.25 करोड़ के व्यय को शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के बजाए शीर्ष 3601.01.726.05.00.31- 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि मामले को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में अनुपालना के लिए नोट कर लिया गया है।

4.7.3 अनुदान के समान प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8 छठे स्तर अर्थात, विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिकता इकाई का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले कुछ विषय शीर्ष और व्यय के विवरण **अनुबंध 4.2** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 23 अनुदान/विनियोग में 30 मामलों में कुल ₹2,992.75 करोड़ की निधियाँ विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात विषय शीर्षों में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका निम्न तालिका में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.13: विषय शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
1.	4-परमाणु ऊर्जा विभाग	11.33	3401/50 एवं 34	विभाग विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, सोसाइटियों तथा गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता के अंतर्गत अनुदान प्रदान करता है। तथापि शीर्ष 'सहायता अनुदान' परिचालित करने के स्थान पर व्यय 'अन्य प्रभार' (₹3.64 करोड़) तथा छात्रवृत्ति/वजीफा (₹7.69 करोड़) विषय -शीर्षों के अंतगत दर्ज किया गया था।	(प.उ.वि.) ने बताया (अक्तूबर 2013) कि इन दोनों विषय - शीर्षों, नामतः 'छात्रवृत्ति/वजीफा' तथा 'अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज व्यय की प्रकृति वित्तीय शक्तियों की प्रत्यावर्तन नियमावली के वर्गीकरण के अनुसार थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के लेखे में विश्वविद्यालयों, समितियों आदि को सहायता का वि.श.प्र.नि. के अनुसार शीर्ष सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधान/वर्गीकरण किया जाना चाहिए था तथा न कि 'छात्रवृत्ति/ वजीफा' अथवा 'अन्य प्रभारों' के अंतर्गत

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
2.	6- रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	2.50	2852/31	हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड द्वारा देय ब्याज को '64-बट्टे खाते/ हानियों' के स्थान पर '31-सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 31 मई 2013 को लेन-देन किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि नया विषय शीर्ष '64- बट्टे खाता/हानियां' बना लिया गया है और वर्ष 2013-14 हेतु अनुदान के लिए विस्तृत मांग में मुद्रित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि संशोधन केवल अगले वित्तीय वर्ष के लिए की गई थी।
3.	10-कोयला मंत्रालय	24.21	2230/32	कोयला खान भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक प्रभारों के कारण ₹24.21 करोड़ तथा अन्वेषण, अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के कारण ₹231 करोड़ के व्यय किए गए थे तथा अंशदान के रूप में इनका गलत प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। इन व्ययों को, कोयला एवं लिगनाईट क्षेत्र के प्रति विशिष्ट सहायता होने से, संबंधित विषय शीर्षों के अंतर्गत 'सहायता अनुदान सामान्य' के रूप में सही प्रकार से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि मुख्य शीर्ष 2230 के अंतर्गत व्यय को इसके आरंभ से ही कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है तथा मुख्य शीर्ष 2803 के अंतर्गत व्यय के दर्ज किये जाने को लेखा महा नियंत्रक के परामर्श से ठीक किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि व्यय को मुख्य शीर्ष 2803 के अंतर्गत विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने के कार्य की शुरूआत कर दी गयी है।	
4.		231.00	2803/32			
5.	11-वाणिज्य विभाग	34.00	3453/31	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को ₹34 करोड़ का सहायता-अनुदान '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत कोलकोता परिसर (सिविल कार्य) के निमार्ण पर व्यय को पूरा करने के लिए जारी किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2013) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ नोट कर ली गई हैं और संबंधित प्रशासनिक प्रभाग में 2014-15 हेतु अनुदान की विस्तृत अनुदान हेतु मांग में सुधार करने के लिए भेजा जा रहा है।	
6.	12-औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग	2.56	2070/50	विषय शीर्ष 50-अन्य प्रभार में दर्ज ₹2.56 करोड़ के व्यय में से ₹1.33 करोड़ राशि का व्यय विभिन्न सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्यों के प्रति किया गया था, जिसे सही रूप में शीर्ष '27 प्रमुख निर्माण कार्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि सिविल निर्माण कार्यों को प्रति किया गया ₹1.33 करोड़ का व्यय, योजना "पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा उन्नयन संगठन पे.वि.सु.उ.सं." से संबंधित है तथा इसे '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया गया था क्योंकि 'लघु निर्माण कार्यों' के अंतर्गत पे.वि.सु.सं. को आवंटित बजट केवल गैर-आयोजन गतिविधियों के लिए ही है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यय का वर्गीकरण वि.श.प्र.नि. के अनुरूप होना चाहिए जो व्यय को योजनागत तथा गैर-योजनागत के आधार पर अलग नहीं करती है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
7.	13-डाक विभाग	8.00	3201/32	डाक सेवा कर्मचारी कल्याण निधि को संवितरित सहायता अनुदान सही वि.शी. '31-सहायता अनुदान सामान्य' अथवा '36-सहायता अनुदान वेतन' के स्थान पर वि.शी. 32 के अंतर्गत दर्ज था।	डाक विभाग ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि टिप्पणियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।	इन मामलों को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 में इंगित किया गया था परंतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई थी।
8.		6.02	3201/50	यूनिवर्सल डाक यूनियन को किए गए अंशदान को सही विषय शीर्ष 32-अंशदान के स्थान पर गलत रूप से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।		
9.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	0.05	3425/ 2552/ 3475 वि.शी.- 52	₹0.05 करोड़ के व्यय को राजस्व मुख्य शीर्ष सहित पूंजीगत प्रकृति की विषय श्रेणी 6 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। आगे यह प्रकट हुआ था कि व्यय भार एवं माप पर अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को सहायता से संबंधित था जिसे सही प्रकार से सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि 2007-08 के पूर्व तक ये निधियां राज्यों की 'सहायता-अनुदान' के रूप में जारी होती थीं। 2007-08 से, विभाग ने केन्द्रीकृत रूप से मशीनों एवं उपकरणों के खरीद एवं उन्हें राज्यों/के.शा.क्षे. तक सीधे आपूर्ति करने का निर्णय लिया तथा प्रावधान की पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत मांग की गई थी। तथापि, इन्हें वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व व्यय में बदल दिया गया था। विभाग ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि जब भी ई.एफ.सी. तथा इसके दिशानिर्देश संशोधित किए जाएगें तथा राज्यों से सलाह प्राप्त की जाएगी 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।	विभाग का उत्तर (नवम्बर 2013) इस तथ्य के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं है कि किसी प्रकार में सहायता पर व्यय उपयुक्त मुख्य शीर्ष के नीचे 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत करने योग्य है।
10.	18- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	26.93	3451/50	आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर किये गये ₹26.93 करोड़ का व्यय दर्ज किया था गतिविधियां सेवा वितरण परियोजना की घटक थीं जिससे सेवा प्रदाता को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं नेटवर्किंग पर अग्रिम निवेश करना तथा सेवा प्रदान करना आवश्यक होता है, इसलिए मंत्रालय को व्यय को पृथक कर उन्हें विषय शीर्षों '13-कार्यालय व्यय' एवं '28-व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत वर्गीकृत करना चाहिए।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब में बताया (नवम्बर, 2013) कि अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और-संबंधित अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते ही प्रदान कर दी जाएगी।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
11.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1363.56	4047/54	'पोतों, वायुयानों एवं बेड़ों के अधिग्रहण' से संबंधित व्यय को सही प्रकार से '54-निवेश' के स्थान पर '52-मशीनें एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	उत्तर प्रतीक्षित	इस मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था परंतु मंत्रालय द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई थी।
12.	44- विनिवेश विभाग	1.13	3451/28	₹12.10 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष '28 व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया था, जिसमें से ₹1.13 करोड़ विज्ञापन पर खर्च किया गया था जिसे मौजूदा नियमावली के अनुसार विषय शीर्ष '26-विज्ञापन एवं प्रचार' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त, 2013) कि इसके पास विज्ञापन एवं प्रचार हेतु कोई अलग विषय -शीर्ष नहीं है और विनिवेश से संबंधित विज्ञापन एवं प्रचार पर किया गया सारा व्यय विषय शीर्ष 28-व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उसने यह भी बताया (अक्तूबर, 2013) कि विज्ञापन एवं प्रचार से संबंधित व्यय को सही शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।	
13.	53-मंत्रिमंडल	310.38	12	व्यय, वायुयानों गृह के अनुरक्षण पर किया गया था, पर उसे विदेश यात्रा व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति वायुयान अनुरक्षण की है और वह '12-वि.या.व्य.' के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं है और उसे सही शीर्ष, '50 अन्य प्रभार' के अंतर्गत वर्गीकृत करना सही प्रतीत होता है।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि एक नया शीर्ष 2013.00.108.01.12, वी.वी.आई.पी. यात्रा हेतु प्रयुक्त वायुयानों के अनुरक्षण लागत के प्रति भुगतानों को विशेषकर दर्ज करने के लिए खोला गया है। आगे, मार्च 2014 में मंत्रालय ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना में ऐसे व्यय को दर्ज करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अलग विषय शीर्ष '50' खोला गया है।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि '12-विदेश यात्रा' व्यय वायुयानों के अनुरक्षण संबंधित व्यय को दर्ज करने हेतु सही विषय शीर्ष नहीं है।
14.	54-पुलिस	77.50	2055/52	व्यय कम्प्यूटरों आदि की खरीद पर किया गया था तथा अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष '52-मशीनें एवं उपकरण' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व लेखे से संबंधित उचित विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया ((सितम्बर, 2013) कि बजट नियंत्रक प्राधिकारों को व्यय को उचित विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के लिए परामर्श जारी कर दिया गया है।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
15.	57-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	11.33	3475, 2215/31	मंत्रालय ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.), नई दिल्ली को मिजोरम में झुग्गी क्षेत्र के निर्माण-कार्य एवं असम में बाजार परिसर के निर्माण हेतु ₹11.33 करोड़ जारी किया था। पूरी राशि विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर विषय शीर्ष '31-सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज की गयी थी।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि निधियां सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु थीं। यह भी बताया गया कि सभी संबंधितों को निधियों को चिन्हित करने और लेखा के उचित शीर्ष के अंतर्गत व्यय के निर्गम के लिए, अनुरोध किया जा चुका है।	
16.		50.00	2217/32	मंत्रालय ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत ऋण जोखिम गारंटी कोष न्यास (ऋ.जो.गां.को.न्या.) की स्थापना हेतु ₹50 करोड़ का व्यय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के स्थान पर शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया था।	मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि ऋ.जो.गां.को.न्या. को बैंकों से ऋण ले रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा न्यून आय समूह की ओर से गारंटी प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था। ऋ.जो.गां.को.न्या. का प्रस्तावित कॉर्पस ₹1000 करोड़ है। कॉर्पस हेतु ₹50 करोड़ के व्यय को 2012-13 हेतु अनुपूरक के प्रथम बैच में संसद की स्वीकृति के पश्चात तथा वित्त मंत्रालय तथा ले.म.नि. की सहमति से विषय शीर्ष अंशदान में दर्ज किया गया था।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि यद्यपि शीर्ष संसद के अनुमोदन से सृजित किये गये थे, उपयुक्त व्यय वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली के अनुसार विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।
17.	63-विधि एवं न्याय मंत्रालय	708.18	3601 3602/31	विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय भवन, न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों हेतु रिहायशी आवास के निर्माण हेतु अनुदान दिऐ गऐ थे और उचित वि.शी. 35 के स्थान पर वि.शी. 31 के अंतर्गत दर्ज किये गये थे।	मंत्रालय नें बताया (जनवरी 2014) कि जुलाई 2010 में एक विशाल अग्नि के कारण, नये विषय शीर्षों के सृजन से संबंधित फाइलों के साथ लगभग सभी अभिलेख नष्ट हो गये थे। बाद के वर्षों में शीर्ष नहीं खोले गये क्योंकि वित्त मंत्रालय अथवा लेखापरीक्षा में से किसी को भी आपत्ति नहीं थी। यह भी बताया गया कि नये बजट शीर्ष संसद के अनुमोदन के पश्चात खोले जाएगें।	
18.	68-नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	0.39	2810/52	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर व्यय का वर्गीकरण विषय शीर्ष 'मशीनें एवं उपकरण' के अंतर्गत किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
19.	69-प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय	11.25	2061/50	भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद तथा प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र को प्रदत्त अनुदान सही विषय शीर्ष, अर्थात 31 या 36 के अंतर्गत दर्ज किये जाने के स्थान पर '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि वर्ष 2012-13 में विषय शीर्ष 36 के अंतर्गत कोई अलग बजट आवंटन नहीं हुआ था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' अप्रैल 2011 से प्रचालन में है।
20.	73-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	0.76	3451/28	अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच सचिवालय, सऊदी अरब में भारत के सदस्यता शुल्क के प्रति व्यय को '32-अंशदान' के स्थान पर '28-व्यावसायिक सेवा' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया था।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि शीर्ष 3451.090.10.01 के नीचे विषय-शीर्ष-32-अंशदान को खोलने के मामले को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया है।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अनुदान के उसी भाग में गलत वर्गीकरण हुआ था तथा वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो चुका है।
21.	90-अंतरिक्ष विभाग	42.89	3402/21	श्रम शक्ति अनुबंधों के द्वारा व्यावसायिक श्रम शक्ति सेवाओं की भर्ती पर किये गये व्यय (पाँच अलग उपशीर्षों के अंतर्गत) को विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	अं.वि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2013) कि यह 'राजस्व' तथा 'पूंजीगत' खंड के अंतर्गत विभिन्न व्ययों की बुकिंग को देखने के लिए एक समिति गठित करना प्रक्रिया में है।	
22.		30.70	5402/52	हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड के निर्माण केन्द्र में सुविधाओं के संवर्धन पर सिविल निर्माण कार्य के प्रति हुआ ₹30.70 करोड़ का व्यय मुख्य निर्माण कार्य (53) के स्थान पर विषय शीर्ष मशीनें एवं उपकरण (52) के अंतर्गत दर्ज किया गया।	अं.वि. ने मार्च 2014 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।	
23.	91- सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वन मंत्रालय	3.59	3454/52	व्यय, कम्प्यूटर आदि की खरीद पर किया गया था तथा अनुदान के राजस्व खंड के अंतर्गत विषय शीर्ष 52 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस व्यय को राजस्व लेखे से संबंधित सही विषय शीर्षें में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि संबंधित प्रभागों को भविष्य में बुकिंग को ठीक करने का निर्देश किया गया है। मंत्रालय द्वारा जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014 में यह फिर से दुहराया गया था।	
24.	93-वस्त्र मंत्रालय	10.00	2852/31	₹19.84 करोड़ के व्यय में से ₹10.00 करोड़ की राशि मैसर्स आई.टी.आई.लि. को वर्ष 2012-13 के दौरान राय बरेली, उत्तर प्रदेश में रा.फै.त.सं. में प्रशिक्षण केन्द्र एवं छात्रावास के निर्माण हेतु जारी की गयी थी और विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के स्थान पर विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अ.वि.मां. में अपेक्षित विषय शीर्ष को संबोधित प्रशासनिक प्रभागों के परामर्श से सृजित किया जाएगा।	मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि यह 2012-13 के दौरान अनुदान के उसी खंड के अंदर गलत वर्गीकरण है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
25.	93- वस्त्र मंत्रालय	2.63	2851/50	मंत्रालय ने ₹5.77 करोड़ का व्यय किया और उसे '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें से ₹2.63 करोड़ राशि के आवर्ती सहायता-अनुदान (योजना) के प्रति हुए व्यय को '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (नवम्बर, 2013) कि वर्ष 2013-14 से वस्त्रोद्योग अनुसंधान संघ/ के.एस. पी.डी.सी./राज्य सरकार द्वारा परिचालित विद्युत करघों सेवा केन्द्रों का परिचालन व्यय '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा था।	
26.	94- पर्यटन मंत्रालय	11.70	3452/50	₹12.99 करोड़ के व्यय में से ₹11.70 करोड़ की राशि का यू.पी.एस., प्रिन्टरों, कम्प्यूटरों, सॉफ्टवेयर की खरीद, गत्यात्मक वेब पोर्टल के विकास, डिजाइन, पर्यटन मंत्रालय के हिन्दी बेबसाइट के विकास एवं होस्टिंग, सार्वभौम ऑनलाइन प्रचार 2011-12 की अदायगी आदि पर व्यय किया गया था और उसे '13-कार्यालय व्यय' के स्थान पर '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि 'कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी' की योजना, जिसके लिए मुख्य शीर्षों 3452 एवं 3601/3602 के अंतर्गत बजटीय प्रावधान, प्रदान किए गए है, मूल्यांकन के अधीन है एवं आगामी वित्तीय वर्ष से खरीद करने की प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी।	
27.	101-शहरी विकास विभाग	0.39	2217/20	विभाग ने ₹54.30 लाख का व्यय किया तथा इसे '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें से ₹38.44 लाख को कार्यक्रम प्रबंधन के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्शदाताओं की निगरानी हेतु किये गये व्यय को '28-व्यावसायिक सेवाओ' के स्थान पर विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर, 2013) कि कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभाग को व्यय को सही विषय शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के साथ नए विषय शीर्ष के सृजन, यदि ऐसा वांछित/आवश्यक समझा जाए, हेतु प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण हेतु लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों से अवगत कर दिया गया है।	व्यय का प्रावधान करना तथा दर्ज करना वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के अनुसार होना चाहिए।
28.		0.33	2052/50	विभाग ने ₹1.60 करोड़ का व्यय किया और इसे विषय-शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया था। इसमें से ₹31.54 लाख का व्यय समाचार पत्रों आदि की आपूर्ति लागत के कारण तथा बैठकों में मनोरंजन के प्रबंध पर हुए ₹1.79 लाख को '13 कार्यालय व्यय' एवं '20 अन्य प्रशासनिक व्ययों' के स्थान पर इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।		

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य/ विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	उत्तर	टिप्पणियाँ
29.	102-लोक निर्माण कार्य विभाग	6.17	2059/53	गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु प्रबंध करने पर किये गये व्यय को विषय शीर्ष '27-लघु निर्माण कार्य', जिसमें निमार्ण कार्य, मशीने एवं उपकरण की मरम्मतों एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय भी शामिल है, के बजाए '53-मुख्य निर्माण कार्य' इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2013) कि निर्माण-कार्य, अस्थायी संरचना (सलामी मंच) के लिए होता है एवं आयोजन की समाप्ति के पश्चात इन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है। यह नियमावली में परिभाषित 'मुख्य निर्माण कार्य' के रूढ़ अर्थ का एक अपवाद है।	मंत्रालय का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय को दर्ज किया जाना वित्तीय शाक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के अनुसार होना चाहिए।
30.		3.27	2059/50	कम्प्यूटरीकरण की योजना से संबंधित व्यय को '50 अन्य प्रभारों' के बजाए '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।	शहरी विकास मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकारते हुए बताया (सितम्बर, 2013) कि वर्ष 2013-14 से कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत प्रावधानों को 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत चिन्हित कर दिया गया है।	तथ्य यह रहता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान के राजस्व खंड में गलत वर्गीकरण हुआ था।
	कुल	2992.75				

4.7.4 'अन्य देशों को सहायता को दर्ज करने हेतु विषय शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8, व्यय के सही वर्गीकरण उद्देश्य हेतु विवरण/परिभाषाओं सहित विनियोग की प्राथमिक इकाइयों, को निर्धारित करता है। किसी भी निकाय/प्राधिकरण को संवितरण सहायता अनुदान को विषय शीर्षों 31 (सहायता-अनुदान-सामान्य), 35 (पूंजीगत परिसंपत्तयों के सृजन हेतु अनुदान), 36 (सहायता-अनुदान-वेतन), के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर हुए व्यय का वर्गीकरण (32-अंशदान) के अंतर्गत किया जाता है।

विनियोग लेखे एवं अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नि.म.ले.प. की वित्त-वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 हेतु संघ सरकार लेखे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रमशः पैरा 2.12 एवं पैरा 4.4.4 तथा वर्ष 2011-12 संघ सरकार लेखे पर 2013 की प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.19 में इंगित करने के वाबजूद नौ मामलों में ₹1,516.65 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, को गलत रूप से दर्ज किया गया तथा विनियोग की प्राथमिक इकाई पर विषय शीर्ष '32-अंशदान' अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति विदेश सरकारों को सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों की थी, इसे विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत सही से दर्ज किया जाना था।

तालिका: 4.14 विदेशी सरकारों को प्रदत्त अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण	व्यय
1.	3605.00.101.09.00.32	बंग्लादेश को सहायता	279.73
2.	3605.00.101.11.00.32	नेपाल को सहायता कार्यक्रम	292.08
3.	3605.00.101.13.00.32	मालदीव को सहायता	16.43
4.	3605.00.101.14.00.32	म्यांमार को सहायता	121.11
5.	3605.00.101.15.00.32	अन्य विकासशील देशों को सहायता	25.37
6.	3605.00.101.20.00.32	अफ्रीकी देशों को सहायता	232.89
7.	3605.00.101.25.00.32	मध्य एशिया को सहायता	32.66
8.	3605.00.101.32.00.32	लैटिन अमरीकी देशों को सहायता	27.61
9.	3605.00.101.33.00.32	अफगानिस्तान को सहायता	488.77
कुल			**1,516.65**

यह ध्यान देने योग्य है कि मंत्रालय ने मंगोलिया को सहायता के कारण ₹0.75 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत सही प्रकार से दर्ज किया था जबकि उपरोक्त नौ मामलों में मंत्रालय ने ₹1,516.65 करोड़ के व्यय को गलत प्रकार से विषय शीर्ष '32-अंशदान' को दर्ज किया।

मंत्रालय ने नि.म.ले.प. के संघ सरकार लेखे पर वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 4.19 के अपने उत्तर में बताया कि मुख्य शीर्ष 3605 में जिस विषय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त किये गये, वे वही थे जो 2010-11 में मौजूद थे। वि.श.प्र.नि. के अनुसार विषय शीर्ष 'अंशदान', 'अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सहायता पर व्यय को सम्मिलित करने वाले' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कोई संपूर्ण परिभाषा नहीं है बल्कि केवल एक समावेशी परिभाषा है। सा.वि.नि. का नियम 206 निर्धारित करता है कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में सहायता-अनुदान एक व्यक्ति अथवा एक सार्वजनिक निकाय अथवा एक ऐसे संस्थान को दिया जा सकता है जिसकी एक पृथक वैध इकाई हो। इस प्रकार, छात्रवृत्ति सहित सहायता-अनुदान, वि.श.प्र.नि. के अंतर्गत ऐसा करने में सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्वायत्त संगठनों, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का आयोजन करने वाले स्वैच्छिक संगठन अथवा गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिणिक अथवा अन्य संस्थानों के छात्रों को वजीफे एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासी संगठनों, सहकारी समितियों एवं समितियों अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा मनोरंजक कार्यों द्वारा अपने आप में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों का प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित कल्पों को संस्वीकृत किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, विदेशी सरकारों को परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता विषय शीर्ष 'सहायता-अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है।

मंत्रालय का तर्क कि विदेशी सरकार को प्रदान सहायता समान्य वित्तीय नियमावली 2005 (सा.वि.नि.) के नियम 206 के अनुसार विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है, इस दृष्टांत से गलत है कि सा.वि.नि. का नियम 211(2) बताता है कि एक 'विदेशी राज्य' किसी भी अनुदान तथा अथवा कर्जे हेतु पात्र है। इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा कार्य 'अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग' तथा कार्यक्रम 'अन्य देशों के साथ सहयोग' के तहत योजना 'विदेशी सरकारों को सहायता अनुदान' के अंतर्गत विदेशी सरकारों को प्रदान किए जाने वाली सहायता अनुदान/सहायता हेतु बजटीय प्रावधान को विनियोग की अपयुक्त प्राथमिकता इकाई के अंतर्गत प्राप्त किया जाना तथा तदनुसार व्यय को लेखाओं में दर्ज किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.19 के संबंध में प्रस्तुत अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए बताया (अप्रैल 2014) कि अगर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते है तो किसी भी कारण से ऐसे सहायता अनुदान शीर्षों के अंतर्गत किसी भी संवर्धन को पूर्व संसदीय स्वीकृति अपेक्षित होगी जो कि एक उपयोगी हल नहीं होगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विदेशी सरकार को सहायता को 'सहायता अनुदान' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप सहायता अनुदान में कोई भी संवर्धन यदि अपेक्षित हो, को वर्तमान निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

4.7.5 लेखा के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का दर्ज किया जाना

जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राज्य जनजाति उप-योजना में योगदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) प्रदान किया गया है। जबकि, 'जनजाति क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखा विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796-जनजाति क्षेत्र उप योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना आपेक्षित है, एक पृथक लघु शीर्ष कोड अर्थात 794, को लेखे की मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची को निर्देश में 'जनजाति उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने के उद्देश्य हेतु उदृष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा ₹852.54 करोड़ की राशि वर्ष 2012-13 में 'जनजाति उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं इसे अनुदान सं. 95-जनजाति कार्य मंत्रालय में लेखा के लघु शीर्ष '796 के जनजाति क्षेत्र उप-योजना' अंतर्गत दर्ज किया गया था। तथापि, उसे लघु शीर्ष '794 जनजाति उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत प्रावधान एवं दर्ज करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वे.ले.का. ने बताया (अक्तूबर 2013) कि सही शीर्ष का वित्त वर्ष 2014-15 से डेबिट किया जाएगा।

4.7.6 अनुदानों की विस्तृत मांगों में गलत कोड शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान करना

लेखाओं की मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में वर्गीकरण कोड तथा उनकी नामावली, का विवरण शामिल है तथा संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा मानकीकृत करने हेतु लघु शीर्ष स्तरों को प्रयोग में लाया जाना होता है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी सिविल अनुदान सं. 20 में ₹15.35 करोड़ प्रावधान को प्राप्त किया तथा कार्यालय भवन पर व्यय को गलत प्रकार से मुख्य शीर्ष '4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय' उप-मुख्य शीर्ष '60-कार्यालय भवन' के अंतर्गत दर्ज किया। लेखे की मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची के अनुसार मुख्य शीर्ष '4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय', उप-मुख्य शीर्ष '01-कार्यालय भवन' सही कोड शीर्ष है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि "कार्यालय भवन" हेतु उप-मुख्य शीर्ष वित्तीय वर्ष 2001-02 से अनुदानों की विस्तृत मांगों में तथा र.ले.म.नि. द्वारा तैयार तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 से ले.म.नि., वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत र.म.(सिविल) के शीर्ष-वार विनियोग लेखे में भी '60-कार्यालय भवन' के रूप में प्रकट हो रहा है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। सामान्य वित्तीय नियमावली अनुबंधित करती है कि व्यय अनुमानों को सही तथा पूरे लेखा वर्गीकरण के साथ तैयार किया जाना चाहिए तथा किसी भी संदेह के मामले में, इसे पहले ही वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग/ले.म.नि. से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4.7.7 लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 72 अनुबंधित करता है कि सरकारी लेन देनों के वर्गीकरण सामान्य नियम के अनुसार सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से घनिष्ठतः जुड़े होने चाहिए, न कि उस विभाग विशेष से जहाँ व्यय हुआ था। लेखे के मुख्य शीर्ष आमतौर पर सरकार के कार्यों के सदृश होते हैं जबकि लघु शीर्ष कार्यों क उद्देश्यों का प्राप्त किए जाने हेतु कार्यक्रमों की पहचान करते हैं।

वर्ष 2012-13 हेतु पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदान सं. 88 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से उजागर हुआ कि बांग्लादेश सरकार को, दो नदी मार्गों की सफाई एवं संचालन सहित अनुरक्षण हेतु ₹6.89 करोड़ की राशि अदा की गई थी तथा व्यय को गलत प्रकार से लघु शीर्ष 3605.00.101-अन्य देशों के साथ सहयोग के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

लेखाओं को मुख्य तथा लघु शर्षों की सूची में शामिल टिप्पणी के अनुसार, यह लघु शीर्ष अन्य देशों तथा स.रा. कार्यक्रमों को सामान्य सहायता पर व्यय को दर्ज करने के लिए है। विशिष्ट उद्देश्य हेतु व्यय को, लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में सम्मिलित सामान्य निर्देशें के अनुसार, लघु 798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत क्रियात्मक शीर्ष को दर्ज किया जाना अपेक्षित है। चूंकि वर्तमान मामले में किया गया व्यय विशिष्ट उद्देश्य के लिए था इसलिए इसे लघु शीर्ष '798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था।

प्रधान मु.ले.नि. ने बताया (नवम्बर,2013) कि ब.अ. 2013-14 में बांग्लादेश को सहायता हेतु मुख्य शीर्ष '3056' में प्रावधान किया गया है। लघु शीर्ष को '101' से बदलकर '798' करने के लिए एक शुद्धि-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।

4.7.8 गृह मंत्रालय में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गलत बुकिंग जारी रहना

वित्त मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, जब तक स्पष्ट रूप से ऐसा करने से छूट न दी गयी हो, सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके आवंटन का 10 प्रतिशत 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम' में परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान करना आवश्यक है। 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम' के विकास हेतु निधियो का मुख्य शीर्षों '2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र' '4552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय' तथा '6552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु ऋण' के अंतर्गत प्रावधान किया जाना चाहिए। बजट की स्वीकृति के पश्चात इन निधियों का बाद में व्यय करने के आशय से लेखों के कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक द्वारा मार्च 2012 में जारी निर्देशों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों हेतु नियत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत किसी भी खर्च को सीधे-दर्ज नहीं किया जाना था।

वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान सं. 54-पुलिस की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत ₹455.80 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

तालिका 4.15: गैर कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत व्यय दर्ज करना

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	प्रावधान	व्यय
4552.00.129.01 आवासीय भवन	265.00	251.68
4552.00.129.02 कार्यालय भवन	200.00	70.01
4552.00.130.01 आवासीय भवन	12.00	9.40
4552.00.130.02 कार्यालय भवन	69.98	47.66
4552.00.131.01 आवासीय भवन	25.02	17.21
4552.00.131.02 कार्यालय भवन	258.00	59.84
कुल		**455.80**

गैर क्रियात्मक शीर्ष में व्यय का दर्ज किया जाना वर्तमान अनुदेशों अनुसार अप्राधिकृत था। इस मुद्दे पर नि.म.ले.प. के संघ लेखे के प्रतिवेदनों में विगत दो वर्षों तक लगातार

टिप्पणी की गयी है, परंतु या तो विभाग या फिर ले.म.नि. द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गयी है।

4.7.9 लेखे के गलत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990 एवं मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची अनुबंधित करती है कि राज्यों को केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत एवं राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के अंतर्गत जारी किया गया सहायता-अनुदान एवं ऋणों को मुख्य शीर्ष '3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान' तथा '7601-राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना होता है।

अनुदान सं.17-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंधित विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि राज्य सरकारों द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खाद्य भण्डारण गोदामों के निर्माण हेतु ₹9.00 करोड़ का बजट उप-शीर्ष 2552.00.308.02 के अंतर्गत प्राप्त किया गया था। इस प्रावधान का अनुदान हेतु अनुपूरक मांग (₹1.00 करोड़) द्वारा ₹10.00 करोड़ तक संवर्धन किया गया था। चूंकि मुख्य शीर्ष 2552-एक गैर-कार्यात्मक शीर्ष है, ₹10.00 करोड़ का समूचा प्रावधान, किसी मूल प्रावधान के बिना ही कार्यात्मक शीर्ष (2408.02.800.03) का पुनर्विनियोजन किया गया था।

लेखे का सही शीर्ष, जिसमें राशि का पुनर्विनियोजन किया जाना था, मुख्य शीर्ष '3601' होना चाहिए था। अतः ₹10.00 करोड़ की राशि लेखे के गलत शीर्ष के अंतर्गत गलत रूप में वर्गीकृत की गयी थी।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि यह कार्यात्मक शीर्ष वित्त वर्ष 2006-07 से ही परिचालित किया जा रहा है, जिसे उस समय गलती से सही नहीं किया जा सकता था। त्रुटि को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा था।

4.7.10 अनुपलब्ध विषय शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.), 1978 का नियम 8 व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु उनके वर्णनों/परिभाषाओं के साथ विनियोग के मानक प्राथमिकता इकाइयों को निर्धारित करता है।

रक्षा मंत्रालय (सिविल) से संबंधित अनुदान सं. 20 की जांच से उद्घटित हुआ कि कुल ₹853.24 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष '00' (मुख्य शीर्ष 2055 के साथ) के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो ई-लेखा पोर्टल का डिफाल्ट विषय शीर्ष निर्धारित है और वि.श.प्र.नि., नियम 8 के अंतर्गत वर्णित नहीं है।

म.नि.र.ले. ने बताया (सितम्बर 2013) कि 2012-13 के दौरान ₹853.24 करोड़ की बुकिंग जम्मू एवं कश्मीर लाईट इंफेंटरी (ज.क.ला.इ.) हेतु लेखे शीर्ष 2055.104.02.00.00 अंतर्गत दर्ज की गई थी क्योंकि विषय शीर्ष राजस्व पुस्तिका, ऋण एवं प्रेषण (रा.ऋ.प्रे.) शीर्ष के अनुसार नहीं खोला गया था तथापि, ज.क.ला.ई. को, रा.ऋ.प्रे. पुस्तिका में संशोधन करने का अधिकार है इसलिए इसमें संशोधन आरंभ करने के लिए निर्देश दिया जा रहा था।

4.8 अंतरिक्ष विभाग द्वारा पूर्व-प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58 (2) के अनुसार संवितरण अधिकारी द्वारा यदि किसी दावे को स्वीकार करने से, आवंटन या विनियोग से राशि अधिक बढ़ जाती है तो वह भुगतान को प्राधिकृत करने से पूर्व प्रशासनिक प्राधिकारी से आदेश लेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी पुनर्विनियोग के द्वारा अथवा अनुपूरक अनुदान द्वारा अथवा आकस्मिक निधि से अग्रिम लेकर निधियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

वर्ष 2012-13 हेतु समेकित मासिक लेखाओं/ई-लेखा डाटा को संवीक्षा ने प्रकट किया कि वास्तविक व्यय उपलब्ध प्रावधान से निम्नलिखित शीर्षों में ₹4.15 करोड़ तक अधिक हो गया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है तथा व्यय करने से पहले निधियां प्रदान करने हेतु कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए गए थे।

तालिका 4.16: पूर्व प्राधिकरण के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	कार्यक्रम	बजट	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5=4-3
340200101040027	पी.एस.एल.पी.सी.	0.15	0.64	0.49
340200101460013	ई.ओ.एन.एम.	0.6	0.82	0.22
340200101460028	ई.ओ.एस.एम.	0.15	0.22	0.07
340200101470050	सरल	0.07	0.11	0.04
340200102120020	आई.आई.आर.एस.	0.06	0.27	0.21
340200102120027	आई.आई.आर.एस.	2.6	3.12	0.52
345100090180014	डी.ओ.एस.	0.01	0.02	0.01
540200101200052	पी.एस.एल.वी.सी.	3.75	6.33	2.58
340200102110012	एन.आर.एस.सी.	0.15	0.16	0.01
कुल		**7.54**	**11.69**	**4.15**

4.9 अंतरिक्ष विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश जारी करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 के साथ पठित परिशिष्ट 3 तथा 4 में एक संगठन द्वारा विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 25(1) में आदेश हैं कि व्यय की सभी संस्वीकृतियों

में, संबंधित अनुदान या विनियोजन जहाँ से इस प्रकार का व्यय किया जाना है, में प्रावधानों के विवरण दर्शाए जाएंगे।

अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग के विनियोग लेखे की जांच से प्रकट हुआ कि जैसे कि संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभागों में प्रचलित पद्धति है, अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में व्यय के अनुमान, योजनागत और गैर योजनागत व्यय के लिए राजस्व तथा पूंजीगत लेखे पर पृथक रूप से विषय शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित तैयार किए गए थे। तथापि, व्यय करने का प्राधिकार देने वाले अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश, राजस्व तथा पूंजीगत लेखे के अंतर्गत योजनागत तथा गैर योजनागत तथा राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में डेबिट की जाने वाली व्यय की राशि को अलग-अलग निर्दिष्ट नहीं करते हैं। संस्वीकृति आदेश वर्गीकरण के छठे स्तर तक पूर्ण निर्देश देने की बजाय केवल उपशीर्ष स्तर अर्थात वर्गीकरण के चौथे स्तर तक वर्गीकरण किए जाने वाले व्यय की राशि को निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार, अंतरिक्ष विभाग में प्राधिकारियों द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि ये व्यय की उचित बुकिंग तथा वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं देते।

संस्वीकृति आदेशों में वर्गीकरण के ब्यौरों के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में छठे स्तर तक वर्गीकरण दर्शाते हुए लेखे किस प्रकार तैयार करके संकलित किए गए हैं।

इस मामले पर वर्ष 2010-11 के लेखाओं पर भी वर्ष 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा सं. 4.5.3 एवं 2013 हेतु प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.25 के रूप में टिप्पणी की गई थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई दृष्टिगोचर कार्रवाई नहीं की गई।

अंतरिक्ष विभाग ने अपने पहले के उत्तर को दुहाराते हुए (जुलाई 2013) उत्तर दिया कि चूंकि समस्त परियोजना व्यय को लम्बी अवधि के लिए एक सम्पूर्ण योजना के रूप में समझा गया, परियोजना संस्वीकृति आदेश चौथे स्तर तक जारी किए गये हैं तथा प्रारम्भिक स्तर पर विषय शीर्षों के प्रति आवंटन का पता नहीं लगाया जा सकता तथा इसलिए संस्वीकृति आदेशों को उपशीर्ष स्तर तक जारी किया गया था।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में अंतर्विष्ट प्रावधान पर विचार करते हुए विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। चूंकि संसद अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के विषय शीर्ष स्तर तक व्यय के अनुमानों का अनुमोदन करती है, व्यय करने के लिए जारी संस्वीकृति आदेशों में संबंधित अनुदान या विनियोग जहां से विषय-शीर्षों तक ऐसा व्यय किया जाना होता है, के संबंध में वर्गीकरण के ब्यौरे दर्शाए जाने चाहिए।

4.10 एकमुस्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातिय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी

योजनाएं इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए है। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, दोनों भौतिक तथा वित्तीय प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (अ.जा.उ.यो.) तथा जनजातीय उप योजना (ज.उ.यो.) हेतु आवंटनों को तैयार करने हेतु की पहलकदमियां गई थी। सरकार ने समर्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित प्रथम रूप से प्रावधान प्राप्त किए गए हैं। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, अ.जा.उ.यो. तथा ज.उ.यो. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उसी शीर्ष को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है जिससे विपथन की किसी भी संभावना से बचा जाता है।

पांच अनुदानों की वर्ष 2012-13 हेतु अनुदानों की विस्तृत मांगों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सामान्य संघटक; अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक; तथा जनजाति क्षेत्र उप-योजना संघटक हेतु अलग तथा पृथक बजट सीमांए विद्यमान है जिसके लिए संसदीय प्राधिकरण प्राप्त किए गए थे। वर्ष के दौरान, इन योजनाओं/संघटकों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करते समय एक मुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए थे तथा उन्हें तीनों संघटकों में संवितरित किया गया था। चूंकि सभी तीनों योजनाओं में विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' वर्गीकरण के अंतिम स्तर तक शामिल है इसलिए वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस शीर्ष के प्रावधान का संवर्धन, नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमा को आकर्षित करता है। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों को एक मुश्त अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के बजाए तीनों योजनाओं के अंतर्गत अलग से राशि विशिष्ट अनुपूरक अनुदान प्राप्त करनी चाहिए थी।

निम्नलिखित मामलों में गलत अनुपूरक प्राप्त करने के परिणाम के रूप में तथा वर्तमान अनुदेशों के उल्लंघन में 2012-13 में पांच अनुदानों में प्राधिकरणों से अधिक कुल ₹255.42 करोड़ का अधिक व्यय पाया गया था।

तालिका 4.17: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	योजना	प्रावधान			व्यय	आधिक्य
		मूल	उ.पू.क्षै.के अन्तर्गत शीर्ष	कुल		
2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	राष्ट्रीय कृषि नवपर्वतन परियोजना/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना 2415.01.796.02.00.35	0.50	--	0.50	1.19	0.69
	कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजना 2415.01.796.05.00.35	3.00	--	3.00	12.00	9.00
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2210.06.796.05.01.31	3.40	0.00	3.40	8.41	5.01
58-विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2202.02.789.07.00.35	378.80	6.16	384.96	477.03	92.07
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2202.02.796.08.00.35	177.46	28.21	205.67	234.21	28.54
59-उच्चतर शिक्षा विभाग	भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान, शिमला 2202.03.789.05.00.31	0.58	0.09	0.67	1.57	0.90
	भारतीय उन्नत शिक्षा संस्थान, शिमला 2202.03.796.05.00.31	0.26	0.04	0.30	0.70	0.40
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.31	4.00	0.52	4.52	6.02	1.50
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.35	0.70	-	0.70	4.22	3.52
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.789.05.00.36	3.40	0.38	3.78	4.68	0.90
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.31	2.00	0.26	2.26	3.01	0.75
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.35	0.35	-	0.35	2.11	1.76
	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2202.05.796.05.00.36	1.70	0.19	1.89	2.34	0.45
	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 2202.05.789.06.00.31	0.80	0.12	0.92	2.92	2.00
	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान 2202.05.796.06.00.31	0.24	0.02	0.26	0.88	0.62
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.789.08.00.31	19.64	2.45	22.09	22.99	0.90
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.796.08.00.31	9.82	1.23	11.05	11.50	0.45
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.789.08.00.35	142.36	15.55	157.91	176.81	18.90
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2203.00.796.08.00.35	71.18	7.77	78.95	88.40	9.45
	राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची 2203.00.789.11.00.35	1.92	0.00	1.92	3.12	1.20
	राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची 2203.00.796.11.00.35	0.96	0.00	0.96	1.56	0.60

अनुदान सं.	योजना	प्रावधान			व्यय	आधिक्य
		मूल	उ.पू.क्षै.के अन्तर्गत शीर्ष	कुल		
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 2203.00.789.14.00.35	4.50	0.00	4.50	8.25	3.75
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 2203.00.796.14.00.35	2.25	0.00	2.25	4.12	1.87
	भारतीय खनन संस्थान, धनबाद 2203.00.789.15.00.35	14.02	0.00	14.02	17.77	3.75
	भारतीय खनन संस्थान, धनबाद 2203.00.796.15.00.35	7.01	0.00	7.01	8.89	1.88
	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार 2203.00.789.19.00.35	0	0.15	0.15	0.37	0.22
	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार 2203.00.796.19.00.35	0	11.62	11.62	34.02	22.40
	योजना एवं वास्तुकला के नवीन स्कूल की स्थापना 2203.00.789.21.00.35	3.15	0.00	3.15	9.15	6.00
	योजना एवं वास्तुकला स्कूल की स्थापना 2203.00.796.21.00.35	1.58	0.00	1.58	4.59	3.01
	भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान 2203.00.789.22.00.35	71.10	0.00	71.10	75.60	4.50
	भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान 2203.00.796.22.00.35	35.55	0.00	35.55	37.80	2.25
	नवीन भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2203.00.789.23.00.35	0.03	0.00	0.03	7.28	7.25
	नवीन भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2203.00.796.23.00.35	0.02	0.00	0.02	3.63	3.61
	नवीन भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2203.00.789.24.00.35	1.35	2.02	3.37	6.38	3.01
	नवीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 2203.00.796.24.00.35	1.58	2.37	3.95	5.45	1.50
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर 2203.00.796.18.00.35	2.37	0.00	2.37	3.87	1.50
	भारतीय विज्ञान सस्थान, बंगलुरू को अनुदान 2203.00.789.04.00.31	6.75	0.00	6.75	11.25	4.50
	भारतीय विज्ञान सस्थान, बंगलुरू को अनुदान 2203.00.796.04.00.31	3.37	0.00	3.37	5.62	2.25
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड 2235.02.103.42.02.31	0.50	0.00[3]	0.50	0.82	0.32
	2235.02.103.42.02.36	5.00	0.00	5.00	5.13	0.13
	2235.02.103.42.03.31	3.04	0.00	3.04	4.60	1.56
	2235.02.103.42.03.36	8.00	0.00	8.00	8.25	0.25
	2235.02.103.42.02.31	0.50	0.00	0.50	0.82	0.32
कुल		**994.74**	**79.17**	**1073.91**	**1329.33**	**255.42**

[3] शीर्ष '2552' के अंतर्गत बजट प्रावधान प्राप्त किया गया था। तथापि यह प्रावधान अ.वि.मा.में एक मुश्त राशि में रूप दर्शाता गया था एवं विशिष्ट बजट सीमा (कार्यात्मक शीर्ष में विस्तृत शीर्ष स्तर पर) के संदर्भ में कोई विसंगति मौजूद नहीं रही। इसी प्रकारः एक मुश्त अनुपूरक प्रावधान भी 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' के अंतर्गत विशिष्ट बजट सीमा की अपेक्षाओं हेतु राशि विशिष्ट ब्यौरे दिये बगैर प्राप्त किया गया था।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए कोई पृथक आवंटन नहीं था तथा बजट अनुमान विवरण (व.अ.वि.) के अनुसार इसको योजना, जिससे यह संबंधित है, के आवंटन में दर्शाया गया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने (जनवरी 2014) बताया कि संवर्धन एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान के माध्यम से नहीं किया गया था। इसके स्थान पर, प्रावधान में संवर्धन उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ हेतु योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधियों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गैर-कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत योजनावार प्रावधान ब्यौरा, इस संबंध में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 सितम्बर 2005 के बावजूद अ.वि.मां. में भी उपलब्ध नहीं था।

विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बताया (दिसंबर 2013) कि वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपूरक मांग के प्रारूप में केवल मुख्य शीर्षों हेतु ब्यौरे थे और इसे तद्नुसार, सहायता-अनुदान सामान्य तथा अलग से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों की तरह विषय-शीर्ष-वार रखा गया था, जबकि अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों में अ.जा.उ.पो. (789) तक ज.उ.स. (796) जैसे लघु शीर्ष के, लिए ब्यौरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2014), कि तीन संघटनों के अन्तर्गत अपेक्षित अनुपूरक का विवरण आगे से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया था। निर्धारित प्रारूप में अ.जा.उ.यो. (लघु शीर्ष 789) तथा ज.उ.यो. (शीर्ष 796) जैसे लघु शीर्षों के विवरणों के उल्लेख का वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित योजनाओं में अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों को मुख्य शीर्ष-वार तथा योजनाओं में निधियों की आवश्यकता के अनुसार आगे विषय शीर्ष-वार ब्यौरा उल्लिखित करते हुए प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त यह बताया गया (फरवरी 2014) कि अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

मंत्रालयों/विभागों का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा सं.93-वस्त्र मंत्रालय में राशि विशिष्ट अलग अनुपूरक प्रावधान को योजना के सभी तीनों संघटकों हेतु प्राप्त किया गया था। अन्य मंत्रालय भी, जहाँ कहीं अलग बजट सीमाएं विद्यमान हैं, समान प्रक्रिया को आपनाएं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि किया गया व्यय सा.वि.नि. के प्रावधानों के भीतर था क्योंकि इन मामलों में निधियां पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के दृष्टांत में तर्कसंगत नहीं है कि योजना 'केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड' को विस्तृत शीर्ष स्तर पर कुछ उप-संघटकों में विभाजित किया गया था। 'सहायता अनुदान' संर्वधन हेतु संसद की स्वीकृति पृथक रूप से संघटक-वार प्राप्त नहीं की गई थी।

4.11 विषय शीर्षों के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबंधित है कि शीर्ष एकमुश्त (विषय शीर्ष 42) अंतर्गत प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, के संबंध में व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 हेतु विनियोग लेखे की जांच ने प्रकट कि निम्नलिखित मामलों में व्यय के पूर्व ब्यौरे सहित संसदीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बजाए ₹10 लाख से अधिक के एक मुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे, जो वर्तमान नियमावली के तहत आवश्यक था।

तालिका 4.18: एकमुश्त प्रावधान

क्र.सं.	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान (₹करोड़ में)	व्यय (₹करोड़ में)	टिप्पणियाँ
1.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	3475.00.105.04.00.42	0.52	0.61	भुगतान, सहायक न्यायालयीन परिमापक, उच्च न्यायालय कोलकाता के कार्यालय में वेतनों, चिकित्सा व्ययों, यात्रा व्ययों एवं अन्य कार्यालय व्ययों के लिए किया गया था। इस मामले को नि.म.ले.प. के वर्ष 2011-12 हेतु प्रतिवेदन सं. 1 में भी सूचित किया गया था। विभाग ने बताया (नवम्बर, 2013) कि उसने लेखापरीक्षा से उनके कार्यालय की वर्ष 2014-15 हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए प्रावधानों को विभाजित करने का परामर्श/सूत्रित करने का अनुरोध किया है। विभाग ने आगे बताया (जनवरी, 2014) कि यह वे.ले.का. से बजटीय प्रयोजन हेतु अपेक्षित लेखा शीर्षों के सृजन का अनुरोध कर रहा है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, चूंकि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 विनियोग की मानक प्राथमिक इकाई अर्थात विषय शीर्ष, व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु वर्णन एवं परिभाषा के साथ, निर्धारित करता है।

क्र.सं.	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय	टिप्पणियाँ
			(₹करोड़ में)		
2.	45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2408.01.103.01.03.42	0.21	0.20	--
3.	52-गृह मंत्रालय	2070.00.105.17.00.42 आई.एस. अन्य अवैध गतिविधियों (निषेध) अधिकरण	0.45	0.28	मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि अधिकरण का व्यय विभिन्न घटकों अर्थात अधिकरण की बैठकों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। व्यय का ठीक-ठाक अनुमान लगाना संभव नहीं था। उसने यह भी बताया कि संबंधित बजट नियंत्रण प्राधिकारियों से एक मामले में उत्तर प्रतिक्षित था। उत्तर इस अनुबंधन के दृष्टांत से तर्कसंगत नहीं है कि जब भी एक मुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक हो तो विवरण के ब्यौरे प्रदान किए जाने चाहिए। इसलिए इन सभी मामलों में प्रावधान 'एक मुश्त प्रावधान' के बजाए विशिष्ट विषय शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
4.		2070.00.105.18.00.42 उ.पू. हेतु अन्य अवैध गतिविधियां (निषेध) अधिकरण	0.70	0.55	
5.		2070.00.105.19.00.42 उत्तर भारत हेतु अन्य अवैध गतिविधियां निवेश अधिकरण	1.00	0.66	
6.		2070.00.119.03.11.42 अनुवाद में प्रशिक्षण देने हेतु नगद कार्यक्रम	0.34	0.28	
7.	88-दमन एवं दीव	3056.00.003.01.00.42	1.00	1.00	मंत्रालय ने ₹1.00 करोड़ के व्यय को भारतीय अंतर्देशीय जल निकाय प्राधिकरण (मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) को तकनीकी अध्ययनों के आयोजन हेतु जारी राशि होने के कारण नियमानुसार '31 सहायता-अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज करने के स्थान पर विषय शीर्ष '42-एकमुश्त प्रावधान' के अंतर्गत दर्ज किया था। प्र.मु.रि.ले.नि ने बताया (नवम्बर, 2013) कि मुख्य शीर्ष 3056 के अंतर्गत विषय शीर्ष '31 सहायता-अनुदान-सामान्य' को ब.अ. 2013-14 में खोला गया है और प्रावधान भी किया गया है।
8.	99-दमन एवं दीव	उपभोक्ता मामले मंत्रालय 3475.00.106.01.00.42	0.14	0.10	--
9.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अन्य मदें 2235.02.103.17.00.42	1.00	0.34	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2013) कि विषय शीर्ष 42 के अंतर्गत व्यय के ब्यौरे इस स्तर पर नहीं दिए जा सकते हैं। तथापि, इसने बताया कि था कि कथित व्यय बैठकों/सम्मेलनों, आदि पर खर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया कि ऐसे व्यय वर्ष 2013-14 के बाद से विषय शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत दर्ज किये जाएंगे।

4.12 निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(2) के अनुसार, संवितरण कार्यालय द्वारा यदि किसी दावे को स्वीकार करने से आवंटन या विनियोग से राशि अधिक बढ़

जाती है तो वह दावे का भुगतान करने से पहले प्रशासनिक प्राधिकारी से आदेश लेगा। प्रशासनिक प्राधिकारी या तो पुनर्विनियोग या अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके या भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर निधियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

वर्ष 2012-13 हेतु समेकित मासिक लेखे की पांच अनुदानों में लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि वास्तविक व्यय उपलब्ध प्रावधानों से ₹1,944.26 करोड़ तक अधिक था जैसा नीचे विवरण दिया गया है। सेवा हेतु प्रावधान करने के पुनर्विनियोग आदेश व्यय करने के पश्चात आगामी तिथियों में जारी किए गए थे।

तालिका 4.19: पुनर्विनियोग के जारी होने के पूर्व व्यय प्रावधान से किए गए अधिक व्यय के मामले

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	बजट प्रावधान	माह जिसमें व्यय उपलब्ध प्रावधान से अधिक हुआ		राशि जिससे व्यय प्रावधान से अधिक हुआ (पुनर्विनियोग से पहले)
		व्यय	व्यय	
अनुदान सं.46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
2071.01.118.01.00.06	630.00	773.51	फरवरी-13	143.51
2210.01.001.03.01.06	0.67	0.80	जनवरी-13	0.13
2210.01.001.03.01.11	1.10	1.24	फरवरी -13	0.14
2210.01.103.24.01.01	381.55	403.54	फरवरी -13	21.99
2210.01.103.24.01.13	10.71	12.91	फरवरी -13	2.20
2210.01.103.24.01.21	234.79	330.10	फरवरी -13	95.31
2210.01.104.02.00.13	0.80	1.35	फरवरी -13	0.55
2210.01.110.19.01.13	22.50	29.42	जनवरी -13	6.92
2210.01.110.19.01.21	32.13	47.82	दिसम्बर-12	15.69
2210.01.110.19.99.13	0.70	0.93	दिसम्बर-12	0.23
2210.01.110.20.03.01	177.53	189.97	फरवरी -13	12.44
2210.01.110.20.03.20	0.08	0.13	जनवरी -13	0.05
2210.01.110.20.03.21	34.08	39.40	फरवरी -13	5.32
2210.01.800.26.00.36	12.00	34.30	मार्च-13	22.30
2210.05.105.28.01.31	271.00	325.70	जनवरी -13	54.70
2210.05.105.28.01.36	586.00	672.00	जनवरी -13	86.00
2210.05.105.39.00.01	1.00	6.00	फरवरी -13	5.00
2210.05.105.36.00.31	0.00	29.92	जून -12	29.92
2210.05.105.36.00.35	0.00	44.85	जून -12	44.85

शीर्ष	बजट प्रावधान	माह जिसमें व्यय उपलब्ध प्रावधान से अधिक हुआ		राशि जिससे व्यय प्रावधान से अधिक हुआ (पुनर्विनियोग से पहले)
		व्यय	व्यय	
2210.05.105.36.00.36	0.00	60.00	जून -12	60.00
2210.05.105.43.00.31	0.00	23.92	जून -12	23.92
2210.05.105.43.00.35	0.00	29.92	जून -12	29.92
2210.05.105.43.00.36	0.00	120.00	जून -12	120.00
2210.05.105.44.00.31	0.00	5.00	अगस्त-12	5.00
2210.06.101.30.03.31	2.97	25.95	जून -12	22.98
2210.06.101.30.13.31	36.50	53.00	फरवरी -13	16.50
2210.06.102.09.00.31	12.00	19.38	मार्च -13	7.38
2210.06.796.13.00.31	4.60	8.40	दिसम्बर-12	3.80
2210.06.800.24.03.21	5.30	37.67	जनवरी -13	32.37
2210.06.800.24.13.21	2.00	2.12	दिसम्बर-12	0.12
2211.00.108.08.01.31	10.00	22.86	फरवरी -13	12.86
2211.00.109.09.02.21	464.49	516.11	फरवरी -13	51.62
2211.00.796.04.01.31	109.50	154.89	सितम्बर-12	45.39
2211.00.796.04.02.31	419.26	697.77	सितम्बर-12	278.51
कुल				**1,257.62**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि संशोधित अनुमानों की सीमा के परिणामस्वरूप, विनियोग के उप-शीर्षों/इकाइयों की एक बड़ी संख्या के अंतर्गत बचतों का पुनः आवंटन एवं प्रावधानों का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, स्वीकृत अनुमानों का एक विस्तृत विवरण सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ जारी किया गया था एवं इसके प्रति भुगतान को भी प्राधिकृत किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लाभार्थ योजना के मामले में, व्यय को कार्यात्मक शीर्ष में दर्ज किया गया है। तथापि, संपूर्ण अनुदान हेतु वित्त वर्ष की समाप्ति पर एक समेकित आदेश जारी किया जा रहा था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध है। किसी भी सेवा पर व्यय करने से पहले, प्रशासनिक प्राधिकरण को या तो पुनर्विनियोग या फिर अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्रावधान उपलब्ध कराने चाहिए।

अनुदान सं..53-मत्रिमंडल				
2013.00.108.02.01.11	6.50	10.63	जनवरी-13	4.13
2055.00.118.01.01.20	7.12	9.30	सितम्बर-12	2.18
कुल				**6.31**

शीर्ष	बजट प्रावधान	माह जिसमें व्यय उपलब्ध प्रावधान से अधिक हुआ		राशि जिससे व्यय प्रावधान से अधिक हुआ (पुनर्विनियोग से पहले)
		व्यय	व्यय	
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2013) कि भुगतान (क्र.सं. 2 के संबंध में) कर दिये गये थे क्योंकि भुगतान को पुनर्विनियोजन तक रोके रखना संभव नहीं था। आगे बताया गया (क्रम सं. 1 के संबंध में) कि अतिरिक्त व्यय हेतु प्राधिकरण जनवरी 2013 में वे.ले.का. के पास भेज दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया (मार्च-2014) कि घरेलू यात्रा व्यय (क्रय सं. 1 के संबंध में) हेतु अतिशीघ्र निधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए संस्वीकृति जारी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।				
अनुदान सं. 54-पुलिस				
2055.00.119.01.00.06	41.25	48.66	फरवरी 2013	7.41
2055.00.003.01.02.01	25.50	25.53	फरवरी 2013	0.03
2055.00.003.01.02.28	16.70	16.72	फरवरी 2013	0.02
4055.00.201.03.00.51	110.00	110.81	फरवरी 2013	0.47
4055.00.204.02.00.52	35.00	42.15	नवम्बर 2013	7.15
4055.00.212.09.04.52	60.00	127.82	फरवरी 2013	67.82
4055.00.216.13.01.52	0.20	0.26	जनवरी 2013	0.06
2055.00.003.06.01.02	0.30	0.34	फरवरी 2013	0.04
2055.00.105.03.01.41	1.25	1.40	फरवरी 2013	0.15
कुल				**83.15**
मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2013) कि व्यय पुनर्विनियोग आदेशों की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया था क्योंकि यह अधिकांश भुगतान अनिवार्य थे तथा इनमें विलम्ब नहीं किया जा सकता था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।				
अनुदान सं.55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय				
2245.80.102.04.00.01	7.00	7.40	फरवरी -13	0.40
2245.80.102.14.01.01	219.71	227.14	फरवरी -13	7.44
2245.80.102.14.01.23	14.00	16.63	जनवरी 2013	2.63
कुल				**10.47**
मंत्रालय ने बताया (मार्च 2014) कि कर्मचारियों को वेतन तथा राशन की लागत के भुगतान की अत्यावश्कता के दृष्टांत से फरवरी माह में भुगतान किया गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मौजूदा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध था।				
अनुदान सं..90- अंतरिक्ष विभाग				
168 मामले अनुबंध 4.3 में सूचीबद्ध				**586.71**
अ.वि.ने अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (मार्च 2014) किया। कुछ मामलों में प्रावधानों से अधिक व्यय हेतु स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में उसने उल्लेख किया कि पुनर्विनियोग मार्च 2013 में किया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना बजट प्रावधान के अधिक में व्यय करना अनुमत नहीं है। इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोग आदेश दूसरे उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) द्वारा जारी किए गए थे न कि अं.वि. द्वारा तथा इसलिए स्वीकार्य नहीं थे।				
कुल योग				**1944.36**

4.13 डाक विभाग

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए अनुदान सं. 13-डाक विभाग की लेखापरीक्षा जांच से कई वित्तीय कमियाँ प्रकट हुई जिनका आगामी पैराग्राफों में सारांश दिया गया है।

4.13.1 बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) में यह प्रावधान है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। शीर्ष वार विनियोग लेखाओं की जांच से पता चला कि चार ममालों में कोई बजट प्रावधान उपलब्ध किए बिना, कोई संसदीय प्राधिकार दिए बिना ₹0.72 करोड़ की राशि का व्यय किया गया, जिसके विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 4.20: बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	राशि	विभाग का उत्तर
1.	5201.00.101.01 भूमि	0.11	डाक विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमति जताते हुए बताया (दिसंबर 2013) कि परिमंडलों को ऐसे व्ययों को करने के लिए कारण बताने का निर्देश दे दिया गया हे।
2.	5201.00.104.31 टिकट संग्रहण का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण	0.004	
3.	5201.00.104.33 डाक लेखे प्रबंधन	0.58	
4.	5201.00.104.37 प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण	0.03	
कुल		**0.72**	

4.13.2 पुनर्विनियोग आदेशों का जारी न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 में यह प्रावधान है कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा ऐसे अन्य सामान्य अथवा विशिष्ट प्रतिबंध जैसाकि इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए जाएं, के अधीन भी एक अनुदान या विनियोग के भीतर विनियोग की एक प्राथमिकता इकाई से दूसरी ऐसी इकाई में निधियों के पुनर्विनियोग को वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसा अनुदान या विनियोग संबंधित है, की समाप्ति से पूर्व किसी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया जा सकता है तथा पुनर्विनियोग की आदेश की प्रति लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

डाक विभाग में केवल पुनर्विनियोग के उन मामलों में जहाँ वित्त मंत्रालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, संस्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। गैर-क्रियात्मक शीर्ष से क्रियात्मक शीर्ष में निधियों के पुनर्वियोग सहित अन्य सभी मामलों में विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी अन्य इकाई में निधियाँ पुनर्विनियोग हेतु सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति केवल फाइल में ली गई है तथा कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था।

इस मामले को नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.31.3 में सूचित किया गया था। किन्तु डाक विभाग द्वारा सामानय वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 के प्रावधान में कोई विवेकशील कार्रवाई नहीं की गई है।

4.14 रक्षा सेवाएं

4.14.1 बचतों/आधिक्य की राशियों को गलत दर्शाना

संघ सरकार के विनियोग लेखे का अभिप्रेत राजस्व प्रभारित/दत्तमत तथा पूंजीगत प्रभारित/दत्तमत हेतु अलग से सकल व्यय के अनुदान-वार ब्यौरे प्रदान करना है। विनयोग लेखे में संस्वीकृत प्रावधान तथा विशिष्ट लेखा शीर्ष के अंतर्गत किए गये व्यय के बीच विभिन्नता अर्थात् बचतों/आधिक्य, हेतु स्पष्टीकरण भी शामिल होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु सिविल, रक्षा तथा डाक के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संघ सरकार की 106 अनुदानों में से सौ में टिप्पणियों के तहत उपशीर्षों के अंतर्गत अंतरों हेतु स्पष्टीकरण तथा विनियोग लेखे में टिप्पणियां संस्वीकृत प्रावधान अर्थात् मूल तथा अनुपूरक प्रावधानों के संदर्भ में दी गई है।

रेलवे के विनियोग लेखे में भी, 16 अनुदानों को शामिल करके अंतर की राशि सहित अंतरों हेतु स्पष्टीकरण को संस्वीकृत प्रावधान के संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया है।

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे के मामले में छः अनुदानों को शामिल करके अंतरों की राशि को अंतिम अनुदान अर्थात् मूल + अनुपूरक ± पुनर्विनियोग के आधार पर परिकलित किया जाता है। चूंकि संसद को सूचित किए जा रहे विनियोग लेखे को इसके द्वारा प्राधिकृत प्रावधान की तुलना में वर्ष में खर्च राशि के आधार पर तैयार किया गया है इसलिए अंतरों को केवल मूल तथा अनुपूरक प्रावधानों के संदर्भ में परिकलित किया जाना चाहिए।

इस अनियमितता को वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु संघ सरकार के लेखे पर 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में इंगित किया गया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे में कोई शोधि उपाय नहीं किए गए हैं तथा विभिन्नताओं को अंतिम अनुदान के आधार पर स्पष्ट किया जा रहा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2014) कि लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रणाली 'अंतरों के कारण तथा उनका प्रस्तुतीकरण को दर्ज करने हेतु मापदण्ड' के नोट 2, जो बजट नियमपुस्तिका के अनुबंध-IV (अध्याय-III) में शामिल है, से अलग है। उसने आगे बताया कि वर्तमान प्रक्रिया का लम्बे समय से अनुपालन किया जा रहा है तथा स्थापित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सशस्त्र दलों की कार्रवाई की तैयारी को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित ईष्टतम उपयोग के लिए उपलब्ध अनुदानों के भीतर निधियों का पुनर्विनियोग करने हेतु सेवाओं के उपलब्ध लचीलेपन को रद्द करेगा।

मंत्रालय का उत्तर इस दृष्टांत से सही नहीं है कि बजट नियमपुस्तिका का नोट 2 स्वयं अनुबंध करता है कि अंतर, शीर्ष-वार विनियोग लेखे के कॉलम 1 (अभ्यर्पण तत्व सहित पुनर्विनियोग) तथा कालम 4 के अंतर्गत एक साथ लिए गए अंतरों को सूचित करते हैं।

इसलिए, वर्तमान प्रक्रिया, यद्यपि मंत्रालय द्वारा लम्बे समय से अपनाई जा रही है, को बदला जाना चाहिए तथा सिविल, डाक तथा रेलवे के विनियोग लेखे में अनुपालन की जा रही सही प्रक्रिया के साथ बराबर किया जाना चाहिए। विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय के लेखे हैं जिसकी तुलना दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोग के साथ की जाती है, जैसा संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के अनुसूचित परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है तथा किसी भी बचत/आधिक्य को केवल संसद द्वारा प्राधिकृत प्रावधानों के संदर्भ में परिकलित किया जाना चाहिए। आधिक्य एवं बचते दर्शाने तथा इसकी व्याख्या किए जाने का भी मंत्रालय के पास उपलब्ध पुनर्विनियोग की शक्तियों पर कोई असर नहीं हुआ है।

अध्याय 5: सहायता अनुदान : एक विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

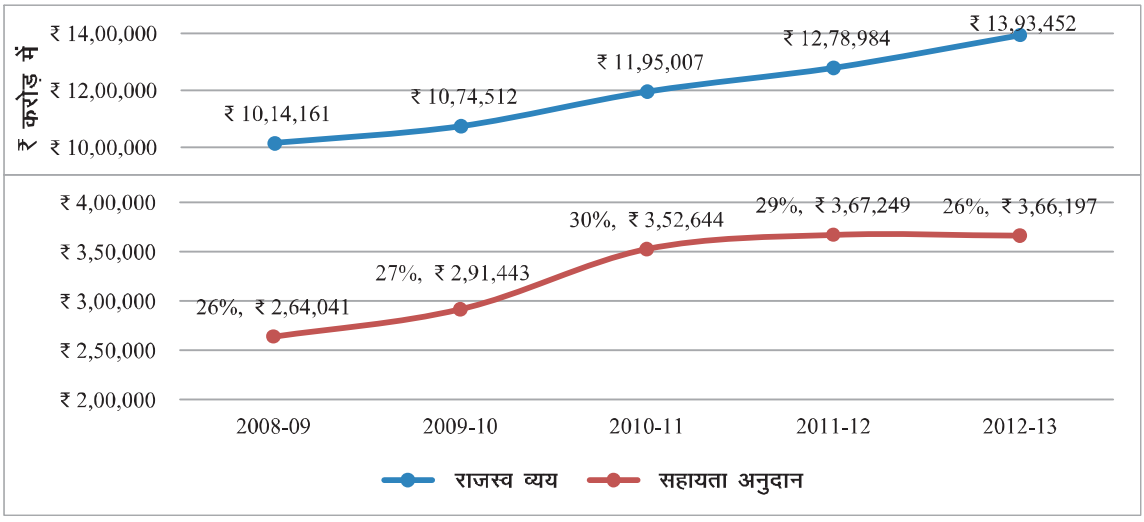
लोक प्रशासन के विवर्ती उदाहरण ने नई तथा सदा विकसित हो रही पद्धतियों के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण को अपरिहार्य किया है। सहायता अनुदान, संघ सरकार के व्यय के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। वास्तव में, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, सहायता-अनुदान ऋण पुर्नभुगतानों के अपवाद के साथ, संघ सरकार के लिए व्यय की एक मात्र विशालतम मद रहा था।

सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा अन्य सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्ति विशेष को प्रदान की गई सहायता, दान अथवा अंशदानों के रूप में किए गए भुगतान हैं। सहायता-अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाती है। संघ सरकार अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त निधियां प्रदान करती है। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारिता संस्थानों तथा अन्यों को भी सहायता अनुदान संवितरित करती है। जारी किए गए अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन व्ययों को पूरा करने तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जाता है।

5.2 व्यय की प्रवृत्ति

सहायता अनुदान को रोकड़ अथवा जिस रूप में भी प्रदान किया गया हो, किंतु इसे, उद्देश्य जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, पर विचार किए बिना अनुदानग्राही के खातों में हमेशा राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना होता है। 2008-09 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान, सहायता-अनुदान पर व्यय को संघ सरकार के राजस्व व्यय के 26 से 30 प्रतिशत तक दर्ज किया गया, जिसे नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में सहायता अनुदान



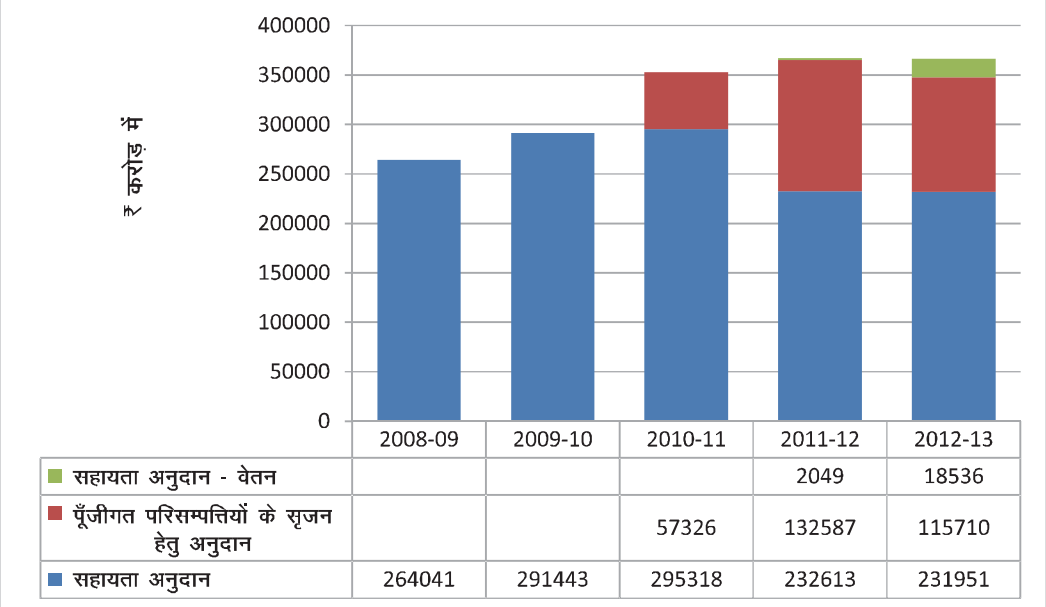
नोटः स्रोतः ई-लेखा डाटा डम्प। डाटा में सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों के व्यय, निवल वसूलियां शामिल हैं परंतु 'रेलवे' शामिल नहीं है।

2008-09 से 2012-13 तक पाँच वर्षों में कुल राजस्व व्यय की 37 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सहायता अनुदान 39 प्रतिशत अधिक दर से बढ़ा है।

सहायता अनुदान व्यय को विसमूहन के सबसे नीचे स्तर पर अर्थात एक वस्तु शीर्ष के रूप में बजट तथा लेखों में दर्शाया गया है। 2008-09 तक सहायता अनुदान पर संघ सरकार के व्यय को एक ही वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा था। तथापि, वर्तमान में इस व्यय को दर्ज किए जाने हेतु अलग से तीन वस्तु शीर्ष संचालित किए जा रहे हैं। ये वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य; 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा 36-सहायता अनुदान वेतन हैं। वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2009-10 से खोला गया था, तथा विद्यमान वस्तु शीर्ष नामतः '31-सहायता अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2010-11 से संशोधित कर '31-सहायता अनुदान सामान्य' पढ़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' को वित्तीय वर्ष 2011-12 से खोला गया था।

नीचे दिया गया ग्राफ पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदानों को दर्शाता है।

चार्ट 5.2: सहायता अनुदानों के प्रकार



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सहायता अनुदान - वेतन				2049	18536
पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान			57326	132587	115710
सहायता अनुदान	264041	291443	295318	232613	231951

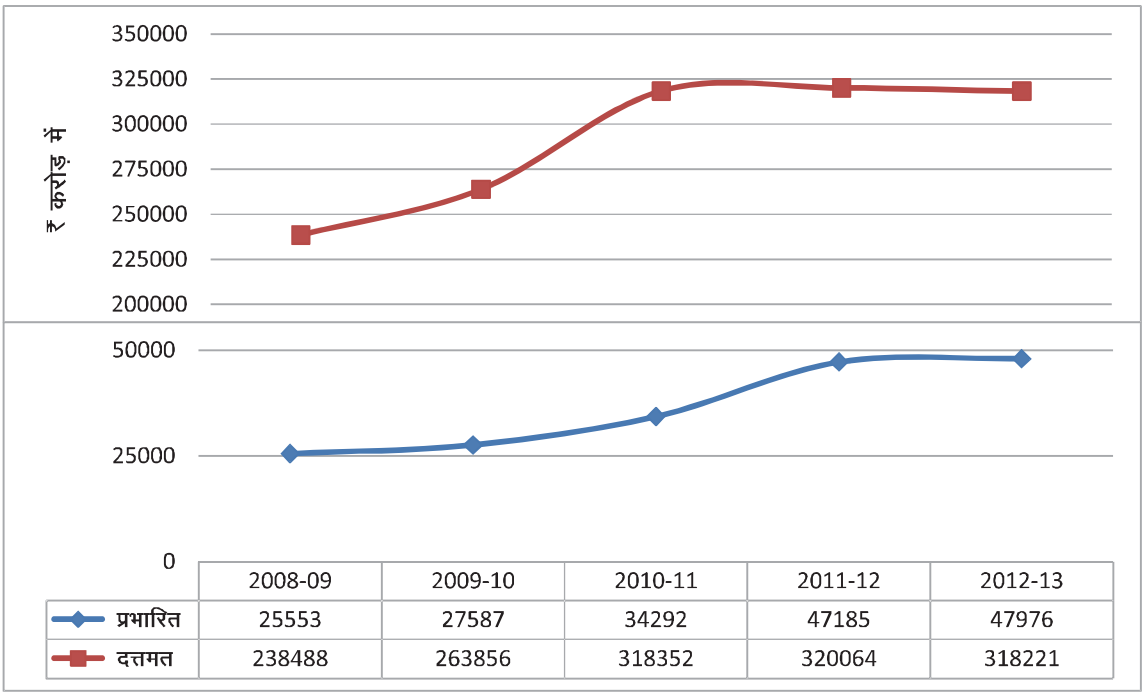
नोटः स्रोत ई-लेखा डाटा डम्प। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे' शामिल नहीं है (पूंजीगत लेखा में गलती से वर्गीकृत सहायता अनुदान को छोड़कर)।

5.2.1 प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कुल सहायता अनुदान व्यय में से प्रभारित व्यय लगभग 13 प्रतिशत था। ये अनुदान, जो प्रकृति में गैर-योजनागत हैं, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अनुसार बनाए

गए हैं। नीचे चार्ट पांच वर्षों की अवधि के प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदानों का विवरण दर्शाता है।

चार्ट 5.3: प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रभारित	25553	27587	34292	47185	47976
दत्तमत	238488	263856	318352	320064	318221

नोटः स्रोतः ई-लेखा डाटा डम्प। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा सहायता अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे ' शामिल नहीं है। (पूंजीगत लेखा में गलती से वर्गीकृत सहायता अनुदान को छोड़कर) /

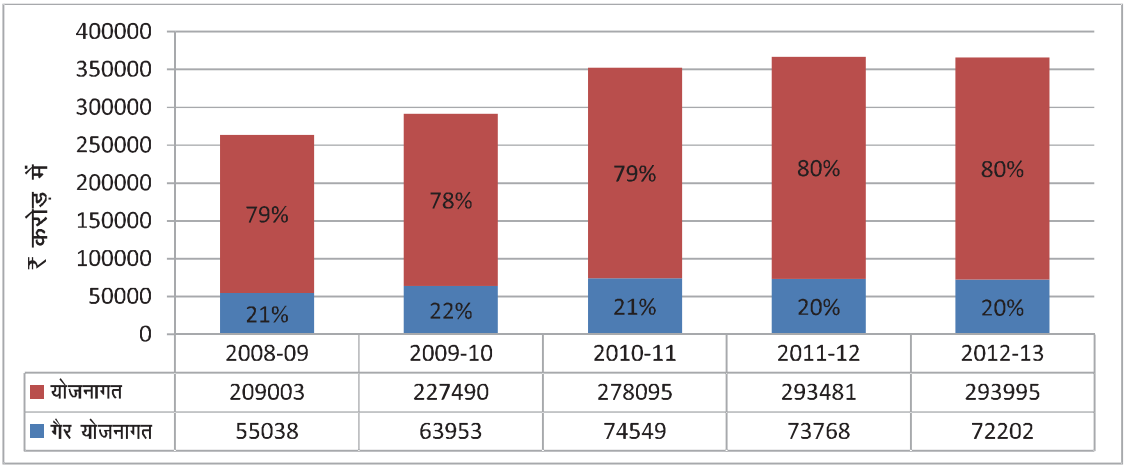
वर्ष 2012-13 के लिए प्रभारित सहायता अनुदान को मुख्य रूप से दो अनुदानों में अर्थात् राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण तथा जनजाति कार्य मंत्रालय को जारी किया गया था। ₹47,976 करोड़ के प्रभारित अनुदानों में से राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ₹42,576 करोड़ के अनुदान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित थे। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान, मुख्य रूप से, राज्यों के गैर-योजनागत राजस्व घाटे, प्रारम्भिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों को सुधारने, सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण, स्थानीय निकायों, आपदा राहत के लिए हैं। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को सृजित करने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।

5.2.2 योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान

संघ सरकार द्वारा दोनों, नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु तथा अन्य उद्देश्यों हेतु भी, सहायता अनुदान प्रदान की जाती हैं। नीचे चार्ट योजनागत तथा गैर-योजनागत द्वारा सहायता अनुदानों के विवरण दर्शाता है। सहायता अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु

प्रदान किया गया सहायता अनुदान है, 2008-09 से 2012-13 के दौरान योजनागत सहायता अनुदान का अंश कुल सहायता अनुदान के 78 से 80 प्रतिशत के बीच था।

चार्ट 5.4: योजनागत बनाम गैर-योजनागत सहायता अनुदान



	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
योजनागत	209003	227490	278095	293481	293995
गैर योजनागत	55038	63953	74549	73768	72202

नोटः स्रोतः ई-लेखा डाटा डम्प। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा सहायता अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे ' शामिल नहीं है (पूंजीगत लेखा में गलती से वर्गीकृत सहायता अनुदान को छोड़कर)।

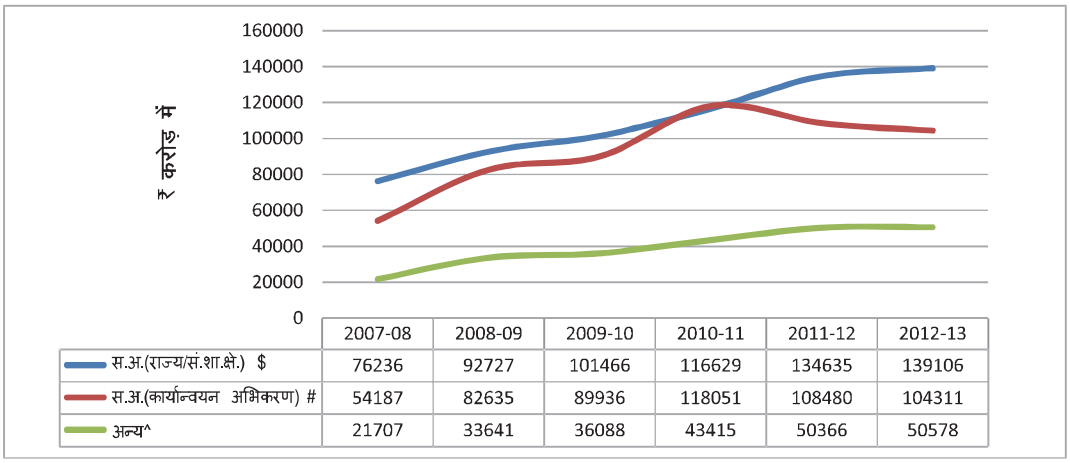
2008-09 से 2012-13 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान योजनागत अनुदानों ने 41 *प्रतिशत* की वृद्धि सूचित की जबकि गैर-योजनागत अनुदान 31 *प्रतिशत* तक बढे हैं।

5.3 योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति

नब्बे के मध्य से संघ सरकार कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित धन को, कार्यान्वयन अभिकरणों, जो कि समितियां, स्वायत्त निकाय, गैर-सरकारी संगठन आदि हैं, के खातों में सीधे अंतरित करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर रही है। अंतरण की इस पद्धति को प्रायः 'समिति पद्धति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसी संस्थाऐं राज्य तथा जिला स्तर दोनों पर हैं तथा उनकी निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं। संघ सरकार की अन्य पद्धति राज्य सरकार को अनुदानों का अंतरण करना है तथा यह "राजकोषीय पद्धति" के रूप में संदर्भित हैं, जो इस प्रकार अंतरण की गई राशि को राज्यों की समेकित निधि में क्रेडिट करने पर जोर देता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुरूप है। क्रेडिट की गई राशि को फिर वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से समेकित निधि से विनियोजित किया जाता है। अंतरण की यह पद्धति एक संतुलित लेखांकन प्रणाली द्वारा समर्थित है जो लेखांकन में व्यय के अंतिम शीर्ष तक का पता लगाती है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन के वाउचर राजकोष तथा राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध होते हैं। यह सुविकसित लेखांकन ढांचा उचित वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है तथा व्यय की गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण प्रदान करता है।

समिति पद्धति के माध्यम से अनुदानों के अंतरण की प्रमात्रा तेजी से बढ़ी है। प्रथम वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2006-07 से जिसके लिए तुलनीय डाटा उपलब्ध है, संघ सरकार के लेखों में दर्ज व्यय ₹43,816 करोड़* का है। वर्ष 2012-13 के दौरान, यह आंकड़ा ₹1,04,971 करोड़* तक बढ़ा है जो लगभग ढाई गुना वृद्धि है। नीचे चार्ट राजकोष पद्धति के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को, समिति पद्धति से सीधे निर्गमों को तथा कार्यान्वयन अभिकरणों एवं मंत्रालय के क्रियात्मक शीर्षों से अन्य निकाय/प्राधिकरणों को जारी की गई सहायता अनुदानों के ब्यौरों को दर्शाता है।

चार्ट 5.5: राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को योजनागत सहायता अनुदान



	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
स.अ.(राज्य/सं.शा.क्षे.) $	76236	92727	101466	116629	134635	139106
स.अ.(कार्यान्वयन अभिकरण) #	54187	82635	89936	118051	108480	104311
अन्य^	21707	33641	36088	43415	50366	50578

$-डाटा स्रोतः ई-लेखा डाटा डम्प। इसमें जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे' शामिल नहीं है।

#- डाटा स्रोतः व्यय बजट की विवरणी सं. 18 का खण्ड-I।

^संतुलन आंकड़ा

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियों के अंतरण के लिए राज्यों की समेकित निधि के बाहर राज्य तथा जिला स्तरीय अभिकरणों को स्थापित करने की एक मुख्य अभिप्रेरणा, ऐसे अंतरणों को राज्यों द्वारा अपने अर्थोपाय उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने से बचाना था। राशियों का अर्थोपाय उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है, के आधार पर समिति पद्धति के माध्यम से निर्गमों का औचित्य तर्कसंगत नहीं है। वास्तव में कई राज्य सरकारों ने हाल के वर्षों में बड़े रोकड़ आधिक्य का संचयन किया है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली को कार्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लोक निधियों का व्यय करने में कार्यान्वयन अभिकरणों को अधिक प्रत्यायोजित तथा लचीला बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया था। तथापि, जवाबदेही ढ़ांचे का अनुकूल सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है। विकेन्द्रित

* वर्ष 2006-07 एवं 2012-13 (प्रावधानिक) में राजस्व वर्ग के अंतर्गत का का.अ. को क्रमशः ₹43,372 करोड़ तथा ₹1,04,311 करोड़ के प्रत्यक्ष निर्गम।

समिति/कार्यान्वयन अभिकरण पद्धति में प्राधिकार के फालतू तथा दुरूपयोग के नियंत्रण की जिम्मेदारी नाकाम हो गई है।

यह देखा गया था कि विभिन्न विकासात्मक एवं सामाजिक सहायता को तर्कसंगत करने के वृहतर प्रयास के भाग के रूप मे, मौजूदा केन्द्र प्रायोजित/ए.सी.ए. योजनाएं, योजना आयोग के जुलाई 2013 के निर्देशों के अनुसार 66 योजनाओं में पुनर्गठित की गयी है। सभी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निधि के साथ इन 66 योजनाओं के संबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों के समेकित निधि के द्वारा 2014-15 से चरणबद्ध तरीके से अंतरित की जाएगी।

5.3.1 कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) के लेखों में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष

वर्ष 2012-13 में, संघ सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹ 1,04,971[1] करोड़ जारी किए। चूंकि कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) द्वारा निधियों का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया था, उनके खातों में अव्ययित निधि की बड़ी राशि पड़ी थी। सरकारी खाते से बाहर का.अ. के खाते में रखी गयी, अव्ययित शेषों की कुल राशि तुरंत सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकारी व्यय, जैसा कि लेखों में दर्शाया गया है, को उस सीमा तक अधिक बताया गया है। सरकारी लेखे प्रत्यक्ष निर्गमों की यथार्थ राशि भी प्रकट नहीं करते।

लोक व्यय के दक्ष प्रबंधन पर रंगराजन समिति (समिति) ने समिति पद्धति के कार्यान्वयन में कुछ कमियाँ पाई। कमियों में का.अ. हेतु लेखांकन कार्यढ़ांचा का एक समान न होना, सृजित परिसम्पत्तियों के आश्वासन तथा लेखांकन की कमी, का.अ. द्वारा किए गए व्यय पर कोई केन्द्रित डाटा न होना, क्या उपयोग प्रमाणपत्र विश्वसनीय है पर कोई आश्वासन न होना, बड़े अव्ययित शेषों का प्रणाली के बाहर प्रवाह के रूप में रहना तथा नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र का सभी उप-अनुदान ग्राहियों पर व्यापक न होना शामिल है।

समिति ने यह भी पाया कि राजकोष के माध्यम से निर्गत निधियों के लाभों पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। उसने यह भी बताया कि यह पद्धति सभी विपत्तियों का निपटान न कर पाए फिर भी यह बहु-अभिकरणों तथा संस्थान जिन पर 'राज्य' का कम नियंत्रण था, वाली प्रणाली से अच्छी थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी बताया था कि इष्टतम समाधान निधियों का निर्गम राज्य बजटों के माध्यम से करें जिससे कि राजकोष प्रणाली निधियों के उपयोग को सूचित कर सके तथा राज्य सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सके।

समिति ने आगे सिफारिश की कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना से सभी नई योजनाओं के साथ यथासंभव निधियों के अंतरण को पूर्णतः राजकोष पद्धति में सीधे अंतरण करना प्रारंभ किया जाए। विद्यमान योजनाओं के लिए आवश्यक समायोजन हेतु लघु परवर्ती अवधि अपेक्षित थी। तथापि, जबकि राजकोष पद्धति में पूर्ण अंतरण कर दिया गया था, फिर भी समिति पद्धति के अंतर्गत

[1] व्यय बजट 2014-15 (खण्ड-I), विवरणी 18 के अनुसार

योजनाओं के लेखांकन, बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण तथा लेखापरीक्षण को तर्कसंगत किया जाना था।

व्यय विभाग ने लोक लेखा समिति को अपने उत्तर (जनवरी 2014) में स्वीकार किया कि विकास अथवा सामाजिक सहायता हेतु आवश्यक निधियों का बेकार पड़े रहना, न केवल एक अपर्याप्त वित्तीय स्थिति में ऋण लेने के उच्च कीमत के कारण अस्वीकार्य हैं अपितु इसलिए भी कि इन निधियों से आयोजित की जाने वाली गतिविधियां भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी। विभाग ने इसके अतिरिक्त बताया कि संशोधित अनुमानों की बैठकों के दौरान, कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पड़े अव्ययित शेषों की सावधानी से जाचं की गयी एवं मंत्रालय को ऐसे शेषों की मात्रा को कम करने की सलाह दी गयी है। इसके अतिरिक्त, स्वायत्त निकायों/गै.स.सं./संस्थान एवं केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय निकाय स्तर के संगठन (राज्य सरकार को छोड़कर) को किसी प्रकार का अनुदान जारी न करने के निर्देश भी जारी (नवम्बर 2012) किये जा चुके हैं यदि उस निकाय ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों से संबंधित सभी उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो। विभाग ने बताया कि 66 पुनर्गठित योजनाओं हेतु केन्द्रीय निधि राज्यों की समेकित निधि के माध्यम से 2014-15 से एक चरणबद्ध तरीके से अंतरित की जाएगी।

5.3.2 सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन

सार्वजनिक सेवा वितरण मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी अभिकरणों, सरकार के विभिन्न स्तरों तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित निजी क्षेत्र के बीच बढ़ते हुए जटिल अंतःसंबंध द्वारा वर्णित किया गया है। हाल के वर्षों में, प्रमुख कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जो योजनागत व्यय का सार्थक अनुपात संघटित करती हैं, के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकारी नीति में उदाहरणीय परिवर्तन है।

संघ सरकार, सरकार की योजनागत योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों को जारी सभी सहायता अनुदानों का एक डाटाबेस का अनुरक्षण करती है। डाटाबेस को केन्द्रीय नियोजित योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.नि.यो.मॉ.प्र.) कहा जाता है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए के.नि.यो.मॉ.प्र. के डाटा के आधार पर, सहायता अनुदान व्यय का व्यापक विश्लेषण किया गया था। प्राप्तकर्ताओं की सैद्धांतिक श्रेणियों के अनुसार विद्यमान सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रबंधों सहित व्यय के विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 5.1: 2012-13 में श्रेणीवार योजनागत अनुदानों तथा लेखापरीक्षा अधिदेश को दर्शा रही है।

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	नि.म.ले.प. (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के संदर्भ में नि.म.ले.प. का लेखापरीक्षा अधिदेश
केन्द्रीय सरकारी संस्थान*	923.31	883.13	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकार/सं.शा.क्षे.	152809.42	1571.08	धारा 13
केन्द्रीय सरकारी सा.क्षे.उ.	3593.64	3172.67	धारा 19(1)
राज्य सा.क्षे.उ.	2405.81	2343.91	धारा 19(1)
सांविधिक निकाय	7966.63	6149.04	धारा 19(2) एवं (3)

श्रेणी	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	नि.म.ले.प. (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के संदर्भ में नि.म.ले.प. का लेखापरीक्षा अधिदेश
स्थानीय निकाय	3981.47	3863.25	धारा 14, 15 एवं 20 तथा तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता (प्र.भा.स.) के अंतर्गत
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वा.नि.)	159662.00	253978.26	धारा 14, 15 एवं 20
पंजीकृत समितियां (गै.स.सं.)	1531.44	1549.93	धारा 14, 15 एवं 20
निजी क्षेत्र कम्पनियां	1637.16	1288.92	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकारी संस्थान	1269.32	1231.22	धारा 13, 14, 19 एवं 20
अंतराष्ट्रीय संगठन	72.44	30.35	--
व्यक्तिगत	16.11	12.45	--
ट्रस्ट	689.07	618.45	--
कुल योजना सहायता अनुदान	**336557.82**	**276692.66**	

स्रोतः अक्तूबर 2013 में ले.म.नि. द्वारा प्रस्तुत के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प। अभिकरणों हेतु व्यवस्थित संस्वीकृति को संस्वीकृति अनुदान के खाने में लिया गया है।

** डाटाबेस में दर्शाये गये श्रेणी के नाम (अभिकरण का प्रकार) केवल 'केन्द्र सरकार' है। अभिकरण के प्रकारों में अन्य श्रेणी ब्यौरे को के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटाबेस में दर्शाए गए के अनुसार माना गया है।*

राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. के मामले में, यह उल्लेखनीय है कि 2012-13 में जारी अनुदान, ₹ 1,52,809.42 करोड़ की संस्वीकृत राशि के प्रति केवल ₹ 1,571.08 करोड़ था। इसके विपरीत, पंजीकृत समितियों (सरकारी स्वा.नि.) तथा पंजीकृत समितियों (गै.स.सं.) के मामले में निर्गत अनुदान, संस्वीकृत अनुदान से अधिक था। पंजीकृत समितियों (सरकारी स्वा.नि.) के मामले में जारी अनुदान ₹ 1,59,662 करोड़ की संस्वीकृत राशि के प्रति ₹ 2,53,978.26 करोड़ था, जो ₹ 94,316.26 करोड़ का अतिरिक्त निर्गम था। यह सोच से परे है कि उपर्युक्त मामलों में जारी किये गये अनुदान संस्वीकृत अनुदान से इतने अधिक मात्रा में भिन्न कैसे हैं। के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा में इन असंगतियों की लेखा महा-नियंत्रक द्वारा जांच करना आवश्यक है।

उपरोक्त **तालिका 5.1** में प्रथम पांच श्रेणियां सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को प्रदर्शित करती है। ऐसे मामलों में भा.नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा छूट सुस्पष्ट है। इन मामलों में अंतरण की पद्धति एक उच्च लेखांकन प्रणाली से समर्थित है तथा विशेषकर राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों से संबंधित व्यय का पता अंत में लगाया जा सकता है। जहां प्रत्यक लेन-देन से संबंधित वाउचर राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध हैं।

- योजनागत निधियों की पर्याप्त राशि पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों को भी जारी की गई है। इनमें से अधिकांश संस्थान नि.म.ले.प. के प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं हैं। नि.म.ले.प. (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 निर्धारित करता है कि नि.म.ले.प. द्वारा, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों अथवा प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा तब की जा सकेगी जब उस संस्थान के कुल व्यय का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा निधिबद्ध किया गया हो, तथा

अनुदान या ऋण के रूप में सहायता ₹ 25 लाख से अधिक हो। नि.म.ले.प. भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से वैकल्पिक रूप से उन संस्थानों की लेखापरीक्षा कर सकेगा, अगर उन संस्थानों को दी गई सहायता ₹ 1 करोड़ से अधिक हो। इस प्रकार, नि.म.ले.प. द्वारा इन संस्थाओं की, जो कि पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा निधिबद्ध है, लेखापरीक्षा करने हेतु अनुदानग्राही संस्थान के कुल व्यय के विवरण की आवश्यकता इस संतुष्टि के लिए होगी कि सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान/सहायता उन संस्थानों के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से अधिक है। यह ऐसे अस्तित्वों के वार्षिक लेखों को नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना अपेक्षित करता है। नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा एवं लेखा पर अधिसूचित विनियम में एक प्रावधान है कि सरकारों एवं विभागाध्यक्षों, जो निकायों अथवा प्राधिकरणों के अनुदान एवं ऋण संस्वीकृत करती है, को लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों की विवरणी प्रस्तुत करें जिन्हें कुल ₹ 10 लाख एंव/अथवा अधिक का ऋण विगत वर्ष के दौरान प्रदान किये गये थे, इसमें (क) सहायता की राशि; (ख) जिस प्रयोजन हेतु सहायता संस्वीकृत की गयी; तथा (ग) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाया गया हो। तथापि, वर्तमान में सरकार के पास स्वयं के द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों के वार्षिक लेखों को प्राप्त करने तथा इन लेखों को नि.म.ले.प. को प्रेषित करने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं है। यह ऐसे संस्थानों की समय से लेखापरीक्षा करने तथा नि.म.ले.प. द्वारा संसद को लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समय पर सूचित करने को भी सीमित करता है।

- कुछ प्रमुख कार्यक्रम तथा योजना दिशानिर्देश वास्तविक व्यय तथा कार्यक्रम सुपुर्दगी हेतु उप-अनुदानग्राहियों को एक भाग अथवा पूर्ण राशि सौंपने वाले प्रधान दानभोगी निकाय अथवा प्राधिकरण के साथ के माध्यम से सरकारी सहायता करने का विचार करते हैं। सरकारी निधीयन प्राप्त कर रहे विभिन्न अभिकरण तथा समितियों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 की धारा 14, 15, 19 तथा 20 के अंतर्गत की जाती है। तथापि, विद्यमान प्रावधानों में उप-अनुदानग्राहियों, कार्यान्वयन अभिकरणों, समितियों आदि जो समेकित निधि से या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, की लेखापरीक्षा हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं हैं।

- मनरेगस जैसी कुछ योजनाओं के मामले में सरकार ने सभी कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए यह अधिदेशित किया है कि उनकी लेखा पुस्तिकाओं तक नि.म.ले.प. की पहुँच को अनुमत करें। तथापि, अन्य अधिकांश मामलों में वैधिक/सांविधिक अधिदेश तो क्या कोई ऐसा कार्यकारी आदेश तक भी नहीं है। इन संस्थानों की लेखापरीक्षा प्रारम्भिक रूप से उन संस्थानों के शासी निकायों द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जा रही है। इस लेखापरीक्षा में संसद को सूचित करने की बाध्यताओं सहित स्वतन्त्रता की कमी की स्वाभाविक कमजोरी थी। मामला, लेखांकन नीतियों, लेखांकन विवरणियों के

फार्मेट अथवा इन अधिकांश संस्थानों हेतु प्रकटन आवश्यकताओं को नियंत्रित करने वाले उपयुक्त संस्थागत प्रबंधनों की कमी के पृष्ठभूमि में अधिक महत्व ग्रहण करता है।

- इसके अतिरिक्त, एक पर्याप्त संख्या में समितियां पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट केवल प्रथम स्तरीय अनुदानग्राही हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से नियोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल नहीं हैं। वे बदले में, कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुदान प्रदान करते हैं। ऐसे उप-अनुदानग्राही सीधे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते।
- स्थानीय निकायों जैसे पंचायती राज संस्थान तथा शहरी निकायों जैसे निगम एवं नगरपालिकाओं के मामलों में, अधिकांश राज्यों में, नि.म.ले.प. प्राथमिक लेखापरीक्षक नहीं है परन्तु प्राथमिक लेखापारीक्षकों को तकनीकी निर्देशन तथा पर्यवेक्षण/सहायता प्रदान कर रहा है।

अतः सहायता अनुदान से संबंधित व्यय की पर्याप्त राशि के लिए नि.म.ले.प. ना ही उन्मुक्त और ना ही अप्रतिबंधित है। इससे सार्वजनिक व्यय के प्रति उत्तरदायित्व के बड़े मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है।

यह विचार करते हुए कि सार्वजनिक लेखापरीक्षा का कार्य पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना है इसलिए इन निकायों के नि.म.ले.प. अधिदेश पर विचार-विमर्श करने हेतु नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 के विद्यमान प्रावधानों के लिए संशोधनों की सलाह दी गई थीं (नवम्बर 2009)। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्तावित किया गया था कि, समेकित निधि से सीधे अनुदानें प्राप्त कर रहे सभी निकायों तथा प्राधिकरणों तथा अन्य ऐसे निकाय/प्राधिकरण, जो अनुदान प्राप्त कर रहे अनुदानग्राहियों द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध है, की लेखापरीक्षा की जाए। इसी प्रकार यह सुनिश्चित करने हेतु कि राजस्व, छूट आदि के बांटने के माध्यम से सरकार का पक्ष संरक्षित है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान की गई थी, संविदागत करार तथा अन्य साझेदारी प्रबंधन जैसेकि पी.पी.पी. को नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा के विस्तार क्षेत्र में लाने हेतु संशोधनों को प्रस्तावित किया गया था।

व्यय विभाग ने (जनवरी 2014) में अपने उत्तर में लोक लेखा समिति को बताया कि नि.म.ले.प. (डी.पी.सी.) संशोधन अधिनियम वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई है एवं उसे मसौदा संशोधन अधिनियम में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

5.4 योजनागत सहायता अनुदान पर व्यय डाटा; समग्रता एवं उपलब्धता के मामले

सहायता अनुदान व्यय संघ सरकार हेतु योजनागत व्यय के सबसे बड़े घटक हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान व्यय ने संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के कुल योजनागत

व्यय का 75 प्रतिशत[2] संघठित किया। योजनागत सहायता अनुदान व्यय में राज्यों, पंजीकृत समितियों, कार्यान्वयन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को सहायता अनुदान व्यय की पर्याप्त प्रमात्रा संघठित करती है।

सभी नियोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्गमों को मॉनीटर करने तथा योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय के संबंध में सूचना का प्रग्रहण करने के भी दृष्टांत से केन्द्रीय नियोजित योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.नि.यो.मॉ.प्र.) स्थापित की गई थी। केन्द्रीय नियोजित योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.नि.यो.मॉ.प्र.) का अभिप्रेत प्रत्येक केन्द्रीय नियोजित योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रवाह, व्यय तथा उपयोग की गई राशि पर राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम/कार्यान्वयन अभिकरण-वार रिपोर्ट तैयार करने के साथ केन्द्र सरकार द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक विभिन्न राज्यों/अभिकरणों को किए गए निर्गमों के प्रति किए गए व्यय का पता लगाना तथा सूचित करना है। यह भी बताया गया था कि के.नि.यो.मॉ.प्र., केन्द्र द्वारा राज्य तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को किए गए निर्गमों को अंतराबध करने हेतु बैंकिंग नेटवर्क को लाभ पहुँचाने तथा योजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर निधि की स्थिति पर डाटा तथा सूचना में विसंगतियों को कम करने तथा संभावित रूप से अंतिम अभिप्रेत लाभार्थी तक भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी लक्षित है।

केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों में, के.नि.यो.मॉ.प्र. पूर्ण रूप से परिचालनात्मक है तथा सभी निर्गमों का एकल संस्वीकृति आई.डी. के सृजन के माध्यम से प्रग्रहण किया जा रहा है। सभी 785 सक्रिय नियोजित योजनाओं (अर्थात् राज्य योजनाओं से संयोजित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) हेतु वास्तविक समय आधार पर सहायता अनुदान के निर्गम के संबंध में योजना-वार, राज्य-वार, अभिकरण-वार तथा भौगोलिक योजना-वार निर्गमों पर विविध समय श्रृंखला रिपोर्ट को उपलब्ध बताया गया था।

5.4.1 डाटा के अभाव एवं संस्वीकृतियों तथा निर्गमों के मध्य अंतर

2012-13 को समाप्त हो रहे पिछले तीन वर्षों हेतु के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा जो लेखा महानियंत्रक द्वारा 15 अक्तूबर 2013 को उपलब्ध कराए गए थे, का उपलब्ध विश्लेषण डाटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि निम्नलिखित अन्य अभ्युक्तियों के अलावा अनेक डाटा कॉलम/तत्व रिक्त छोड़े गये थे।

- तीन वित्त वर्षों, 2010-13 के दौरान कुल 2,36,958 संस्वीकृतियां[3] जारी हुई थीं।
- 32,968 संस्वीकृति आदेशों में एकीकृत वित्त प्रभाग (स.वि.प्र.) द्वारा प्राधिकरण की तिथि रिक्त छोड़ी गयी थीं।

[2] पैरा सं. 1.3.7 के संदर्भ में

[3] जैसा कि संस्वीकृत लेन-देन की तालिका में सूचित है।

- 62 संस्वीकृति आदेशों में स.वि.प्र. द्वारा प्राधिकरण की तिथियां वित्त वर्ष 2012-13 की समाप्ति के बाद की थीं।

- 1,415 संस्वीकृति आदेशों में स.वि.प्र. द्वारा प्राधिकरण की तिथियां 1 अप्रैल 2010 के पूर्व की थीं, जबकि संस्वीकृति आदेश 2010-2013 के वर्षों से संबंधित थे। इनमें से एक संस्वीकृति आदेश में स.वि.प्र. द्वारा प्राधिकरण वर्ष 2000 के रूप में दिया गया था, तथा 21 मामलों में प्राधिकरण वर्ष 2001 के रूप में दर्शाया गया था।

- एक अन्य तालिका[4] में, 43,939 संस्वीकृतियों के ब्यौरे नहीं पाये गये।

- 1,00,733 संस्वीकृतियों के निर्गम हेतु बिलों/वाउचरों की तिथियों का उल्लेख नहीं था।

- 1,00,582 संस्वीकृतियों से संबंधित भुगतान करते समय उपकरणों की तिथियां, नहीं डाली गयी थीं।

- संस्वीकृतियों के निर्गम से संबंधित तालिका से प्रकट हुआ कि कुल ₹ 438.77 करोड़ की 36 संस्वीकृतियों के प्रति भुगतान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति की तिथि से पूर्व जारी[5] किया गया दर्शाया गया था।

- कुल ₹1989.56 करोड़ की 279 संस्वीकृतियों में, निर्गम को तिथि स.वि.प्र. द्वारा संस्वीकृति की तिथि के पूर्व की दर्शायी गयी थीं।

- तीन निर्गमों को छोड़कर, सभी निर्गम उपकरण प्रकार 'चैक' के माध्यम से जारी किये गये दिखाये गये थे, जबकि उपकरण संख्याएं दर्शाती थीं कि निर्गम ई-भुगतान के माध्यम से किये गये थे।

- वहां सात अभिकरण थे जो डाटाबेस में एक से अधिक बार एवं अलग पहचान के साथ पंजीकृत हुए थे। ये अभिकरण 'अभिकरण प्रकार' के अंतर्गत अलग श्रेणियों में पंजीकृत किये गये थे एवं उनको तीन वर्षों 2010-13 के दौरान कुछ समय के लिए अनुदान जारी किये गये थे। डाटाबेस में भिन्न पहचानों के साथ नौ बार पंजीकृत एक अनुदान भोगी अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट मामला नीचे दर्शाया गया है।

अभिकरण पहचान	अभिकरण का नाम	अभिकरण प्रकार
719	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	राज्य सरकारी सा.क्षे.उ.
16623	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	राज्य सरकारी सा.क्षे.उ.
17103	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान	राज्य सरकारी संस्थान
28889	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	केन्द्र सरकार
92540	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	केन्द्र सरकार
116389	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	सांविधानिक निकाय

[4] संस्वीकृत अभिकरण के ब्यौरों की तालिका

[5] प्रलेखित तिथि को वास्तविक निर्गम की तिथि के रूप में मानते हुए।

अभिकरण पहचान	अभिकरण का नाम	अभिकरण प्रकार
112932	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कृषि	केन्द्र सरकार
591204	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	केन्द्र सरकार
979602	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी	केन्द्र सरकार

अतः के.नि.यो.मॉ.प्र. के डाटाबेस में असंगतियो की बडी संख्या डाटाबेस की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता तथा नियोजन एवं मॉनीटरिंग उद्देश्यों हेतु डाटबेस से सृजित एम.आई.एस रिपोर्टों की शुद्धता के मुद्दे की ओर इंगित करती है।

5.4.2 सहायता अनुदान पर योजनागत व्यय से संबंधित डाटा के तीन स्रोतों में विभिन्नता

भारत सरकार लेखांकन मानक-2 के अनुसार, सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों के बयौरे को संबंधित वर्षों के वित्त लेखे में दर्शाना अधिदेशित है। ऐसे प्रकटीकरण वित्त लेखे के विवरणी सं.9 में एक परिशिष्ट के माध्यम से किये जाते रहे हैं। सहायता अनुदान पर व्यय से संबंधित सूचना भी ई-लेखा पोर्टल पर उपलब्ध है।

निम्न **तालिका 5.2** वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल योजनागत सहायता-अनुदान एवं राज्य/सं.शा.क्षे. सरकारों को जारी सहायता अनुदान पर व्यय की तुलना प्रस्तुत करती है, जैसाकि डाटा के तीनों स्रोतों में निहित है।

तालिका 5.2: वित्तीय वर्ष 2012-13 में तीन डाटा स्रोतों में अंतर

(₹ करोड़ में)

	वित्त लेखे के अनुसार (विवरणी सं. 9 के परिशिष्ट)	ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार	के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प के अनुसार	
			संस्वीकृत राशि	जारी राशि
राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. को जारी योजनागत सहायता अनुदान	1,42,044	1,39,106*	1,52,809@	1,571Ω
जारी कुल योजनागत अनुदान	2,93,998	2,93,995#	3,36,557^	2,76,693μ

** केवल योजनागत से सबंधित श्रेणियों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3601 एवं 3602 के अंतर्गत दर्ज किया गया वि.शी. 31, 35 तथा 36 के अंतर्गत कुल व्यय*

केवल योजनागत से संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वि.शी. 31, 35 तथा 36 के अंतर्गत कुल व्यय

@अभिकरण प्रकार राज्य सरकारें/सं.शा.के. के अंतर्गत वि.शी. 31, 35 तथा 36 के अंतर्गत अभिकरणों हेतु व्यवस्थित कुल संस्वीकृतियां.

^ वि.शी. 31,35 तथा 36 के अंतर्गत अभिकरणों हेतु व्यवस्थित कुल संस्वीकृतियां।

Ω वि.शी. 31,35 तथा 36 के अंतर्गत तथा अभिकरण प्रकार राज्य सरकारें/सं.शा.क्षे. के अंतर्गत उपकरणों/वाउचरों की कुल राशि.

μ वि.शी. 31,35 तथा 36 के अंतर्गत उपकरणों/वाउचरों की कुल राशि

नोटः 15 अक्तूबर 2013 को प्रस्तुत के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प तथा 25 जुलाई 2013 को प्रस्तुत ई-लेखा डाटा डम्प

यह तथ्य कि डाटा के तीनों स्रोत मुख्य संघटकों में व्यापक विभिन्नता सूचना के संग्रहण तथा वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक द्वारा उसके प्रकटीकरण में गंभीर कमियों की ओर संकेत करती है।

इन भिन्नताओं को देखते हुए, योजनागत सहायता अनुदान व्यय पर डाटा की प्रमाणिकता संदेहजनक थी।

सहायता अनुदान पर अंतरणों की गति को देखते हुए, लेखापरीक्षा महालेखा नियंत्रक से नियोजित योजनाओं के अंतर्गत अंतरणों के लेखांकन में शुद्धता एवं पूर्णता के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प की मांग करता है। तथापि, दीर्घकाल तक पत्राचार के बाद, के.नि.यो.मॉ.प्र. का अपूर्ण डाटा अक्तूबर 2013 में जाकर ही उपलब्ध कराया गया था।

5.5 उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)

केन्द्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदानों की प्रभावकारिता तथा उपयोग को उपयोग प्रमाणपत्रों के साधन के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 209 किसी भी अनुदानग्राही को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है तथा संस्वीकृति देने वाले प्राधिकरण को सा.वि.नि. 39 के प्रारूप में अनुदानों की पंजिका का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212 सा.वि.नि. 19क में निर्धारित उपयोग प्रमाणपत्र के साधन के माध्यम से जारी किए गए अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग को शामिल करता है। अनुदानग्राही को वित्तीय वर्ष समाप्ति से बारह माह के अन्दर उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराना अपेक्षित है। सा.वि.नि. का नियम 212(3) अनुदानग्राही निकायों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को उपलब्धि-सह-निष्पादन रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रावधान करता है।

31 मार्च 2013 तक बकाया उ.प्र. से संबंधित ब्यौरे, जैसा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गये, निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.3: बकाया उ.प्र. के विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया उ.प्र. की सं.	उ.प्र. की राशि *(₹ करोड़ में)*
1.	कृषि मंत्रालय	1496	5483.20
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	673	47.73
3.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	53	53.69
4.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1	19.00
5.	कार्पोरेट मामले मंत्रालय	18	6.70
6.	संस्कृति मंत्रालय	3574	264.62
7.	उ.पू.क्षेत्र विकास मंत्रालय	1	0.60
8.	भू विज्ञान मंत्रालय	1154	92.67
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6472	13228.90

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया उ.प्र. की सं.	उ.प्र. की राशि *(₹ करोड़ में)*
10.	आर्थिक कार्य विभाग	3	2.83
11.	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	52	198.05
12.	वाणिज्य विभाग	368	702.94
13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2650	460.63
14.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	6350	1057.79
15.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	7	1.85
16.	भारी उद्योग विभाग	28	766.64
17.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3997	3145.18
18.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	26	1.54
19.	पंचायती राज मंत्रालय	242	888.26
20.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	143	240.57
21.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	10420	1164.93
22.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	310	288.94
23.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1	18.73
24.	शहरी विकास मंत्रालय	225	334.89
25.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	345	513.78
26.	वस्त्र मंत्रालय	3432	314.09
27.	जनजाति कार्य मंत्रालय	187	68.74
28.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	8	2.51
29.	खनन मंत्रालय	18	2.98
30.	पोतपरिवहन मंत्रालय	14	7.44
31.	योजना मंत्रालय	63	1.45
32.	अंतरिक्ष विभाग	339	29.74
	योग	**42670**	**29411.61**

फरवरी 2014 को 32 मंत्रालयों/विभागों में ₹ 29,411.61 करोड़ के 42,670 उ.प्र., जो 31 मार्च 2013 को देय थे, बकाया थे। मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान किया गया था, उ.प्र. एकमात्र साधन हैं। बकाया उ.प्र. की बड़ी संख्या संबंधित मंत्रालयों में खराब मॉनीटरिंग तथा अनुपालन क्रियाविधि को दर्शाती हैं।

5.6 उच्च शिक्षा विभाग एवं वस्त्र मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच

दो मंत्रालयों/विभागों अर्थात् उच्चतर शिक्षा विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय में सहायता अनुदानों के अंतर्गत किये गये व्यय की लेखापरीक्षा में, अनुदानों के संस्वीकृति एवं मॉनीटरिंग के तंत्र तथा किये गये व्यय की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता आदि के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए समीक्षा की गयी थी। ऐसी जांच से उजागर परिणामों पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.6.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

उच्च शिक्षा विभाग एवं वस्त्र मंत्रालय के कुल व्यय का काफी हिस्सा सहायता-अनुदान पर किया जाता है। सहायता-अनुदान पर दोनों मंत्रालय/विभाग के व्यय की समीक्षा, किये गये व्यय की गुणवत्ता के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गयी है। इस प्रक्रिया में, मंत्रालय/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं प्रस्तुत किये गये उत्तर डाटा के अलावा, ई-लेखा एवं के.नि.यो.मॉ.प्र. डम्प की सूचना/डाटा का भी उपयोग किया गया है। समीक्षा का आयोजन निम्नलिखित मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया है:

- अनुदान प्रदान करने के लिए मंत्रालयों में सुस्पष्ट सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं की मौजूदगी;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में निर्धारण के अनुसार विभाग विशिष्ट नियमों तथा विनियमों की मौजूदगी;
- निर्धारित नियमों, विनियमों, सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालन करते हुए सहायता अनुदान की संस्वीकृति;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 बजट परिपत्रों एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सहायता-अनुदान के निर्गम को अधिशासित करने वाले दस्तावेजों में निहित निर्देशों का अनुपालन;
- वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान पर व्यय का समान प्रवाह;
- मंत्रालयों में सहायता-अनुदान के समयबद्ध उपयोग, निर्गमित अनुदानों से किये गये व्यय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की जांच के संबंध में प्रभावी मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग तंत्र की मौजूदगी।

अनुदान सं. 59 उच्च शिक्षा विभाग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

5.6.2 प्रस्तावना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा क्षेत्र की मूलभूत अवसरंचना के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तरदायी है। एक नियोजित विकास प्रक्रिया के अंतर्गत, विभाग, उच्च शिक्षा तक पहुंच के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार का, प्रमुख महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से देश के मानव संसाधन संभावना के उच्च शिक्षा क्षेत्र में, समानता एवं समावेश के साथ संपूर्णतः

उपयोग के माध्यम से, देख-रेख करता है।

उच्च शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को निर्धारित करना हैः

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
- विश्वविद्यालय का योजनागत विभाग तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा
- भारतीय भाषाओं का विकास,
- योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति,
- पुस्तकों को प्रोत्साहन तथा कॉपीराइट अधिनियम का प्रशासन तथा
- शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को सहित अंतराष्ट्रीय सहयोग।

उच्च शिक्षा विभाग के अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित स्वायत्त निकाय/संस्थान तथा कुछ मुख्य केन्द्रीय योजनाएं हैं।

- 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- 45 तकनीकी संस्थान -आई.आई.टी/एन.आई.टी
- 13 प्रबंधन संस्थान – आई.आई.एम.
- चार आई.टी. संस्थान
- विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान
- तीन योजना एवं वास्तुकला संस्थान
- चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान – एन.आई.टी.टी.आर.
- 11 अन्य संस्थान
- योजनाएं–
  - नये/मौजूदा बहुशिल्पों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण
  - शिक्षा ऋण ब्याज आर्थिक सहायता,
  - तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम,
  - पॉलीटेकनिकों में महिला छात्रावास का निर्माण (चरण-II)
  - नए आई.आई.एम. की स्थापना

5.6.3 बजट एवं व्यय

विभाग का कुल व्यय 2010-11 के ₹ 15,461.93 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 20,454.29 करोड़ हो गया। विभाग का योजनागत व्यय 61 से लेकर 65 प्रतिशत तक एवं गैर-योजनागत व्यय 2010-11 से 2012-13 के दौरान कुल व्यय के 35 से 38 प्रतिशत के मध्य था। विभाग का लगभग 99 प्रतिशत व्यय विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में किया गया था। इसी प्रकार, योजनागत एवं गैर-योजनागत श्रेणी में, व्यय का 98 से 99 प्रतिशत केवल सहायता-

अनुदान पर ही था। निम्न तालिका 5.4 2010-11 से 2012-13 के दौरान बजट प्रावधान (अनुपूरक प्रावधान सहित), कुल व्यय एवं सहायता-अनुदान पर व्यय की प्रबलता को दर्शाती है।

तालिका 5.4. प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		सहायता अनुदान पर व्यय	
	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत	योजनागत	गैर योजनागत
2010-11	11089.32	7694.02	9379.64	6082.29	9297.77 (99.13)	5973.96 (98.22)
2011-12	13169.72	8812.02	12574.90	6916.88	12478.62 (99.23)	6808.18 (98.43)
2012-13	15438.06	9441.02	12727.10	7727.19	12545.00 (98.57)	7597.00 (98.32)

स्रोत मु.ले.नि./मा.सं.वि. द्वारा प्रस्तुत अ.वि.मं./व्यय आंकड़ा

नोटः कोष्ठक में आंकड़े सहायता-अनुदान पर व्यय की योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय के अंतर्गत कुल व्यय के समक्ष प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

2010-11 से 2012-13 हेतु विषय शीर्ष '31 सहायता अनुदान सामान्य'; '35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानें' तथा '36 सहायता-अनुदान-वेतन' के द्वारा अनुदानों पर व्यय का गैर-समूहन निम्नानुसार हैः

तालिका 5.5: विषय शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
31-सहायता अनुदान सामान्य	10396.36	12194.58	6955.00	29545.94
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4875.37	7092.22	6989.00	18956.59
36-सहायता अनुदान वेतन	--	--	6198.00	6198.00
कुल	**15271.73**	**19286.80**	**20142.00**	**54700.53**

स्रोत मु.ले.नि./मा.सं.वि. द्वारा प्रस्तुत अ.वि.मं./व्यय आंकड़ा

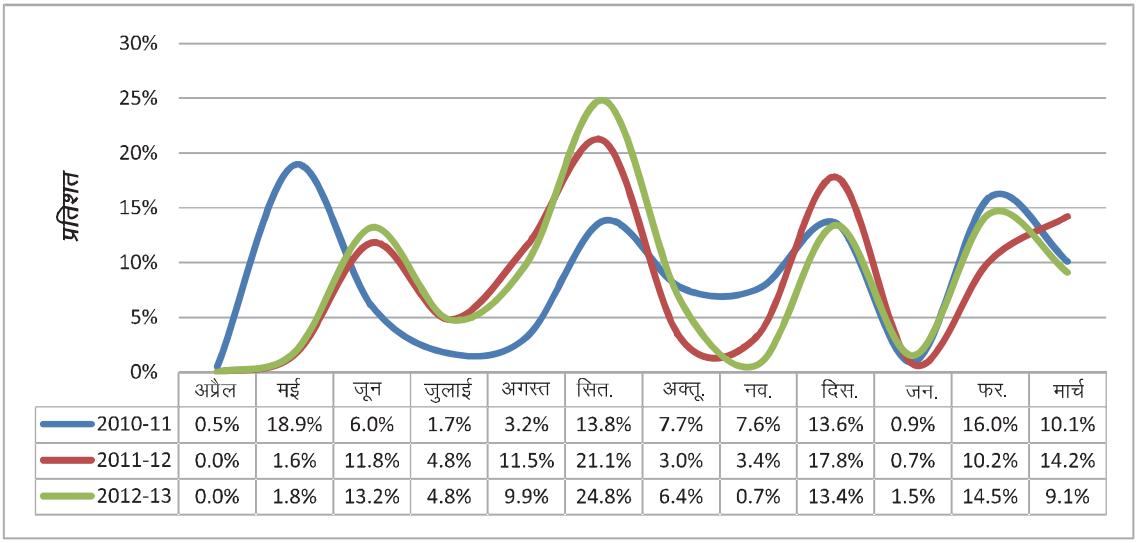
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पर व्यय 2010-11 में ₹4,875.37 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹6,989 करोड़ हो गया। सामान्य एवं वेतन प्रयोजनों हेतु अनुदानों पर व्यय 2010-11 में ₹10,396.36 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹13,153 करोड़ हो गया था।

5.6.4 सहायता अनुदानों पर व्यय का माह-वार प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियतावली, 2005 के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग को पूरे वर्ष में सहायता अनुदान पर व्यय के बराबर-प्रवाह को सुनिश्चित करना चाहिए।

वर्ष के दौरान विभाग के पूंजीगत व्यय के प्रवाह की जांच के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटाबेस की मदद से की गयी थी। यह पाया गया था कि विभाग ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान जारी करते समय उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया था। नीचे रेखाग्राफ सहायता अनुदान पर योजनागत व्यय के मासिक प्रवाह को दर्शाता है।

चार्ट 5.6: सहायता अनुदान पर योजनागत व्यय का प्रवाह (के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प से)

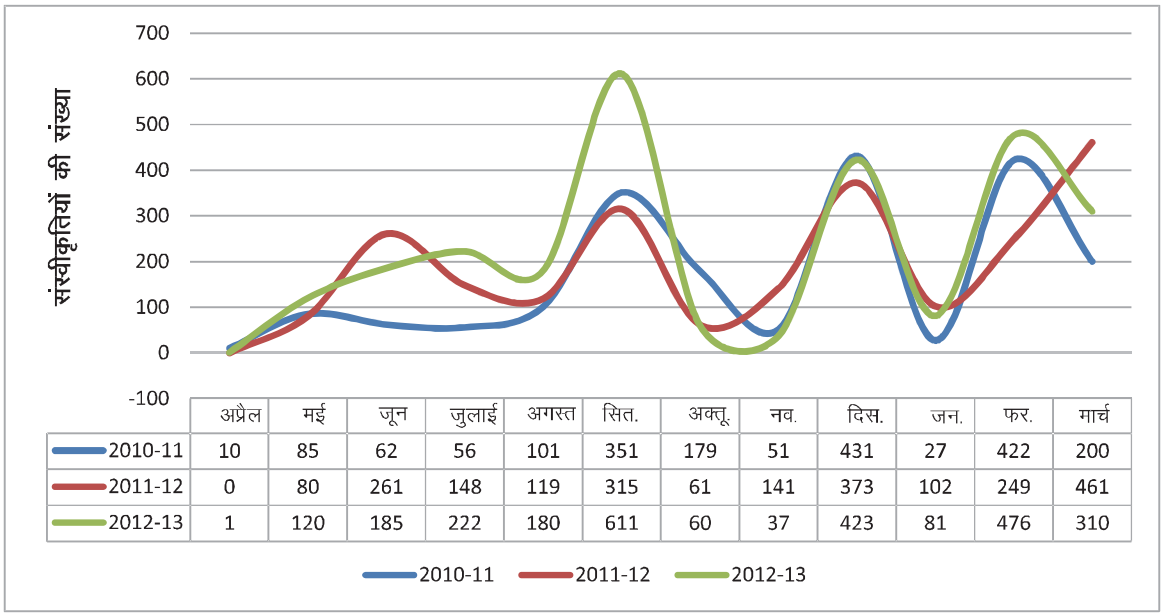


	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2010-11	0.5%	18.9%	6.0%	1.7%	3.2%	13.8%	7.7%	7.6%	13.6%	0.9%	16.0%	10.1%
2011-12	0.0%	1.6%	11.8%	4.8%	11.5%	21.1%	3.0%	3.4%	17.8%	0.7%	10.2%	14.2%
2012-13	0.0%	1.8%	13.2%	4.8%	9.9%	24.8%	6.4%	0.7%	13.4%	1.5%	14.5%	9.1%

उपर्युक्त चार्ट यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान वर्ष भर मासिक व्यय समान नहीं था। योजनागत व्यय का बड़ा भाग (2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 21.1 एवं 24.8 प्रतिशत) सितम्बर के महीने में किया गया था, जबकि पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान अप्रैल तथा जनवरी के महीने में व्यय नगण्य था।

के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा से आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि यहां तक कि अधिकांश संस्वीकृतियां वर्ष भर करने की बजाय सितम्बर, दिसम्बर एवं फरवरी के महीने में 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान प्रदान की गयी थीं।

चार्ट 5.7: सृजित संस्वीकृतियों का प्रवाह (के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प से)



	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2010-11	10	85	62	56	101	351	179	51	431	27	422	200
2011-12	0	80	261	148	119	315	61	141	373	102	249	461
2012-13	1	120	185	222	180	611	60	37	423	81	476	310

5.6.5 संस्थाओं - सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय, पंजीकृत समितियां आदि के संबंध में संस्वीकृत एवं जारी किये गये अनुदान

महालेखा-नियंत्रक नियोजित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों को जारी सभी सहायता अनुदानों के डाटाबेस का अनुरक्षण करता है। प्राप्तकर्ताओं की मुख्य श्रेणियों के संबंध में के.नि.यो.मॉ.प्र. से विश्लेषित वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान जारी सहायता अनुदानों के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं

तालिका 5.6: प्राप्तकर्ताओं के मामले में व्यय

(₹ करोड़ में)

अभिकरण का नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
	अनुदान ग्राहियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अनुदान ग्राहियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अनुदान ग्राहियों की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
केन्द्र सरकार संस्थान	1	2.00	1.00	2	1.00	1.00	2	69.00	69.00
केन्द्र सरकार सा.क्षे.उ.	9	499.66	495.56	4	821.67	820.47	6	1140.38	1132.21
अंतराष्ट्रीय संगठन	00	0	0.00	00	0	0.00	1	18.48	6.16
निजी क्षेत्र कम्पनियां	01	0.07	0.07	00	0	0.00	00	0	0.00
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	108	10401.06	7716.10	108	11880.37	10086.49	105	10883.99	9667.96
पंजीकृत समितियां (गै.स.सं).	78	5.14	3.89	9	1.91	1.83	3	2.49	1.98
राज्य सरकार	12	520.07	5.00	32	1277.15	1.55	33	650.82	4.59
राज्य सरकार संस्थान	117	43.24	40.04	7	5.54	2.78	5	5.94	5.88
राज्य सरकार सा.क्षे.उ.	499	146.49	137.35	30	3.23	3.06	22	3.71	3.13
सांविधिक निकाय	10	444.06	395.48	10	507.88	493.68	9	532.67	498.39
ट्रस्ट	14	0.06	0.05	4	0.02	0.02	00	0	0.00
कुल	**849**	**12061.85**	**8794.54**	**206**	**14498.77**	**11410.88**	**186**	**13307.48**	**11389.30**

स्रोतः अक्तूबर 2013 में म.ले.नि. द्वारा प्रस्तुत के.नि.यो.मा.प्र. डाटा डम्प

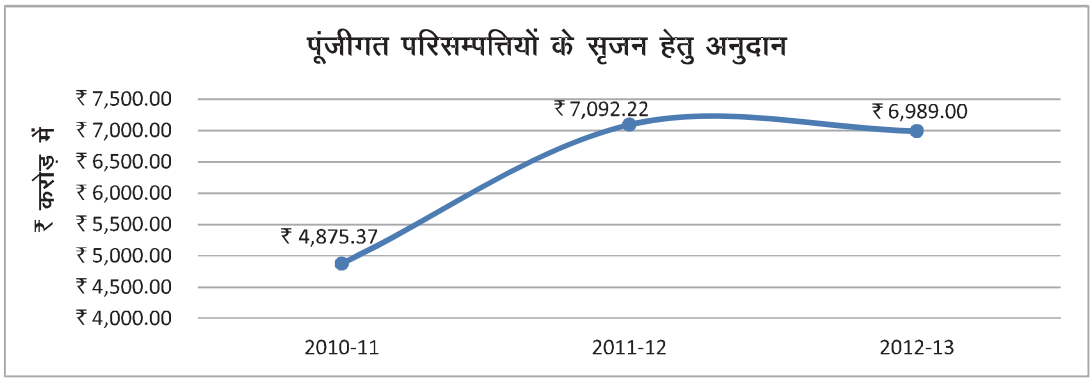
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र के अनुसार, विभाग द्वारा अनुदान हेतु विस्तृत मांग (अ.वि.मा.) में गैर-सरकारी निकायों को सहायता-अनुदान के भुगतान हेतु बजट अनुमानों में शामिल प्रावधानों को दर्शाने वाली एक अनुसूची संलग्न करना अपेक्षित है। अ.वि.मां. में संलग्न सूचियां,

के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा में उद्घटित संस्थानों की संख्या से बहुत अधिक भिन्न थीं। इसके अतिरिक्त जहां किसी योजना के अंतर्गत संस्थानों से संबंधित ब्यौरे के बगैर-एकमुश्त प्रावधान किये गये थे, संस्थानवार संवितरण के ब्यौरे संसद को बाद के चरण में सूचित करना अपेक्षित है। तथापि, विभाग के अ.वि.मां. में गैर सरकारी निकायों को सहायता अनुदान के भुगतान हेतु अनुमानों से संबंधित सूचना को शून्य दिखाया गया था, जबकि कई गैर-सरकारी निकाय पूंजीगत अनुदान प्राप्त कर रहे थे जो उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है।

विभाग ने त्रुटियों को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2014) कि भविष्य में संस्थान वार संवितरण से संसद को उचित रूप से सूचित किया जाएगा।

5.6.6 सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण

वित्त वर्ष 2009-10 एक नया वस्तु शीर्ष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भोगी निकायों को जारी अनुदानों को सुस्पष्ट रूप से दर्ज करने के लिए शुरू की गयी थी। यह शीर्ष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु जारी अनुदानों को दर्ज करने के लिए था। वर्ष 2010-11, से 2012-13 के दौरान विभाग ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ₹18,956.59 करोड़ के अनुदान जारी किए जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है:



सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 215(3)(1) यह भी आदिष्ट करता है कि किसी प्रायोजित परियोजना एवं योजना के वित्त पोषण के मामले में, यह निर्धारित किया जाए कि ऐसी निधियों से सृजित अथवा अर्जित भौतिक एवं बौद्धिक परिसंपत्तियों में स्वामित्व प्रायोजक में निहित रहे।

2012-13 के दौरान, ₹ 6,989 करोड़ के पूंजीगत अनुदान में से ₹ 1,501.56 करोड़ पांच[6] स्वायत्त निकायों को जारी किया गया था। विभाग निरंतर संस्वीकृति आदेश में एक शर्त शामिल किए जा रहा था कि सृजित परिसम्पत्तियों को विभाग की अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जाएगा। तथापि, कोई केन्द्रीकृत अभिलेख/डाटाबेस, यथा अनुदानभोगी का नाम, सृजित परिसंपत्तियों के

[6] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (₹1041.20 करोड़) ए.आई.सी.टी.ई. (₹0.12 करोड़) आई.आई.टी., दिल्ली (₹142.60 करोड़) आई.आई.टी., खडगपुर (₹153.01 करोड़) आई.आई.टी., मुम्बई (₹164.63 करोड़)

ब्यौरे, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वास्तव में उपयोग में लाये गये अनुदान की राशि, पूंजीगत हेतु वास्तव में उपयोग में लाये गये अनुदान की राशि, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स्वामित्व, इस प्रकार सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों की भौगोलिक स्थिति आदि, विभाग द्वारा न तो अनुरक्षित किये गये थे और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे।

ऐसे विवरण के अभाव में, यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यय वास्तव में उसी का परिणाम है जिससे यह पूंजीगत परिसम्पत्तियां सृजित की गई, जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत थी। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग, उस विभाग में किसी सूची जिसे विद्यमान होना चाहिए था, के अभाव में, किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा था कि अनुदानभोगी निकाय इन अनुदानों से सृजित परिसंपत्तियों को इसकी अनुमति के बिना कैसे निपटान कर रहे थे।

विभाग ने बताया कि वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 अप्रैल 2005 के अनुसार, केवल केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों के संबंध में ही परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा इस तात्पर्य में स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित परिसम्पत्तियाँ शामिल नहीं हैं चाहे परिसंपत्तियां सहायता अनुदानों के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदत्त निधीयन से सृजित की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि कार्यालय ज्ञापन केन्द्र सरकार से संबंधित परिसंपत्ति रजिस्टर को बनाने से संबंधित है, जैसाकि राजस्व उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के अंतर्गत अपेक्षित है। विभाग को, जारी किये गये अनुदानों से सृजित परिसंपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने चाहिए और ऐसी परिसंपत्तियों की एक संपूर्ण वस्तु-सूची का अनुरक्षण करें जैसा उनके अपने संस्वीकृति आदेशों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली में परिकल्पित है।

5.6.7 सहायता अनुदान रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

सा.वि.नि. 212 (4) तथा सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 4.27.2 के अनुसार, दोहरे भुगतान की सम्भाव्यता से सुरक्षा के दृष्टांत से मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा फार्म सा.वि.नि.-39 तथा सि.ले.नि.-28 में दिए गए फॉर्मैट में अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे जब तक कि उसे संबंधित संस्वीकृति के प्रति अनुभाग के रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो। यह एक मुश्त संस्वीकृति के मामले में किश्तों, यदि कोई हो, में भुगतानों पर निगरानी करने हेतु भी सुविधा प्रदान करता है।

तथापि, यह पाया गया है कि विभाग ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विभिन्न स्वायत्त निकायों/अभिकरणों को जारी सहायता अनुदानों के रजिस्टर का निर्धारित फॉर्मेट में अनुरक्षण नहीं किया है। निर्धारित रजिस्टर के अनुरक्षण के अभाव में उचित निगरानी तथा समय पर अनुदान की संस्वीकृति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता एवं अनुदान के दोहरे भुगतान को भी नहीं रोका जा सकता ।

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि सभी संबंधितों को निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार सहायता अनुदान रजिस्टर का अनुरक्षण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

5.6.8 अनुमोदन प्रक्रिया में कमिया

(क) कार्यक्रम प्रभाग द्वारा अनुमोदन तथा वास्तव में जारी भुगतान के बीच अंतर

सिविल लेखा नियमपुस्तिका के पैरा 2.3.1 के अनुसार भुगतान हेतु बिलों के उनकी प्राप्ति के अधिकतम सात कार्य दिवसों के भीतर पारित करके चैक जारी किया जाना चाहिए। लघु अवधि के अंदर बिलों को पारित करने तथा भुगतान करने के प्रति प्रयास किए जाने चाहिए तथा प्र.ले.मु.नि./ले.मु.नि./ले.नि. को इस संबंध में प्रतिमान निर्धारित करने के साथ-साथ उनके अनुपालन को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर करना चाहिए।

के.नि.यो.मॉ.प्र. के डाटा डम्प के विश्लेषण ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को योजना अनुदान के संदर्भ मे चैक जारी करने में मंजूरीदाता प्राधिकारियों द्वारा संस्वीकृति आदेश जारी करने में विलम्ब था जैसा कि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.7: सहायता अनुदान जारी करने में विलम्ब (के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा डम्प से)

(₹ करोड में)

दिनों में विलम्ब	2010-11		2011-12		2012-13	
	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि
8-30	843	2968.22	535	1867.48	752	3282.27
31-60	167	186.67	4	2.38	115	165.92
61-90	50	18.46	5	7.72	14	22.39
91-120	22	10.50	3	0.28	1	0.30
120 दिनों से अधिक	66	10.86	1	0.07	1	0.06
कुल	**1148**	**3194.71**	**548**	**1877.93**	**883**	**3470.94**

विभाग ने देरी को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2014) कि वर्ष 2012-13 के दौरान उ.प्र. जारी न किए जाने अथवा उ.प्र. को वैबसाईट पर न डाले जाने के कारण चैकों को समय पर जारी नहीं किया जा सका। तथापि, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान चैकों को जारी करने में विलम्ब के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ख) मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदान प्राप्त निकायों से संबंधित सूचना प्रदर्शित न करना

सामान्य वित्तीय नियम, 2005, के नियम 209 के अनुसार, वह संस्थान या संगठन जो सहायता अनुदान चाहते हैं उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से उसी उद्देश्य के लिए अनुदान न तो प्राप्त किया है, न ही आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त अनुदान के दोहराव को रोकने के लिए परिकल्पित नियम बताता है कि, प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को उन संस्थाओं या संगठनों के राशि विवरण के साथ अनुदान के उद्देश्य की एक सूची बनाकर उसे वेबसाइट पर डालनी चाहिए।

ऐसी कोई सूची, जो संस्था या संगठन के राशि-विवरण एवं संगठन को जारी अनुदान-राशि के उद्देश्य आदि को इंगित करती है, को नहीं बनाया गया था और न ही वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने (जनवरी 2014) मे बताया कि संबंधित प्रभाग को इस संदर्भ मे आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है ।

(ग) संगठन के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 208 (vii) के अनुसार प्रति वर्ष रूपये पांच करोड़ से अधिक की सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे सभी संगठनों को प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) किया जाना चाहिए जिसमें निवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य के कार्यक्रम के ब्यौरे के संबंध में उत्पादन लक्ष्यों तथा उत्पादन में गुणात्मक सुधार को स्पष्ट रूप से बताया गया हो। औसत दर्जे की प्रदर्शन इकाईयों को, बजटीय सहायता जो इन संगठनों को विस्तारित की गयी थी के आधार पर, उत्पादन लक्ष्य दिया गया था।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित संगठनों को ₹21,142.75 करोड़ की सीमा तक के अनुदान जारी किए गए थे परंतु विभाग ने इन संगठनों के साथ कोई स.ज्ञा. नहीं किया था क्योंकि इस संबंध में कोई सूचना/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। यहां तक कि संस्वीकृति आदेशों में भी स.ज्ञा. की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया था।

तालिका 5.8: बिना स.ज्ञा. के जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
आई.आई.टी., मुंबई	202.23	283.37	247.20	732.80
आई.आई.टी., खड़गपुर	186.77	264.50	277.14	728.41
आई.आई.टी., दिल्ली (आई.आर.डी.)	207.26	251.64	176.00	634.90
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.)	219.99	230.00	400.00	849.99
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	4315.80	5495.17	4640.87	14451.84
भारत संचार निगम लिमिटेड	270.49	107.00	111.92	489.41
कैनरा बैंक जी.बी.एम.	0.00	0.00	999.99	999.99
सी.एस.आई.एस.- ई.एल.	203.28	697.01	00.00	900.29
आई.आई.टी. चैन्नई	122.30	206.41	187.11	515.82
आई.आई.टी.कानपुर	107.89	129.84	163.85	401.58
इग्नू	93.76	91.00	105.00	289.76
एन.आई.टी., कर्नाटक	63.08	57.00	27.88	147.96
योग				**21142.75**

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि सभी संबंधितों को सा.वि.नि. 208 (vii) में शामिल निर्देशों के अनुसार स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) निर्गम, व्यय न किया जाना - अग्रिमों का गैर-प्रकटीकरण

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 (1) के नीचे नोट 2 प्रकट करता है कि केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के संबंध में, उपयोग प्रमाणपत्र किए गए वास्तविक व्यय तथा भण्डार एवं परिसम्पत्तियों हेतु आपूर्तिकर्ताओं को, निर्माण अभिकरणों को, स्टाफ को (गृह भवन एवं वाहन खरीद आदि हेतु) दिए गए ऋण एवं अग्रिमों जो ऐसे स्तर पर व्यय संघटित नहीं करती, को अलग से प्रकट करेगा। इन ऋण एवं अग्रिमों को अप्रयुक्त अनुदानों के रूप में माना जाएगा परंतु इन्हें आगे ले जाना अनुमत होगा। अनुवर्ती वर्ष हेतु अनुदान को विनियमित करते समय आगे लाई गई राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

विभाग को प्रस्तुत स्वायत्त निकाय/संस्थानों के उपयोग प्रमाणपत्रों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण अभिकरणों, स्टाफ सदस्यों आदि को ₹201.81 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम, संस्थान द्वारा प्रदान किए गए थे जैसा **अनुबंध 5.1** में ब्यौरा दिया गया है, परंतु किए गये वास्तविक व्यय तथा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, जो व्यय संघटित नहीं करते हैं, के संबंध में पृथक प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, अपेक्षित सूचना के अभाव में विभाग ने इसे उपयोग की गई अनुदानों के रूप में माना तथा इसे अनुवर्ती वर्ष में आगे नहीं ले जाया गया।

विभाग ने उत्तर (जनवरी 2014) दिया कि निर्माण अभिकरणों को दिए गए अग्रिम भुगतान का भाग है तथा इन अभिकरणों को कुल निर्गमों में इसका समायोजन किया गया है तथा ऋणों को भी विद्यमान प्रतिमानों के अनुसार समायोजित किया गया है।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के दृष्टांत में स्वीकार्य नहीं है कि निकाय द्वारा उ.प्र. में किए गए वास्तविक व्यय तथा प्रदान किए ऋण एवं अग्रिमों के संबंध में कोई अलग प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया था, और न ही विभाग द्वारा सा.वि.नि. के अनुपालन करने पर जोर दिया गया। उ.प्र. में ऐसे विवरण के अभाव में, विभाग ने संपूर्ण अनुदान को प्रयुक्त माना और सा.वि.नि. के उल्लंघन के कारण निकाय द्वारा दिए गए अग्रिमों को अनुवर्ती वर्षों मे अग्रेषित नहीं किया।

5.6.9 जारी किए गए अनुदानों की निगरानी

(क) स्वायत्त निकायों की बाह्य पीयर रिव्यू नहीं किया गया

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 208 (v) स्वायत्त संगठनों की प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों पर कार्य के आकार तथा प्रवृत्ति के अनुसार, में बाह्य अर्थात् पीयर रिव्यू की एक तंत्र प्रदान करता है ऐसी समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ उद्देश्य, जिसके लिए संगठन स्थापित किया

गया था, व उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं, पर विशेष ध्यान देगी। संगठन की गतिविधियों को जारी रखने के लिए या तो वे प्रासंगिक नहीं थी या पूर्ण हो चुकी थी या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से असफल रही थी; जबकि सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग शुल्क समान दर से लगाए गए थे; आंतरिक संसाधन उत्पादन के क्षेत्र का बढ़ाना ताकि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता आदि को कम किया जा जाए।

यह देखा गया कि 140 से अधिक स्वायत्त संगठन या संस्थान उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। ये निकाय निरंतर योजना और गैर-योजना सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। कुछ निकायों ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभाग से प्राप्त किए गए कुल ₹17,397.94 करोड़ के अनुदान का विवरण निम्नलिखित है, लेकिन इन निकायों के बाह्य पीयर रिव्यू के संदर्भ में सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

तालिका 5.9: निकायों का ब्यौरा जिनकी बाह्य पीयर रिव्यू नही किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्वा.नि.का नाम	'योजनागत' के अंतर्गत अदा की गई स.अ.			
		2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	4315.80	5495.17	4640.87	14451.84
2.	आई.आई.टी., मुंबई	202.23	283.37	247.20	732.80
3.	आई.आई.टी., खड़गपुर	186.77	264.50	277.14	728.41
4.	आई.आई.टी., दिल्ली (आई.आर.डी.)	207.26	251.64	176.00	634.90
5.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अ.भा.त.शि.प.)	219.99	230.00	400.00	849.99
कुल		**5132.05**	**6524.68**	**5741.21**	**17397.94**

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि वि.आ. तथा अ.भा.त.शि.प. की बाह्य पीयर रिव्यू अपेक्षित नहीं है क्योंकि इन स्वायत्त संगठनों को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। आई.आईटी. के संबंध में बाह्य पीयर रिव्यू किए जाने हेतु प्रयास किए गए हैं।

(ख) निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया

सामान्य वित्तीय नियम 212(3)(i) निर्धारित करता है कि अनुदानग्राही संस्थानों अथवा संगठनों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होनी चाहिए। इस संबंध में संबंधित प्राधिकरण द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की जाए और यह आवश्यकता सहायता अनुदान और स्वीकृत आदेश में शामिल किया जाए।

अनुदान संस्वीकृत करने वाले विभाग द्वारा जारी स्वायत निकायों/अभिकरणों/संस्थानों आदि को सहायता अनुदान के निर्गम हेतु जारी संस्वीकृति आदेश, आवश्यकता तथा समय सीमा, जिसके भीतर अनुदानग्राही संस्थान को निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी कल्पित थीं, का उल्लेख नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदनों की प्राप्ति को मॉनीटर करने हेतु विभाग में कोई क्रियातंत्र विद्यमान नहीं है।

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि निष्पादन प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में सभी संबंधितों को सूचना जारी कर दी गई है।

(ग) त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण

संघ सरकार के लेखे के विभागीयकरण की योजना लेखे में विशुद्धता तथा लेखांकन ढांचे के संचालन में दक्षता, को सुनिश्चित करने हेतु एक आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना का प्रावधान करती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, लेखापरीक्षा जांच के परिपालन को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रीय सूचनाएं, सामान्यतः भारत सरकार एवं विशेष मंत्रालय द्वारा स्थापित नियमों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुकुल हैं। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित वित्तीय एंव लेखा अभिलेख, नियमों का अनुपालन एवं विनियमन, नियत्रंण शिथिलताएं इत्यादि जाँच से अलग आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्पादन पहलू पर भी गौर करना चाहिए एवं जारी की गई निधि के वास्तविक उपयोग तथा जो योजनाएं लागू की गई हैं के द्वारा अभिप्रेत लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, का मूल्यांकन करना चाहिए।

सा.वि.नि. 212(1) भी बताता है कि मंत्रालय एवं विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा सौंपा गया प्रतिवेदन एवं भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निष्पादन प्रतिवेदन, यदि कोई हो, उस वर्ष के अनुदान स्वीकृत करते समय इसे भी ध्यान मे रखना चाहिए ।

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, तथा वह उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत निकायों/संस्थान आदि सहित इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान की आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.10: आंतरिक लेखापरीक्षा के ब्यौरे

वर्ष	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा किए जाने हेतु नियोजित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की वास्तविक संख्या
2010-11	145	2	1
2011-12	145	0	0
2012-13	145	6	2

यह स्पष्ट है कि 145 इकाईयों में से वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु क्रमशः केवल 2 तथा 6 इकाईयों की योजना की गई थी, जबकि 2011-12 के दौरान किसी भी इकाई की योजना नहीं की गई थी। विभाग द्वारा संपूर्ण राशि खर्च किए जाने के बावजूद भी, आंतरिक निगरानी प्रणाली, आकार, व्यय तथा विभाग के कार्यों के अनुरूप नहीं है। एक मजबूत और प्रभावी आंतरिक निगरानी के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता कि

विभाग नियमों का पालन, विनियमन एवं अनुदान प्राप्त निकायों के दिन प्रति दिन के कार्यों एवं कार्यक्रम के वितरण में प्रचलित निर्देशों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित करता है ।

विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि उत्तम प्रयासों के बावजूद प्रखर संसाधनों की कमी के कारण सभी स्वीकृत इकाईयों की लेखापरीक्षा को शामिल नहीं किया जा सका।

(घ) वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से संसद को ब्यौरों की सूचना न देना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 212 (2)(i) प्रावधान करता है कि ₹10 लाख से रूपये ₹25 लाख तक की आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे निजी/स्वैच्छित संगठनों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों अथवा विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक ऐसे संगठनों को प्रदान निधियों की प्रमात्रा तथा उद्देश्य जिसके लिए इनका उपयोग किया गया को दर्शाने वाली एक विवरणी संसद को सूचना प्रदान के लिए शामिल करनी चाहिए। निजी एंव स्वैच्छिक संगठन जो ₹25 लाख या इससे अधिक का आवर्ती अनुदान प्राप्त कर्ज वाले अनुदानग्राही संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं लेखाओं को आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीनों के अन्दर संसद पटल पर रखा जाना चाहिए।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा 15 निजी संस्थानों/व्यक्तिगतों को हिन्दी के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु क्रमशः ₹5.39 करोड़ तथा ₹5.32 करोड़ का आवर्ती अनुदान जारी किया गया था जैसा **अनुबंध 5.2** में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान निम्नलिखित पंजीकृत समितियों (गै.स.सं.) को ₹6.65 करोड़ का आवर्ती अनुदान भी प्रदान किया था।

तालिका 5.11: आवर्ती सहायता अनुदान के भुगतान के विवरण

(₹ करोड़ में)

पंजीकृत समिति का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	*कुल
भारतीय विश्वविद्यालय संघ	0.60	0.58	0.44	1.62
पर्यावरण शिक्षा केन्द्र	1.16	0.00	0.30	1.46
सभ्यता अध्ययन केन्द्र	1.10	1.02	1.24	3.36
राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	0.00	0.21	0.00	0.21
कुल	**2.86**	**1.81**	**1.98**	**6.65**

**स्रोतः के.नि.यो.मॉ.प्र. से प्राप्त डाटा*

जैसाकि सा.वि.नि. के अन्तर्गत अपेक्षित था, विभाग ने संसद को सूचना हेतु अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उपरोक्त अभिकरणों के नाम तथा उद्देश्य जिसके लिए उन्हें अनुदान जारी किया गया था, को शामिल नहीं किया है।

(ङ) बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)

सा.वि.नि., 2005 का नियम 212(1) निर्धारित करता है कि संस्थान या संगठन को अनावर्ती अनुदान प्रदान करने के संबंध में, सा.वि.नि. के प्रपत्र 19 (ए) में जिस उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र करने हेतु, अनुदान स्वीकृति आदेश मे इस बात पर बल दिया जाना चाहिए। आवर्ति अनुदान के संबंध में, उ.प्र. में इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए कि विशेषीकृत, मानकीकृत एवं गुणात्मक लक्ष्य, निर्गत राशि के सापेक्ष तथ्यतः प्राप्त किए गए है, और यदि नहीं, तो इसका कारण बताया जाना चाहिए । उ.प्र. में आगत आधारित निष्पादन मूल्यांकन के स्थान पर उत्पादन आधारित निष्पादन मूल्यांकन को शामिल किया जाना चाहिए। आवर्ती अनुदान के संबंध मे, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष का उ.प्र. प्राप्त होने के पश्चात ही आगामी वित्तीय वर्ष का अनुदान जारी करना चाहिए।

संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के बारह माह के भीतर उ.प्र. प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय या विभाग को ऐसे उ.प्र. की प्राप्ति की संवीक्षा करनी होगी, जहाँ अनुदानग्राही संस्थाओं से निर्धारित समय के भीतर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, मंत्रालय या विभाग को ऐसी संस्था या संगठन को भविष्य में अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सरकारी वित्तीय सहायता न प्रदान करने हेतु काली सूची में डालने की स्वतन्त्रता होगी। सा.वि.नि. के नियम 209(1) के अंतर्गत टिप्पणी में संदर्भ में है इस तथ्य को वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए।

विभाग में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया है कि विभाग द्वारा 2011-2012 में जारी किए गए अनुदान के संदर्भ में 13 नवम्बर 2013 तक 2634 उ.प्र. जिनकी कुल राशि ₹1001.89 करोड़ थी, बकाया थे जैसा कि अनुबंध 5.3 मे वर्णित हैं।

आयुवार विश्लेषण ने प्रकट किया कि ₹1.57 करोड़ (0.16 प्रतिशत) की कुल राशि के उ.प्र. 30 वर्षों से अधिक से लंबित थे, ₹26.45 करोड़ (2.64 प्रतिशत) के 20 वर्षों से अधिक से, ₹50.33 करोड़ (5.02 प्रतिशत) के 10 वर्षों से तथा ₹923.54 करोड़ (92.18 प्रतिशत) के पिछले 10 वर्षों (2003-2012 तक) से समायोजन हेतु लंबित थे। अनुदानों की संस्वीकृति को सबसे पहले की अवधि, जिसके लिए उपयोग प्रमाणपत्र बकाया है, वर्ष 1977-78 से संबंधित हैं।

विभाग ने न तो दोषी संस्थानों/ संगठनों को काली सूची में डालने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ की और न ही बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की लम्बिता को कम करने हेतु कोई प्रयास किए।

चूंकि निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. एकमात्र एक क्रियाविधि है, विभाग को उ.प्र. की सामयिक प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्थ क्रियाविधि स्थापित करना चाहिए। उन मामलों में निधियों की धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिनमें अनुदानभोगी संगठनों ने उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण में असाधरण रूप से विलम्ब किया है।

बकाया उ.प्र. की राशि दिसम्बर 2013 में ₹632.44 करोड़ तक नीचे आई। विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि बकाया उ.प्र. को कम करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

5.6.10 वि.अ.आ. को अधिक अनुदान जारी किया जाना

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2012-13 के लिए वि.अ.आ. को सामान्य अनुदान हेतु (उ.पू.क्षे.) ₹419.62 करोड़ का आबंटन किया गया था। मार्च 2013 में स.अ. चरण पर आबंटन को ₹419.62 करोड़ के मूल आबंटन के प्रति ₹385.24 करोड़ तक घटा दिया गया था।

वि.अ.आ. ने दिनांक मई 2012 के अपने पत्र के द्वारा विभाग को सूचित किया कि पिछले वर्ष से संबंधित ₹187.41 करोड़ की अप्रयुक्त राशि उनके पास 31 मार्च 2012 तक पड़ी रही एवं अव्ययित शेष को 2012-13 के दौरान उपयोग करने के लिए अग्रेषित करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था, जिसे विभाग द्वारा इस शर्त पर स्वीकार किया गया था कि उस वर्ष 2012-13 हेतु आबंटन के अतिरिक्त नहीं होगा।

विभाग ने कुल ₹130.47 करोड़ जारी किए जिसमें सितम्बर 2012 में ₹25.56 करोड़ की प्रथम किश्त तथा जुलाई 2012 तथा ₹104.91 करोड़ की दूसरी किश्त सितम्बर 2012 में जारी की।

बाद में, वि.अ.आ. ने लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय विभाग को सूचित किया कि 2011-12 के दौरान उनके द्वारा प्राप्त ₹381.73 करोड़ का संपूर्ण अनुदान अप्रयुक्त पड़ा रहा।

अतः वर्ष 2012-13 के दौरान वि.अ.आ. के पास ₹512.20 करोड़ उपलब्ध था, जो कि ₹385.24 करोड़ के सं.अ. से ₹126.96 करोड़ अधिक था जो वि.अ.आ. द्वारा लेखापरीक्षित लेखों तथा उ.प्र. के प्रस्तुत किए जाने पहले वि.अ.आ. द्वारा कम अप्रयुक्त शेष सूचित किए जाने के कारण था। इस प्रकार, मंत्रालय के पास निधियों के निर्गम के पूर्व अनुदानग्राही संस्थानों के पास अव्ययित शेष को मॉनीटर करने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं थी।

विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते समय बताया (जनवरी 2014) कि प्रथम तिमाही हेतु अनुदानों के निर्गम के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय वि.अ.आ. ने जुलाई 2012 में ₹187 करोड़ का प्रावधानिक अव्ययित शेष सूचित किया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रथम तिमाही हेतु अनुदानों को प्रावधानिक उ.प्र. के आधार पर अव्ययित निधियों का निर्धारण करने के पश्चात जारी किया गया था। तथापि, जनवरी 2013 में प्रस्तुत लेखापरीक्षित उ.प्र. के अनुसार वि.अ.आ. ने ₹381.73 करोड़ का अव्ययित शेष सूचित किया। इस विसंगति को वि.अ.आ. के संज्ञान में लाया गया था। अगली तिमाहियों के लिए आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

अनुदान सं. 93- वस्त्र मंत्रालय

5.6.11 प्रस्तावना

वस्त्र मंत्रालय नीति निरूपण, योजना एवं विकास, निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार विनिमय, वस्त्र क्षेत्र की सदियों पुरानी संस्कृति धरोहर को बढ़ावा देने एवं संरक्षित करने हेतु उत्तरदायी है। मुख्य उप-क्षेत्र, जो वस्त्र क्षेत्र को बनाते हैं, में संघटित सूत/मैन मेड फाईबर टेक्सटाईल मिल इंडस्ट्री, मैन/मेड फाईबर/फिलामेन्ट यार्न इण्डस्ट्री, ऊन एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम उत्पादन एवं रेशम वस्त्र उद्योग, हथ करघा, हस्तशिल्प, जूट एवं जूट वस्त्र तथा वस्त्र निर्यात शामिल है।

मंत्रालय के दो संलग्न कार्यालय अर्थात् कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा कार्यालय विकास आयुक्त (हथ करघा) और दो अधिनस्थ कार्यालय अर्थात् कार्यालय वस्त्र आयुक्त तथा कार्यालय जूट आयुक्त हैं।

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संगठन/निकाय निम्नलिखित हैः-

11	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
05	सांविधिक निकाय
02	स्वायत्त निकाय
11	निर्यात प्रोत्साहन परिषद्
08	वस्त्र अनुसंधान संघ
08	परामर्शी निकाय

(स्रोतः परिणाम बजट 2013-14)

5.6.12 राजस्व लेखा पर प्रावधान एवं व्यय

मंत्रालय का राजस्व व्यय 2011-12 में ₹4799.55 करोड़ से 2012-13 में ₹4249.67 करोड़ तक कम हुआ है। सहायता अनुदान पर व्यय मंत्रालय के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक है। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान पर व्यय योजना राजस्व व्यय के 30 से लेकर 39 प्रतिशत के बीच था, जबकि गैर योजनागत सहायता अनुदान व्यय के लिए, यह 4 से लेकर 58 प्रतिशत के बीच था जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। 2010-11 में, गैर-योजनागत राजस्व व्यय के प्रति गैर-योजनागत सहायता अनुदान व्यय की प्रतिशतता ऋण माफी तथा हानि की प्रतिपूर्ति पर अधिक व्यय से ₹7,297.67 करोड़ तक घटा, जबकि अनुदानों पर व्यय की मात्रा उसी सीमा में रही।

तालिका 5.12: राजस्व लेखा पर प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		सहायता अनुदान पर व्यय		वास्तविक व्यय की तुलना में सहायता अनुदान का प्रतिशत	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
2010-11	4696.41	8603.83	4214.01*	8598.82*	1371.42	367.18	33	04
2011-12	5282.64	816.60	4188.40	611.15	1248.18	357.49	30	58
2012-13	6977.77	797.93	3593.66	656.01	1398.03	326.23	39	50

स्रोतः ई-लेखा

** अनुदानों हेतु विस्तृत मांग (अ.वि.मां)*

5.6.13 अनुदानों पर विषय शीर्ष वार व्यय

2010-11 से 2012-13 के लिए वस्तु शीर्षों '31-सहायता अनुदान सामान्य',35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा 36-सहायता अनुदान वेतन द्वारा व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 5.13: विषय शीर्ष वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
31-सहायता अनुदान सामान्य	1738.60	1199.26	1122.64	4060.50
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	शून्य	388.63	361.93	750.56
36-सहायता अनुदान वेतन	शून्य	17.78	239.69	257.47
कुल	**1738.60**	**1605.67**	**1724.26**	**5068.53**

(स्त्रोत: ई-लेखा)

तालिका से यह स्पष्ट है कि 'सहायता अनुदान सामान्य' पर व्यय मंत्रालय द्वारा अनुदानों पर किए गए कुल व्यय के 80 प्रतिशत से भी अधिक था।

5.6.14 अस्तित्वों के अनुसार व्यय - सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय, पंजीकृत सामितियां आदि

प्राप्तकर्ताओं की मूल श्रेणियों के अनुसार के.यो.यो.मा.प्र. डाटाबेस से विश्लेषित 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान जारी योजनागत सहायता अनुदान के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए है:

तालिका 5.14: प्राप्तकर्ताओं के अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

अभिकरण का नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
	अनुदानग्राही की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अनुदानग्राही की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	अनुदानग्राही की संख्या	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
केन्द्र सरकारी निकाय	-	-	-	-	-	-	1	7.40	
केन्द्र सरकारी सा.क्षे.उ.	11	365.93	175.20	8	133.89	75.53	7	196.95	157.83
निजी क्षेत्र कम्पनियां	39	288.66	205.78	33	230.55	170.74	57	385.40	261.40

पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	59	365.20	165.63	59	203.76	125.55	52	134.72	109.60
पंजीकृत समितियां (गै.स.सं.)	1094	119.41	93.71	1098	125.32	96.92	958	117.61	97.25
राज्य सरकार	28	163.71	1.76	28	267.29	0.94	24	108.72	0.32
राज्य सरकारी संस्थान	2	0.29	0.17	3	0.24	0.24	5	0.83	0.35
राज्य सरकारी सा.क्षे.उ.	70	44.13	35.67	67	49.66	40.54	64	38.04	20.64
सांविधिक निकाय	7	498.75	466.83	6	738.25	528.55	9	947.25	616.18
स्थानीय निकाय	1	0.18	0.18						
ट्रस्ट	16	5.17	4.44	32	12.26	9.44	26	11.12	10.81
व्यक्तिगत	34	0.87	0.79	14	0.34	0.29	13	0.42	0.30
कुल	**1361**	**1852.30**	**1150.16**	**1348**	**1761.56**	**1048.74**	**1216**	**1948.47**	**1278.05**

(स्रोतः- के.यो.यो.मा.प्र.) डाटा ढेर आंकड़े केवल वस्तु शीर्ष कोड '31,35 तथा 36' के लिए। संस्वीकृत अनुदान=प्रत्येक अभिकरण को संस्वीकृत राशि जैसी संस्वीकृत अभिकरण व्यवस्था हेतु तालिका में व्यवस्था दी गई है। जारी अनुदान=संस्वीकृत भुगतान निपटानों की तालिका में दर्शायी राशि।

मंत्रालय के बजट अनुभाग ने अनुदेयी के प्रकार/श्रेणी तथा किस उद्देश्य के लिए किसे सहायता अनुदान संवितरित किया था से संबंधित व्यापक जानकारी का अनुरक्षण नहीं किया था। हालांकि,मंत्रालय के अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में पिछले वर्षो के लिए निजी संस्थानों/संस्थाओं/व्यक्ति को ₹ 5 लाख (आवृत्ति)/₹10 लाख (अनावृत्ति) से अधिक के संवितरित अनुदानों और गैर-सरकारी निकायों को आवृत्ति अनुदानों के भुगतान हेतु प्रावधान से संबंधित कुछ सूचना दी गई है।

न तो मंत्रालय और न ही ले.म.नि. सहायता अनुदानों का उप-अनुदानग्राही वार संवितरण तथा इन संवितरणों के प्रति वर्ष वार व्यय का अनुरक्षण करता है जबकि केन्द्रीय रेशम बोर्ड जैसे सांविधिक निकायों को जारी अनुदानों की बड़ी राशि को आगे राज्य सरकारों द्वारा उप-अनुदानग्राहियों को जारी किया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान योजनागत अनुदानों की बड़ी राशि (29 प्रतिशत अथवा ₹369.46 करोड़) गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों को जारी की गई थी। इनमें से अधिकांश संस्थान प्रत्यक्ष रूप से नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं हैं।

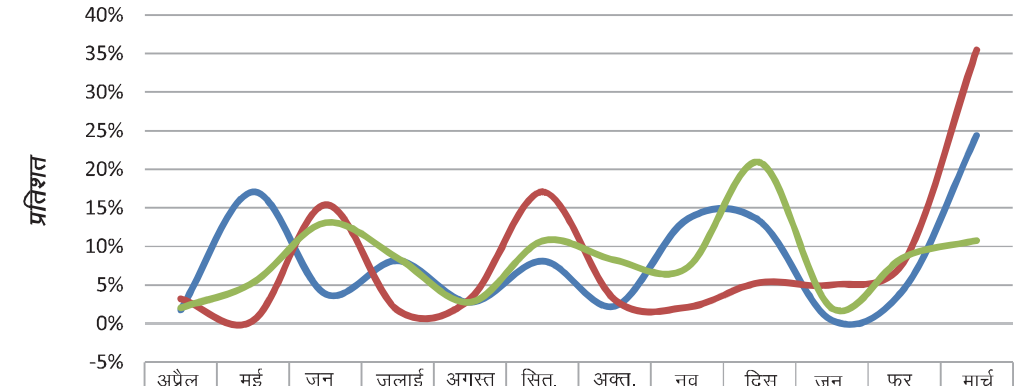
मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि के.यो.यो.मा.प्रा. में सूचना को अनुरक्षित किया जा रहा था और सभी प्रभागों को 2014-15 से सहायता अनुदान के अनुदानग्राही एवं उप-अनुदानग्राही वार संवितरण तथा वास्तविक व्यय के पृथक अभिलेख का अनुरक्षण करने हेतु एक संदर्भ किया जा रहा था।

5.6.15 सहायता अनुदान पर माह वार व्यय का प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग को पूरे वर्ष में व्यय के समान प्रवाह को सुनिश्चित करना चाहिए।

तथापि, यह पाया गया था कि वस्त्र मंत्रालय ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान जारी करते समय सा.वि.नि. के उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया था जैसा नीचे चार्ट से सुस्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में, जून, सितम्बर के महीनों में अधिक अनुदान जारी किए गए और मार्च में सबसे अधिक स्तर पर पहुँच गए थे। जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए, दिसम्बर के माह में सबसे अधिक अनुदान जारी किए गए थे।

चार्ट 5.8: सहायता अनुदान को माह-वार जारी किया जाना

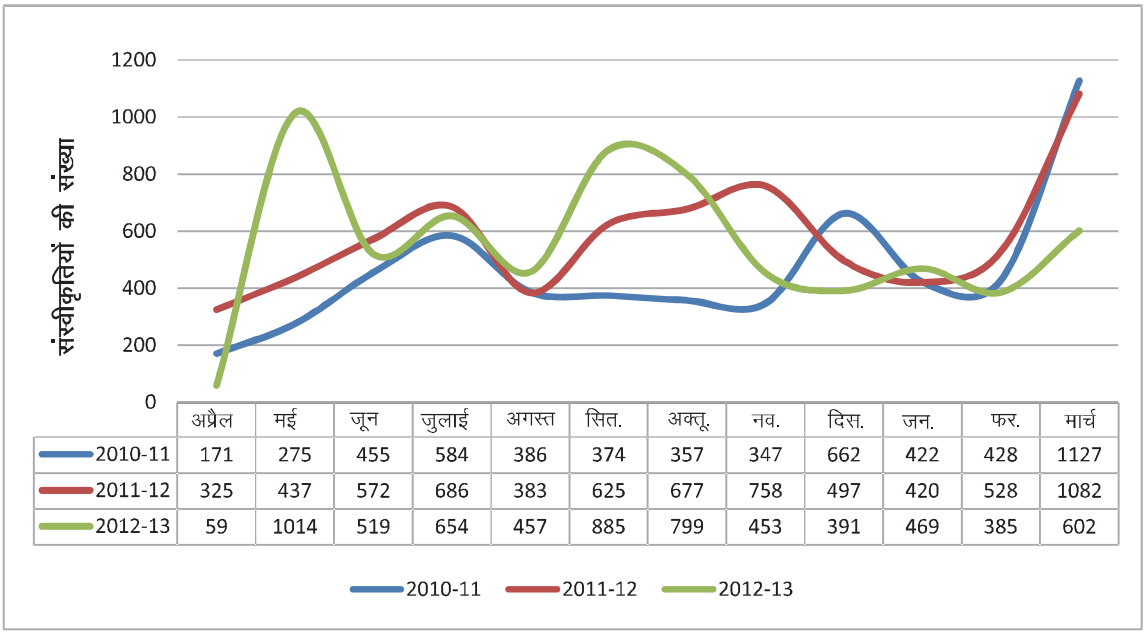


	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2010-11	2%	17%	4%	8%	3%	8%	2%	14%	13%	0%	5%	24%
2011-12	3%	0%	15%	2%	3%	17%	3%	2%	5%	5%	8%	35%
2012-13	2%	5%	13%	8%	3%	11%	8%	7%	21%	2%	9%	11%

(स्रोतः ई-लेखा)

लेखापरीक्षा को प्रदत्त के.यो.यो.मा.प्र. डाटा में से बाद के विश्लेषण ने प्रकट किया कि यहां तक की प्रत्येक माह की सृजित संस्वीकृतियों की संख्या सार्थक रूप से विविध थी। यह देखा जा सकता है कि मार्च 2011, मार्च 2012 और मई 2012 के महीनों में अनुमोदनों की संख्या बहुत अधिक थी। दूसरी ओर, अप्रैल 2010 एवं अप्रैल 2012 के महीनों में यह संख्या बहुत कम थी।

चार्ट 5.9: सृजित संस्वीकृतियों की संख्या का माह वार प्रवाह



	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2010-11	171	275	455	584	386	374	357	347	662	422	428	1127
2011-12	325	437	572	686	383	625	677	758	497	420	528	1082
2012-13	59	1014	519	654	457	885	799	453	391	469	385	602

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.16 मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा ₹750.56 करोड़ के मूल्य की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन का आश्वासन न देना

वित्तीय वर्ष 2009-10 से, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानग्राही निकायों को जारी किए गए अनुदानों की स्पष्ट रूप से गणना के लिए सरकार द्वारा एक नए वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' शुरू किया गया था।

वस्त्र मंत्रालय ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान विषयशीर्ष पूंजीगत परिसंपत्तियों को सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत ₹750.56 करोड़[7] जारी किए। मंत्रालय कुछ संस्वीकृति आदेशों में एक शर्त शामिल किए जा रहा था कि अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों का मंत्रालय की स्वीकृति के बिना निपटान नहीं किया जाएगा। सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 215(3) (1) भी आदिष्ट करता है प्रायोजित परियोजना एवं योजनाओं के निधिकरण के मामले में, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि ऐसी निधियों से प्राप्ति या सृजित भौतिक और बौद्धिक परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्रायोजक में निहित होगा।

[7] 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹388.63 एवं ₹361.93 करोड़, अर्थात 2010-11 में इस शीर्ष के अंतर्गत कोई राशि दर्ज नहीं की गई थी।

तथापि, मंत्रालय द्वारा कोई केन्द्रीकृत रिकार्ड/डाटाबेस अर्थात-अनुदानग्राही का नाम, परिसम्पत्तियों की प्रकृति सहित सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए वास्तविक अनुदान के उपयोग की राशि उन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व आदि, अनुरक्षित नहीं किया गया था।

उक्त अनुदान में से ₹356.88 करोड़ की राशि निम्नलिखित दो संगठनों को जारी की गई थीं:-

तालिका 5.15: पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन का आश्वासन न देना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	सहायता अनुदान का उद्देश्य	जारी अनुदान 2011-12	जारी अनुदान 2012-13
1.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	प्रशासनिक व्यय के प्रति पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु	23.00	13.85
		रेशम उद्योग के प्रति पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु	152.03	130.86
		उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के प्रति पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु	19.60	15.88
2.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	बोर्ड की स्वीकृत योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु	1.16	0.50
योग			**195.79**	**161.09**
कुल योग			**356.88**	

स्रोतः ई-लेखा

तथापि ऊपर उल्लेखित मामलों में मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृति आदेशों में न तो सृजित किए जाने वाली परिसम्पत्तियों के ब्यौरों के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश शामिल थे और न ही अनुदानग्राही को प्राप्त अनुदानों के बदले सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के ब्यौरों के संबंध में मंत्रालय को सूचित करना अपेक्षित था।

चूंकि मंत्रालय के पास अनुदानग्राही द्वारा सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए गए ₹750.56 करोड़ के व्यय का आश्वासन नहीं दिया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप जिसके लिए अनुमोदन संस्वीकृत किया गया था उसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट नहीं है कि विभाग में किसी वस्तुसूची की अनुपस्थिति में, विभाग कैसे यह सुनिश्चित कर रहा था कि बिना उसके अनुमोदन के, जैसा कि संस्वीकृति आदशों में निर्धारित है, इन अनुदानों में से सृजित परिसंपत्तियों का निपटान अनुदानग्राही निकाय नहीं कर रह थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि सभी प्रभागों को जिस उद्देश्य के लिए अनुदान संस्वीकृत किए जा रहे थे, उसके लिए अभिलेख/डाटाबेस का अनुरक्षण करने हेतु अनुरोध किए जा रहे थे तथा संबंधित संगठनों को अपने प्रमाण पत्रों में सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों, स्वामित्व, मूल्य, भौगोलिक स्थिति, परिसम्पत्ति प्रकार आदि के विवरण सहित यह प्रमाणित करना चाहिए कि राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए अनुदान संवितरित किया गया था।

5.6.17 ₹5 करोड़ से अधिक का सहायता अनुदान जारी किए जाने के मामले में समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) हस्ताक्षरित नहीं किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 208 (vii) के अनुसार, ₹5 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ आनुपातिक निवेश आवश्यकताओं सहित कार्य के कार्यक्रम तथा उत्पादन में गुणात्मक सुधार के विवरणों के अनुसार उत्पादन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से बताने वाला एक स.ज्ञा. अपेक्षित है। निष्पादन के परिणाम योग्य इकाइयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य इन संगठनों को दिए गए बजटीय सहायता बढ़ाने का आधार होने चाहिए।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान, ₹1,163.09 करोड़ के औसतन योजनागत अनुदानों को निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को जारी किया गया था, परन्तु प्रत्येक को ₹5 करोड़ प्रतिवर्ष से भी अधिक की बजटीय सहायता दिए जाने के बावजूद मंत्रालय द्वारा अनुदानग्राही निकायों के साथ कोई स.ज्ञा. नहीं किया गया था।

तालिका 5.16: संस्थानों के साथ हस्ताक्षर न किए गए स.ज्ञा.

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों/संगठनों का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	योग
1.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	320.00	314.56	255.08	889.64
2.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	98.04	12.00	8.57	118.61
3.	वस्त्र समिति	7.46	*	*	7.46
4.	हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन परिषद	11.95	7.60	5.83	25.38
5.	फेयरडील वस्त्र उद्यान प्रा.लि.	12.00	12.00	0.00	24.00
6.	किशनगढ़ हाई-टेक वस्त्र उद्यान लि.	24.00	0.00	0.00	24.00
7.	लुधियाना एकीकृत वस्त्र उद्यान लि.	20.00	0.00	0.00	20.00
8.	अस्मिता इन्फ्राटेक प्रा.लि.	8.00	12.00	12.00	32.00
9.	ब्रज एकीकृत वस्त्र उद्यान लि.	12.00	0.00	0.00	12.00
10.	भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.	0.00	0.00	10.00	10.00
योग					**1163.09**

(स्रोत-के.नि.यो.मॉ.प्र. डाटा)

** 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान वस्त्र समितियों को क्रमशः ₹ 4.22 करोड़ तथा ₹ 4.57 करोड़ के योजनागत अनुदानें जारी किए गए थे।*

मंत्रालय ने (फरवरी 2014) बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

5.6.18 अनुदानग्राही से राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों की प्रमात्रा का पता लगाए बिना अनुदानों का निर्गम

सा.वि.नि. के नियम 209(1) में यह कहा गया है कि सहायता अनुदान की मांग करने वाले किसी भी संस्थान या संगठन को प्रमाणित करना होगा कि उसने उसी उद्देश्य या गतिविधि के लिए राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग से अनुदान प्राप्त या आवेदन नहीं

किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बजट परिपत्र 2012-13 में बताया गया है कि जहां एक निकाय के क्रियाकलापों में सरकार के एक से अधिक कार्य शामिल हैं तथा अनुदानों हेतु निकाय का कुछ विभागों को सिफारिश करना संभव है वहां अनुदानों को स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित विभागों के बीच परामर्श किया जाना चाहिए। निकाय को अन्य केन्द्रीय विभागों तथा राज्य सरकारों से भी प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तावित सहायता के विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशिष्ट रूप से कहा जाना चाहिए।

2012-13 के दौरान, मंत्रालय ने किसी भी राज्य सरकार या अन्य केन्द्र सरकार विभाग से अनुदानों की प्राप्ति से संबंधित कोई भी जानकारी लिए बिना राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.फै.प्रौ.सं.) को ₹19.84 करोड़ की राशि के अनुदान जारी कर दिए थे, हालांकि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति के संदर्भ में मार्च 2012 तक रा.फै.प्रौ.सं. के पास ₹52.13 करोड़ का अव्ययित शेष था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.19 अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब

सिविल लेखा नियमपुस्तिका के पैरा 2.3.1 के अनुसार, भुगतान हेतु बिलों को उनकी प्राप्ति के अधिकतम सात कार्यदिवसों के भीतर पारित करके चैक जारी किया जाना चाहिए। कम अवधि के भीतर बिलों को पारित करने तथा भुगतान करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए और प्र.ले.मु.नि./ले.मु.नि./ले.नि. को इस संबंध में प्रतिमान निर्धारित करने के साथ-साथ उनकी अनुपालना को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर करना चाहिए।

के.यो.यो.मॉ.प्र. डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को भुगतान जारी करने की तिथि में अनुदानों की संस्वीकृति की तिथि से 8 दिनों से लेकर 3 महीनों से अधिक तक का विलम्ब था जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 5.17: प्राधिकरण तथा वास्तव में जारी सहायता अनुदान के बीच अंतर का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विलम्ब	2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
	संस्वीकृति आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृति आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृति आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृति आदेशों की संख्या	राशि
8 दिनों से 1 महीना	276	329.73	405	263.40	278	754.99	959	1348.12
1 -3 महीने	245	42.71	526	47.00	556	80.35	1327	170.06
3 महीनों से अधिक	46	2.12	112	5.05	140	2.02	298	9.19
योग	**567**	**374.56**	**1043**	**315.45**	**974**	**837.36**	**2584**	**1527.37**

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.20 ₹259.87 करोड़ के अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना जारी अनुदान

सा.वि.नि. के नियम 209 (6) (iii) में बताया गया है कि जब एक ही उद्देश्य हेतु उसी संस्थान अथवा संगठन को सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाता है तो अनुवर्ती अनुदान को संस्वीकृत करते हुए पिछले अनुदान के अव्ययित शेष को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मंत्रालय ने निम्नलिखित दो संगठनों को ₹1415.52 करोड़ के आवर्ती सहायता अनुदान जारी किए परंतु उसने ₹1,415.52 करोड़ के बाद के आवर्ती अनुदानों को जारी करते हुए इन संगठनों के पास उपलब्ध ₹259.87 करोड़ के अव्ययित अनुदानों को ध्यान में नहीं रखा।

तालिका 5.18: अव्ययित शेषों को ध्यान में रखे बिना जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	निम्न को अव्ययित अनुदान	अव्ययित अनुदान की राशि (वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार)	निर्गम का वर्ष	जारी आवर्ती अनुदानों की राशि		
				योजनागत	गैर-योजनागत	कुल
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	31 मार्च 2010	उ.न.	2010-11	98.00	10.00	108.00
	31 मार्च 2011	111.25	2011-12	12.00	59.00	71.00
	31 मार्च 2012	70.87	2012-13	18.57	1.27	19.84
	कुल	**182.12**				**198.84**
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	31 मार्च 2010	21.03	2010-11	320.00	200.97	520.97
	31 मार्च 2011	18.69	2011-12	118.37	224.24	342.61
	31 मार्च 2012	38.03	2012-13	97.41	255.69	353.10
	कुल	**77.75**				**1216.68**
	कुल योग	**259.87**				**1415.52**

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड को प्रदान की गई अनुदान राशि संगठन द्वारा दर्ज अग्रिमों, जमाओं को प्रदर्शित करती है जिनका ध्यान अनुवर्ती वर्षों में उनका समायोजन करते समय रखा गया है। रा.फै.प्रौ.सं. के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि रा.फै.प्रौ.सं. को अलग योजना के अंतर्गत राशि जारी की गई थी। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सा.वि.नि. के नियम 209(6)(i) के अनुसार, संगठन के अव्ययित शेष पर विचार किया जाना चाहिए तथा पहले जारी की गई किस्तों के उचित उपयोग के उचित सबूत प्रदान करने पर अनुदानग्राही संस्थानों के लिए वार्षिक अनुदान की आखिरी किस्त सशर्त होनी चाहिए।

5.6.21 उप.प्र. में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के नीचे नोट 2 में बताया गया है कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के संदर्भ में, उस स्तर पर व्यय को गठित न करने वाले स्टाफ (गृह भवन एवं वाहन के क्रय, आदि के लिए) निर्माण अभिकरणों, भंडारण एवं परिसंपत्तियों के

आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा किए गए वास्तविक व्यय को उपयोग प्रमाणपत्र में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुप्रयुक्त अनुदानों के रूप में माना जा सकता है परन्तु अग्रेषित करने की अनुमति है। आगामी वर्ष के लिए अनुदानों का विनियमन करते हुए, अग्रेषित राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, संगठनों को क्रमशः ₹608.24 करोड़ तथा ₹533.53 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया था जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है, परंतु निम्न संगठनों ने वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2012 को प्राप्त किए गए अनुदानों में से प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों में ₹117.64 करोड़ के संवितरित ऋणों तथा अग्रिमों को उजागर नहीं किया था। मंत्रालय ने भी 2012-13 के दौरान ₹533.53 करोड़ के अनुदानों को जारी करने से पहले न तो अनुदानग्राही को पूछा और न ही अनुदानग्राही के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे से पता लगाया। इस प्रकार, अनुवर्ती अनुदान जारी करते समय मंत्रालय द्वारा ₹117.64 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदानों (ऋण तथा अग्रिम) को ध्यान में नहीं रखा गया था।

तालिका 5.19: ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	2011-12 के दौरान जारी अनुदान	31 मार्च 2012 को संवितरित ऋण तथा अग्रिम (वार्षिक लेखे के अनुसार)	2012-13 के दौरान जारी अनुदान
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	537.24	35.97	513.69
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	71.00	81.67	19.84
कुल	**608.24**	**117.64**	**533.53**

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.22 उपयोग प्रमाणपत्र (उप.प्र.)

(क) सा.वि.नि., 2005 के नियम 212(1)में निर्धारित किया गया है कि संस्थान या संगठन को दिए गए गैर-आवर्ती अनुदानों के संदर्भ में, सहायता अनुदानों को संस्वीकृत करने वाले आदेश में, फार्म सा.वि.नि. 19-क में जिस उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए थे उसके लिए अनुदानों की वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाना चाहिए। आवर्ती अनुदानों के संदर्भ में, उ.प्र. में निर्दिष्ट, मात्रा निर्धारित और गुणात्मक लक्ष्य जिन्हें उपयुक्त राशि के प्रति प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था, वास्तव में प्राप्त हुए है, और यदि नहीं, तो उसके कारणों को भी दर्शाया जाना चाहिए था। उ.प्र. में निवेश आधारित निष्पादन आकलन की बजाय उत्पादन आधारित निष्पादन आकलन निहित होना चाहिए। आवर्ती अनुदानों में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदानों से संबंधित उ.प्र. जमा कर देने के पश्चात ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कोई राशि जारी की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बारह महीनों के भीतर उप.प्र. जमा कर दिया जाना चाहिए। ऐसे उ.प्र. की प्राप्ति की संवीक्षा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा की जानी चाहिए। जहाँ कहीं भी निर्धारित समय में अनुदानग्राही से ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति नहीं होती है,तब मंत्रालय या विभाग के पास ऐसे संस्थान या संगठन को भविष्य में सरकार से किसी अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए काली सूची में डाल देने का अधिकार होगा। इस तथ्य को सा.वि.नि. के नियम 209(1) के अंतर्गत नोट के संदर्भ में वेबसाइट पर डाल दिया जाना चाहिए।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ब्यौरे के अनुसार, 31 मार्च 2012 को कुल ₹240.31 करोड़ के 2,070 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे जिसका ब्यौरा **अनुबंध-5.4** में दिया गया है। संस्वीकृत अनुदानों की सबसे पुरानी अवधि, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया हैं, 1978-79 है। मंत्रालय ने शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की लंबमानता को कम करने के लिए न तो कोई प्रयास किए और न ही दोषी संस्थानों/संगठनों को काली सूची में डालने के लिए कोई कार्रवाई की शुरूआत की।

चूंकि उप.प्र. की प्राप्ति ही केवल ऐसा तंत्र है जो निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने का साक्ष्य है, मंत्रालय को अनुदानग्राही निकायों द्वारा उप.प्र. के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। जिन मामलों में अनुदानग्राही निकायों द्वारा उप.प्र. के प्रस्तुतीकरण में असामान्य रूप से देरी हुई है वहां पर जालसाजी/निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) फरवरी 2010 में, मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.फै.प्रौ.सं.) को ₹77.64 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया था तथा रा.फै.प्रौ.सं. द्वारा संपूर्ण अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तत्पश्चात्, यह पाया गया कि रा.फै.प्रौ.सं. द्वारा गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.), हैदराबाद एवं दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंचरचना विकास निगम लिमि. (दि.रा.औ.अ.वि.नि.), दिल्ली को भुगतान हेतु क्रमशः ₹21.13 करोड़ एवं ₹5.25 करोड़ की राशि के तैयार किए गए चैक वितरित नहीं किए गए थे। इस प्रकार, न केवल रा.फै.प्रौ.सं. ने अनुदान के वास्तविक उपयोग के बिना गलत उ.प्र. प्रस्तुत किए बल्कि जारी किए गए अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जांच के लिए मंत्रालय के पास भी कोई तंत्र नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि उन्होंने मामले को समझ लिया था और वापसी की राशि पर दांडिक ब्याज की जमा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रा.फै.प्रौ.सं. के साथ मुद्दे का अनुसरण कर रहा है।

5.6.23 निष्पादन सह उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(3) के अनुसार, अनुदानग्राही संस्थान अथवा संगठन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस संबंध में संबंधित मंजूरीदाता प्राधिकारण द्वारा सहायता अनुदान संस्वीकृति आदेश में एक समय सीमा निर्धारित की जाए। आवर्ती अनुदानों के मामलें में, सभी मामलों में प्रायः निष्पादन-सह-उपलब्धियों प्रतिवेदनों के प्रस्तुततीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(1) में बताया गया है कि आवर्ती अनुदानों के संबंध में, जब पिछले वर्ष में जारी किए गए सहायता अनुदानों संबंधित मंत्रालय/विभाग की आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे तभी आगामी संस्वीकृत वित्तीय वर्ष के लिए कुल संस्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत के आधिक्य में सहायता अनुदान को जारी किया जाएगा।

2010-11 से 2012-13 के दौरान, मंत्रालय ने प्रतिवर्ष निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को ₹1557.01 करोड़ के आवर्ती सहायता अनुदान जारी किए थे। हालांकि, मंत्रालय के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राही निकायों द्वारा निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदनों को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था, जबकि, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों में एक खण्ड निहित था जिसमें बताया गया था कि अनुदानों की अगली किस्त जारी किए जाने से पहले निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

तालिका 5.20: निकायों का ब्यौरा जिनके लिए निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	जारी अनुदान			
		2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	520.97	342.61	353.10	1216.68
2.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	108.00	71.00	19.84	198.84
3.	वस्त्र समिति	21.00	18.80	21.00	60.80
4.	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	12.24	13.03	14.51	39.78
5.	सरदार बल्लभ भाई वस्त्र प्रबंधन संस्थान	17.50	0.00	0.00	17.50
6.	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ	2.41	0.93	0.93	4.27
7.	सिन्थेटिक तथा कला रेशम मिल्स अनुसंधान संघ	1.60	1.29	1.30	4.19
8.	दक्षिणी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ	2.35	0.91	0.91	4.17
9.	उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ	2.15	0.83	0.83	3.81
10.	बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ	2.41	0.93	0.00	3.34
11.	ऊन अनुसंधान संघ, ठाणे, महाराष्ट्र	0.75	0.57	0.57	1.89
12.	मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ	0.78	0.48	0.48	1.74
	कुल योग	692.16	451.38	413.47	**1557.01**

उपरोक्त संस्थाओं द्वारा पिछले वर्ष जारी किए गए सहायता अनुदानों से संबंधित वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणियों को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बिना, अगले वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकार्य सीमा से अधिक आवर्ती अनुदान इन संस्थाओं को जारी कर दिया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.24 अनुदानग्राही निकायों से पर्याप्त प्रस्तावों के बिना बजटों की तैयारी

सा.वि.नि. के नियम 209(6)(ii) प्रदत्त करता है कि अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान की संस्वीकृति अथवा निर्गम में विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय अथवा विभाग को सरकार से अनुदानों की मांग कर रहे संस्थान को वर्ष, जिसके लिए अनुदान की मांग की गई है, के पूर्व वर्ष में अक्तूबर की समाप्ति तक सहायक विवरणों सहित अपनी आवश्यकता प्रस्तुत करने हेतु दबाव डाला जाना चाहिए। मंत्रालय अथवा विभाग को अत्यंत शीघ्रता से अनुरोधों की जांच को अंतिम रूप देना चाहिए तथा जिन अनुदानों को संस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया जाएगा, उनके लिए आवश्यक बजट प्रावधान करने चाहिए। संस्थान को अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल तक उनके अनुरोधों के परिणाम से सूचित किया जाना चाहिए।

सांविधिक निकायों तथा अन्य सरकारी स्वायत्त निकायों के अलावा, बजट प्रस्ताव निर्धारित समय से पहले मांगे नहीं गए थे। पंजीकृत समितियों के मामलें में, बजट प्रस्तावों के स्वीकृत होने के पश्चात वित्तीय वर्ष के दौरान स्वयं विकास आयुक्तों द्वारा आवेदन पत्रों की मांग की गई थी। इसलिए अनुदान के अनुमानों के संबंध में विकास आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव वास्तविक आवश्यकता द्वारा परिपुष्ठ नहीं थे बल्कि वे पिछली प्रवृत्तियों, प्रक्षेपणों पर आधारित होते थे, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बचत हुई थी। उदाहरणार्थ, 2012-13 में ₹2082.50 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान का योजना "हथकरघा" क्षेत्र के पुनरूद्धार, सुधार एवं पुनर्निर्माण पैकेज के अंतर्गत संस्थानों तथा प्रत्येक को प्रस्तावित अनुदानों की राशि के संदर्भ में संसद को विवरण दिए बिना ही सहायता अनुदान के प्रति बजट में प्रावधान प्राप्त किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वास्तविक संवितरण केवल ₹291.03 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,791.47 करोड़ की बचतें हुई ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.25 अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212 (4) (क) और सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 4.27.2 के अनुसार, दुबारा भुगतान किए जाने से बचाव की दृष्टि से मंजूरीदाता प्राधिकरण द्वारा क्रमशः फार्म सा.वि.नि.-39 तथा सि.ले.नि.पु.-28 में दिए गए फार्मेट में अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए जब तक की उससे संबंधित संस्वीकृति के प्रति इसे रजिस्टर में नोट न कर लिए जाए। इससे एकमुश्त संस्वीकृति के मामले में किस्तों में भुगतान यदि कोई हो, तो उस पर भी नजर रखने में सहायता मिलती है।

यह देखा गया था कि अनुदान रजिस्टर को केंद्रीकृत रूप से, मंत्रालय स्तर तथा अनुभागीय स्तर पर भी अनुरक्षित किया गया था। हालाँकि बहुत सी आवश्यक सूचनाएं अर्थात अनुदान के साथ संलग्न शर्तें उ.प्र. एवं लेखा विवरणी की प्राप्ति की देय तिथि, उ.प्र. एवं लेखा विवरणी की प्राप्ति की वास्तविक तिथि, अव्ययित शेष के विवरण, आदि को रजिस्टर में नहीं डाला गया था। इस प्रकार, अनुदानों के संवितरण हेतु मूल अभिलेखों के अनुरक्षण की स्थिति उचित नहीं थी जिसका प्रभाव निधियों की संस्वीकृति संवितरण उपयोग की मॉनीटरिंग पर पड़ रहा था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.26 मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का गैर-प्रकटीकरण

सा.वि.नि. 2005 के नियम 209 के अनुसार, सहायता अनुदान की मांग कर रहे संस्थान अथवा संगठन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि इसने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से एक ही उद्देश्य अथवा कार्य हेतु अनुदान प्राप्त अथवा आवेदन नहीं किया है। आगे, नीचे दी गई टिप्पणी विचार करती है कि सहायता अनुदान में आवृत्ति से बचने हेतु मंत्रालय अथवा विभाग को अपनी वेबसाईट पर प्रदान की गई अनुदानों की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरे सहित संस्थानों अथवा संगठनों की एक सूची का अनुरक्षण करना चाहिए।

यह पाया गया था कि ऐसी कोई सूची, जिसमें अनुदानों की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरों सहित संस्थानों अथवा संगठनों का विवरण शामिल हों, वस्त्र मंत्रालय की वेबसाईट पर नहीं डाली गई थी। हालाँकि विकास आयुक्त (हथकरघा), मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, अपनी वेबसाईट पर इस कार्यालय द्वारा संवितरित अनुदान से संबंधित सूची प्रदर्शित कर रहा था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.27 वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से संसद को विवरणों की सूचना न दिया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 212(2) व्यादेश देता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद की सूचना हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ₹10 लाख से ₹25 लाख तक आवर्ती अनुदानों के प्रकार में निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों को प्रदत्त निधियों की प्रमात्रा तथा उद्देश्य, जिसके लिए उनका उपयोग किया गया था, को दर्शाने वाली एक विवरणी शामिल करनी चाहिए। इसी प्रकार ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की एक बार गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रहे संगठनों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद की सूचना हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन प्रत्येक संगठनों को प्रदत्त निधियों की प्रमात्रा तथा उद्देश्य, जिसके लिए निधियों का उपयोग किया गया था, को दर्शाने वाली विवरणियां शामिल करनी चाहिए।

मंत्रालय की लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि मंत्रालय द्वारा ₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच के आवर्ती सहायता अनुदान, कुल ₹1.15 करोड़ तथा ₹1.57 करोड़ क्रमशः वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान निजी संस्थानो/संगठनों को जारी की गई थी, जैसा **अनुबंध 5.5** में विवरण दिया गया है परंतु यह ब्यौरे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जो संसद में प्रस्तुत की गई थी, में शामिल नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

5.6.28 स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 208(V) स्वायत्त संगठनों की प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों में कार्यों के आकार तथा प्रवृत्ति पर निर्भर बाह्य अथवा पीयर समीक्षा की एक क्रियाविधि की विद्यमानता हेतु प्रावधान करता है। ऐसी समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ उन उद्देश्यों जिसके लिए स्वायत्त संगठन स्थापित किया गया था, को प्राप्त किया गया है अथवा किया जा रहा हैः संगठनों के कार्यों की निरंतरता क्योंकि वह आगे संगत नहीं है या पूरे किए जा चुके हैं या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति में भारी विफलता; क्या प्रदत्त सेवा हेतु उपभोक्ता प्रभारों को उपयुक्त दरों पर वसूला गया; आंतरिक संसाधन सृजन को बढ़ाने हेतु गुंजाईश जिससे कि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सके, आदि पर ध्यान देना चाहिए।

2010-11 से 2012-13 के दौरान वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित स्वायत्त निकायों को कुल ₹1891.73 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया परंतु मंत्रालय द्वारा कभी भी इन निकायों की बाह्य अथवा पीयर समीक्षा नहीं कराई गई थी।

तालिका 5.21: वह स्वायत्त निकाय जिनकी पीयर रिव्यू नहीं की गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	520.97	537.24	513.69	1571.90
2	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	108.00	71.00	19.84	198.84
3	वस्त्र समिति	21.00	18.80	21.00	60.80
4	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	12.24	14.19	15.01	41.44
5	सरदार बल्लभ भाई वस्त्र प्रबंधन संस्थान	17.50	1.25	0.00	18.75
	कुल योग	**679.71**	**642.48**	**569.54**	**1891.73**

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया था।

5.6.29 त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण

संघ सरकार के लेखे के विभागीकरण की योजना लेखे में यथार्थता तथा लेखांकन ढांचे के संचालन में दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना का प्रावधान करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा जांच करता है कि विभिन्न फील्ड संरचना आमतौर पर भारत सरकार तथा विशिष्ट रूप से संबंधित मंत्रालय द्वारा स्थापित नियमावलियों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रही हैं। विभिन्न फील्ड कार्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखांकन तथा वित्तीय अभिलेखों की यर्थाथता, नियमों एवं विनयमों की अनुपालना, नियंत्रण कमजोरियों आदि की जांच के अतिरिक्त आंतरिक लेखापरीक्षा, निष्पादन पहलुओं की जांच करेगी तथा जारी निधियों के वास्तविक उपयोग, तथा यह जांचने हेतु कि कार्यान्वित योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, का मूल्यांकन करेगी।

सा.वि.नि. का नियम 212(1) यह भी बताता है कि आगे अनुदानें संस्वीकृत करते समय मंत्रालय अथवा विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वर्ष हेतु प्राप्त निष्पादन प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कुछ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि मंत्रालय द्वारा अनुदानग्राहियों को जारी सहायता अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रस्तुत की गई थीं। टिप्पणियों की प्रकृति निम्नानुसार थीं:

- सरकारी अनुदान में से कर्मचारियों को अदा किए ऋणों तथा अग्रिमों का गैर-प्रकटीकरण,
- मंत्रालय की अनुमति के बिना बेकार/अप्रचलित परिसम्पत्तियों का निपटान,
- अन्य उद्देश्यों हेतु अनुदान का विपथन,
- योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदानों के अलग सहायक लेखे का गैर-अनुरक्षण,

- अनुदानग्राही द्वारा अर्जित राजस्व को न दर्शाना,
- सरकारी अनुदान के संबंध में अलग बैंक खाते का गैर-अनुरक्षण तथा
- मंत्रालय की स्वीकृति के बिना सावधि जमाओं में निधि का विपथन।

निकायों/प्राधिकरणों को जारी अनुदानों के संबंध में वस्त्र मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान की गई लेखापरीक्षा निरीक्षण के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

तालिका 5.22 संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	इकाईयों की संख्या जिनको सहायता अनुदान जारी किया गया (के.नि.यो.मा.प्र. डाटा के अनुसार)	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इकाईयों की संख्या (जैसा आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा सूचित किया गया)	लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा किए बिना शेष इकाईयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2010-11	1361	175	87	9	78	90
2011-12	1348	176	64	13	51	80
2012-13	1216	204	75	40	35	47

मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदानों पर 40% से अधिक का व्यय किए जाने के बावजूद आंतरिक पर्यवेक्षण क्रियाविधि व्यय के आकार तथा मंत्रालय के कार्य के अनुरूप नहीं है। एक सुदृढ़ तथा प्रभावी आंतरिक पर्यवेक्षण के अभाव में, लेखापरीक्षा में इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि मंत्रालय अनुदानग्राही निकायों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन कार्यों तथा कार्यक्रम की सुपुर्दगी के विषय पर नियमों, विनियमों तथा वर्तमान अनुदेशों की अनुपालना को कैसे सुनिश्चित करता है।

इस तथ्य, कि मंत्रालय ने अपने द्वारा नियमित आधार पर जारी सहायता अनुदानों की समीक्षा नहीं की थी, को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2014) कि प्रौ.उ.नि.यो.[8] के साथ योजना-वार लेखापरीक्षा प्रारम्भ कर दी गई थी तथा ए.व.पा.यो.[9], ए.इ.वि.यो.[10] जैसी अन्य योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में शामिल किया जाएगा।

5.6.30 निधियों की पार्किंग

वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर शहरी हॉटों को स्थापित करने हेतु योजना के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को, अंश लागत आधार अर्थात कार्यान्वयन एजेंसियों/राज्य सरकार के 30% के हिस्से तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा विकास आयुक्त (हथकरघा) के प्रत्येक कार्यालय के लिए 35% हिस्से पर ₹2.80 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए। संस्वीकृत आदेशों में यह शर्तें निहित थी कि यदि कोई अनुदानग्राही, अनुदान को उस उद्देश्य, जिसके लिए वह संस्वीकृत

[8] प्रौद्योगिकी उन्नयन निधियां योजना
[9] एकीकृत वस्त्र पाक योजना
[10] एकीकृत इस्पात विकास योजना

किया गया है, हेतु उपयोग करने में विफल रहता है तो वह अनुदान की राशि को उस पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित वापस करेगा।

अक्तूबर 2013 तक संवितरित राशियां 19 से 61 महीनों के बीच तक कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पड़ी थीं क्योंकि हॉटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था जिसका परिणाम कार्यान्वयन अभिकरणों के पास निधियों की पार्किंग में हुआ।

तालिका 5.23: कार्यान्वयन अभिकरणों के पास निधियों की पार्किंग

कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	शहरी हाट का स्थान	जारी किए गए अनुदान		पहली किश्त जारी करने (अक्तूबर 2013 से) की अवधि	परियोजना की स्थिति (15.05.2013 तक)
		जारी करने की तिथि	राशि		
पश्चिम बंगाल राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति, कोलकाता	सॉल्टलेक	10.1.2011	52.50	33 माह	राज्य सरकार ने नई भूमि आबंटित की है निर्माण तथा कार्य शीघ्र आरंभ हो जाएगा।
		24.1.2011	52.50	33 माह	
तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमि, चेन्नई	कन्याकुमारी	15.10.2008	35.00	60 माह	शहरी हाट के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
		22.3.2012	35.00	19 माह	
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी	झांसी	30.9.2008	52.50	61 माह	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त हुआ है तथा निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा ।
		22.10.2008	52.50	60 माह	
योग			**280.00**		

मंत्रालय ने (जनवरी 2014) बताया कि कार्यान्वयन अभिकरणों को शहरी हाट के निर्माण के प्रति कार्य योजना प्रस्तुत करने तथा परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसकी विफलता पर उन्हें सरकारी नियमावली के अनुसार दण्डनीय ब्याज सहित अनुदान की पूर्ण राशि को वापस करने को कहा जाएगा।

5.6.31 रूचि के अन्य विषय

(क) रा.फै.प्रौ.सं. से ब्याज की वसूली न होना

सा.वि.नि. 2005 के नियम 209(6)(ix) में यह प्रावधान है कि अनुदान जारी करने से पहले अनुदानग्राही कार्यकारी समिति के सदस्यों को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में या अलग-अलग वचन देने हेतु निर्धारित फार्मेट में (क) लक्षित तिथियों यदि कोई हो, उसमें निर्दिष्ट हो, से सहायता अनुदान की शर्तों का पालन करने तथा (ख) अनुदान का विपथन न करने अथवा योजना का निष्पादन या संबंधित निर्माणकार्य किसी अन्य संस्थान (संस्थानों) या संगठनों (संगठनों) को न

सौंपने तथा (ग) सहायता अनुदान शासित करने वाले अनुबंध में विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्तों का पालन करने के लिए, बाँड का निष्पादन करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि कोई अनुदानग्राही बाँड की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या बाँड की शर्तों को भंग करता है तो बाँड के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग अनुदान की संपूर्ण या एक भाग की राशि पर दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित या बाँड के अंदर निर्दिष्ट राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करेंगे।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.फै.प्रौ.सं.) ने उसके विभिन्न परिसरों द्वारा उपयोग न किए गए ₹45.46 करोड़ के सहायता अनुदान जिनका विवरण नीचे दिया गया है, वस्त्र मंत्रालय को वापस किए। तथापि रा.फै.प्रौ.सं. से अनुदान की वापसी तथा अप्रयुक्त अनुदानों पर ₹8.27 करोड़ राशि के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी जबकि राशि को रा.फै.प्रौ.सं. ने 374 से 1147 दिनों की अवधि तक अपने बैंक खाते में रखा हुआ है।

तालिका 5.24: अप्रयुक्त वापस किए गए अनुदानो पर ब्याज का संग्रहित न किया जाना

(₹करोड़ में)

मंत्रालय द्वारा अनुदान निर्गम की तिथि	रा.फै.प्रौ.सं. द्वारा वापसी की तिथि	वापसी की राशि	दिनों के लिए रोकी गई राशी (दिनों की संख्या)	10% की दर पर ब्याज अदा नहीं किया गया
16.7.2008	08.09.2011	10.40	1147	3.27
17.3.2009	20.10.2011	3.42	945	0.88
17.3.2009	01.12.2011	5.26	984	1.42
8.2.2010	17.02.2011	26.38	374	2.70
कुल		**45.46**		**8.27**

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि मंत्रालय 2011-12 में वापस की गई राशि पर दण्डनीय ब्याज अदा करने हेतु रा.फै.प्रौ.सं. के साथ लगातार मामले को उठा रहा था।

(ख) 'एकीकृत वस्त्र उद्यान' योजना कार्यान्वित करने वाले वि.उ.वा. से अनुदानों की मुख्य राशि तथा ब्याज की वसूली न होना

वस्त्र मंत्रालय, विभिन्न औद्योगिक समूहों/स्थानों में उच्च वृद्धि संभाव्यता सहित वस्त्र यूनिटों को स्थापित करने के लिए विश्व उत्कृष्ट आधारभूत सुविधाओं सहित उद्योग प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र उद्यान योजना (ए.व.उ.यो.) कार्यान्वित कर रहा है। योजना को, विशेष उद्देश्य वाहन (वि.उ.वा.) जहाँ उद्योग संघ/उद्यम समूह एकीकृत वस्त्र उद्यान (ए.व.उ.) के मुख्य प्रोत्साहक हैं, के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक ए.व.उ. में स्थानीय उद्योग, वित्तीय संस्थानों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से बनाया एक पृथक वि.उ.वा. होगा। वि.उ.वा., कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक निगमित निकाय के रूप में होगा। वि.उ.वा. हेतु किसी विभिन्न अवसंरचना के लिए परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। वि.उ.वा.

के पास परिचालनात्मक स्वायत्तता होनी चाहिए ताकि वे प्रतिनियुक्त सार्वजनिक उद्यम न हो जाए या केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाएं।

ए.व.उ.यो. की परियोजना लागत, वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त अनुदान/इक्विटी, का मिश्रण, राज्य सरकारें, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उद्योग, परियोजना प्रबंधक परामर्शदाता, तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों द्वारा निधिवृद्धि की जानी होती है। ए.व.उ.यो. के अंतर्गत मंत्रालय की सहायता ₹40 करोड़ की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत की 40 प्रतिशत (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम तथा ज.व.क. राज्यों में दो परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत) तक सीमित होती है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, वि.उ.वा. एक अलग खाते का संचालन करेगा जो केवल वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के लिए होगा। अनुदान की राशि पर उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान की अंतिम किश्त जारी करने के समय सरकार के अंश के रूप में दर्ज किया जाएगा।

वस्त्र मंत्रालय ने मार्च 2006 से मार्च 2010 के दौरान 10 ए.व.पा.यो. के संबंध में सहायता अनुदान के रूप में ₹50.89 करोड़ की राशि जारी की थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी ₹50.89 करोड़ में से अनुदानग्राहियों (वि.उ.वा.), ₹28.90 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, जिसे अभी भी वापस किया जाना था, द्वारा ₹21.99 करोड़ की राशि वापस की गई थी। अनुदानग्राही संस्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज के भुगतान हेतु भी उत्तरदायी थे। केवल दो अनुदानग्राहियों ने अप्रयुक्त अनुदान सहित ₹0.26 करोड़ का ब्याज अदा किया था तथा शेष आठ अनुदानग्राहियो ने कुल ₹17.79 करोड़ (31 मार्च 2012 को) का ब्याज अदा नहीं किया था जिसके विवरण अनुबंध 5.6 में दिए गए है। इस प्रकार अनुदानग्राहियों (वि.उ.वा) से ₹46.69 करोड़ की कुल राशि वसूलनीय थी।

(ग) इसके अतिरिक्त, दो पूर्ण परियोजनाओं अर्थात पल्लादम हाई-टेक विविंग पार्क लिमिटेड तथा करूर एकीकृत वस्त्र उद्यान लि. के मामलों में यह पाया गया था कि इन वि.उ.वा. ने सरकारी अनुदानों का सावधि जमा में निवेश किया तथा क्रमशः ₹1.86 करोड़ तथा ₹0.61 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया। तथापि, मंत्रालय द्वारा अनुदान की अंतिम किश्त में अर्जित ब्याज का कोई समायोजन नहीं किया गया था जिसका परिणाम इन दोनो वि.उ.वा. को अनुदानों के रूप में ₹2.47 करोड़ के अधिक निर्गम में हुआ। इसी प्रकार, एक अन्य वि.उ.वा. गुजरात इको वस्त्र उद्यान लि. ने सरकारी अनुदान पर कुल ₹0.43 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया परंतु जून 2010 में कुल ₹4.00 करोड़ की अनुदान की अंतिम किश्त जारी करते समय मंत्रालय द्वारा इसका समायोजन/दर्ज नहीं किया गया था।

(घ) वि.उ.वा. के एक अन्य मामले अर्थात पल्लादम हाई टेक विविंग पार्क में यह पाया गया था कि वि.उ.वा. ने भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों के लिए ही अनुरक्षित बैंक खाते में से विभिन्न वित्तीय संस्थानों से उसके द्वारा लिए गए कर्जों पर ₹0.33 करोड़ का ब्याज अदा किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में बताया कि सभी पी.एम.सी./वि.उ.वा. को संबंधित बैंक से विवरणी, प्रमाणपत्र सहित भारत सरकार की अनुदान पर अर्जित ब्याज के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है।

5.7 निष्कर्ष

लोक सेवा सूपुर्दगी का बदलता प्रतिमान सहायता अनुदान व्यय में तीव्र वृद्धि का कारण बना है तथा आज ऋण भुगतानों के अपवाद सहित, अनुदानों हेतु यह व्यय का एकमात्र सबसे बड़ी मद है। 2012-13 में ई-लेखा के अनुसार संघ सरकार के राजस्व व्यय का 26 प्रतिशत (₹3,66,197 करोड़) से अधिक भाग सहायता अनुदान से व्यय का बना। इसमें से, योजनागत अनुदान ₹2,93,995 करोड़ का था और गैर योजनागत अनुदान ₹72,202 करोड़ का था। योजनागत अनुदानों की भारी राशियां अनुदानग्राहियों जैसे समितियों, गै.स.सं. न्यासों आदि, जिन पर नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा छूट न तो उन्मुक्त और न ही अनियंत्रित है, को जारी की गई थी। सहायता अनुदान की लेखापरीक्षा के संबंध में, नि.म.ले.प. (क.से.श.) अधिनियम 1971 में सहायता अनुदान की लेखापरीक्षा के संबंध में पारदर्शिता लाने तथा जवाबदेही हेतु प्रस्तावित संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 2012-13 हेतु, संघ सरकार ने राज्य सरकार बजट के बाहर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹1,04,971 करोड़ की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखे के बाहर अनुरक्षित इनके खातों में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिश्चित थी। अतः लेखाओं में दर्शाया गया सरकारी व्यय उस सीमा तक अधिक बताया गया था।

सहायता अनुदान से व्यय की सही मात्रा को ध्यान में रखते हुए व्यय की इस मद से संबंधित वर्तमान नियंत्रण क्रिया विधि का गहन परीक्षण किया गया था। इस उद्देश्य हेतु मुख्यतः अनुदान संस्वीकृत करने की प्रक्रिया, अनुदानग्राही संगठन की पार्श्विका, मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुरक्षित अनुग्राहियों के डाटाबेसों, अनुदानों में से किए गए व्यय की सच्चाई तथा आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि के संदर्भ में दो मंत्रालय/ विभाग अर्थात उच्चतर शिक्षा विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय में सहायता अनुदान पर व्यय को पुनरीक्षण हेतु चयन किया था।

हमने पाया कि अनुदानों के उपयोग के उचित अनुश्रवण हेतु अभिलेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता अपर्याप्त थी। मंत्रालय/विभाग, अनुदानग्राही संगठनों द्वारा भेजे गए उपयोग प्रमाण-पत्रों, जैसाकि सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में निर्धारित है, पर अधिक निर्भर थे जो अनुदानों के पूर्ण उपयोग के संबध में पर्याप्त आश्वासन देने के लिए व्यापक नहीं थे तथा असमर्थ थे क्योंकि वे वाउचरों द्वारा समर्पित नहीं है। कई मामलों में, ये बड़े अपारदर्शी, उपयोग प्रमाणपत्र भी गलत या भ्रामक पाए गए थे। मंत्रालय/विभाग में उपयोग प्रमाणपत्रों तथा लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों के परीक्षण की गुणवत्ता से बहुत दूर है। ऐसे कई उदाहरण थे जिनमें अनुदानग्राही निकायों के बैंक

खातों में अनुदान पड़े थे तथा उस उद्देश्य, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, हेतु खर्च नहीं किए जा रहे थे। जैसाकि सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में अपेक्षित है, मंत्रालय ब्याज सहित उपयुक्त अनुदान वसूल करने में विफल रहा। कई मामलों में भी अनुदानग्राही निकायों से उपयोग प्रमाणपत्र 30 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे तथा मंत्रालय/विभाग नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। हमने आगे पाया कि मंत्रालय/विभाग, अनुदानग्राही निकायों को जारी अनुदानों में से उनके द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों की मात्रा तथा मूल्य से अवगत नहीं थे।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा विभिन्न निकायों तथा प्राधिकरणों को जारी सहायता अनुदानों से व्यय करने की वर्तमान मॉनीटरिंग तथा सूचित करने के तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 7 जुलाई 2014

(ए.डब्ल्यू.के. लैंगस्टीह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.7 के संदर्भ में)

योजना व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण*

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
001 कृषि एवं सहकारिता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	15,749.22	40.65	9.84	0.00	15.37	0.00	25.00	1,890.64	17,730.72
कुल योजना व्यय का %	88.82%	0.23%	0.06%	0.00%	0.09%	0.00%	0.14%	10.66%	100.00%
002 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	964.85	730.41	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2,519.09
कुल योजना व्यय का %	38.30%	28.99%	32.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	100.00%
003 पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,605.27	0.00	3.42	0.00	10.71	0.00	0.00	117.32	1,736.72
कुल योजना व्यय का %	92.43%	0.00%	0.20%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	6.76%	100.00%
004 परमाणु ऊर्जा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	126.76	611.43	0.00	0.00	728.34	0.00	0.00	1,073.22	2,539.75
कुल योजना व्यय का %	4.99%	24.07%	0.00%	0.00%	28.68%	0.00%	0.00%	42.26%	100.00%
005 नाभिकीय शक्ति योजना									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	174.67	0.00	396.88	571.88
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	30.54%	0.00%	69.40%	100.00%
006 रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2.90	29.70	0.00	1,552.00	0.00	0.00	21.70	0.30	1,606.60
कुल योजना व्यय का %	0.18%	1.85%	0.00%	96.60%	0.00%	0.00%	1.35%	0.02%	100.00%
007 उर्वरक विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	9.40
कुल योजना व्यय का %	20.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.47%	100.00%
008 औषधीय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	29.29	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.63	51.27
कुल योजना व्यय का %	57.14%	31.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.75%	1.23%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
009 नागरिक उड्डयन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.90	59.29	0.00	0.00	0.24	6,010.00	0.00	7.74	6,078.16
कुल योजना व्यय का %	0.01%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	98.88%	0.00%	0.13%	100.00%
010 कोयला मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	159.01	0.00	0.00	0.00	231.75	390.76
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	40.69%	0.00%	0.00%	0.00%	59.31%	100.00%
011 वाणिज्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	441.19	42.09	0.00	473.80	725.09	100.00	0.00	15.66	1,797.83
कुल योजना व्यय का %	24.54%	2.34%	0.00%	26.35%	40.33%	5.56%	0.00%	0.87%	100.00%
012 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	119.55	551.93	12.91	396.69	13.99	44.10	0.00	42.46	1,181.63
कुल योजना व्यय का %	10.12%	46.71%	1.09%	33.57%	1.18%	3.73%	0.00%	3.59%	100.00%
014 दूरसंचार विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	150.00	0.00	0.00	0.00	3.26	60.00	0.00	2,150.72	2,363.98
कुल योजना व्यय का %	6.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	2.54%	0.00%	90.98%	100.00%
015 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	798.71	35.60	123.70	0.00	3.36	0.00	0.00	898.51	1,859.87
कुल योजना व्यय का %	42.94%	1.91%	6.65%	0.00%	0.18%	0.00%	0.00%	48.31%	100.00%
016 उपभोक्ता मामले विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	6.80	28.28	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	85.32	126.40
कुल योजना व्यय का %	5.38%	22.38%	0.00%	0.00%	4.75%	0.00%	0.00%	67.50%	100.00%
017 खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	44.48	10.00	2.50	0.00	0.25	23.28	0.00	2.89	83.39
कुल योजना व्यय का %	53.34%	11.99%	3.00%	0.00%	0.29%	27.92%	0.00%	3.46%	100.00%
018 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	8.00	0.00	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	24.43
कुल योजना व्यय का %	32.75%	0.00%	0.00%	0.00%	67.25%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
019 संस्कृति मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	397.57	61.24	25.38	0.00	27.94	0.00	0.00	291.66	803.79
कुल योजना व्यय का %	49.46%	7.62%	3.16%	0.00%	3.48%	0.00%	0.00%	36.29%	100.00%
028 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	122.64	1,358.25	0.00	0.00	142.23	21.53	60.00	13.62	1,718.25
कुल योजना व्यय का %	7.14%	79.05%	0.00%	0.00%	8.28%	1.25%	3.49%	0.79%	100.00%
029 भू-विज्ञान मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	602.48	0.00	14.12	0.00	47.67	0.00	0.00	146.72	811.00
कुल योजना व्यय का %	74.29%	0.00%	1.74%	0.00%	5.88%	0.00%	0.00%	18.09%	100.00%
030 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	870.25	422.20	0.00	0.00	59.67	0.00	0.00	284.05	1,636.17
कुल योजना व्यय का %	53.19%	25.80%	0.00%	0.00%	3.65%	0.00%	0.00%	17.36%	100.00%
031 विदेश मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	476.02	1,614.02
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.51%	29.49%	100.00%
032 आर्थिक कार्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.45	0.00	0.00	457.55	1,560.00
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.67%	0.00%	0.00%	29.33%	100.00%
033 वित्त सेवाएं विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00	0.00	0.00	14,652.00
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
035 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	43,001.16	29,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.70	0.00	82,904.42
कुल योजना व्यय का %	51.87%	35.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.85%	0.00%	100.00%
038 व्यय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
कुल योजना व्यय का %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
039 पेंशन									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योजना व्यय का %									
045 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	601.79	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09	655.87
कुल योजना व्यय का %	91.75%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	100.00%
046- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	16,776.82	1,130.87	535.11	0.00	1,055.94	150.00	0.00	1,259.26	20,908.02
कुल योजना व्यय का %	80.24%	5.41%	2.56%	0.00%	5.05%	0.72%	0.00%	6.02%	100.00%
047- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	305.16	167.82	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	38.42	580.61
कुल योजना व्यय का %	52.56%	28.90%	11.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.62%	100.00%
048- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	275.14	90.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	460.31
कुल योजना व्यय का %	59.77%	19.55%	20.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	100.00%
049- एड्स नियंत्रण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	766.41	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	548.30	1,316.07
कुल योजना व्यय का %	58.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	41.66%	100.00%
050- भारी उद्योग विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	341.94	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	2.09	404.03
कुल योजना व्यय का %	0.00%	84.63%	0.00%	0.00%	0.00%	14.85%	0.00%	0.52%	100.00%
051- सार्वजनिक उद्यम विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	6.17
कुल योजना व्यय का %	86.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.33%	100.00%
052- गृह मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	60.65	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	804.09	870.98
कुल योजना व्यय का %	6.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	92.32%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
054- पुलिस									
व्यय (₹ करोड़ में)	27.69	0.00	0.00	0.00	4,794.01	0.00	0.00	190.87	5,012.57
कुल योजना व्यय का %	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	95.64%	0.00%	0.00%	3.81%	100.00%
055- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय									
व्यय (₹ करोड़ में)	42.17	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	148.54
कुल योजना व्यय का %	28.39%	52.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.10%	100.00%
056- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.21
कुल योजना व्यय का %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
057- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	834.93	17.84	3.00	5.01	0.00	0.00	0.00	69.33	930.11
कुल योजना व्यय का %	89.77%	1.92%	0.32%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	7.45%	100.00%
058- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	29,337.16	12,287.58	578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.39	42,303.23
कुल योजना व्यय का %	69.35%	29.05%	1.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	100.00%
059- उच्च शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	5,037.72	6,989.23	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	186.12	12,731.25
कुल योजना व्यय का %	39.57%	54.90%	4.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%	100.00%
060- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	90.00	7.10	0.00	0.00	23.35	0.00	333.50	158.14	612.09
कुल योजना व्यय का %	14.70%	1.16%	0.00%	0.00%	3.81%	0.00%	54.49%	25.84%	100.00%
061- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	530.77	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.79	1,702.89
कुल योजना व्यय का %	31.17%	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.64%	100.00%
063- विधि एवं न्याय									
व्यय (₹ करोड़ में)	712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.42	787.73
कुल योजना व्यय का %	90.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.57%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
065- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,650.76	67.99	1.30	344.11	2.80	75.00	0.00	87.56	2,229.52
कुल योजना व्यय का %	74.04%	3.05%	0.06%	15.43%	0.13%	3.36%	0.00%	3.93%	100.00%
066- खनन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.57	305.07
कुल योजना व्यय का %	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.90%	100.00%
067- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,386.10	640.26	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	32.00	2,158.00
कुल योजना व्यय का %	64.23%	29.67%	0.00%	0.00%	0.00%	4.62%	0.00%	1.48%	100.00%
068- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	733.97	0.00	1.00	385.81	5.00	76.00	0.00	28.79	1,230.57
कुल योजना व्यय का %	59.64%	0.00%	0.08%	31.35%	0.41%	6.18%	0.00%	2.34%	100.00%
070- पंचायती राज मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	378.57	3,523.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19	3,936.73
कुल योजना व्यय का %	9.62%	89.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	100.00%
072- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	3.14	3.00	0.00	0.00	48.19	0.00	0.00	94.79	149.12
कुल योजना व्यय का %	2.10%	2.01%	0.00%	0.00%	32.32%	0.00%	0.00%	63.57%	100.00%
074- योजना मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	7.34	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	1,357.80	1,405.12
कुल योजना व्यय का %	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	2.85%	0.00%	0.00%	96.63%	100.00%
075- विद्युत मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	94.88	687.56	0.00	23.09	1.00	334.20	1,566.99	43.23	2,750.95
कुल योजना व्यय का %	3.45%	24.99%	0.00%	0.84%	0.04%	12.15%	56.96%	1.57%	100.00%
081- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	9.17	2,695.42	0.00	0.00	9,346.22	7,780.00	0.00	122.32	19,953.12
कुल योजना व्यय का %	0.05%	13.51%	0.00%	0.00%	46.84%	38.99%	0.00%	0.61%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
082- ग्रामीण विकास विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	7,067.11	42,287.72	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	774.36	50,142.69
कुल योजना व्यय का %	14.09%	84.33%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.54%	100.00%
083- भू-संसाधन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	2,986.40
कुल योजना व्यय का %	99.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.34%	100.00%
084- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	13,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	13,074.06
कुल योजना व्यय का %	99.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	100.00%
085- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	954.80	809.65	308.26	0.00	6.42	0.00	13.00	46.18	2,138.31
कुल योजना व्यय का %	44.65%	37.86%	14.42%	0.00%	0.30%	0.00%	0.61%	2.16%	100.00%
086- विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	680.69	668.08	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	1,544.84
कुल योजना व्यय का %	44.06%	43.25%	12.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	100.00%
087- जैव-तकनीकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	746.33	407.52	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	1,267.85
कुल योजना व्यय का %	58.87%	32.14%	6.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.90%	100.00%
088- पोत परिवहन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.11	144.08	0.00	0.90	267.66	0.00	0.00	77.40	495.15
कुल योजना व्यय का %	1.03%	29.10%	0.00%	0.18%	54.06%	0.00%	0.00%	15.63%	100.00%
089- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	4,575.12	61.56	3.85	0.00	0.00	202.65	0.00	37.21	4,880.40
कुल योजना व्यय का %	93.74%	1.26%	0.08%	0.00%	0.00%	4.15%	0.00%	0.76%	100.00%
090- अंतरिक्ष विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	145.61	0.00	6.00	0.00	221.59	0.00	0.00	3,410.03	3,783.23
कुल योजना व्यय का %	3.85%	0.00%	0.16%	0.00%	5.86%	0.00%	0.00%	90.14%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
091- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	221.76	3,745.65	1.12	0.00	9.79	0.00	0.00	119.88	4,098.20
कुल योजना व्यय का %	5.41%	91.40%	0.03%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	2.93%	100.00%
092- इस्पात मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
कुल योजना व्यय का %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
093- कपड़ा मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,033.10	361.93	3.00	2,144.51	21.95	0.00	0.00	62.90	3,627.39
कुल योजना व्यय का %	28.48%	9.98%	0.08%	59.12%	0.60%	0.00%	0.00%	1.73%	100.00%
094- पर्यटन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	48.09	537.55	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	275.38	865.96
कुल योजना व्यय का %	5.55%	62.08%	0.00%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	31.80%	100.00%
095- जनजातीय मामले मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1,930.50	1,035.21	18.61	0.00	0.00	68.10	0.00	4.27	3,056.68
कुल योजना व्यय का %	63.16%	33.87%	0.61%	0.00%	0.00%	2.23%	0.00%	0.14%	100.00%
096- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह									
व्यय (₹ करोड़ में)	81.78	55.12	12.59	2.91	298.05	0.25	0.00	1,033.56	1,484.25
कुल योजना व्यय का %	5.51%	3.71%	0.85%	0.20%	20.08%	0.02%	0.00%	69.64%	100.00%
097- चंडीगढ़									
व्यय (₹ करोड़ में)	147.75	0.00	0.00	0.02	266.53	0.06	0.00	205.15	619.51
कुल योजना व्यय का %	23.85%	0.00%	0.00%	0.00%	43.02%	0.01%	0.00%	33.12%	100.00%
098- दादरा एवं नगर हवेली									
व्यय (₹ करोड़ में)	131.71	120.90	0.00	0.79	223.54	0.00	0.10	87.27	564.30
कुल योजना व्यय का %	23.34%	21.42%	0.00%	0.14%	39.61%	0.00%	0.02%	15.46%	100.00%
099- दमन एवं दीव									
व्यय (₹ करोड़ में)	91.32	25.00	0.00	0.21	128.08	0.21	0.00	180.07	424.88
कुल योजना व्यय का %	21.49%	5.88%	0.00%	0.05%	30.14%	0.05%	0.00%	42.38%	100.00%

	अनुदान			33	53	54	55	अन्य	कुल योग
	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान - वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम		
100- लक्षद्वीप									
व्यय (₹ करोड़ में)	68.68	0.00	3.55	2.20	66.18	0.09	0.21	103.63	244.54
कुल योजना व्यय का %	28.08%	0.00%	1.45%	0.90%	27.06%	0.04%	0.09%	42.38%	100.00%
101- शहरी विकास विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	23.68	291.03	0.00	0.00	274.94	2,376.72	2,577.93	90.23	5,634.53
कुल योजना व्यय का %	0.42%	5.17%	0.00%	0.00%	4.88%	42.18%	45.75%	1.60%	100.00%
102- लोक निर्माण कार्य									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	159.75	0.00	0.00	11.33	171.08
कुल योजना व्यय का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.38%	0.00%	0.00%	6.62%	100.00%
103- लेखन सामग्री एवं मुद्रण									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योजना व्यय का %									
104- जल संसाधन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	155.91	0.00	0.00	0.00	129.87	0.00	0.00	238.22	524.00
कुल योजना व्यय का %	29.75%	0.00%	0.00%	0.00%	24.78%	0.00%	0.00%	45.46%	100.00%
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	16,732.01	121.36	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64	16,954.12
कुल योजना व्यय का %	98.69%	0.72%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	100.00%
106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	694.18	0.00	172.80	0.00	1.11	0.00	0.00	17.24	885.33
कुल योजना व्यय का %	78.41%	0.00%	19.52%	0.00%	0.12%	0.00%	0.00%	1.95%	100.00%
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**1,77,622.13**	**1,12,727.26**	**3,645.60**	**5,496.02**	**20,302.85**	**32,308.49**	**16,394.14**	**22,255.45**	**3,90,751.93**
योजना व्यय का कुल %	**45.46%**	**28.85%**	**0.93%**	**1.41%**	**5.20%**	**8.27%**	**4.20%**	**5.70%**	**100%**

अनुबंध I.2

(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण#

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
001 कृषि एवं सहकारिता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	45	694	2,759	3,026	1,106	2,404	480	792	2,323	886	1,892	1,621	18,028
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.3%	3.8%	15.3%	16.8%	6.1%	13.3%	2.7%	4.4%	12.9%	4.9%	10.5%	9.0%	100.0%
002 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	359	522	1,933	26	0	0	386	0	204	0	811	376	4,619
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.8%	11.3%	41.9%	0.6%	0.0%	0.0%	8.4%	0.0%	4.4%	0.0%	17.5%	8.2%	100.0%
003 पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	55	55	239	121	188	561	59	105	92	69	238	372	2,153
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.5%	2.6%	11.1%	5.6%	8.7%	26.1%	2.8%	4.9%	4.3%	3.2%	11.0%	17.3%	100.0%
004 परमाणु ऊर्जा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	823	584	603	679	0	627	785	969	653	717	876	1,470	8,786
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.4%	6.7%	6.9%	7.7%	0.0%	7.1%	8.9%	11.0%	7.4%	8.2%	10.0%	16.7%	100.0%
005 नाभिकीय शक्ति योजना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	98	174	106	202	0	127	230	1,106	134	192	545	1,147	4,061
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.4%	4.3%	2.6%	5.0%	0.0%	3.1%	5.7%	27.2%	3.3%	4.7%	13.4%	28.2%	100.0%
006 रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	255	7	506	8	809	27	2	4	1	17	7	43	1,685
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	15.1%	0.4%	30.0%	0.5%	48.0%	1.6%	0.1%	0.2%	0.1%	1.0%	0.4%	2.5%	100.0%
007 उर्वरक विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9,478	9,868	6,182	7,945	5,596	7,395	6,000	4,772	4,434	2,500	580	5,871	70,622
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.4%	14.0%	8.8%	11.2%	7.9%	10.5%	8.5%	6.8%	6.3%	3.5%	0.8%	8.3%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
008 औषधीय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	14	1	6	14	1	9	17	1	1	7	15	87
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.7%	16.2%	1.7%	7.0%	15.5%	1.6%	10.3%	19.0%	1.2%	1.1%	7.8%	16.9%	100.0%
009 नागरिक उड्डयन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	677	7	1,909	8	358	808	266	535	152	2,007	7	336	7,069
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.6%	0.1%	27.0%	0.1%	5.1%	11.4%	3.8%	7.6%	2.2%	28.4%	0.1%	4.8%	100.0%
010 कोयला मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	-27	2	2	111	33	-2	2	55	109	74	94	292	745
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	-3.6%	0.2%	0.3%	14.9%	4.4%	-0.2%	0.3%	7.4%	14.7%	10.0%	12.6%	39.2%	100.0%
011 वाणिज्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	51	255	466	1,312	509	412	265	369	216	207	367	269	4,698
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.1%	5.4%	9.9%	27.9%	10.8%	8.8%	5.6%	7.9%	4.6%	4.4%	7.8%	5.7%	100.0%
012 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	22	155	27	123	30	502	28	35	33	30	203	190	1,378
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.6%	11.3%	2.0%	8.9%	2.2%	36.4%	2.1%	2.5%	2.4%	2.2%	14.7%	13.8%	100.0%
014 दूरसंचार विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	321	479	592	537	1,531	655	473	863	433	590	531	1,588	8,595
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.7%	5.6%	6.9%	6.3%	17.8%	7.6%	5.5%	10.0%	5.0%	6.9%	6.2%	18.5%	100.0%
015- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	68	116	156	67	265	188	175	77	153	59	297	281	1,903
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.6%	6.1%	8.2%	3.5%	13.9%	9.9%	9.2%	4.0%	8.0%	3.1%	15.6%	14.8%	100.0%
016 उपभोक्ता मामले विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9	39	24	90	69	17	9	37	62	22	30	80	487
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.8%	8.0%	4.9%	18.4%	14.1%	3.4%	1.8%	7.7%	12.7%	4.6%	6.2%	16.3%	100.0%
017 खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15,449	6,159	16,255	8,443	9,094	11,993	163	4,947	4,970	6,366	1,761	10,865	96,465
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	16.0%	6.4%	16.9%	8.8%	9.4%	12.4%	0.2%	5.1%	5.2%	6.6%	1.8%	11.3%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
018 कार्पोरेट कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15	15	18	9	32	12	12	23	30	10	12	17	206
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.1%	7.5%	8.7%	4.5%	15.7%	5.7%	6.0%	11.1%	14.7%	4.7%	5.9%	8.4%	100.0%
019 संस्कृति मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	65	65	298	157	81	126	62	58	110	62	180	125	1,391
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4.7%	4.7%	21.4%	11.3%	5.8%	9.1%	4.5%	4.2%	7.9%	4.5%	13.0%	9.0%	100.0%
020- रक्षा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	374	1,507	1,329	1,015	1,283	1,256	974	1,247	1,226	1,235	4,164	15,610
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	2.4%	9.7%	8.5%	6.5%	8.2%	8.0%	6.2%	8.0%	7.9%	7.9%	26.7%	100.0%
021- रक्षा पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	2,670	4,037	-718	4,877	3,042	2,356	4,645	3,139	3,003	4,824	11,493	43,368
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	6.2%	9.3%	-1.7%	11.2%	7.0%	5.4%	10.7%	7.2%	6.9%	11.1%	26.5%	100.0%
028 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	149	149	133	63	363	41	107	313	42	63	317	1,742
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	8.6%	8.5%	7.6%	3.6%	20.8%	2.4%	6.1%	18.0%	2.4%	3.6%	18.2%	100.0%
029 भू-विज्ञान मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	46	44	34	41	174	318	73	39	87	96	135	88	1,177
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.9%	3.8%	2.9%	3.5%	14.8%	27.0%	6.2%	3.3%	7.4%	8.1%	11.5%	7.5%	100.0%
030 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	31	87	228	172	195	186	171	114	56	243	152	361	1,997
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.5%	4.4%	11.4%	8.6%	9.8%	9.3%	8.6%	5.7%	2.8%	12.2%	7.6%	18.1%	100.0%
031 विदेश मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	656	376	1,639	718	1,076	501	561	443	727	634	744	2,046	10,121
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.5%	3.7%	16.2%	7.1%	10.6%	4.9%	5.5%	4.4%	7.2%	6.3%	7.4%	20.2%	100.0%
032 आर्थिक कार्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	13	114	300	5,261	38	30	572	467	294	1,864	845	1,740	11,538
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	1.0%	2.6%	45.6%	0.3%	0.3%	5.0%	4.0%	2.5%	16.2%	7.3%	15.1%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
033 वित्त सेवाएं विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	10	-103	135	718	508	3,572	103	6	1,178	21	18	15,126	21,293
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	-0.5%	0.6%	3.4%	2.4%	16.8%	0.5%	0.0%	5.5%	0.1%	0.1%	71.0%	100.0%
034- विनियोग-ब्याज भुगतान													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	22,678	26,967	17,534	21,250	48	34,202	18,244	26,398	28,994	20,519	32,413	79,677	3,28,922
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.9%	8.2%	5.3%	6.5%	0.0%	10.4%	5.5%	8.0%	8.8%	6.2%	9.9%	24.2%	100.0%
035 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4,462	6,219	7,238	8,213	14,512	9,446	7,594	7,554	18,088	7,993	12,196	27,998	1,31,514
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.4%	4.7%	5.5%	6.2%	11.0%	7.2%	5.8%	5.7%	13.8%	6.1%	9.3%	21.3%	100.0%
036- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	353	-349	7	12	20	23	21	20	20	8	9	42	185
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	190.3%	-188.4%	3.8%	6.4%	10.5%	12.1%	11.6%	10.9%	10.9%	4.3%	4.9%	22.7%	100.0%
038 व्यय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9	6	6	14	7	6	8	14	8	7	17	14	116
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.5%	5.0%	5.4%	11.9%	5.9%	5.0%	6.6%	12.5%	7.3%	5.8%	15.1%	12.0%	100.0%
039 पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1,270	1,548	1,446	1,531	1,428	1,486	1,325	1,356	1,787	1,852	1,831	2,724	19,584
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.5%	7.9%	7.4%	7.8%	7.3%	7.6%	6.8%	6.9%	9.1%	9.5%	9.3%	13.9%	100.0%
040- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	368	209	223	105	9	286	217	220	254	234	247	342	2,714
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.6%	7.7%	8.2%	3.9%	0.3%	10.5%	8.0%	8.1%	9.4%	8.6%	9.1%	12.6%	100.0%
041- राजस्व विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	143	38	34	37	47	36	69	75	34	63	56	123	755
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	19.0%	5.1%	4.5%	4.9%	6.2%	4.7%	9.1%	9.9%	4.6%	8.3%	7.4%	16.3%	100.0%
042- प्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	344	274	276	262	261	284	279	269	239	291	301	631	3,710
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.3%	7.4%	7.4%	7.1%	7.0%	7.7%	7.5%	7.3%	6.4%	7.8%	8.1%	17.0%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
043- अप्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	452	278	279	282	279	284	319	272	280	279	269	208	3,481
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.0%	8.0%	8.0%	8.1%	8.0%	8.2%	9.2%	7.8%	8.1%	8.0%	7.7%	6.0%	100.0%
044- विनिवेश विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	4	1	3	0	0	2	0	1	1	1	3	18
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8.2%	23.5%	3.1%	18.4%	2.3%	2.0%	8.8%	2.4%	3.2%	7.7%	3.9%	16.4%	100.0%
045 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	72	44	29	39	246	10	9	25	35	85	69	665
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	10.9%	6.6%	4.4%	5.9%	36.9%	1.5%	1.4%	3.8%	5.2%	12.8%	10.4%	100.0%
046- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	457	755	4,471	920	1,909	7,144	668	914	1,849	835	3,375	3,577	26,876
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.7%	2.8%	16.6%	3.4%	7.1%	26.6%	2.5%	3.4%	6.9%	3.1%	12.6%	13.3%	100.0%
047- आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	10	33	79	31	44	222	3	4	70	13	37	209	755
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.3%	4.3%	10.5%	4.1%	5.8%	29.3%	0.4%	0.6%	9.3%	1.8%	4.9%	27.6%	100.0%
048- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	118	88	157	6	10	60	0	118	0	0	163	720
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	16.4%	12.2%	21.7%	0.8%	1.4%	8.3%	0.0%	16.3%	0.1%	0.1%	22.6%	100.0%
049- एड्स नियंत्रण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	2	264	27	24	495	2	61	141	32	81	187	1,316
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.2%	20.1%	2.0%	1.8%	37.6%	0.2%	4.6%	10.7%	2.4%	6.1%	14.2%	100.0%
050- भारी उद्योग विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	1	1	117	46	372	16	1	1	1	1	209	769
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.3%	0.2%	0.2%	15.2%	5.9%	48.4%	2.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	27.2%	100.0%
051- सार्वजनिक उद्यम विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	2	1	15
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6.2%	5.5%	4.1%	21.1%	7.1%	5.6%	5.2%	6.2%	10.1%	4.1%	15.9%	8.8%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
052- गृह मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53	51	110	235	68	628	73	56	53	50	148	101	1,626
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3.3%	3.1%	6.8%	14.4%	4.2%	38.6%	4.5%	3.4%	3.2%	3.1%	9.1%	6.2%	100.0%
053- मंत्रिमंडल													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53	56	44	231	50	31	30	55	36	42	41	255	925
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5.7%	6.1%	4.8%	24.9%	5.5%	3.3%	3.3%	6.0%	3.9%	4.6%	4.5%	27.6%	100.0%
054- पुलिस													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4,667	3,543	3,366	3,670	3,619	4,007	3,995	3,368	2,977	3,697	3,612	3,338	43,859
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.6%	8.1%	7.7%	8.4%	8.3%	9.1%	9.1%	7.7%	6.8%	8.4%	8.2%	7.6%	100.0%
055- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	68	92	112	138	99	216	128	99	136	131	140	259	1,620
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4.2%	5.7%	6.9%	8.5%	6.1%	13.4%	7.9%	6.1%	8.4%	8.1%	8.7%	16.0%	100.0%
056- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	183	287	260	114	124	264	122	10	230	116	211	1,921
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	9.5%	14.9%	13.6%	5.9%	6.4%	13.8%	6.4%	0.5%	12.0%	6.0%	11.0%	100.0%
057- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	1	1	180	29	181	2	2	174	25	168	173	937
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.1%	0.1%	19.2%	3.1%	19.3%	0.2%	0.2%	18.6%	2.6%	18.0%	18.5%	100.0%
058- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	8,514	1,013	6,997	6,489	4,880	1,034	3,352	3,718	1,867	3,720	3,527	45,113
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	18.9%	2.2%	15.5%	14.4%	10.8%	2.3%	7.4%	8.2%	4.1%	8.2%	7.8%	100.0%
059- उच्च शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	20	251	3,105	813	759	5,210	1,150	624	2,827	46	3,630	2,024	20,458
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	1.2%	15.2%	4.0%	3.7%	25.5%	5.6%	3.1%	13.8%	0.2%	17.7%	9.9%	100.0%
060- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	39	29	774	91	26	273	53	86	38	375	185	655	2,625
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.5%	1.1%	29.5%	3.5%	1.0%	10.4%	2.0%	3.3%	1.4%	14.3%	7.1%	25.0%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
061- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	46	251	95	94	1,592	458	59	82	305	49	262	349	3,643
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.3%	6.9%	2.6%	2.6%	43.7%	12.6%	1.6%	2.2%	8.4%	1.3%	7.2%	9.6%	100.0%
062- निर्वाचन आयोग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4	2	3	3	2	7	3	3	6	3	3	1	39
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.2%	5.3%	7.0%	7.7%	5.4%	17.4%	6.8%	7.8%	14.9%	7.5%	6.8%	3.3%	100.0%
063- विधि एवं न्याय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	12	14	64	140	198	241	57	126	113	49	91	78	1,184
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.0%	1.2%	5.4%	11.8%	16.7%	20.4%	4.8%	10.6%	9.5%	4.2%	7.7%	6.6%	100.0%
064- विनियोग-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16	8	10	9	9	11	11	9	9	10	9	4	117
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13.7%	7.3%	8.9%	7.9%	7.8%	9.4%	9.2%	8.1%	7.6%	8.6%	7.6%	3.9%	100.0%
065- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	18	236	703	156	52	141	40	193	289	33	326	331	2,517
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.7%	9.4%	27.9%	6.2%	2.1%	5.6%	1.6%	7.7%	11.5%	1.3%	13.0%	13.2%	100.0%
066- खनन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	78	53	52	56	53	109	124	-9	50	51	52	129	799
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.8%	6.6%	6.5%	7.0%	6.6%	13.7%	15.6%	-1.1%	6.3%	6.4%	6.5%	16.1%	100.0%
067- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	122	161	113	80	69	201	159	682	72	287	225	2,174
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	5.6%	7.4%	5.2%	3.7%	3.2%	9.3%	7.3%	31.4%	3.3%	13.2%	10.4%	100.0%
068- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5	106	47	50	297	158	64	50	61	62	90	254	1,244
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.4%	8.5%	3.8%	4.0%	23.9%	12.7%	5.1%	4.1%	4.9%	5.0%	7.3%	20.4%	100.0%
069- प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	2	7	3	4	8	3	2	19	15	3	15	83
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.5%	2.6%	8.1%	4.0%	4.9%	9.3%	3.4%	2.6%	23.0%	17.8%	4.0%	17.8%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
070- पंचायती राज मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	334	87	25	372	354	227	460	183	79	564	1,251	3,937
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	8.5%	2.2%	0.6%	9.4%	9.0%	5.8%	11.7%	4.6%	2.0%	14.3%	31.8%	100.0%
071- संसदीय कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.2%	6.7%	6.9%	7.0%	8.1%	8.2%	7.9%	7.6%	9.8%	7.1%	6.3%	12.3%	100.0%
072- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	59	71	71	69	66	86	76	63	70	53	64	75	823
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.2%	8.6%	8.6%	8.3%	8.1%	10.5%	9.3%	7.6%	8.5%	6.4%	7.8%	9.1%	100.0%
073- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	1	7,539	21,086	10,992	315	114	259	250	30,306	310	26,248	97,423
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	0.0%	7.7%	21.6%	11.3%	0.3%	0.1%	0.3%	0.3%	31.1%	0.3%	26.9%	100.0%
074- योजना मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	187	57	139	127	31	90	50	69	159	78	182	309	1,479
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.6%	3.8%	9.4%	8.6%	2.1%	6.1%	3.4%	4.7%	10.8%	5.3%	12.3%	20.9%	100.0%
075- विद्युत मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	13	196	125	752	76	682	157	16	116	30	189	3,951	6,303
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	3.1%	2.0%	11.9%	1.2%	10.8%	2.5%	0.3%	1.8%	0.5%	3.0%	62.7%	100.0%
076- विनियोग-कर्मचारी, आवास एवं राष्ट्रपति के भत्ते													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	31
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.6%	7.9%	7.1%	8.7%	7.6%	8.3%	9.1%	7.8%	9.5%	7.8%	7.7%	8.0%	100.0%
077- लोक सभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	48	38	31	36	2	36	43	37	37	39	35	88	470
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.3%	8.0%	6.5%	7.7%	0.5%	7.6%	9.1%	7.8%	7.9%	8.3%	7.5%	18.7%	100.0%
078- राज्य सभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	27	19	17	25	26	21	26	17	22	34	18	26	278
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9.5%	6.7%	6.3%	9.0%	9.5%	7.7%	9.3%	6.2%	7.8%	12.4%	6.4%	9.3%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
079- विनियोग-सं.लो.से.आ													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15	11	9	13	10	11	15	13	10	16	11	12	147
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.4%	7.6%	6.3%	9.0%	7.1%	7.5%	10.1%	9.1%	6.6%	10.6%	7.4%	8.4%	100.0%
080- उप-राष्ट्रपति सचिवालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.1%	8.4%	9.1%	8.6%	7.7%	7.5%	7.9%	10.0%	7.5%	8.0%	8.7%	4.5%	100.0%
081- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	43	1,732	2,389	1,025	607	619	4,739	944	3,611	1,337	1,102	6,184	24,331
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.2%	7.1%	9.8%	4.2%	2.5%	2.5%	19.5%	3.9%	14.8%	5.5%	4.5%	25.4%	100.0%
082- ग्रामीण विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3,489	6,908	8,651	3,231	2,362	2,781	6,413	1,132	3,121	2,701	2,701	6,696	50,187
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.0%	13.8%	17.2%	6.4%	4.7%	5.5%	12.8%	2.3%	6.2%	5.4%	5.4%	13.3%	100.0%
083- भू-संसाधन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	354	51	33	1,566	7	57	356	7	128	80	354	2,994
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	11.8%	1.7%	1.1%	52.3%	0.2%	1.9%	11.9%	0.2%	4.3%	2.7%	11.8%	100.0%
084- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	323	1,963	993	896	1,495	405	153	2,481	28	2,374	1,967	13,079
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	2.5%	15.0%	7.6%	6.8%	11.4%	3.1%	1.2%	19.0%	0.2%	18.2%	15.0%	100.0%
085- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	124	111	389	198	307	436	102	109	335	105	140	168	2,524
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4.9%	4.4%	15.4%	7.9%	12.2%	17.3%	4.0%	4.3%	13.3%	4.2%	5.6%	6.6%	100.0%
086- विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1	540	1	217	57	822	-6	-1	771	-27	562	9	2,946
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.0%	18.3%	0.0%	7.4%	1.9%	27.9%	-0.2%	0.0%	26.2%	-0.9%	19.1%	0.3%	100.0%
087- जैव-तकनीकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16	89	71	237	87	275	30	113	67	51	104	143	1,283
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.2%	7.0%	5.5%	18.5%	6.8%	21.4%	2.3%	8.8%	5.2%	4.0%	8.1%	11.2%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
088- पोत परिवहन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	20	23	48	72	146	157	59	120	227	44	120	168	1,203
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.6%	1.9%	4.0%	6.0%	12.1%	13.1%	4.9%	10.0%	18.8%	3.7%	10.0%	13.9%	100.0%
089- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4	4	923	88	137	729	150	231	1,487	23	171	1,024	4,972
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.1%	18.6%	1.8%	2.8%	14.7%	3.0%	4.7%	29.9%	0.5%	3.4%	20.6%	100.0%
090- अंतरिक्ष विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	384	288	258	324	0	342	279	696	395	666	488	737	4,856
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.9%	5.9%	5.3%	6.7%	0.0%	7.0%	5.7%	14.3%	8.1%	13.7%	10.0%	15.2%	100.0%
091- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	94	315	319	414	281	388	241	445	598	494	282	605	4,475
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2.1%	7.0%	7.1%	9.3%	6.3%	8.7%	5.4%	9.9%	13.4%	11.0%	6.3%	13.5%	100.0%
092- इस्पात मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	12	14	3	8	9	4	2	11	153	15	10	243
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.0%	5.1%	5.8%	1.4%	3.3%	3.7%	1.5%	0.7%	4.5%	62.8%	6.3%	3.9%	100.0%
093- कपड़ा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	60	106	873	183	137	613	261	166	809	98	504	574	4,385
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.4%	2.4%	19.9%	4.2%	3.1%	14.0%	5.9%	3.8%	18.5%	2.2%	11.5%	13.1%	100.0%
094- पर्यटन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	7	24	61	71	95	227	44	84	85	43	60	133	934
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.7%	2.6%	6.5%	7.6%	10.1%	24.4%	4.7%	8.9%	9.1%	4.6%	6.5%	14.2%	100.0%
095- जनजातीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2	2	600	89	12	1,477	44	57	263	97	185	245	3,073
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	0.1%	19.5%	2.9%	0.4%	48.1%	1.4%	1.9%	8.6%	3.1%	6.0%	8.0%	100.0%
096- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	227	201	243	157	191	209	235	216	162	224	210	548	2,824
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8.0%	7.1%	8.6%	5.6%	6.8%	7.4%	8.3%	7.6%	5.7%	7.9%	7.4%	19.4%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
097- चंडीगढ़													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	242	234	302	0	181	257	257	262	225	190	288	686	3,125
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.8%	7.5%	9.7%	0.0%	5.8%	8.2%	8.2%	8.4%	7.2%	6.1%	9.2%	21.9%	100.0%
098- दादरा एवं नगर हवेली													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	19	193	280	28	40	437	220	200	197	499	145	90	2,347
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.8%	8.2%	11.9%	1.2%	1.7%	18.6%	9.4%	8.5%	8.4%	21.2%	6.2%	3.8%	100.0%
099- दमन एवं दीव													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	95	87	104	118	100	103	108	100	180	86	121	60	1,263
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7.5%	6.9%	8.2%	9.3%	7.9%	8.2%	8.6%	7.9%	14.2%	6.8%	9.6%	4.8%	100.0%
100- लक्षद्वीप													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	67	91	59	40	123	30	58	68	76	64	68	59	805
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8.3%	11.3%	7.4%	4.9%	15.3%	3.7%	7.2%	8.4%	9.4%	8.0%	8.5%	7.4%	100.0%
101- शहरी विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	101	618	547	117	106	1,318	285	560	2,341	101	115	365	6,575
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1.5%	9.4%	8.3%	1.8%	1.6%	20.1%	4.3%	8.5%	35.6%	1.5%	1.7%	5.6%	100.0%
102- लोक निर्माण कार्य													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	187	166	180	153	155	151	158	153	142	144	154	112	1,856
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.1%	8.9%	9.7%	8.3%	8.3%	8.1%	8.5%	8.3%	7.7%	7.8%	8.3%	6.0%	100.0%
103- लेखन सामग्री एवं मुद्रण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	28	19	16	18	19	15	19	20	27	19	19	4	224
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12.5%	8.7%	7.3%	7.8%	8.7%	6.9%	8.3%	8.9%	12.2%	8.4%	8.4%	1.9%	100.0%
104- जल संसाधन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	110	92	80	127	113	62	92	90	72	69	87	63	1,056
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10.4%	8.7%	7.6%	12.0%	10.7%	5.9%	8.7%	8.5%	6.8%	6.6%	8.2%	6.0%	100.0%
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	14	2,674	1,231	146	1,879	3,874	48	90	3,202	123	1,625	2,129	17,037
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.1%	15.7%	7.2%	0.9%	11.0%	22.7%	0.3%	0.5%	18.8%	0.7%	9.5%	12.5%	100.0%

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
106- युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3	34	171	226	153	60	21	79	42	10	140	61	999
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0.3%	3.4%	17.1%	22.7%	15.3%	6.0%	2.1%	7.9%	4.2%	1.0%	14.0%	6.1%	100.0%
माह के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**69,862**	**88,584**	**1,09,898**	**1,07,203**	**81,221**	**1,24,933**	**65,704**	**74,490**	**1,06,352**	**98,020**	**93,498**	**2,43,558**	**12,63,323**
वार्षिक व्यय की कुल प्रतिशतता	**5.5%**	**7.0%**	**8.7%**	**8.5%**	**6.4%**	**9.9%**	**5.2%**	**5.9%**	**8.4%**	**7.8%**	**7.4%**	**19.3%**	**100.0%**

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्ष का विवरण जिसमें लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' जो 2012-13 मे कार्यान्वित किया गया था जिसमे कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च को मुख्य शीर्ष के अतंगर्त दर्ज किया गया

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय-अन्य व्यय	मुख्य शीर्ष की तुलना में लघु शीर्ष में व्यय की प्रतिशतता
		(₹ हजार में)		
1.	2079-रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	13405906	7677905	57
2.	2236-पोषण	912828	556919	61
3.	2250-अन्य सामाजिक कार्य	449949	448245	100
4.	2416-कृषि वित्तीय संस्थान	54158452	54000000	100
5.	2552-उत्तर-पूर्व क्षेत्र	999266	832885	83
6.	2711-बाड़ नियंत्रण एवं जल निकास	1987692	1920538	97
7.	2803 कोयला और लिग्नाइट	3971357	2195900	55
8.	3053-नागरिक उड्डयन	11450275	10663457	93
9.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	87377	87279	100
10.	4211परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2355	2355	100
11.	4402-मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	3700	3700	100
12.	4408- खाद्य, भंडारण एवं भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	260338	209756	81
13.	4853- धातु शोधन संबंधी उद्योगों एवं नॉन-फेरस खनन पर पंजीगत परिव्यय	1462454	1462454	100
14.	5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15234261	15210583	100
15.	5453-विदेश व्यापर पर पूंजीगत परिव्यय	7234347	6610883	91
16.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8844574	6263292	71
योग		**120465131**	**108146151**	

अनुबंध 2.2

(पैरागाफ 2.1.3 के संदर्भ में)

सरकारी लेखों से परे नियामकों के कोष

क्र. सं.	नियामकों/स्वायत्त निकायों का नाम	निवेशों/पूंजीगत निधि के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय सुरक्षा एवं प्रतिभूति बोर्ड	अधिशेष निधि/समग्र निधि	1651.38
2.	बीमा नियामक एवं विकास संस्था	अधिशेष निधि	991.64
3.	पेंशन निधि विकास नियामक संस्था	पूंजीगत/समग्र निधि	2.14
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद्	1. स्वयं के संसाधनों से निवेश 2. भवन निधि	264.13
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	स्वयं के संसाधनों से निवेश	74.88
6.	भारतीय औषधी परिषद्	भवन निधि	16.50
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद्	स्वयं के संसाधनों से निवेश	46.82
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	मुख्य लेखा निध	0.94
9.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	लोक जमा लेखे	4.95
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो	पूंजीगत/समग्र निधि	30.70
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	बैंक के पास एफ.डी.आर. जनरल	575.00
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत खाता खाते	1032.50
13.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्	सावधि जमा (परीक्षा निधि)	6.24
14.	भारतीय मानक ब्यूरो	समग्र /पूंजीगत निधि	84.24
योग			**4782.06**

अनुबंध 2.3

(पैरागाफ 2.1.3 -ग के संदर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग में निलंब लेखों के संचालन का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	केन्द्र	अनुमोदन सं. एवं तिथि और राशि	योजना का उद्देश्य और नाम	बैंक का विवरण	31 मार्च 2013 को शेष	ब्याज
1	**एल.पी.एस.सी.**	3/5(5)/2002-III 27/3/2003 तथा 3/5/7/2002-III 28/3/2003 **(₹40.66 करोड़)**	तरल हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना मैसर्स आन्ध्र चीनी लिमिटेड, थानुकु	भा.स्टे.बैं., वी.एम.सी.	172.62	697.68
2	**एल.पी.एस.सी.**	13015/5/2010 धारा-3 (खण्ड II) 27/3/2010 **(₹9.71 करोड़)**	क्रायो एवं सेमीक्रायो गतिविधियों के लिए सी.यू.-सी.आर-जेट.आर.टी.आई. ताम्बे एलोय प्लेट की प्राप्ति। मैसर्स नॉन-फैरस पदार्थ प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (ना.फै.प.फौ.वि.के.), हैदराबाद	भा.स्टे.बैं., वी.एम.सी.	567.65	211.44
3	**एल.पी.एस.सी.**	3/5/7/2005-III, 24.03.2005 **(₹38.25 करोड़)**	एल.पी.एस.सी., महेन्द्र गिरि में ट्रस्ट चेम्बर टेस्ट तरल सेवा प्रणाली की प्राप्ति मैसर्स लिंडे प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्राइवेट लि. वड़ोदरा	भा.स्टे.बैं., वालियामल, त्रिवेंद्रम	0.00	778.70
4	**एल.पी.एस.सी.**	3/5/7/2005-III, 24.03.2005 **(₹56.48 करोड़)**	एल.पी.एस.सी., महेन्द्र गिरि में ट्रस्ट चेम्बर टेस्ट तरल सेवा प्रणाली की प्राप्ति मैसर्स लिंडे क्रायो तकनीकी ए.जी., स्वीट्जरलैण्ड	भा.स्टे.बैं., वालियामल, त्रिवेंद्रम्	0.00	685.83
5	**वी.एस.एस.सी.सी.**	बी.12011/11/2009 -धारा-2 21/12/2009 **(₹18.00 करोड़)**	मिधानी में ई.बी. पिघलाने वाली भट्टी की स्थापना	भा.स्टे.बैं. कंचनबाग	1800.00	221.79
6	**वी.एस.एस.सी.सी.**	सी.13011/24/ 2010-11 29/3/2010 **(₹28.14 करोड़)**	न्योवयम उत्पादन सुविधा की स्थापना	भा.स्टे.बैं. नचरम शाखा, हैदराबाद	2234.08	181.01
7	**वी.एस.एस.सी.सी.**	सी.13011/19/ 2010-11 24/3/2010 तथा सं.सी.13011/ 2010-11/4/3/2011 **(₹23.74 करोड़)**	टी.सी.सी. कोच्ची में सोडियम क्लोरेट उत्पादन सुविधा की स्थापना	भा.स्टे.बैं. अलुवा शाखा, अलुवा	25.87	21.12
8	**वी.एस.एस.सी.सी.**	3/1/2/2004-III 18/2/2004 3/1/2/2004-III 21/7/2004 **(₹15.60 करोड़)**	हिंदु उच्च निर्वात, बैंगलौर से एस.आई.सी. कोटिंग तथा रसायन वाष्प डेपोसियन प्रावधान के साथ निर्वात प्रवर्तन भट्टी का प्रापण	भा.स्टे.बैं.पीनया ईडल शाखा, बैंगलोर	238.49	350.63
9	**वी.एस.एस.सी.सी.**	3/16/(3)/03-III, 28.02.2003 **(₹8.73 करोड़)**	मैसर्स टी.ए.एम.एल., बैंगलौर द्वारा योक एवं सौर पैनल का निर्माण एवं आपूर्ति	भा.स्टे.बैं. रेसकोर्स रोड़, बैंगलोर	0.00	60.00

क्र. सं.	केन्द्र	अनुमोदन सं. एवं तिथि और राशि	योजना का उद्देश्य और नाम	बैंक का विवरण	31 मार्च 2013 को शेष	ब्याज
10	**वी.एस.एस.सी.पी.**	सी.13011/19/ 2006-धारा-3 24/3/2006 **(₹31.13 करोड़)**	ए.आई. एलॉय कास्ट हाउस की स्थापना तथा बिलैट की आपूर्ति	भा.स्टे.बैं. बाल्को टाउनशिप शाखा, कोरबा	203.25	221.45
11	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1/10/2003-III 01.10.2003 सी.13011/5/ 2003-III सी.13011/5/ 2003-धारा-3 30/3/2009 **(₹39.50 करोड़)**	बाल्को द्वारा सुविधा आवर्धन तथा शीट	भा.स्टे.बैं. बाल्को टाउनशीप शाखा, कोरबा	432.40	200.00
12	**वी.एस.एस.सी.पी.**	सी.13011/5/ 2006-धारा-3 20/2/2006 13011.5.2006/ धारा-31/3/2010 **(₹143.11 करोड़)**	के.एम.एम.एल. द्वारा टाइटेनियम स्पॉन्ज की स्थापना	भा.स्टे.बैं., कोम्मल, शाखा, कोल्लम	251.00	3506.00
13	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1/12/2005-III 15/3/2005 **(₹31.01 करोड़)**	हिन्द हाई वैक्यूम से निर्वात प्रणाली का प्रापण	भा.स्टे.बैं., पीनया औद्योगिक शाखा, बैंगलौर	0.00	50.00
14	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1(15)/2001-III 27/3/2002 3/1(15)/2001-III 27/3/2003 3/1(15)/2001-III 24/3/2004 सी.13011/1/ 2001-धारा- 31/3/2008 **(₹75.40 करोड़)**	बे-फोर्ज लिमिटेड द्वारा रिंग रोलिंग मिल की स्थापना	भा.स्टे.बैं., कोम्मल शाखा, चैन्नई	0.00	43.50
15	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1/5/03-III 1/12/2003 3/1/5/01-III (खण्ड II) 22/2/2005 सी.13011/1/ 2001- धारा- 17/1/2006 सी.13011/1/2001 -III 7/11/2006 **(₹20 करोड़)**	बे-फोर्ज लिमिटेड द्वारा रिंग रोलिंग मिल की स्थापना	भा.स्टे.बैं., विदेश, चैन्नई	2000.00	48.00
16	**वी.एस.एस.सी.पी.**	सी.13011/42/ 2006-III 20/2/2007 **(₹2.75 करोड़)**	एस.आई.एफ.एल. का सुविधा आवर्धन	भा.स्टे.बैं., बलियामाला	0.00	0.21
17	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1/19/2005-III 28/3/2005 13011/39/2005- III 28.1.2009 **(₹159.50 करोड़)**	एल. एवं टी. द्वारा हवा सुरंग प्रणाली का डिजाइन, निर्माण	भा.स्टे.बैं., नि.म.ले.प. शाखा, मुम्बई	6065.00	1534.00

क्र. सं.	केन्द्र	अनुमोदन सं. एवं तिथि और राशि	योजना का उद्देश्य और नाम	बैंक का विवरण	31 मार्च 2013 को शेष	ब्याज
18	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1/11/2005 10/3/2005 **(₹20.10 करोड़)**	न्यूमन एवं एसर द्वारा उच्च दाब प्रणाली का प्रापण	भा.स्टे.बैं., चिंचवाड, पुणे	0.00	17.00
19	**वी.एस.एस.सी.पी.**	3/1/10/04-III 27/3/2004 3/1/10/2004-III 24/3/2005 3/1/10/2004-III 20/1/2006 (₹ 69.30 **करोड़**)	मिधानी का सुविधा आवर्धन	भा.स्टे.बैं., चन्द्रयानागत शाखा, हैदराबाद	0.00	1187.18
	योग	**₹ 831.11 करोड़**			**13990.36**	**10015.54**

अनुबंध 2.4

(पैरागाफ 2.3.6 के संदर्भ में)

निष्क्रिय रिर्जव निधियों/जमाओं को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति रिर्जव	31 मार्च 2013 को शेष (₹ हजार में)	निम्न से निष्क्रिय
1.	8116-राजस्व रिर्जव निधि	रिजर्व	826894	2001-02
2.	8118.105-दूरसंचार पूंजीगत रिर्जव निधि	रिजर्व	6	2001-02
3.	8121.119-Staff स्टाफ लाभ निधि (रेलवे)-निवेश लेखे	रिजर्व	100	1999-00
4.	8121.111-आकस्मिकता रिर्जव निधि-विद्युत	रिजर्व	13075	2006-07
5.	8223.101-अकाल सहायता निधि	रिजर्व	3	2008-09
6.	8229.101-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	रिजर्व	7	2002-03
7.	8229.102-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रायोजन हेतु विकास निधि	रिजर्व	60	2002-03
8.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधि	रिजर्व	102	2002-03
9.	8229.117 राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिक कोर निधि	रिजर्व	32513	2002-03
10.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	रिजर्व	5811202	2008-09
11.	8230.102- विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	रिजर्व	166624	2007-08
12.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभाग/ उपक्रमों की सामान्य रिर्जव निधि	रिजर्व	7586	2008-09
13.	8235.104-रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	रिजर्व	407441	2003-04
14.	8235.105-सामान्य बीमा निधि	रिजर्व	2613201	2005-06
15.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधि	रिजर्व	177020	2008-09
16.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि निवेश लेखा	जमा	6512	2001-02
17.	8337.104-गैर-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कमचारी भविष्य निधि निवेश लेखा	जमा	50	2001-02
18.	8342.104-कोयला खनन पेंशन योजना 1998	जमा	2946846	2006-07
19.	8342.107-संपदा शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	131	2008-09
20.	8342.110-दूरभाष आवेदन पत्र जमा	जमा	2239801	2005-06
21.	8342.111-टेलेक्स आवेदन पत्र जमा	जमा	79306	2003-04

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति रिर्जव	31 मार्च 2013 को शेष (₹ हजार में)	निम्न से निष्क्रिय
22.	8342.114-पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा जमा	जमा	16947	2001-02
23.	8342.108-आयकर, भव्यकर, आधिक्य लाभ, कर तथा अधिभार के जमा	जमा	12161	2001-02
24.	8443.114-निर्यात व्यापार जमा	जमा	152527	1988-89
25.	8443.122-खदान श्रमिक कल्याण जमा	जमा	2335	1988-89
26.	8443.127- पाकिस्तान में जा बसे ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेशनरों दावों को पूरा करने के लिए स्थनीय निकायों के जमा	जमा	2107	1996-97
27.	8443.130-प्रोविडेंट समिति परिसमापन लेखे	जमा	13	2008-09
28.	8445.102-शाखा सीमा कम्पनी के जमा	जमा	65	1992-93
29.	8448.103-छावनी निधि	जमा	1	2000-01
30.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधि	जमा	52	1988-89
31.	8448. 120- अन्य निधियां	जमा	226	2004-05
32.	8449.104-खादान भविष्य निधियों का जमा	जमा	1601	1988-89
33.	8449.106-भारत समझौता अधीन खाते 1974	जमा	16	1991-92
34.	8449.107-आयकर, भव्यकर, आधिक्य लाभ, कर तथा अधिभार के जमा	जमा	13393	1991-92
35.	8449.108- ऋण से मुक्ति के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	3297	2000-01
36.	8449.113-तेल बीज एवं खाद्य तेल विकास निधि	जमा	36613	1999-00
37.	8449.118-जापानी सहायता प्रदत्त योजनाओं के लिए अधिक जमा	जमा	10360	1995-96
38.	8450.101-पांडीचेरी का शेष	जमा	401290	2008-09
39.	8450.102-गोवा, दमन, दीयु का शेष	जमा	163026	1988-89
40.	8450.104-अरूणाचल प्रदेश का शेष	जमा	568251	1988-89
41.	8450.105-मिजोरम का शेष	जमा	1244138	1988-89
42.	8009.01.103- आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देयताएं	201	1999-00
43.	8009.03.102-अंतरण हुई रेलवे कार्मिक भविष्य निधि	अन्य देयताएं	3536	2000-01
44.	8010.105-अन्य ट्रस्ट	अन्य देयताएं	1923	1999-00

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति रिर्जव	31 मार्च 2013 को शेष (₹ हजार में)	निम्न से निष्क्रिय
45.	8010.102-अवध के स्वर्गीय राजा के द्वारा दान	अन्य देयताएं	9104	1992-93
46.	8010.104-धर्मार्थ एवं शिक्षण संस्थाओं के दान	अन्य देयताएं	12	2008-09
47.	8011.102-पारिवारिक पेंशन निधि	अन्य देयताएं	610	2008-09
48.	8012.103-ग्रामीण विद्युत कार्पोशन को जारी विशेष प्रतिभूति	अन्य देयताएं	1628305	1988-89
कुल			**46122208**	

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)

विदेश में किए गए क्रयों के लिए उचंत लेखा में शेष राशि (2003 से)

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	आयातक का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
2.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
3.	परिवारिक स्वास्थ्य सहायता महाराष्ट्र	1	218
4.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
5.	रेल मंत्रालय	2	8399
6.	पाईराईट फोस्टफेट एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
7.	रेल कोच कारखाना (कपूरथला)	1	1895
8.	रेलवे बोर्ड	1	13138
9.	रेल स्प्रिगं कुण्डली	1	7111
10.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
11.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
12.	दूर संचार विभाग	6	14737
13.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	341
14.	भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड	3	14257
15.	लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल	1	9962
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	136
17.	गृह मंत्रालय	1	2255
18.	सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3	3729
19.	सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तकनीकी	3	15277
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
21.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1	3648
22.	दिल्ली विद्युत आपुर्ति उपक्रम दिल्ली	1	78009
23.	भिलाई स्टील प्लांट	1	1200
24.	कोल इंडिया लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	3	231832
25.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
26.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
27.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
28.	आ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड आ.प्र.	1	47476
29.	भारतीय हैलीकॉप्टर कार्पोरेशन	1	672356
30.	कृभको वर्षा कृषि तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
31.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग	1	4560
32.	जिला गरीबी उपक्रमण परियोजना	1	14630
33.	कृषि मंत्रालय	1	3602
योग		**50**	**2104583**

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण के अंतर्गत प्रतिकुल शेष

(₹ हजार में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2012 को शीर्ष		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 13					
1.	8115.00.101	विमूल्यन रिर्जव निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डेबिट	27167883	2009-10
2.	8117.00.101	रेलवे विकास निधि (वाणिज्यिक लाईन)	डेबिट	15480118	2009-10
3.	8118.00.106	रेलवे पूंजीगत निधि	डेबिट	3252349	2010-11
4.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि- वाणिज्यिक लाईन	डेबिट	18908664	2009-10
5.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट	2004601	2007-08
6.	8231.00.102	रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	डेबिट	1	2004-05
7.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमा	डेबिट	492074	2006-07
8.	8445.00.104	रेलवे जमा ट्रस्ट ब्याज खाता	डेबिट	198265	2005-06
9.	8445.00.800	रेलवे जमा-अन्य जमा	डेबिट	7693048	2005-06
10.	8446.00.800	डाक संबंधी जमा अन्य जमा	डेबिट	159441	2005-06
11.	8448.00.102	निगम निधि स्थानीय निधि जमा	डेबिट	3	2007-08
12.	8448.00.104	भारतीय बीमा संघ की निधियां स्थानीय निधियों के जमा	डेबिट	291	Pre-1976-77
13.	8451.00.101	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे एवं राहत निधि	डेबिट	9309008	2005-06
14.	8451.00.102	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे राहत निधि निवेश खाता	डेबिट	9216338	2005-06
15.	8670.00.101	पूर्व लेखापरीक्षा चैक	डेबिट	16681951	2011-12
16.	8670.00.111	लेखा एवं संवितरण कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	7968473	2011-12
विवरणी सं. 14					
17.	6002.00. 207	यूरोपियन आर्थिक समूह से कर्जे	डेबिट	771524	2000-01
18.	6002.00. 208	फ्रांस सरकार से कर्जे	डेबिट	24799504	2000-01
19.	6002.00. 223	स्विस संघ सरकार और स्विस बैंक से कर्जे	डेबिट	98913	2010-11

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2012 को शीर्ष		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
20.	6002.00. 226	अंतरराष्ट्रीय विकास अमेरिका के लिए अभिकरण से ऋण	डेबिट	6707281	1995-96
21.	6002.00. 227	पी.एल.-480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा जमा के अधीन यू.एस.ए. सरकार से कर्जा	डेबिट	4787983	1995-96
22.	8013.01.101	जमा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना, 1989	डेबिट	655086	2007-08
विवरणी सं. 14-क					
23.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं प्रतिभूतियॉ	डेबिट	404339	2010-11
24.	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तिय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को जारी प्रतिभूतियाँ	डेबिट	200120	2002-03
25.	6001.00.106	क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋणपत्र-7% बचत ऋणपत्र 2002	डेबिट	117466	2009-10
विवरणी सं. 15					
26.	6202.01. 203	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
27.	6215.02.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	18346	2001-02
28.	6216.80.190	सार्वजनिक निकाय एवं अन्य उपक्रम को कर्जे	क्रेडिट	2	2008-09
29.	6216.80.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	11889	2010-11
30.	6225-01-800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	829	1994-95
31.	6245.01.101	पेंशन सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
32.	6245.02.101	पेंशन सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
33.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रेडिट	7625	1995-96
34.	6402.00.203	भूमि -सुधार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
35.	6404.00.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	4642331	2004-05
36.	6405.00.106	मछली पकड़ने के शिल्प मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2006-07
37.	6416.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	174472	2012-13
38.	6425.00.108	अन्य सहकारिताओं को ऋण	क्रेडिट	3975945	2003-04
39.	6515.00.102	समुदाय विकास	क्रेडिट	121	1986-87

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2012 को शीर्ष		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
40.	6801.00.201	जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट	3068415	2004-05
41.	6801.00.205	ट्रांसमिशन एवं वितरण	क्रेडिट	1240335	2005-06
42.	6851.00.102	लघु उद्योग	क्रेडिट	4222	2006-07
43.	7052.02.101	एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	क्रेडिट	2941224	2011-12
44.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	377537	2010-11
45.	7425.00.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट	3074	2005-06
46.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रेडिट	25000	2011-12
47.	7601.01.436	फसल कृषिकर्म- वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2012-13*
48.	7601.03.413	सहकारिता- अन्य सहकारिता को ऋणें	क्रेडिट	4184	2012-13*
49.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण- मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	2033	2012-13*
50.	7601.03.576	पशु-पालन-मवेशी एवं भैंस विकास	क्रेडिट	11	2012-13*
51.	7601.03.601	दुग्धशाला विकास	क्रेडिट	29	2012-13*
52.	7601.03.727	ग्रामीण एवं लघु उघोग - लघु उधोग	क्रेडिट	139	2012-13*
53.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋणें	क्रेडिट	71707	2012-13*
54.	7601.03.787	समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं- अन्य ऋणें	क्रेडिट	1239	2012-13*
55.	7601.04.267	जल आपूर्ति - अन्य ऋणें	क्रेडिट	149604	2012-13*
56.	7601.04.312	शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रेडिट	191427	2012-13*
57.	7601.04.360	अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण-अन्य ऋणें	क्रेडिट	408	2012-13*
58.	7601.04.411	सहकारिता-साख सहकारियाँ	क्रेडिट	32522	2012-13*
59.	7601.04.413	अन्य सहकरियां	क्रेडिट	1686	2012-13*
60.	7601.04.436	फसल कृषिकर्म-वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	131131	2012-13*
61.	7601.04.443	फसल कृषिकर्म-अन्य ऋणें	क्रेडिट	326226	2012-13*
62.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण- मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	962.29	2012-13*
63.	7601.04.579	पशु-पालन-भेड़ एवं ऊन विकास	क्रेडिट	175	2012-13*

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2012 को शीर्ष		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
64.	7601.04.601	दुग्धशाला विकास	क्रेडिट	36	2012-13*
65.	7601.04.726	ग्रामीण एवं लघु उद्योग- हस्तकरघा उद्योग	क्रेडिट	6960	2012-13*
66.	7601.04.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग- लघु उद्योग	क्रेडिट	853	2012-13*
67.	7601.04.729	ग्रामीण एवं लघु उद्योग- नारियल जटा उद्योग	क्रेडिट	354	2012-13*
68.	7601.04.747	ग्रामीण एवं लघु उद्योग- अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रेडिट	1088	2012-13*
69.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण - अन्य ऋण	क्रेडिट	4730	2012-13*
70.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग- कार्य	क्रेडिट	17910	2012-13*
71.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग - मशीनरी एवं उपकरण	क्रेडिट	555	2012-13*
72.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13*
73.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	1580	2012-13*
74.	7602.04.412	सहकारिता- उपभोक्ता सहकारियां	क्रेडिट	14	2012-13*
75.	7605.00.071	मोजाम्बिक सरकार को ऋण	क्रेडिट	1	2012-13*
76.	7605.00.094	मॉरिशस सरकार को ऋण	क्रेडिट	13313	2012-13*
सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण					
77.	7610.00.203	अन्य वाहनों के क्रय के लिए अग्रिम	क्रेडिट	380141	2004-05
विवरणी सं. 16					
78.	8002.00.103	राजकोष बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
79.	8002.00.104	रक्षा बचत प्रमाणपत्र	डेबिट	1726	2012-13
80.	8002.00.105	बचत प्रमाण पत्र (बैंक क्रम)	डेबिट	189	2007-08
81.	8002.00.106	राष्ट्रीय विकास बॉडस	डेबिट	12940	2012-13

*म.नि.ले.प. ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाने हेतु लंबित रहने तथा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रतिकूल शेष, शेषों को बट्टे खाते में डालने के कारण थे।

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.4.5 के संदर्भ में)

विभाग द्वारा प्रबंधित सरकारी उपक्रम के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम 2012-13

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयारी लेखे की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2012-13
2.	शीत -सह हिमीकरण,संयन्त्र, कोच्ची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद	2010-11
4.	भारी जल संयत्र मुबई	2010-11
रक्षा मंत्रालय		
5.	कैंटीन भंडारण विभाग	2011-12
वित्त मंत्रालय		
6.	सरकारी क्षारद निर्माण, नीमच	2010-11
7.	सरकारी क्षारद निर्माण,गाजीपुर	2009-10
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	राजकीय चिकित्सा भंडार ड़िपो, कोलकाता	2007-08
12.	राजकीय चिकित्सा भंडार, हैदराबाद	2009-10
13.	राजकीय चिकित्सा भंडार, नई दिल्ली	2008-09
14.	राजकीय चिकित्सा भंडार विभाग, मुंबई	2006-07
15.	केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का शाकाहारी बगीचा कांके, राँची	2011-12
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
16.	फिल्म शाखा, मुंबई	2009-10
ऊर्जा मंत्रालय		
17.	विद्युत विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2010-2011
18.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2008-09
नौपरिवहन मंत्रालय		
19.	प्रकाश गृह एवं द्वीप नौका, नोएडा	2011-12
20.	अण्डमान नौका सेवा	2004-05
21.	नौ परिवहन सेवाएं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
22.	समुद्रीय विभाग (डाकयार्ड) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2003-04
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय		
23.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम	2009-10
24.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2011-12
शहरी विकास मंत्रालय		
25.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे
26.	भारत सरकार प्रेस, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली	2011-12

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम तैयारी लेखे की अवधि
27.	भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड़, नई दिल्ली	2011-12
28.	भारत सरकार प्रेस, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2011-12
29.	भारत सरकार प्रेस, निलोखरी	2012-13
30.	भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद	2012-13
31.	भारत सरकार प्रेस, शिमला	2012-13
32.	भारत सरकार प्रेस, कोयम्बटूर	2012-13
33.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक प्रेस, भुवनेश्वर	2011-12
34.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक प्रेस, मैसूर	2011-12
35.	भारत सरकार प्रेस, कोलकाता	2011-12
36.	भारत सरकार प्रेस, कोरट्टी	2012-13
37.	भारत सरकार प्रेस, नासिक	2012-13
38.	भारत सरकार प्रेस, अलीगढ़	2011-12
39.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक प्रेस, चंडीगढ़	2012-13
40.	भारत सरकार प्रेस, गंगटोक	2007-08
41.	भारत सरकार प्रेस, सत्रगाची, हावड़ा	2011-12

अनुबंध 2.8

(पैराग्राफ 2.4.6 के संदर्भ में)

2012-13 के दौरान कुल हानि/माफ किए गए हानियों एवं अप्राप्य बकायों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानि को बट्टे खाते में डालने से एवं अप्राप्य बकायों के कारण									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/ कपट आदि		अन्य कारण		वसूली की छूट		अनुग्रही भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	26	10.5	0	0	0	0
शहरी विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.96
अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	4	0.80	2	11.14	0	0
डाक व दूरसंचार	24	0.03	35	31.73	47	31.18	32	40.01	153	5.38
जल संसाधन मंत्रालय	5	9.05	1	0.37	5	2.78	0	0	0	0
मण्डलीय वन अधिकारी, दक्षिण अण्डमान	0	0	0	0	3	3.91	0	0	2	1.13
वित्त मंत्रालय सी.बी.ई.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
उपभोक्ता मामलें एवं खाद्य जन वितरण मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.08
औद्योगिक एवं खनन विभाग	0	0	0	0	1	0.07	0	0	0	0
वित्त मंत्रालय, सेबी कोलकाता	0	0	0	0	1	1.25	0	0	0	0
संस्कृति मंत्रालय- आर.आर.एल.एफ. कोलकाता	0	0	0	0	1	0.02	0	0	0	0
पर्यटन मंत्रालय एवं सी.एन.सी.एस.एम. कोलकाता	0	0	0	0	3	17.43	0	0	0	0
संस्कृति मंत्रालय वी.एम.एच. कोलकाता	0	0	0	0	1	9.26	0	0	0	0
संस्कृति मंत्रालय आई.एम. कोलकाता	0	0	0	0	2	0.31	0	0	0	0
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ई.पी.एफ.ओ हावड़ा	0	0	0	0	1	34.59	0	0	0	0
वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग	0	0	0	0	1	0.43	0	0	0	0
कृषि मंत्रालय	0	0	0	0	2	0.72	0	0	0	0
अण्डमान व निकोबार प्रशासन	0	0	0	0	0	0	0	0	03	29.16
रोड़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	05	2.80	15	34.06	54	129.44	01	0.21	05	8.70

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानि को बट्टे खाते में डालने से एवं अप्राप्य बकायों के कारण									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/ कपट आदि		अन्य कारण		वसूली की छूट		अनुग्रही भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण का मुंबई बेस, मुंबई	0	0	0	0	0	0.05	0	0.05	0	0
भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण बोटा वाला चेम्बर, मुंबई	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0
योग	**34**	**11.88**	**51**	**66.16**	**152**	**242.76**	**35**	**51.41**	**167**	**63.41**
बट्टे खाते मामले में डाली गई हानियां: मामले- 237, राशि ₹320.80							माफ की गई वसूली एवं अनुग्रह भुगतानः मामले 202, ₹114.82			

अनुबंध-3.1

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत (-) आधिक्य (+)
क– सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	919615.39	71562.39	991177.78	883875.92	(-) 107301.86
II. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित)	159440.81	4443.97	163884.78	93194.59	(-) 70690.19
योग	**1079056.21**	**76006.35**	**1155062.56**	**977070.51**	**(-) 177992.05**
प्रभारित					
III. राजस्व	387306.10	4844.46	392150.56	378805.71	(-) 13344.85
IV. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	3798123.77	31.00	3798154.77	3437589.76	(-) 360565.01
योग	**4185429.87**	**4875.46**	**4190305.33**	**3816395.47**	**(-) 373909.86**
कुल योग	**5264486.08**	**80881.81**	**5345367.89**	**4793465.98**	**(-) 551901.91**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			**131006.19**	**115890.39**	
कुल निवल प्रावधान			**5214361.70**		
कुल निवल संवितरण				**4677575.59**	

ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	14379.61	940.88	15320.49	15480.63	+160.14
II. पूंजीगत	615.77	--	615.77	145.59	-470.18
योग	**14995.38**	**940.88**	**15936.26**	**15626.22**	**-310.04**
प्रभारित					
III. राजस्व	0.10	0.65	0.75	0.52	-0.23
IV. पूंजीगत	--	0.69	0.69	0.68	-0.01
योग	**0.10**	**1.34**	**1.44**	**1.20**	**-0.24**
कुल योग	**14995.48**	**942.22**	**15937.70**	**15627.42**	**-310.28**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां	665.05		665.05	688.77	
कुल निवल प्रावधान			**15272.65**		
कुल निवल संवितरण				**14938.65**	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत आधिक्य (+)
ग - रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I राजस्व	118876.67	--	118876.67	116707.76	-2168.91
II. पूंजी	79526.98	0.01	79526.99	70483.32	-9043.67
योग	**198403.65**	**0.01**	**198403.66**	**187191.08**	**-11212.58**
प्रभारित					
III. राजस्व	59.60	10.99	70.59	262.11	(+)191.52
IV. पूंजी	51.65	--	51.65	15.80	-35.85
योग	**111.25**	**10.99**	**122.24**	**277.91**	**(+)155.67**
कुल योग	**198514.90**	**11.00**	**198525.90**	**187468.99**	**-11056.91**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			541.82	484.78	
कुल निवल प्रावधान			**197984.08**		
कुल निवल संवितरण				**186984.21**	**(-)10999.87**

घ - रेलवे					
दत्तमत	241816.89	2731.91	244548.80	226054.95	-18493.85
प्रभारित	259.24	81.44	340.68	284.35	-56.33
योग	**242076.13**	**2813.35**	**244889.48**	**226339.30**	**-18550.18**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			79254.00	76026.97	
कुल निवल प्रावधान			**165635.48**		
कुल निवल संवितरण				**150312.33**	

04 - रक्षा आयुध कारखाना

कुल

योग भा.सं.नि.	**दत्तमत**	**1534272.13**	**79679.15**	**1613951.28**	**1405942.76**	**-208008.52**
	प्रभारित	**4185800.46**	**4969.23**	**4190769.69**	**3816958.93**	**-373810.76**
कुल योग भा.सं.नि.		**5720 072.59**	**84648. 38**	**5804720.97**	**5222901.69**	**-581819.28**
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				**211467.06**	**193090.91**	**18376.15**
विनियोग लेखे (भा.सं.नि.) के अनुसार कुल व्यय				**5593253.91**	**5029810.78**	**563443.13**
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					**(+) 0.02**	
वित्त लेखे के अनुसार भा.सं.नि. से कुल संवितरण					**5029810.80**	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवित
ा कहलाता है।

भा.सं.नि.: भारत की संचित निधि

अनुबंध -3.2

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदानें तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत (-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	111167. 63	70690. 19	3865.77	--	(-)107301. 86	(-)70690. 19
अनुदानों की संख्या	91	70	2	--		
प्रभारित	14044.47	360565.01	699.62	--	(-)13344. 85	(-)360565.01
विनियोगों की संख्या	32	11	3	--		
ख - डाक						
दत्तमत		470.18	160.14		+160.14	(-)470.18
अनुदानों की संख्या		1	1			
प्रभारित	0.23	0.01			-0.23	-0.01
विनियोगों की संख्या	1	1				
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	2168.91	9043.67	--	-	(-)2168.91	(-)9043.67
अनुदानों की संख्या	5	1	--	-	-	-
प्रभारित	4.01	35.85	195.53	-	(+)191.52	(-)35.85
विनियोगों की संख्या	2	1	3	-	-	-
घ - रेलवे						
दत्तमत	11022.42	9140. 38	1668.94	-	(-) 9353. 48	(-) 9140. 38
अनुदानों की संख्या	12	4*	3	-		
प्रभारित	44. 52	13. 10	1. 30	-	(-)43.22	(-)13. 10
विनियोगों की संख्या	5	4*	7	-		

* एक अनुदान के चार खण्ड

अनुबंध-3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

		प्राधिकरण			संवितरण				
क्र. सं.	वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80

अनुबंध-3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल					
21- रक्षा पेंशन					
1.	2071.02.101.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	मू. अ. सं.	33971.48 211.91 (-)70.59	37570.70	3457. 90
2.	2071.02.102.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	मू. अ. सं.	1322.20 16.59 (-)10.13	1517.85	189.19
3.	2071.02.103.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	मू. अ. सं.	2312.36 10.30 (-)59.08	2525.03	261.45
31– विदेश मंत्रालय					
4.	2061.00.101.01-प्रबंधन एवं स्थापना	मू. अ. सं.	1526.22 15.00 (+)92.42	1709.57	75.93
5.	2061.00.789.03-संयुक्त राष्ट्र संगठन	मू. सं.	152.80 (-)7.50	150.96	5.66
6.	3605.00.101.12-श्रीलंका-अन्य सहायता कार्यक्रम	मू. सं.	290.00 (-)57.04	248.20	15.24
34- विनियोग-ब्याज भुगतान					
7.	2049.02.217 जापान सरकार से लिए गए ऋण पर ब्याज	मू. सं.	1517.03 (-)47.24	1475.08	5.29
8.	2049.03.104.01-सामान्य भविष्य निधि	मू. सं.	6329.24 (-)988.48	5907. 44	566. 68
9.	2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधि	मू. सं.	1443.50 (+)455.76	3091.08	1191.82
10.	2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. सं.	2042.53 (-)56.23	2144.74	158.44
11.	2049.03.108.06-डाक बीमा एवं जीवन वृति निधि	मू. सं.	474.54 (-)44.88	961.89	532.23
39- पेंशन					
12.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. सं.	10221.01 (-)387.00	9872.67	38.66
13.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	मू. सं.	2476.85 (-)208.15	2349.21	80.51
14.	2071.01.117.01-सरकारी अंशदान	मू. सं.	1000.00 (+)130.00	1197.36	67.36

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
15.	2210.06.101.31-राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	मू. सं.	27.22 (-)16.83	22.64	12.25
16.	2211.00.109.09-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	मू. सं.	467.64 (+)52.43	525.38	5.31
17.	3601.04.246.02- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	मू. सं.	512.37 (-)180.21	339.17	7.01
54- पुलिस					
18.	2055.00.102.01- स्थापना	मू. अ. सं.	8968.04 2.79 (+)623.84	9696.02	101.35
19.	2055.00.105.01 महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल	मू. अ. सं.	8413.93 1.81 (+)443.89	8933.55	73.92
20.	2055.00.105.03-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	मू. अ. सं.	2320.65 1.80 (+)89.17	2457.48	45.86
21.	2055.00.107.01-निर्देशन एवं प्रशासन	मू. अ. सं.	3766.12 1.80 (+)197.01	3990.42	25.49
22.	2055.00.120.01- स्थापना	मू. अ. सं.	1844.88 1.80 (+)227.60	2114.00	39.72
74- योजनाएं					
23.	3475.00.800.83 योजनागत लेखांकन और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली	मू. सं.	130.00 -120.89	14.45	5.34
100- लक्षद्वीप					
24.	2202.80.198.01- पंचायतें	मू. अ. सं.	70.49 19.67 (-)2.46	95.66	7.96
25.	4059.80.051.26-भवन	मू. सं.	1.00 (-)0.75	7.30	7.05
102– लोक निर्माण विभाग					
26.	2059.01.104.01- स्थानीय निकायों को किराया दरों एवं करों का भुगतान	मू. सं.	135.37 शून्य	152.29	16.92
रक्षा सेवाएं **22- रक्षा सेवाएं - थल सेना**					
27.	2076.00.101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	मू. सं.	13.00 (-)1.69	187.42	176.11

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
28.	2076.00.101 थल सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. सं.	45014.03 (-) 1341.00	45151.99	1478.96
29.	2076.00.104- गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. सं.	3660.57 (-)90.32	3673.96	103.71
30.	2076.00.109-निरीक्षण संगठन	मू. सं.	795.98 (-)124.22	696.56	24.80
31.	2076.00. 111- निर्माण कार्य	मू. सं.	5634.95 (+)115.00	5768.73	18.78
32.	2076.00.112-राष्ट्रीय राईफल	मू. सं.	3497.80 (+) 168.43	4076.22	409.99
33.	2076.00.113-राष्ट्रीय क्रैडिट कोर (रा.कै.को.)	मू. सं.	1076.58 (-)293.24	790.25	6.91
23 – रक्षा सेवाएं - नौ सेना					
34.	2077.00.101- नौ सेना के वेतन एवं भत्ते (*प्रभारित*)	मू. सं.	0.70 (+)3.04	14.10	10.36
35.	2077.00.101- नौ सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. सं.	3430.00 (-)534.76	3126.53	231.29
36.	2077.00.104- गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. सं.	1844.00 (-)353.00	1548.13	57.13
37.	2077.00.105- परिवहन	मू. सं.	400.00 (-)65.53	380.49	46.02
38.	2077.00.106- मरम्मत एवं दुरूस्ती	मू. सं.	700.00 (-)61.77	653.81	15.58
39.	2077.00.110- भण्डार	मू. सं.	3896.00 (+)38.68	3981.91	47.23
40.	2077.00.111 – निर्माण कार्य	मू. सं.	750.00 (-)28.08	759.64	37.72
41.	2077.00.112 – संयुक्त स्टाफ	मू. सं.	1371.82 (-)114.07	1294.38	36.63
42.	2077.00.800-अन्य व्यय	मू. सं.	350.00 (-)34.58	351.07	35.65
24 – रक्षा सेवाएं – वायु सेना					
43.	2078.00.101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	मू. अ. सं.	0.10 0.20 (+)1.03	12.47	11.14
44.	2078.00.101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. सं.	7379.68 (-)233.63	7492.37	346.32
45.	2078.00.104- गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. सं.	899.83 (-)65.15	872.49	37.81

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाली विवरणी
(₹ पांच करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
46.	2078.00.111- निर्माण कार्य	मू.	1683.65	1774.36	128.66
		सं.	(-)37.95		
25 – रक्षा आयुध कारखाना					
47.	2079.00.054-उत्पादन	मू.	4460.74	4335.73	308.76
		सं.	(-)433.77		
26 – रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास					
48.	2080.00.111- निर्माण कार्य	मू.	546.45	621.39	6.27
		सं.	(+)68.67		
27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय					
49.	4076.01.050-भूमि	मू.	80.00	65.11	8.10
		सं.	(-)22.99		
50.	4076.01.103- अन्य उपकरण	मू.	8250.04	6658.19	146.87
		सं.	(-)1738.72		
51.	4076.02.103- अन्य उपकरण	मू.	3272.53	2773.06	328.97
		सं.	(-)828.44		
52.	4076.02.104- संयुक्त स्टाफ	मू.	898.80	924.21	25.45
		सं.	(-)0.04		
53.	4076.02.202- निर्माण कार्य	मू.	604.41	527.10	104.37
		सं.	(-)181.68		
54.	4076.02.204- नौसैनिक बेड़े	मू.	13617.39	11074.27	341.07
		सं.	(-)2884.19		
55.	4076.02.205- नौसैनिक डॉकयार्ड	मू.	1039.50	751.84	155.66
		सं.	(-)443.32		
56.	4076.03.050-भूमि	मू.	90.00	19.78	14.78
		सं.	(-)85.00		
57.	4076.03.101- वायुयान एवं हवाई-इंजन	मू.	23701.44	23572.95	25.75
		सं.	(-)154.24		
58.	4076.03.102-भारी एवं मध्यम वाहन	मू.	0.00	81.40	12.53
		सं.	(+)68.87		
59.	4076.03.103- अन्य उपकरण	मू.	4802.46	7398.65	118.35
		सं.	(+)2477.84		
60.	4076.03.206-विशेष परियोजना	मू.	631.36	586.98	8.11
		सं.	(-)52.49		
	कुल				**11860. 38**

अनुबंध-3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बजट आवंटन	बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व – दत्तमत				
1.	01- कृषि अनुसंधान और सहकारिता विभाग	20466.80	2480.33	12
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	5392.04	773.40	14
3.	03-पशुपालन, दुग्ध-उत्पादन एवं मत्स्य-पालन विभाग	2338.60	197.69	8
4.	04- परमाणु ऊर्जा	5564.05	233.31	04
5.	06-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	1764.00	100.78	06
6.	08-औषध विभाग	211.04	128.64	61
7.	09- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	1179.62	122.28	10
8.	11-वाणिज्य विभाग	4054.85	186.76	05
9.	12-औद्योगिक एवं उन्नयन विभाग	1494.19	173.78	12
10.	14-दूरसंचार विभाग	11587.39	3985.03	34
11.	15-यांत्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2877.54	1117.86	39
12.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	614.42	135.60	22
13.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	14723.46	711.62	05
14.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	1750.33	236.34	14
15.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	1464.45	406.00	28
16.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	3012.34	1091.15	36
17.	31– विदेश मंत्रालय	8288.95	311.05	04
18.	32- आर्थिक कार्य विभाग	9199.72	1587.03	17
19.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	8535.26	1270.16	15
20.	35 -राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	105786.55	21476.42	20
21.	39- पेंशन	19710.00	190.44	01
22.	41- राजस्व विभाग	1167.05	371.53	32
23.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	30685.78	5109.84	17
24.	47-आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1161.23	406.04	35
25.	48-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	908.03	187.59	21
26.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	1751.56	436.85	25
27.	50-भारी उद्योग विभाग	558.87	184.78	33
28.	52-गृह मंत्रालय	2925.38	1345.01	46
29.	55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1725.56	183.32	11
30.	56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2154.89	305.68	14
31.	57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1163.01	226.46	19
32.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	70559.80	4691.40	7
33.	59-उच्चत्तर शिक्षा विभाग	25379.08	4868.65	19
34.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4634.46	807.90	17
35.	63-विधि एवं न्याय	1515.60	331.98	22
36.	65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3071.88	632.60	21
37.	67-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	3054.70	980.02	32

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बजट आवंटन	बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
38.	68-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1456.48	293.76	20
39.	70 – पंचायती राज मंत्रालय	5350.76	1413.49	26
40.	74-योजना मंत्रालय	1661.23	441.81	27
41.	75- विद्युत मंत्रालय	10949.40	9200.23	84
42.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	22495.36	2836.25	13
43.	82- ग्रामीण विकास विभाग	129923.04	26266.79	20
44.	83-भू-संसाधन विभाग	3208.20	214.66	07
45.	84-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	14005.25	925.97	07
46.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2842.89	340.10	12
47.	86-वैज्ञानिक एवं औद्यागिक अनुसंधान विभाग	3475.10	529.44	15
48.	87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1500.40	217.56	15
49.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	1403.45	566.08	40
50.	89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5708.33	939.48	16
51.	90-अंतरिक्ष विभाग	3575.94	761.47	21
52.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4926.36	461.50	9
53.	93- वस्त्र मंत्रालय	7775.70	3513.98	45
54.	94-पर्यटन मंत्रालय	1279.98	347.72	27
55.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	410.21	127.80	31
56.	101-शहरी विकास विभाग	1321.73	232.27	18
57.	104- जल संसाधन मंत्रालय	1937.32	966.23	50
58.	105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	18584.03	1547.22	8
59.	106- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1150.75	152.94	13
राजस्व – प्रभारित				
60.	35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	58357.46	13104.04	22
61.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3627.80	905.69	25
पूंजीगत – दत्तमत				
62.	4-परमाणु ऊर्जा	3822.32	1240.57	32
63.	5- नाभिकीय ऊर्जा योजना	567.07	385.74	68
64.	07-उर्वरक विभाग	244.04	244.04	100
65.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	6155.82	143.72	02
66.	11-वाणिज्य विभाग	971.68	146.59	15
67.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1874.56	276.91	15
68.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	349.00	121.25	35
69.	31– विदेश मंत्रालय	2403.01	260.21	11
70.	32-आर्थिक कार्य विभाग	58961.13	52110.34	88
71.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	15902.02	1249.36	08
72.	42-प्रत्यक्ष कर	809.29	384.78	48
73.	43-अप्रत्यक्ष कर	119.21	109.26	92
74.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2298.32	998.37	43
75.	54-पुलिस	9333.60	2999.21	32
76.	60- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	544.01	189.30	35
77.	74- योजना मंत्रालय	515.80	256.69	50
78.	75- विद्युत मंत्रालय	5464.22	235.64	04

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बजट आवंटन	बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
79.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	24643.50	5610.90	23
80.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	583.09	217.55	37
81.	90-अंतरिक्ष विभाग	3138.22	1096.57	35
82.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	739.25	269.91	36
83.	99 दमन और दीव	350.44	125.66	36
84.	100-लक्षद्वीप	261.11	133.10	51
85.	101-शहरी विकास विभाग	6346.84	927.18	15
पूंजीगत – प्रभारित				
86.	35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	12000.00	1347.30	11
87.	37-विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	3786074.35	359181.41	09
रक्षा सेवाएं				
राजस्व - दत्तमत				
88.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	79980.55	463.60	0.58
89.	23-रक्षा सेवाएं - नौसेना	12741.82	645.87	5
90.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	18322.87	200.37	1.09
91.	26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	6034.95	816.63	14
पूंजीगत – दत्तमत				
92.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	79526.99	9043.67	11
डाक सेवाएं				
पूंजीगत – दत्तमत				
93.	13-डाक विभाग	615.77	470.18	76
रेलवे				
राजस्व - दत्तमत				
94.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	5343.50	112.13	2
95.	4-स्थायी मार्ग का मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	8786.79	553.38	6
96.	7-संयत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	5062.24	256.93	5
97.	9-परिचालन व्यय-यातायात	15229.49	145.46	1
98.	11-कर्मचारी कल्याण और सुविधाएँ	4342.68	277.85	6
99.	12-विविध कार्य व्यय	4605. 46	382.40	8
100.	14-निधियों का विनियोग - भविष्य निधि, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि	43567.00	7730.75	18
101.	15-सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान तथा अतिपूंजीकरण का परिशोधन	9804.32	1337.81	14
पूंजीगत – दत्तमत				
102.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - पूंजीगत	61239.51	476.68	0.78
103.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - रेलवे सुरक्षा निधि	1998.40	414.32	21
104.	16-परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन-रेलवे निधि	20025.75	8217.50	41
		योग	**586098.89**	

अनुबंध-3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व (दत्तमत)				
1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2010-11	17776.21	471.03	03
	2011-12	17450.74	745.54	04
	2012-13	20466.80	2480.33	12
3-पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	2010-11	1749.63	265.53	15
	2011-12	2021.25	373.79	18
	2012-13	2338.60	197.69	08
4-परमाणु ऊर्जा	2010-11	5096.90	257.71	05
	2011-12	5636.46	242.10	04
	2012-13	5564.05	233.31	04
6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2010-11	1641.32	413.75	25
	2011-12	1419.83	145.26	10
	2012-13	1764.00	100.78	06
9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	2010-11	1475.36	235.63	16
	2011-12	1010.70	191.22	19
	2012-13	1179.62	122.28	10
11-वाणिज्य विभाग	2010-11	5994.65	1388.81	23
	2011-12	5629.41	1891.18	34
	2012-13	4054.85	186.76	05
14-दूरसंचार विभाग	2010-11	10575.51	298.37	03
	2011-12	8745.83	111.54	01
	2012-13	11587.39	3985.03	34
15- यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2010-11	3558.03	578.06	16
	2011-12	2871.23	936.08	33
	2012-13	2877.54	1117.86	39
20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	2010-11	11895.28	436.97	04
	2011-12	13403.35	107.09	01
	2012-13	14723.46	711.62	05
28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2010-11	1618.34	118.58	07
	2011-12	1631.58	107.71	07
	2012-13	1750.33	236.34	14
29-भू-विज्ञान मंत्रालय	2010-11	1079.67	109.93	07
	2011-12	1284.96	211.33	16
	2012-13	1464.45	406.00	28
32-आर्थिक कार्य मंत्रालय	2010-11	6845.63	674.55	10
	2011-12	8070.63	984.86	12
	2012-13	9199.72	1587.03	17
33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2010-11	36686.98	1812.23	05
	2011-12	16391.96	9880.35	60
	2012-13	8535.26	1270.16	15
35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2010-11	83988.83	12463.68	15
	2011-12	91403.62	8476.79	09
	2012-13	105786.55	21476.42	20

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2010-11	24142.17	875.44	04
	2011-12	26912.38	2130.62	08
	2012-13	30685.78	5109.84	17
52-गृह मंत्रालय	2010-11	4232.66	135.18	03
	2011-12	4921.61	1828.47	37
	2012-13	2925.38	1345.01	46
56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2010-11	1924.11	307.80	16
	2011-12	2058.29	641.90	31
	2012-13	2154.89	305.68	14
57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2010-11	1007.07	178.83	18
	2011-12	1107.63	147.14	13
	2012-13	1163.01	226.46	19
58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2010-11	53330.83	783.89	01
	2011-12	60158.65	1009.08	02
	2012-13	70559.80	4691.40	07
59-उच्चत्तर शिक्षा विभाग	2010-11	18783.34	3216.58	17
	2011-12	21981.74	2335.60	11
	2012-13	25379.08	4868.65	19
61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2010-11	3435.68	377.43	11
	2011-12	3789.20	299.77	08
	2012-13	4634.46	807.90	17
65- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2010-11	2667.18	110.37	04
	2011-12	2834.54	672.31	24
	2012-13	3071.88	632.60	21
67-अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2010-11	2500.37	594.40	24
	2011-12	2751.01	568.23	21
	2012-13	3054.70	980.02	32
75- विद्युत मंत्रालय	2010-11	11418.97	3837.54	34
	2011-12	12018.97	7281.05	61
	2012-13	10949.40	9200.23	84
81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2010-11	18474.45	589.81	03
	2011-12	20026.47	651.83	03
	2012-13	22495.36	2836.25	13
82- ग्रामीण विकास विभाग	2010-11	148217.71	17918.55	12
	2011-12	149209.75	42368.46	28
	2012-13	129923.04	26266.79	20
88-पोत परिवहन मंत्रालय	2010-11	1654.44	489.53	30
	2011-12	2086.54	653.89	31
	2012-13	1403.45	566.08	40
89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2010-11	4374.05	338.88	08
	2011-12	5183.05	333.97	06
	2012-13	5708.33	939.48	16
90-अंतरिक्ष विभाग	2010-11	3100.26	542.78	18
	2011-12	3676.97	916.54	25
	2012-13	3575.94	761.47	21

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2010-11	2287.84	308.66	13
	2011-12	4880.83	1761.88	36
	2012-13	4926.36	461.50	09
93- कपड़ा मंत्रालय	2010-11	13300.24	482.83	04
	2011-12	6099.24	1220.55	20
	2012-13	7775.70	3513.98	45
101-शहरी विकास विभाग	2010-11	1183.24	125.67	11
	2011-12	1232.54	151.30	12
	2012-13	1321.73	232.27	18
104- जल संसाधन मंत्रालय	2010-11	1050.56	121.13	12
	2011-12	1150.06	166.20	14
	2012-13	1937.32	966.23	50
105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2010-11	11070.55	370.56	03
	2011-12	16183.04	506.98	03
	2012-13	18584.03	1547.22	08
106- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	2010-11	2377.91	653.08	27
	2011-12	1117.01	132.30	12
	2012-13	1150.75	152.94	13
राजस्व – प्रभारित				
35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2010-11	32639.01	1124.81	03
	2011-12	49298.62	5325.95	11
	2012-13	58357.46	13104.04	22
पूंजीगत – दत्तमत				
4-परमाणु ऊर्जा	2010-11	3008.05	512.07	17
	2011-12	3448.86	818.98	24
	2012-13	3822.32	1240.57	32
5- नाभिकीय शक्ति योजनाएं	2010-11	1450.41	1052.15	73
	2011-12	1087.40	190.12	17
	2012-13	567.07	385.74	68
9- नागरिक विमानन मंत्रालय	2010-11	1428.70	141.06	10
	2011-12	1393.00	172.59	12
	2012-13	6155.82	143.72	02
32-आर्थिक कार्य विभाग	2010-11	13177.56	2451.67	19
	2011-12	25804.18	11998.50	46
	2012-13	58961.13	52110.34	88
42-प्रत्यक्ष कर	2010-11	1679.01	106.73	06
	2011-12	905.70	644.70	71
	2012-13	809.29	384.78	48
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2010-11	1221.04	265.79	22
	2011-12	1989.13	916.16	46
	2012-13	2298.32	998.37	43
54-पुलिस	2010-11	7426.59	2466.59	33
	2011-12	8464.47	2983.03	35
	2012-13	9333.60	2999.21	32
75- विद्युत मंत्रालय	2010-11	5139.49	1959.76	38
	2011-12	3041.81	687.43	23
	2012-13	5464.22	235.64	04

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	बजट आवंटन	वर्ष के दौरान बचतें	बजट आवंटन की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2010-11	20418.53	945.36	05
	2011-12	22221.38	3282.64	15
	2012-13	24643.50	5610.90	23
90-अंतरिक्ष विभाग	2010-11	2676.88	752.16	28
	2011-12	2948.19	1918.03	65
	2012-13	3138.22	1096.57	35
पूंजीगत (प्रभारित)				
35-राज्य एवं सं.शा.क्षे.सरकारों को अंतरण	2010-11	11413.44	1199.69	11
	2011-12	13000.00	3004.64	23
	2012-13	12000.00	1347.30	11
37-विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	2010-11	3398559.15	583785.03	17
	2011-12	3524713.20	28784.50	01
	2012-13	3786074.35	359181.41	09
डाक सेवाएं				
पूंजीगत (दत्तमत)				
13-डाक विभाग	2010-11	474.55	200.90	42
	2011-12	527. 74	317.51	60
	2012-13	615. 77	470.18	76
रेलवे				
राजस्व (दत्तमत)				
14-निधियों का विनियोग - मूल्य ह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि	2010-11	25283.09	2533.20	10
	2011-12	28068.41	2802.84	10
	2012-13	43567.00	7730.75	18
पूंजीगत (दत्तमत)				
16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - पूंजीगत	2010-11	48528.08	745.58	02
	2011-12	54215.47	1510.81	03
	2012-13	61239.51	476.68	01
16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन-रेलवे निधि	2010-11	15465.19	856.19	06
	2011-12	15137.70	3565.24	24
	2012-13	20025.75	8217.50	41
16-परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन - रेलवे सुरक्षा निधि	2010-11	1698.40	596.96	35
	2011-12	1998.40	669.87	34
	2012-13	1998.40	414.32	21

अनुबंध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचत से ज्यादा राशियों का अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान/विनयोग	अनुभाग के अंतर्गत बचत	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	08-औषधीय विभाग	128.64	128.69
2.	31– विदेश मंत्रालय	311.05	365.02
3.	39-पेंशन	190.44	236.00
4.	51-सार्वजनिक उद्यम विभाग	6.93	7.02
5.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	461.50	468.01
6.	98-दादर और नागर हवेली	21.79	21.90
पूंजीगत - दत्तमत			
7.	31– विदेश मंत्रालय	260.21	265.00
8.	66- खदान मंत्रालय	2.80	3.99
9.	85 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	18.53	18.65
10.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	7.41	9.95
11.	98- दादर और नागर हवेली	18.79	19.08
रक्षा सेवाएं			
पूंजीगत - दत्तमत			
12.	22-रक्षा सेवाएं -थल सेना	463.60	1926.79
13.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	645.87	1153.11
14.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	200.37	620.07
15.	25-रक्षा आयुध कारखाने	42.45	426.00
16.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9043.67	9990.74

अनुबंध-3.8

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे, तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2480.33	2400.27	2400.27	97	80.06
2.	3-पशुपालन, डेरी कार्य तथा मत्स्य पालन विभाग	197.69	170.41	170.41	86	27.28
3.	6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	100.78	100.77	100.77	100	0.01
4.	8-औषध विभाग	128.64	128.69	128.69	100.03	*
5.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	122.28	120.80	120.80	99	1.48
6.	11-वाणिज्य विभाग	186.76	178.46	2.58	01	8.30
7.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	173.78	151.71	151.71	87	22.07
8.	15- यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1117.86	1076.29	1076.29	96	41.57
9.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	135.60	130.87	130.87	97	4.73
10.	29-भू-विज्ञान मंत्रालय	406.00	388.46	388.46	96	17.54
11.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1091.15	930.45	11.17	1.02	160.70
12.	31– विदेश मंत्रालय	311.05	365.02	365.02	117	*
13.	32 – आर्थिक कार्य विभाग	1587.03	1477.50	1477.50	93	109.53
14.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	1270.16	1268.65	1268.65	100	1.51
15.	35 – राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	21476.42	19666.71	18666.71	87	1809.71
16.	39-पेंशन	190.44	236.00	236.00	124	*
17.	41-राजस्व विभाग	371.53	361.49	361.49	97	10.04
18.	46 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5109.84	4532.21	4532.21	89	577.63
19.	47-आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	406.04	404.19	404.19	100	1.85
20.	48- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	187.59	183.00	183.00	98	4.59

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे, तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				*(₹ करोड़ में)*
21.	49- एड्स नियंत्रण विभाग	436.85	380.33	380.33	87	56.52
22.	50- भारी उद्योग विभाग	184.78	183.04	183.04	99	1.74
23.	52- गृह मंत्रालय	1345.01	588.60	588.60	44	756.41
24.	55-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	183.32	--	--	--	183.32
25.	56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	305.68	300.92	300.92	98	4.76
26.	57- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	226.46	205.00	205.00	91	21.46
27.	58 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4691.40	4666.77	4666.77	99	24.63
28.	59 – उच्चतर शिक्षा विभाग	4868.65	4814.86	4814.86	99	53.79
29.	61- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	807.90	562.90	562.90	70	245.00
30.	63-विधि एवं न्याय	331.98	269.72	269.72	81	62.26
31.	65 – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	632.60	620.96	620.96	98	11.64
32.	67-अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय	980.02	972.32	972.32	99	7.70
33.	70-पंचायती राज मंत्रालय	1413.49	1413.37	1413.37	100	0.12
34.	74- योजना मंत्रालय	441.81	429.20	429.20	97	12.61
35.	75- विद्युत मंत्रालय	9200.23	9200.14	9200.14	100	0.09
36.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2836.25	2759.71	217.51	08	76.54
37.	82- ग्रामीण विकास विभाग	26266.79	26247.53	26247.53#	100	19.26
38.	83-भू-संसाधन विभाग	214.66	212.64	212.64	99	2.02
39.	84- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	925.97	925.96	925.96	100	0.01
40.	87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग	217.56	214.86	14.31	7	2.70
41.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	566.08	559.20	333.36	59	6.88
42.	89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	939.48	937.89	937.89	100	1.59
43.	93- कपड़ा मंत्रालय	3513.98	3311.18	3311.18	94	202.80
44.	94-पर्यटन मंत्रालय	347.72	340.21	340.21	98	7.51
45.	95-जनजातीय मामलों के मंत्रालय	127.80	127.08	127.08	99	0.72
46.	101-शहरी विकास विभाग	232.27	218.61	218.61	94	13.66

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे, तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				*(₹ करोड़ में)*
47.	104- जल संसाधन मंत्रालय	966.23	844.63	844.63	87	121.60
48.	105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1547.22	1531.12	1531.12	99	16.10
49.	106- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	152.94	146.40	146.40	96	6.54
राजस्व – प्रभारित						
50.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	13104.04	13104.04	13104.04	100	--
51.	95-जनजातीय मामलों का मंत्रालय	905.69	905.69	905.69	100	--
पूंजीगत – दत्तमत						
52.	07-उर्वरक विभाग	244.04	244.04	244.04	100	--
53.	9- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	143.72	143.12	113.04	79	0.60
54.	31– विदेश मंत्रालय	260.21	265.00	265.00	102	*
55.	32 – आर्थिक कार्य विभाग	52110.34	50953.24	50953.24	98	1157.10
56.	33- वित्तीय सेवाएं विभाग	1249.36	1249.36	1249.36	100	--
57.	42-प्रत्यक्ष कर	384.78	375.97	375.97	98	8.81
58.	43-अप्रत्यक्ष कर	109.26	108.28	108.28	99	0.98
59.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	998.37	925.02	925.02	93	73.35
60.	54 – पुलिस	2999.21	2023.16	2023.16	67	976.05
61.	60 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	189.30	181.57	181.57	96	7.73
62.	74- योजना मंत्रालय	256.69	254.15	254.15	99	2.54
63.	75- विद्युत मंत्रालय	235.64	235.64	235.64	100	--
64.	81- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5610.90	5291.61	327.83	06	319.29
65.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	217.55	215.50	1.00	0.46	2.05
66.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	269.91	263.81	263.81	98	6.10
67.	99-दमन और दीव	125.66	125.66	125.66	100	--
68.	100-लक्षद्वीप	133.10	131.91	131.91	99	1.19
69.	101-शहरी विकास विभाग	927.18	926.23	926.23	100	0.95

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित किए गए थे, तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2013 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				*(₹ करोड़ में)*
पूंजीगत - प्रभारित						
70.	35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1347.30	1347.30	1347.30	100	---
71.	37 – विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान	359181.41	341657.64	341657.64	95	17523.77
रक्षा सेवाएं **राजस्व (दत्तमत)**						
72.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	463.60	1926.79	1926.79	415.61	*
73.	23-रक्षा सेवाएं - नौ सेना	645.87	1153.11	1153.11	178.54	*
74.	24-रक्षा सेवाए - वायु सेना	200.37	620.07	620.07	309.46	*
75.	26-अनुसंधान एवं विकास	816.63	793.76	793.76	97.20	22. 87
76.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9043.67	9990.74	9990.74	110.47	*

** अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी।*

राशि को 29 अप्रैल 2013 को अर्थात् वर्ष की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्पित किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 मार्च 2013 को ₹ 29,315.21 करोड़ का अभ्यर्पण किया था (जबकि अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी) जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा उसी दिन स्वीकार किया गया था। संशोधित अभ्यर्पण आदेश अप्रैल 2013 में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।

नोट - अभ्यर्पित तिथि की गणना के लिए,लेखापरीक्षा आदेश की तिथि यथा तिथि जहां अभ्यर्पण वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, को लिया गया है।

अनुबंध 3.9

(पैराग्राफ 3.10 के संदर्भ में)

मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे (₹ पांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
	सिविल				
1.	2- कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग	2415.01.150.09-कृषि आभियंत्रिकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 157.97	5.78	32.25
2.		2415.01.796.05-कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 25.00	9.00	9.00
3.		2415.02.150.02- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा योजना सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 473.26	25.10	71.59
4.		2415.02.150.03-जलवायु प्रत्यास्थी कृषि पहल	मू.- 100.00	7.00	32.00
5.		2415.03.150.01-पशु विज्ञान संस्थान, दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थानों तथा योजनाओं सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 636.36	34.76	69.47
6.		2415.05.150.01-मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं	मू.- 312.62	7.17	34.20
7.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.207.01-एच.डब्ल्यू.पी. से उत्पादन	मू.- 916.00	54.00	104.44
8.	31– विदेश मंत्रालय	2061.00.798.02-अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन	मू.- 22.93	13.59	15.16
9.	34-ब्याज भुगतान	2049.01.200.03-क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	मू.- 1699.25 अ.- 100.00	520.99	538.17
10.		2049.03.109.10-भविष्य सेवानिवृत्ति उपादान निधि के विशेष जमा	मू.- 9346.88 अ.- 50.00	24.12	100.86
11.		2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू.- 141.67	18.48	71.65

मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ पांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
12.	37-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.106.24 - 8% राहत बंधपत्र, 2002	मू.- 16.16	13.81	22.94
13.		6001.00.106.31 – 6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर कर योग्य)	मू.- 20.55	13.72	23.10
14.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.05.105.27-लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और श्रीमती एस.के. अस्पताल	मू.- 198.00	9.01	20.59
15.		2210.05.105.33-क्षेत्रीय स्नात्तकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी	मू.- 275.75	17.00	43.65
16.		2210.06.101.07-राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केन्द्र), दिल्ली	मू.- 41.95	7.32	17.34
17.		2210.06.101.32-राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम	मू.- 20.70	6.03	11.23
18.		2210.06.102.09-भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	मू.- 50.00	6.00	13.55
	डाक				
19.	13-डाक विभाग	3201.02.101.10 ग्रामीण डाक सेवक	मू.- 2300.00 अ.- 74.32	9.37	86.58
20.		3201.07.104. 01 उपादान	मू.- 486.00 अ.- 48.35	25.05	25.63
कुल				**827.30**	

नाटः- मू.- मूल प्रावधान, अ.- अनुपूरक प्रावधान

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.11 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष/लघु-शीर्ष से मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले परिणामस्वरूप उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त व्यय

(₹ पांच करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	उप-शीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
सिविल					
1.	04-परमाणु ऊर्जा	4861.01.204.13-पूर्णतः निर्मित सामान की कम लागत	मू.- 916.00	54.00	104.44
2.	21-रक्षा पेंशन	2071.02.101.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू- 33971.48 अ.- 211.91	70.59	3457.89
3.		2071.02.102.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू- .1322.20 अ- 16.59	10.13	189.18
4.		2071.02.103.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू- 2312.36 अ- 10.30	59.08	261.44
5.	34-ब्याज भुगतान	2049.03.104.04-राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू- 2042.53	56.23	158.44
6.		2049.03.108.06- डाक बीमा तथा जीवन वार्षिकी निधि	मू- 474.54	44.88	532. 24
रक्षा सेवाएं					
7.	22-रक्षा सेवाएं -थल सेना	2076.00.101 – थल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू- 45014.03	1341.00	1478.96
8.		2076.00.104 – गैर-सैनिक के वेतन एवं भत्ते	मू- 3660.57	90.32	103.71
9.	23-रक्षा सेवाएं -नौ सेना	2077.00.111 – निर्माण कार्य	मू- 750.00	28.08	37.72
10.		2077.00.800 – अन्य व्यय	मू- 350.00	34.58	35.65
11.	24-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078.00-101 - वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू- 7379.68	233.63	346.32
12.		2078.00.111 – निर्माण कार्य	मू- 1683.65	37.95	128.66
	कुल			**2060.47**	

नोट : मू- मूल प्रावधान, अ.- अनुपूरक प्रावधान

अनुबंध 3.11

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालय/विभाग में मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत		योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	
2005-06	मूल	260249	164936	32274	602709	1060168
	अनुपूरक	34784	612	2744	424882	463022
	प्रतिशतता	13	-	9	70	44
2006-07	मूल	310212	176989	38951	1103562	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	9377	350290	455450
	प्रतिशतता	29	3	24	32	28
2007-08	मूल	360510	195865	80133	1616206	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	20474	65742	193151
	प्रतिशतता	25	9	26	4	9
2008-09	मूल	437377	243991	43348	1750686	2475402
	अनुपूरक	285013	113	14577	445762	745465
	प्रतिशतता	65	-	34	25	30
2009-10	मूल	667430	268467	61658	1887527	2885082
	अनुपूरक	81044	49	20574	1369563	1471230
	प्रतिशतता	12	-	33	73	51
2010-11	मूल	729198	287617	90171	3390880	4497866
	अनुपूरक	135176	131	31519	19156	185982
	प्रतिशतता	19	-	35	1	4
2011-12	मूल	830436	325521	106393	3155266	4417616
	अनुपूरक	101994	11941	21472	382533	517940
	प्रतिशतता	12	4	20	12	12
2012-13	मूल	919615	387306	159441	3798124	5264486
	अनुपूरक	71562	4844	4444	31	80881
	प्रतिशतता	8	1	3	0	2

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ /उप-शीर्ष	प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	34-ब्याज भुगतान	2049.03.109.10-भविष्य सेवानिवृत्ति उपदान निधि के विशेष जमा	9346.88	50.00	9320.14	76.74	बचत कम दावों की प्राप्ति, शेषों के गैर-समनुरूपण तथा कम आहरणों के कारण थीं।
2.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.05.800.13-सरकारी विश्वविद्यालयों में अं.स्ना./स्ना.उ. सीटों के लिए परामर्श	शून्य	3.70	शून्य	3.70	योजना के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
3.	49-एड्स नियंत्रण विभाग	2210.06.101.33-राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1509.41	53.56	1304.29	258.68	कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन में अंतर तथा कुछ सविदाओं/प्रापण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।

अनुबंध 3.13

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं.4-परमाणु ऊर्जा						
1.	4861.60.190.02 भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	2010-11	203.00	91.69	111.31	55
		2011-12	154.00	--	154.00	100
		2012-13	216.00	--	216.00	100
अनुदान सं.5 – परमाणु शक्ति योजनाएं						
2.	4801.03.190.02-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	2010-11	1400.00	315.00	1085.00	78
		2011-12	1025.00	875.00	150.00	15
		2012-13	536.67	174.67	362.00	67
अनुदान सं. 15- यांत्रिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग						
3.	2852.07.202.60-इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन	2010-11	927.00	264.15	662.85	72
		2011-12	865.14	199.89	665.25	77
		2012-13	752.83	375.05	377.78	50
अनुदान सं. 17- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग						
4.	2408.01.800.01 – चीनी के प्रतिरोधक भण्डार के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता	2010-11	200.00	88.00	112.00	56
		2011-12	50.00	11.49	38.51	77
		2012-13	17.00	4.00	13.00	76
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग						
5.	3075.60.101.01 रेलवे को भुगतान	2010-11	2829.88	2013.26	816.62	29
		2011-12	3022.61	2034.37	988.24	33
		2012-13	3003.89	2286.14	717.75	24
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग						
6.	2416.00.800.07 दीर्घ अवधि सहकारी क्रेडिट संरचना पुनरूद्धार	2010-11	1000.00	--	1000.00	100
		2011-12	1000.00	--	1000.00	100
		2012-13	500.00	--	500.00	100
अनुदान सं. 34- विनियोग-ब्याज भुगतान						
7.	2049.01.116 14 दिनों के खजाना बिलों पर ब्याज (प्रभारित)	2010-11	5107.00	4049.06	1057.94	21
		2011-12	4900.00	3795.52	1104.48	23
		2012-13	5200.00	4285.65	914.35	18
8.	2049.03.108.02 औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवारिक पेंशन सह जीवन प्रत्याभूति (प्रभारित)	2010-11	4508.66	4079.30	429.36	10
		2011-12	4953.65	4551.60	402.05	8
		2012-13	6105.15	5106.43	998.72	16

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण						
9.	3601.02.101.26 – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	2010-11	11500.00	8757.53	2742.47	24
		2011-12	12620.00	7459.01	5160.99	41
		2012-13	14242.00	6503.58	7738.42	54
10.	3601.02.101.36 - जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन	2010-11	11619.00	5284.84	6334.16	55
		2011-12	12522.00	7337.78	5184.22	41
		2012-13	12522.00	5287.77	7234.23	58
11.	3601.02.797.01- राष्ट्रीय निवेश निधि	2010-11	7732.01	2731.42	5000.59	65
		2011-12	7732.00	3976.48	3755.52	49
		2012-13	7365.00	5892.00	1473.00	20
अनुदान सं. 41- राजस्व विभाग						
12.	3601.01.113.05 – वैट संबंधित व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	2010-11	375.00	203.99	171.01	46
		2011-12	224.00	120.36	103.64	46
		2012-13	114.00	98.07	15.93	14
अनुदान सं. – 42 – प्रत्यक्ष कर						
13.	4059.01.800.01- तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण	2010-11	1663.00	1527.23	135.77	08
		2011-12	877.70	256.53	621. 17	71
		2012-13	777.49	421.00	356.49	46
अनुदान सं 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
14.	3601.04.246.01- आर.सी.एच. औषधियों एवं उपकरण की आपूर्ति	2010-11	176.01	72.04	103.97	59
		2011-12	160.50	3.44	157.06	98
		2012-13	164.16	22.81	141.35	86
अनुदान सं. 53- मंत्रीमण्डल						
15.	4055.00.206.03- सामान्य	2010-11	92.00	13.83	78.17	85
		2011-12	166.29	62.25	104.04	63
		2012-13	152.60	149.31	3.29	2
अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय						
16.	2245.80.102.04 – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2010-11	190.42	43.78	146.64	77
		2011-12	348.22	110.62	237.60	68
		2012-13	183.31	151.67	31.64	17
अनुदान सं.. 56-केन्द्र शासित सरकारों को अंतरण						
17.	3602.02.101.01- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2010-11	1233.81	943.48	290.33	24
		2011-12	1192.73	582.30	610.43	51
		2012-13	1031.61	800.34	231.27	22
अनुदान सं. 75- विद्युत मंत्रालय						
18.	2801.06.797.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2010-11	5000.00	2000.00	3000.00	60
		2011-12	5000.00	2086.04	2913.96	58
		2012-13	4761.00	674.85	4086.15	86
19.	6801.00.190.04 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ऋण	2010-11	3230.00	2246.42	983.58	30
		2011-12	1555.60	1443.89	111.71	7
		2012-13	2485.60	1182.52	1303.08	52

उप-शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 81- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
20.	5054.02.337.03 बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य	2010-11	3005.48	2541.92	463.56	15
		2011-12	2611.77	2207.77	404.00	15
		2012-13	2630.71	2350.70	280.01	11
अनुदान सं. 88–पोत परिवहन मंत्रालय						
21.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय सा.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र शिपयार्डों को आर्थिक सहायता	2010-11	588.30	128.19	460.11	78
		2011-12	542.11	122.42	419.69	77
		2012-13	400.00	220.00	180.00	45
अनुदान सं. 90- अंतरिक्ष विभाग						
22.	5252.00.203.03 इनसेट-4/जी सेट उपग्रह	2010-11	259.06	131. 50	127. 56	49
		2011-12	629.66	135.33	494.33	79
		2012-13	314.44	120.64	193.80	62

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

₹ 10 करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
सिविल				
अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग				
1.	2415.80.120.02-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड को सहायता अनुदान	20.00	--	20.00
2.	2415.80.120.03-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्य-पालन विभाग				
3.	2403.00.789.01-पक्षी- इन्फ्लून्जा की रोकथाम, नियंत्रण एवं तैयारी	10.00.	--	10.00
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा				
4.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	216.00	--	216.00
5.	4861.60.203.44-फास्ट रियेक्टर फ्यूल साईकल फैसेलिटी(एफ.आर.एफ.सी.एफ.)	580.00	--	580.00
6.	5401.00.800.24-डी.ए.ई. आउटरीच का विस्तार तथा निर्देशन प्रबंधन	10.00.	--	10.00
7.	5401.00.800.25-वैश्विक नाभकीय ऊर्जा साझेदारी केन्द्र का विकास	14.00	--	14.00
अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजना				
8.	4801. 03.800.40-उन्नत भारी जल रिएक्टर (उ.भा.ज.रि.-I)	10.00	--	10.00
9.	6801.00.206.01-भारतीय नाभकीय शक्ति निगम लिमिटेड को ऋण	14.00	--	14.00
अनुदान सं. 7 – उर्वरक विभाग				
10.	6855.00.190.02-ट्रावनकोर उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	61.75	--	61.75
11.	6855.00.190.08-मद्रास उर्वरक लिमिटेड	87.62	--	87.62
अनुदान सं. 9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय				
12.	3053.80.800.04- हवाई खेल के विकास हेतु भारतीय हवाई-कलब को सहायता अनुदान	12.00	--	12.00
13.	3053-80-800-17- उ.पू. क्षेत्र हेतु भा.वि.प्रा. को सहायता अनुदान	72.90	--	72.90
14.	5053.80.800.01-नागरिक उड्डयन सुरक्षा	69.70	--	69.70

अनुदान सं. 14- दूरसंचार विभाग				
15.	3275.00.796.02-सार्वभौम सेवा दायित्व हेतु सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	10.90	--	10.90
16.	5275.00.101.04-निगरानी सेवाएँ	35.10	--	35.10
अनुदान सं.15- इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				
17.	2852.07.796.02-राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	22.50	--	22.50
अनुदान सं. 19-संस्कृति मंत्रालय				
18.	3601.04.203.01-राज्य सरकारों द्वारा स्मारकों तथा पूरातत्व स्थलों का संरक्षण, बचाव तथा पर्यावरणीय विकास	19.00	--	19.00
अनुदान सं. 29-भू-विज्ञान मंत्रालय				
19.	3455.00.001.05-वायु-वाहित प्लेटफार्म	50.00	--	50.00
अनुदान सं. 30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
20.	2406.04.101.11- हरित भारत मिशन	221.05	--	221.05
अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय				
21.	7605.00.055.01- नए क्रेडिट	250.00	--	250.00
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग				
22.	5465.02.190.09 भारतीय सुरक्षा मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (भा.स.मु.ट.नि.लि.)	400.00	--	400.00
23.	5466.00.207.04 आई.एम.एफ. के ऋण संसाधनों के प्रति भारत का योगदान	50.00	--	50.00
24.	5466.00.207.05-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (प्रतिभूतियों में)	42000.00	--	42000.00
25.	5466.00.207.06-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान (नगद में)	14000.00	--	14000.00
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग				
26.	2416.00.800.01 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान (रा.कृ.एवं ग्रा.वि.बैं.)	200.01	--	200.01
27.	2416.00.800.04-वित्तीय समावेशन निधि (वि.स.नि.) की संरचना के लिए सरकारी योगदान के प्रति नाबार्ड को भुगतान	20.00	--	20.00
28.	2415.00.800.05- वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (वि.स.प्रौ.नि.) की रचना के लिए सरकारी योगदान हेतु (रा.कृ. एवं ग्रा.वि.बैं.) को भुगतान।	30.00	--	30.00
29.	2416-00-800-07 दीर्घ अवधि सहकारिता क्रेडिट अवसंरचना का पुनरूत्थान	500.00	--	500.00
अनुदान सं. 34-विनियोग- ब्याज भुगतान				
30.	2048.00.200.13-सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने पर प्रीमियम का भुगतान	100.00	--	100.00
31.	2049.01.126- बैंक धन जमा बाजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट	110.00	--	110.00

32.	2049.01.128- रोकड प्रबंधन बिल पर छूट	1100.00	--	1100.00
33.	2049.05.105.04-रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	33.43	--	33.43
34.	2049.60.101.09- कोयला खान जमा योजक बीमा निधि	13.96	--	13.96
अनुदान सं. 35-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण				
35.	2075.00.795.03 राज्य सरकारों के ऋण बट्टे खाते में डाले गये	89.04	--	89.04
36.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	--	1000.00
अनुदान सं. 37-ऋण का भुगतान				
37.	6001.00.127.-बिलों का रोकड प्रबंधन	95000.00	--	95000.00
अनुदान सं. 41-राजस्व विभाग				
38.	3601.01.110.05-सू.वृ.क. को प्रारम्भ करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति	81.00	--	81.00
39.	3601.01.110.07-एस.एस.टी. को चरणबद्ध लागू करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति	300.00	--	300.00
अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
40.	2210.06.789.08-ट्रॉमा केन्द्रों को क्षमता निर्माण के लिए सहायता	15.20	--	15.20
41.	2210.06.789.12-पराचिकित्सीय संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/सृजन	30.40	--	30.40
42.	2210.06.796.14-पराचिकित्सीय संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/सृजन	16.40	--	16.40
43.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सी.जी.ई.आई. पी.एस.)	50.00	--	50.00
44.	2210.06.800.47-नवोन्मेष आधारित योजनाएं	50.00	--	50.00
45.	2211.00.789.05-उन्नत अनुपूर्वक देखभाल प्रदत्त करने हेतु जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	19.54	--	19.54
46.	2211.00.789.06-देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जेनेरिक औषधि प्रदान करना	19.54	--	19.54
47.	2211.00.796.07-उन्नत अनुपूर्वक देखभाल प्रदत्त करने हेतु जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	10.59	--	10.59
48.	2211.00.796.07- देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जेनेरिक औषधि प्रदान करना	10.59	--	10.59
49.	2211.00.800.18-उन्नत अनुपूर्वक देखभाल प्रदत्त करने हेतु जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	59.87	--	59.87
50.	2211.00.800.19- देश में सभी जन स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त जेनेरिक औषधि प्रदान करना	59.87	--	59.87
51.	4210.03.105.14-राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली	15.00	--	15.00
52.	4210.04.200.17- बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, ग्युंडी, चैन्नई	23.27	--	23.27
53.	4210.04.200.18-केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	17.57	--	17.57

54.	4210.04.200.21-केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	20.00	--	20.00
55.	4210.04.200.22-स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	45.00	--	45.00
अनुदान सं. 47- आर्युवेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)				
56.	2210.02.789.03-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष फलैक्सीपूल सहित रा.ग्रा..स्वा.मि. के अंतर्गत)	18.00	--	18.00
57.	2210.05.101.12-आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों का विकास तथा उन्नयन	41.64	--	41.64
58.	4210.80.190.04-भारतीय दवा फार्मास्युटिकल निगम लिमिटेड	16.00	--	16.00
अनुदान सं. 48- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग				
59.	2210.05.105.46-स्वास्थ्य अनुसंधान का उन्नयन, समन्वय तथा विकास	30.00	--	30.00
60.	2210.06.001.07 सरकारों/संगठनों/संस्थानों के साथ समन्वय	13.00	--	13.00
61.	2210.06.003.13-औषधि तथा स्वास्थ्य में अनुसंधान	21.00	--	21.00
62.	2210.06.101.41- प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन	30.00	--	30.00
अनुदान सं. 50- भारी उद्योग विभाग				
63.	2852.06.103.28 स्वै.से.यो. के कार्यान्वयन हेतु सा.क्षे.उ. को बैंक वित्त पर ब्याज सहायता	14.00	--	14.00
अनुदान सं. 54-पुलिस				
64.	3601.02.117.01-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचना	155.00	--	155.00
65.	3601.02.117.02- विप्लव विरोधी एवं आतंकवाद विरोधी विद्यालय को सहायता	65.00	--	65.00
66.	4055.00.216.01-राष्ट्रीय खूफिया ग्रिड	70.85	--	70.85
अनुदान सं. 57 – आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय				
67.	2216.02.789.04 शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	11.25	-	11.25
68.	2216.02.800.04 शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	37.55	--	37.55
69.	2217.80.003.06 शहरी अभिशासन समावेशन हेतु संस्थानिक विकास	20.00	--	20.00
70.	3601.04.435.04 रेहड़ी वालों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	30.48	--	30.48
अनुदान सं. 58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
71.	2202.01.112.10-अनाजों की लागत	24.09	--	24.09
अनुदान सं. 59-उच्चत्तर शिक्षा विभाग				
72.	2203.00.105.13- विद्यमान में उन्नयन/नए पॉलिटेकनीक की स्थापना	15.50	--	15.50
73.	3602.04.175.03 विद्यमान/स्थापित नई पॉलिटेकनीक का उन्नयन	11.63	--	11.63

अनुदान सं.60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
74.	2251.00.800.11-राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	20.00	--	20.00
अनुदान सं. 62—चुनाव आयोग				
75.	2015.00.003.02-आई.आई.आई.डी.ई.एम.	32.00	--	32.00
अनुदान सं.. 63—विधि एवं न्याय				
76.	2014.00.104.01-न्यायपालिका के संरचात्मक सुविधा हेतु अनुदान	35.00	--	35.00
77.	2014.00.800.17-राष्ट्रीय न्याय परिदान एवं वैधानिक सुधार मिशन	37.50	--	37.50
अनुदान सं. 65-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय				
78.	2851.00.102.84-राष्ट्रीय नवाचार निधि	70.00	--	70.00
79.	2851.00.105.06 खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. सहायता)	34.90	--	34.90
80.	2851.00.106.08 नारियल जटा उद्योग का पुनर्नवीकरण आधुनिकीकरण,एवं तकनीकी उन्नयन	11.20	--	11.20
81.	2851.00.200.10 परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना	38.72	--	38.72
82.	2851.00.200.14 खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता तथा प्रतियोगितात्मकता को बढाने हेतु योजना	10.47	--	10.47
83.	285.00.789.30 राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि	12.00	--	12.00
84.	2851.00.796.01-तकनीकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता जनजातीय उप योजना	37.50	--	37.50
अनुदान सं. 67 – अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय				
85.	2225.04.277.01-मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान को सहायता अनुदान	100.00	--	100.00
86.	2235.02.200.22-कौशल विकास पहल	15.00	--	15.00
87.	3601.04.378.09-पिछड़े के रूप में चिन्हित 251 शहरों/नगरों में से 100 अल्पसंख्यक संकेन्द्रण शहरों/नगरों में शिक्षा के प्रोत्साहन की योजना	42.50	--	42.50
88.	3601.04.378.10-एम.सी.वी./एम.सी.डी. के द्वारा जो गाँव समाविष्ट नहीं हैं उनके लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	42.80	--	42.80
89.	3601.04.378.11-दि.न.नि. में जिला स्तरीय संस्थानों को सहायता	22.00	--	22.00
अनुदान सं.73 – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
90.	2802.80.105.01-राज्यों/सं.शा.क्षे. के सा.वि.प्र. - कैरोसीन लाभभोगियों हेतु रोकड़ में आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु प्रोत्साहन योजना	100.00	--	100.00
91.	2802.80.106.03-राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान	41.00	--	41.00

अनुदान सं. 75--ऊर्जा मंत्रालय				
92.	2801.80.800.29 राष्ट्रीय विद्युत निधि (रा.वि.नि.)	72.00	--	72.00
93.	4801.05.001.04-कारगिल होते हुए श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण	200.00	--	200.00
अनुदान सं. -81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय				
94.	7075.01.190.02-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	36.00	--	36.00
अनुदान सं. 82– ग्रामीण विकास विभाग				
95.	2501.06.102.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	112.50	--	112.50
96.	2501.06.102.04-जम्मू एवं कश्मीर हेतु कौशल सशक्तिकरण तथा रोजगार योजना	35.00	--	35.00
97.	2501.06.789.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	65.25	--	65.25
98.	2501.06.796.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	47.25	--	47.25
99.	2505.02.101.10-सामाजिक लेखापरीक्षा तथा शिकायत निवारण प्रणाली	200.00	--	200.00
100.	2515.00.105.01-लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद को अनुदान	35.00	--	35.00
101.	2515.00.800.23-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पूरा)	135.00	--	135.00
अनुदान सं. 86- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
102.	3425.60.151.12-सी.एस.आई.आर.-800-योजनाएं	50.00	--	50.00
103.	3425.60.151.13 मुक्त नवोन्मेष हेतु सी.एस.आई.आर. योजना	77.00	--	77.00
104.	3425.60.151.14-साझेदारी एवं सहयोगी अनुसंधान तथा विकास के समावेशन करने हेतु सी.एस.आई.आर. की पहल	10.00	--	10.00
105.	3425.60.151.15-राष्ट्रीय नागरिक विमान विकास	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय				
106.	505.01.106.01 परिवहन सुविधाएं एवं जहाजी बेड़ा	25.00	--	25.00
107.	5052.01.800.01-सर्वेक्षण जलयान	15.00	--	15.00
108.	7051.01.190.02-पोर्ट ट्रस्ट को ऋण	90.00	--	90.00
अनुदान सं.89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
109.	2225.01.789.05-अ.जा. के लिए राजीव गांधी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम	123.00	--	123.00
110.	2225.01.789.20- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय केन्द्र	10.00	--	10.00
111.	2225.01.789.21- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	14.00	--	14.00
112.	2225.03.277.10- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजीव गांधी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम	45.00	--	45.00
113.	3601.04.362.02-वृद्धाश्रम का निर्माण	67.00	--	67.00

114.	3601.04.362.03- विंकलांग छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति	30.00	--	30.00
115.	3601.04.377.05-गैर-अधिसूचित एवं खानाबदोष जनजातीयों का शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास	10.00	--	10.00
अनुदान सं.90- अंतरिक्ष विभाग				
116.	3252.00.053.09-इनसेट 3-डी लांच सेवाएं	33.40	--	33.40
117.	3252.00.053.10-जी सेट-7 लांच सेवाएं	52.70	--	52.70
118.	3402.00.101.48-जी.एस.एल.वी. एम.के. III परिचालन	50.00	--	50.00
119.	5402.00.101.30- ओसिनसेट 2 एवं 3	47.48	--	47.48
अनुदान सं. 93 – कपड़ा मंत्रालय				
120.	2851.00.789.43-हस्तकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार , सुधार एवं पुनरूत्थान पैकेज	122.50	--	122.50
121.	2851.00.796.43- हस्तकरघा क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार , सुधार एवं पुनरूत्थान पैकेज	36.45	--	36.45
अनुदान सं. 94 –पर्यटन मंत्रालय				
122.	3452.01.102.06- बृहत राजस्व सृजन परियोजनाओं हेतु सहायता	40.00	--	40.00
123.	3602.04.826.01-गन्तव्य तथा क्षेत्र हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	10.00	--	10.00
अनुदान सं. 96-अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह				
124.	3053.01.800.06-पोर्ट ब्लैयर-चैन्नई/कोलकाता क्षेत्र के बीच परिचालन हेतु पट्टा आधार पर विमान का अधिग्रहण	35.73	--	35.73
125.	5225.04.209.01-मुख्य भूमि तथा अ. एवं नि. द्वीपसमूह के बीच समुद्र के नीचे ऑपटिकल फाईबर केबल की स्थापना	200.00	--	200.00
अनुदान सं.100- लक्षद्वीप				
126.	5053.02.102.05 हवाई पट्टी	10.00	-	10.00
अनुदान सं. 101 – शहरी विकास विभाग				
127.	2217-05-800.27- सेवास्तर बेंचमार्क को मुख्यधारा में लाने हेतु सहायता की योजना	10.00	-	10.00
अनुदान सं. 104 –जल संसाधन मंत्रालय				
128.	2701.80.001.02-मानव संसाधन विकास/ क्षमता निर्माण	53.00	--	53.00
129.	2701.80.800.18-राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	195.00	--	195.00
130.	3601.01.752.01-सतुलज यमुना लिंक नहर परियोजना	18.04	--	18.04
अनुदान सं. 105 – महिला एव बाल विकास मंत्रालय				
131.	2235.02.103.28-महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि (आर.एम.के)	90.00	--	90.00
132.	3601.04.356.07-बलात्कार पीडितों के लिए सहायता एवं पुनर्वास	17.50	--	17.50

133.	3601.04.356.10-घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम का कार्यान्वयन	18.00	--	18.00
डाक **अनुदान सं. 13 – डाक विभाग**				
134.	5201.104.07 बचत बैंक का कम्प्यूटरीकरण/आधुनिकीकरण	17.00	--	17.00
	कुल			**161185.18**

अनुबंध 3.15

(पैराग्राफ 3.17 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों का 10 प्रतिशत से अधिक हैं

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.119.41-सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन	960.00	783.43	176.57	कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
2.	2401.00.789.17- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	350.00	229.41	120.59	कम प्रस्तावों की प्राप्त तथा कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
3.	2435.01.101.06-ग्रामीण गोदामों का निर्माण	636.00	244.85	391.15	कार्यान्वयन अभिकरण के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
4.	3601.04.453.02 एकीकृत तेलबीज, पॉम ऑयल, दालें एवं मक्का विकास	285.00	161.00	124.00	कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता
अनुदान सं.2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
5.	2415.01.150.03-कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड एवं सूचना महानिदेशालय तथा कृषि प्रकाशन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन	340.22	237.94	102.28	XII योजना की ई.एफ.सी. को अंतिम रूप देने में बिलम्ब के कारण तथा सम्मेलन कक्ष की धीमी प्रगति के कारण संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधानों की कटौती
6.	3401.00.004.15- प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	661.22	224.21	437.00	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो नाभिकीय प्रयोगात्मक रिएक्टर (आई.टी.ई.आर.) के डिजाईन तथा सारणी में बदलाव तथा कुछ परियोजनाओं की संस्वीकृति में विलम्ब।
7.	5401.00.201.84-अतिरिक्त भा.प.अ.के. परिसर	143.00	36.01	106.99	बार्क, विशाखापटनम में केन्द्र रिएक्टर उपकरण तथा जांच प्रणाली (रि.उ.के.प्र.प्रा.) के भवन के कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
अनुदान सं. 5-नाभिकीय शक्ति योजना					
8.	4801.03.190.02- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	536.67	174.67	362.00	पूर्व-परियोजना कार्यों की अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनः संशोधित कार्यक्रम परिवर्तन, करने के कारण।
अनुदान सं. 9-नागरिक विमानन मंत्रालय					
9.	3053.80.800.18-अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु भा.वि.प्रा. को सहायता अनुदान	198.48	59.29	139.19	'गगन' सहित अनेक परियोजनाओं को अंतिम रूप न देना।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 12- औद्योगिक नीति एवं प्रोन्न्यन विभाग					
10.	2852.80.800.10-भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	243.00	84.20	158.80	बृहत चमड़ा समूह योजना एवं सामान्य निरसारी उपचार सयंत्र (सा.नि.उ.सं.) का उन्नयन/संस्थापन के अंतर्गत प्रस्तावों की गैर-स्वीकृति, चमड़ा क्षेत्र के एकीकृत विकास के अंतर्गत उद्योग से कम मांग, तथा नई उप-योजनाओं की गैर -स्वीकृति
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
11.	3451.00.091.01-निदेशालय (दतमत्त)	311.93	202.76	109.17	वेतनों, घरेलू यात्रा व्ययों, विदेश यात्रा व्ययों एवं कार्यालय व्यय के अंतगर्त कम दावों की प्राप्ति के अतंगर्त कम व्यय
12.	2071.01.102.01-सामान्य पेंशन	1019.31	711.67	307.64	कम दावों की प्राप्ति
13.	2071.01.104.01- सामान्य पेंशन	1131.50	989.60	141.90	कम दावों की प्राप्ति
14.	3275.00.103.01- सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	2689.10	625.00	2064.10	बेतार ब्रॉडबेंड योजना के गैर-क्रियान्वयन तथा अनाच्छादित ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (अ.ग्रा.सा.टे.) चरण-II हेतु दावों को अस्वीकृत करना, सोलर फोटों वोल्टाईक (एस.पी.वी.) मोड्यूलो तथा चर्चा संकेतकों का गैर-प्रावधान तथा रोल आउट में कमी
अनुदान सं. 15-सूचना प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिक विभाग					
15.	2852.07.202.60- इलैक्ट्रॉनिक प्रशासन	752.83	375.05	377.78	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती तथा अनुदानग्राही संस्थनों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता
16.	2852.07.202.83-राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	305.00	122.19	182.81	अनुदानग्राही संस्थानों से व्यवहार्य प्रस्तावों उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथ वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण लगाई गई कटौती
अनुदान सं.28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास					
17.	3601.02.101.14-उत्तर पूर्व तथा सिक्किम हेतु संसाधनों के गैर व्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता	879.00	775.00	104.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती के कारण तथा मित्तव्ययी उपाय।
अनुदान सं. 29 भू-विज्ञान मंत्रालय					
18.	3403.00.102.06-ध्रुव विज्ञान तथ क्रायोस्फर	290.00	190.00	100.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती के कारण कार्यों में विलंब।
अनुदान सं.30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
19.	3435.04.101.06-राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	660.30	338.45	321.85	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती, उपयोगिता प्रमाणपत्र का गैर-प्रस्तुतीकरण तथ मितव्ययी उपाय।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
20.	3435.04.104.04-राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	125.00	25.00	100.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 31-विदेश मंत्रालय					
21.	3605.00.101.14- म्यांमार को सहायता	302.21	121.88	180.33	री. टिडिम सड़क परियोजना को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण तथा म्यांमार सरकार द्वारा स्थान की सुपुदर्गी में विलम्ब के कारण वर्ष के आरम्भिक भाग में कालादान परियोजना पर कार्य की धीमी गति।
22.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान को सहायता	707.00	490.96	216.04	गेहूं आपूर्ति की परियोजना मे पुनर्निविदा तथा दोशी तथा चारीवर इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन परियोजना के संघटन में सालमा डैम परियोजना के विनियामक स्वीकृति में विलंब के कारण।
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग					
23.	2235.60.797.02-असंगठित क्षेत्र श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	1000.00	120.00	880.00	योजनाओं को अंतिम रूप न देना।
24.	3075-60-101-01-रेलवे को भुगतान	3003.89	2286.14	717.75	लाभांश राहत हेतु रेलवे को आर्थिक सहायता के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
25.	4046-00-208-01- सिक्के	1645.35	1000.00	645.35	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा टकसाल निगम लिमिटेड (भा.प्र.मु.मि.नि.लि.) के सलाहकारों द्वारा निर्धारित लागत तक सिक्के की लागत को प्रतिबंधित करना।
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग					
26.	2235.60.102.03 असंगठित क्षेत्रों के लोगों को नई पेंशन योजना (न.पें.यो.) से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्वावलंबन योजना	220.00	104.41	115.59	योजना के अंतर्गत धीमा नामांकन।
27.	2416.00.800.02 किसानों को कम अवधि वाले उधार प्रदान करने के लिए ब्याज पर आर्थिक सहायता	6000.00	5400.00	600.00	वित्त मंत्रालय द्वारा गैर-योजनाएं व्यय पर 10% कटौती लागू करने के कारण।
28.	5465.01.190.33-सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का पुनः पूँजीकरण	14588.00	12517.00	2071.00	वांछित स्तर पर टियर-1 सी.आर.ए.आर. को बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकां को प्रदत्त कम पूंजीगत सहायता।
अनुदान सं. 34-विनियोग- ब्याज भुगतान					
29.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज (प्रभारित)	2000.00	248.50	1751.50	सरकार की रोकड़ स्थिति में सुधार।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
30.	2049.01.116 14 दिवसीय खजाना बिल पर ब्याज (प्रभारित)	5200.00	4285.65	914.35	राज्य सरकारों द्वारा मध्यस्थ खजाना बिलों का बोली आधारित खजाना बिलों में निवेश का परिवर्तन।
31.	2049.03.108.02 औद्योगिक श्रमिकों हेतु परिवार पेंशन सह जीवन बीमा निधि	6105.15	5106.43	998.72	कम जमा के कारण
32.	2049.60.701.01-एस.डी.आर. के उपयोग हेतु आइ.एम.एफ. को देय प्रभार	201.03	33.55	167.48	एस.डी.आर. के उपयोग हेतु कम प्रभारों भुगतान
अनुदान सं. 35- राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण					
33.	2245.80.103.02- गम्भीर प्रकृति के आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्यों को सहायतो	4620.00	2810.29	1809.71	कम आपदाओं का होना
34.	2245.80.797.02-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि) को अंतरण	4620.00	2810.29	1809.71	आरक्षित निधि तथा वास्तविक संचित राशि पर आधारित जमा खातों को कम राशि का अंतरण
35.	3601.01.104.05-स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (प्रभारित)	18654.60	14266.68	4387.92	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
36.	3601.01.104.09-सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	4731.00	3663.83	1067.17	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
37.	3601.01.104.13- राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	6723.75	2634.26	4089.49	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
38.	3601.01.104.17- पर्यावरण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	2500.00	1099.26	1400.74	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
39.	3601.01.104.18- प्रशासन हेतु सहायता-अनुदान (प्रभारित)	3528.82	1636.10	1892.72	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूरा न किया जाना।
40.	3601.02.101.26- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	14242.00	6503.58	7738.42	जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
41.	3601.02.101.27- राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्य योजना (रा.ई.प्र.का.यो.)	190.00	89.54	100.46	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
42.	3601.02.101.35-पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	6990.00	5338.00	1652.00	योजना आयोग से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
43.	3601.02.101.36- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	12522.00	5287.77	7234.23	राज्य सरकारों द्वारा बराबर अंश को जारी न किया जाना, परियोजनाओं को वापस होना तथा योजनाओं के प्रारम्भ में विलम्ब।
44.	3601.02.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	7365.00	5892.00	1473.00	विनिवेश से कम प्रगति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 37- ऋणों का पुनर्भुगतान					
45.	6001.00.106.30 - 8% बचत बंधपत्र, 2003 (कर योग्य)	10594.43	5413.95	5180.48	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों की प्राथमिकता।
46.	6001.00.114 - अर्थोपाय अग्रिम	700000.00	124648.00	575352.00	भारत सरकार के रोकड़ शेष में अधिशेष के बावजूद ओवरड्राफ्ट तथा अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग।
अनुदान सं. 39- पेंशन					
47.	2071.01.102.01- साधारण पेंशन	2070.00	1541.88	528.12	वे.ले.का/मंत्रालयों द्वारा प्रत्याशित से कम भुगतान।
48.	2071.01.115.01- साधारण पेंशन	1440.00	1283.64	156.4	कम दावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 42- प्रत्यक्ष कर					
49.	4059.01.800.01- तैयार - बने आवास का अधिग्रहण	777.49	421.00	356.49	कार्यालय भवन की खरीद हेतु कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना तथा अगले वित्तीय वर्ष में दि.न.नि. को सिविक सेंटर भवन के भुगतान का विलम्ब।
अनुदान सं. 45-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
50.	2408.01.103.15-बागवानी आधारित उद्योग -राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिशन योजना	168.00	11.62	156.38	ठेकेदारों/संस्थानों/संगठनों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति।
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
51.	2210.06.101.08-राष्ट्रीय रोगाणु वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	567.15	266.85	300.30	प्रापण अभिकरणों के बिलों का निपटान न करने, सेवाओं का कम प्रापण, राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।
52.	2210.06.101.30-राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	561.97	434.93	127.04	प्रति क्षयरोग दवाईयों के प्रापण हेतु बोलियों को अंतिम रूप न देना।
53.	2210.06.800.24-केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत नई पहल	404.94	154.39	250.55	प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण नई पहलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति तथ कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
54.	2210.06.800.31-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	337.50	88.60	248.90	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति, अवसंचनात्मक विकास का गैर-कार्यान्वयन तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति कम निधियों की आवश्यकता ।
55.	2211.00.109.07- औषधियों एवं उपकरणों (टीका इत्यादि के अलावा) की अधिप्राप्ति	287.65	44.87	242.78	प्रापण अभिकरणों के बिलों का निपटान न किया जाना।
56.	2211.00.109.08-राज्य पी.आई.पी. हेतु आर.सी.एच. फ्लेक्सीबल पूल	2836.56	2222.28	614.28	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
57.	2211.00.796.05-मिशन फ्लेक्सीबल पूल	626.45	438.43	188.02	राज्य समितियों के पास अव्ययित शेंषों की उपलब्धता।
58.	2211.00.800.15- मिशन फ्लेक्सीबल पूल	3364.25	2953.30	410.95	राज्य समितियों के पास अव्ययित शेंषों की उपलब्धता।
59.	3601.04.246.01- आरसीएच औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति	164.16	22.81	141.35	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
60.	3601.04.789.07-परिवार कल्याण-जनन एवं शिशु स्वास्थ्य	293.48	168.28	125.20	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता।
61.	3606.00.237.05-राष्ट्रीय प्रतिरोधक कार्यक्रम एवं पोलियों उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण हेतु सामग्री सहायता।	332.36	94.21	238.15	संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से कम सहायता सामग्री की प्राप्ति।
62.	4210.03.105.12-अ.भा.आ.वि.सं. जैसे अति-विशेषज्ञता वाले अस्पतालों सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	1376.21	854.62	521.59	उपकरणों के प्रापण में धीमी गति के कारण बृहत निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति।
अनुदान सं. 47- आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग					
63.	2210.02.200.30 अस्पतालों एवं औषधालयों (आयुष फ्लैक्सीपूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के तहत)	234.00	71.95	162.05	राज्य से उपयोगिता प्रमाणपत्र की अप्राप्ति
अनुदान सं.50- भारी उद्योग विभाग					
64.	2852.80.003.12 राष्ट्रीय स्वचालित जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	488.48	341.94	146.54	कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय					
65.	3454.02.800.08- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	1754.82	759.43	995.39	मंत्रीमण्डल/मंत्रालयों के समूहो द्वारा योजना की गैर-स्वीकृति।
अनुदान सं.54-पुलिस					
66.	2055.00.001.04-राष्ट्रीय खूफिया ग्रिड	364.09	9.68	354.41	रिक्त पदों को न भरना, योजनागत पदों के सृजन के संबंध में प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा मितव्ययी उपाय।
67.	2055.00.115.08- राज्य पुलिस संगठन को उनके स्वरूप में सहायता	250.00	33.00	217.00	मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
68.	2055.00.800.11- अपराध एवं आपराधिक नैटवर्क प्रणाली	400.00	37.23	362.77	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा प्रतिपूर्ति दावों की गैर-प्राप्ति।
69.	3601.01.116.01राज्य पुलिस संगठन का सुदृढ़ीकरण	860.00	417.00	443.00	मंत्रीमंडल द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
70.	4055.00.201.01- कार्यालयी भवन	1112.29	811.99	300.30	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
71.	4055.00.201.02- आवासीय भवन	390.85	245.12	145.73	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाना।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
72.	4055.00.204.01- कार्यालयी भवन	200.13	43.39	156.74	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सौंपे गए निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाना।
73.	4055.00.216.10-आसूचना ब्यूरो	219.57	93.64	125.93	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का गैर-उपयोग।
अनुदान सं. 55- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
74.	2250.00.800.14-ज.एवं क. में विशेष औद्योगिक पहल	150.00	10.00	140.00	कॉर्पोरेट द्वारा योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब, योजना का कार्यान्वयन के आरम्भिक चरण पर होना।
अनुदान सं. 56- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
75.	3602.02.101.01- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1031.61	800.34	231.27	शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन परियोजना के अंतर्गत निधियों के निर्गम हेतु कम सिफारिशों के कारण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 58 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
76.	2202.02.110.16-उत्कर्ष के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	671.15	475.56	195.59	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
77.	2202.04.200.14-प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	366.96	263.81	103.15	राज्य सरकारों की कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
अनुदान सं. 59- उच्चतर शिक्षा विभाग					
78.	2202.03.789.03-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय	907.40	732.73	174.67	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
79.	2202.80.800.40- आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	592.86	149.12	443.74	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति।
80.	2203.00.112.52- भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	219.08	71.84	147.24	व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति।
81.	3601.01.166.01-विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	2250.00	98.22	2151.78	राज्य सरकारों को व्यवहार्य प्रस्तावों का कम संख्या में प्राप्ति।
82.	3601.04.175.03-विद्यमान के उन्नयन/नई पॉलिटेक्निक की संस्थापना हेतु सहायता।	558.78	323.49	235.29	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 61-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
83.	2230.03.800.13-कौशल विकास पहल	541.21	249.40	291.81	अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति तथा राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में विलम्ब।
अनुदान सं. 63-विधि एवं न्याय					
84.	2014.00.800.09- जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	212.66	72.97	139.69	योजना के अंतर्गत कम मांग की प्राप्ति के कारण एन.आई.सी. को निधियों का कम निर्गमन।
85.	2014.00.800.16- ग्राम न्यायालयों की स्थापना एवं परिचालन हेतु राज्य सरकारों को सहायता।	109.00	4.10	104.90	राज्य सरकार से कम मांग तथ वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 67- अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय					
86.	3601.04.378.04-चयनित अल्पसंख्यक संकेद्रण जिलों में अल्पसंख्यकों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	864.08	638.97	225.11	राज्य सरकारों से प्रर्याप्त प्रस्तावों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा योजना का पनुर्रचना का जारी रहना।
87.	3601.04.378.06-अल्पसंख्यकों हेतु मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	444.00	326.14	117.86	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
अनुदान सं. 70-पंचायती राज मंत्रालय					
88.	3601.02.471.01- पिछड़े क्षेत्रों हेतु अनुदानें	3817.81	2355.40	1462.41	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
89.	3601.02.789.01-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-पंचायती राज	818.10	601.05	217.05	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा संशोधित अनुमान चरण पर लगाइ गई कटौती तथा पहले के निर्गमों का बृहत पैमाने पर अव्ययित शेषों/देरी से प्रस्तुतीकरण के कारण।
अनुदान सं.-73- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
90.	2802-80-102-01 घरेलू एल.पी.जी तथा पी.डी.एस. केरोसिन पर आर्थिक सहायता	3050.00	2730.56	319.44	केरोसिन तथा एल.पी.जी. की बिक्री की वृद्वि में गिरावट।
अनुदान सं. 74-योजना मंत्रालय					
91.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1300.00	1090.05	209.95	आधार कार्डों को तैयार करने हेतु अभिकरणों से दावों की अप्राप्ति, सेमीनारों/कार्यशाला/बैठक का कम आयोजन तथा कार्यालय उपकरण की खरीद को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
92.	3475.00.800.83-योजना लेखांकन तथा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	130.00	14.45	115.55	प्रापण प्रस्तावों की गैर-स्वीकृति/भवन के नवीकरण कार्य की गैर-समाप्ति, कम प्रशिक्षण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की गैर-स्वीकृति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
93.	5475.00.112.38- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	457.00	248.66	208.34	आधार कार्डों को जारी करने हेतु बायोमेट्रिक उपकरण का गैर-प्रापण तथा कुछ परियोजनाओं की गैर-समाप्ति।
अनुदान सं. 75 -ऊर्जा मंत्रालय					
94.	2801.06.789.01-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गा.ग्रा.वि.यो.)	600.00	50.21	549.79	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता, चरण-II परियोजना को सौंपने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से समापन प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति।
95.	2801.06.797.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	4761.00	674.85	4086.15	विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य की अप्राप्ति।
96.	2801-06-800-03 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	3810.00	647.73	3162.27	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता, चरण-II परियोजना को सौंपने में विलम्ब, कार्यान्वयन अभिकरणों से समापन प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति।
97.	2801.80.004.02-केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	265.00	40.36	224.64	XII योजना हेतु योजना को अंतिम रूप न दिया जाना।
98.	2801.80.800.15-ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	197.40	41.50	155.90	XII योजना हेतु योजना को अंतिम रूप न दिया जाना।
99.	2801.80.800.27-ऊर्जा संरक्षण	200.00	37.00	163.00	XII योजना हेतु योजना को अंतिम रूप न दिया जाना
100.	4801.02.190.02-राष्ट्रीय ताप शक्ति निगम लिमिटेड	720.04	214.24	505.80	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
101.	6801.00.190.04-ऊर्जा वित्त निगम को ऋण	2485.60	1182.52	1303.08	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
102.	6801.00.789.01-त्वरित ऊर्जा विकास तथ सुधार कार्यक्रम (त्व.अ.वि.सु.का.)	200.00	34.93	165.07	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं.81 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
103.	3054.01.337.01-सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	1928.03	1440.65	487.38	विस्तारित मॉनसून के कारण कार्य लक्ष्य में संशोधन।
104.	3054.80.797.01-राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण	3627.17	1850.14	1777.03	संबंधित अभिकरणों से सांविधिक स्वीकृति/पर्यावरण स्वीकृति की अप्राप्ति।
105.	3055.00.004.20-सड़क सुरक्षा	215.15	103.42	111.73	चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थानों के निर्माण कार्य का गैर-समापन तथा सड़क सुरक्षा पर समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना।
106.	5054.01.190.01-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	11435.98	7780.00	3655.98	संबंधित अभिकरणों से सांविधिक स्वीकृति का अप्राप्ति।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
107.	5054.01.337.01- सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य	5613.80	893.72	4720.08	विश्व बैंक के साथ ऋण को अंतिम रूप न दिया जाना, कार्य की धीमी प्रगति तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
108.	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य	2630.71	2350.70	280.01	पुनः सतह निर्माण लक्ष्यों में कमी के कारण कम भण्डारण का प्रापण तथा समय पर भूमि अधिग्रहण एवं वन का अनुमति की अप्राप्ति।
अनुदान सं. 82-ग्रामीण विकास विभाग					
109.	2216.03.105.08- इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम संघटन	4038.96	3082.32	956.64	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
110.	2216.03.789.01-इंदिरा आवास योजना	3687.46	2834.73	852.73	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
111.	2216.03.796.01- इंदिरा आवास योजना	2239.58	1951.72	287.86	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
112.	2501.06.101.20-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-कार्यक्रम संघटन	786.55	377.27	409.28	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
113.	2501.06.789.01- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	520.39	216.60	303.79	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
114.	2501.06.796.01- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	365.66	156.80	208.86	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
115.	2505.02.101.12-सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.)	200.00	4.47	195.53	सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
116.	2505.02.101.13-वेतन संवितरण हेतु सेवा प्रभार	500.00	184.99	315.01	डाक विभाग तथा संबंधित बैंको से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
117.	2505.02.101.14-मनरेगस श्रमिकों तक राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (स.सु.बी.यो.) का विस्तार	350.00	60.00	290.00	राज्यों द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ पात्र श्रमिकों के डाटा को न साझा करना।
118.	3054.04.338.01-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता	16042.11	3397.76	12644.35	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा राज्य सरकार की कम ग्रहण क्षमता।
119.	3054.04.338.05-नाबार्ड से मिले ऋण पर ब्याज के संवितरण हेतु एन.आर.आर.डी.ए. को सहायता	941.21	772.52	168.69	नार्बाड से लिए गए अग्रिम ऋण के पुनर्भुगतान के कारण ब्याज का कम संवितरण।
अनुदान सं. 84-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
120.	2515.02.105.21-संपूर्ण स्वच्छता अभियान	2030.00	1673.51	356.49	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर की गई कटौती।
121.	2215.02.789.01-संपूर्ण स्वच्छता अभियान	770.00	549.99	220.01	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
122.	2215.02.796.01- संपूर्ण स्वच्छता अभियान	350.00	249.99	100.01	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर की गई कटौती।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
123.	3425.60.200.56-सहयोग तथा अ.एवं वि. मिशन	366.00	204.08	161.92	ई.एफ.सी./एस.एफ.टी. बैठकों तथा नई योजना की स्वीकृति का स्थगन।
अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मंत्रालय					
124.	2852-06-102-21 गैर केन्द्रीय सा.क्षे.उ. पोत कारखानों तथा निजी क्षेत्रीय पोत कारखानों को आर्थिक सहायता	400.00	220.00	180.00	पोत-कारखानों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण
125.	3051.01.108.01-कोलकाता पत्तनन्यास द्वारा हलदिया चैनल का अनुरक्षण तथा निकर्षण	245.68	68.58	177.10	कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा निकर्षण के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्रों तथा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर।
अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय तथा अधिकारित मंत्रालय					
126.	2235.02.101.10- अन्य योजनाएं	257.55	141.01	116.54	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त/पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा कुछ योजनाओं की गैर-स्वीकृति।
127.	3601.03.789.08-अनुसूचित जाति का कल्याण-आर्थिक विकास	1174.00	872.05	301.95	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति
अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग					
128.	3252.00.053.08-इनसैट/जीसेट ट्रांसपोडरों को किराए पर लेने हेतु सेवा प्रभार	170.00	39.96	130.04	योजना के प्रति कम निधियों की आवश्यकता।
129.	3402.00.101.04- ध्रुवीय उपग्रह लांच वाहन अवस्थिति (पो.उ.ला.वा.सी.) परियोजना	347.91	154.84	193.07	पो.उ.ला.वा. (सी.35 से सी 49) हेतु अतिरिक्त वायुयानों की स्वीकृति प्रस्ताव करने में विलम्ब।
130.	5252.00.203.03- इन्सैट 4/जीसैट उपग्रह	314.44	120.64	193.80	वी.आई.पी.स्यूटस, नई कैन्टीन भवन, वी.एस.एल.सी. प्रदर्शनी भवन, एम.एम.एफ. भण्डारण भवन, सी.एम.एम. एवं पी.पी.एम.एफ. परियोजना कार्य भवन की निर्माण प्रगति में विलम्ब, इनसेट-4/जी सेट उपग्रह श्रृंखला की प्रणाली/उप प्रणाली की सुपुर्दगी सारणी के स्थगन तथा मिशन को जारी रखने हेतु वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण।
131.	5402.00.101.01- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.के.)	295.00	163.47	131.53	सुविधा प्रतिस्थापन एवं संवर्द्धन पर व्यय का भिन्न् क्रमवस्था में होना एवं आर्थिक उपाय।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
132.	5402.00.101.08-इसरो उपग्रह केन्द्र (इसाक)	225.94	86.20	139.74	सुविधा प्रतिस्थापन तथा उच्च शक्ति आर.एफ. जांच प्रयोगशाला, कोटेक्स प्रणालियों तथा आधार उपकरण प्रयोगशाला जैसी संवर्द्धन गतिविधियों तथा स्थापना और सुविधा प्रतिस्थापन एवं भौतिक प्रतिमान मशीन, अंतरिक्षयान स्थान सूचक, उपकरण परिवहन प्रणाली जैसी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता।
133.	5402.00.101.17- सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र -एस एच ए आर (स.ध.अं.के.- एस एच ए आर)	224.84	92.35	132.49	बहु-वस्तु खोज राडार (एम.ओ.आर.) परियोजना की स्वीकृति की देरी से प्राप्ति।
134.	5402.00.101.33- उन्नत संचार उपग्रह (जी सैट-11 प्रक्षेपण सेवाओं सहित)	243.25	84.76	158.49	जांच उपकरणों की सुपुर्दगी सारणी में विसर्पण तथ लांच सेवा संविदा हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 91-सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
135.	3601.03.432.04-भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकीय प्रणाली का आधुनिकीकरण)	170.00	22.35	147.65	अतिरिक्त राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिऐ जाने में विलम्ब तथा राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति।
अनुदान सं. 93-कपड़ा मंत्रालय					
136.	2851.00.103.01-हस्त करघा विकास	330.90	114.84	216.06	कार्यान्वन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति।
137.	2851.00.103.45- हस्त करघा क्षेत्र हेतु पुनरूद्धार, सुधार एवं पुनर्निर्माण पैकेज	2046.05	291.03	1755.02	कड़े पात्रता प्रतिमानों तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण योजना को प्रारम्भ न किया जाना।
138.	2852-08-202-13 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)	2635.75	2024.82	610.93	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
139.	2852-08-202-16 मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति	200.00	68.07	131.93	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावों की प्राप्ति तथ बाजार समर्पित मूल्य प्रक्रिया न अपनाया जाना।
अनुदान सं. 95-जनजाति मामलों का मंत्रालय					
140.	3601.02.796.01-अनुसूचित जनजाति का कल्याण-सांविधान के अनुच्छेद 275(1) की शर्तों के तहत अनुदान (प्रभारित)	2517.00	1672.54	844.46	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर लगाई गई कटौती।
अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग					
141.	4217.60.190.03 दिल्ली मेट्रो रेल निगम	1112.57	750.00	362.57	राज्य सरकारों द्वारा बराबर अंश के गैर-निर्गम के कारण।
142.	4217.60.190.06 बैंगलोर जनसमूह तीव्र परिवहन प्रणाली	900.00	513.92	386.08	राज्य सरकारों द्वारा बराबर अंश का गैर-निर्गम।

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
143.	6217.60.191.12 जे.बी.आई.सी. से दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सहायता	749.12	583.00	166.12	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति।
अनुदान सं. 104 जल संसाधन मंत्रालय					
144.	2702.02.005.16-भूमि जल प्रबंधन तथा विनियमन	285.50	117.98	167.52	डी.जी-एस. एवं डी. द्वारा क्रय प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाना तथा कम समन्वेशी कुओं का निर्माण।
अनुदान सं. 105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
145.	2236.80.800.05-राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि.)	224.98	55.69	169.29	मातृ तथा बाल कुपोषण हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रारम्भ न किया जाना।
146.	3601.04.356.06-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (इं.गा.मा.स.यो.) पहले सोपाथिक मातृत्व लाभ योजना (सो.मा.ला.यो.)	376.60	66.55	310.05	राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
147.	3601.04.358.08-राजीव गांधी किशोर कन्या सशक्तीकरण योजना (रा.गां.कि.क.स.यो.)	533.60	384.25	149.35	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
रक्षा सेवाएं **अनुदान सं. 22 – रक्षा सेवाएं-थल सेना**					
148.	2076.00.113 –राष्ट्रीय कैड़ेट कोर	1076.58	790.25	286.33	वित्त मंत्रालय द्वारा वेतन खंड पर कटौती लागू करने के कारण।
149.	2076.00.800 –अन्य व्यय	2129.30	1638.63	490.67	वित्त मंत्रालय द्वारा आर.ई ऋण पर कटौती लागू करने तथा कोष का प्राथमिक क्षेत्रों जैसे राशन एफ.ओ.एल. एवं औषधियों में विपथन के कारण।
अनुदान सं. 23 – रक्षा सेवाएं-नौसेना					
150.	2077.00.104 –असैनिक को वेतन एवं भत्ते	1844.00	1548.13	295.87	वित्त मंत्रालय द्वारा आर.ई. स्तर पर वेतन खंड़ में 10% कटौती लागू करने के कारण।
अनुदान सं.24 – रक्षा सेवाएं-वायु सेना					
151.	2078.00.800-अन्य व्यय	452.19	333.70	118.49	वित्त मंत्रालय द्वारा आर.ई ऋण पर कटौती लागू करने के कारण।
अनुदान सं.25 – रक्षा आयुद्ध कारखाने					
152.	2079.00.110-भण्डारण	6473.17	5691.76	781.41	आर.ई. स्थानीय खरीद, विदेशी खरीद, समय पूर्व की अपेक्षा सी.के.डी./एस.के.डी. तथा मामलों के पूर्ण मूल्य पर कम व्यय के कारण।
अनुदान सं. 26 – रक्षा सेवाएं -अनुसंधान तथा विकास					
153.	2080.00.004 –अनुसंधान/अनुसंधान विकास	1149.86	516.97	632.89	ए.डी.ए. तथा अन्य अ. एवं वि. बोर्डो की आवश्यकता में कटौती तथा अनेक ए. एवं वि. बोर्डों से सीमांत बचतों का सामूहिक प्रभाव के कारण

क्र. सं.	लघु शीर्ष/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
154.	2080.00.102- असैनिक को वेतन एवं भत्ते	1946.63	1694.22	252.41	प्रदर्शन संबंधित प्रोत्साहन योजना (प्र. सं. प्रो.यो.) के कार्यान्वयन में विलंब तथा समयोपरि कार्य एवं चिकित्सा उपचार हेतू आवश्यक्ता में कमी तथा अपेक्षित व्यय कम करने के कारण।
अनुदान सं. 27 –रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय					
01- थल सेना					
155.	4076.01.101 –वायुयान तथा विमान इंजन	3052.52	2306.94	745.58	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
156.	4076.01.102 –भारी एवं मध्यम वाहन	2249.29	1773.31	475.98	वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कटौती तथा एम.जी.ओ.एवं. ई. - इन.सी.द्वारा लक्ष्यों को अमल में न लाना।
157.	4076.01.103 –अन्य उपकरण	8250.04	6658.19	1591.85	मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
158.	4076.01.112-राष्ट्रीय रायफल	252.17	133.24	118.93	वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
159.	4076.01.202 –निर्माण कार्य	5163.16	3812.94	1350.22	अल्प बुकिंग के परिणामस्वरूप डी.जी. एम.ए.पी. द्वारा बैंक गारंटी का नकदीकरण तथा एम.ए.पी.एवं रोहतांग सुरंग परियोजना में धीमी प्रगति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कमी के कारण।
02- नौसेना					
160.	4076.02.101 – वायुयान तथा विमान इंजन	5303.29	1695.34	3607.95	वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है
161.	4076.02.103-अन्य उपकरण	3272.53	2773.06	499.47	बैकिंग की प्रवृत्ति के आधार तथा संपूर्ण बजटीय संसाधन में कमी को देखते हुए प्राथमिक क्षेत्र को पुनर्विनियोग के माध्यम से कोषों के विपथन के कारण।
162.	4076.02.204-नौसेनिक बेड़ा	13617.39	11074.27	2543.12	वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कटौती।
163.	4076.02.205-नौसैनिक गोदी	1039.50	751.84	287.66	वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षा पूँजी बजट में कटौती।

अनुबंध 3.16

(पैराग्राफ 3.18 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			
सिविल					
अनुदान सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.800.35-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	92.17	10.63	81.54	88
2.	3601.04-789.24-फसल उत्पादन-तेल बीज का विकास	90.00	36.50	53.50	59
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
3.	5401.00.400.02-परिवर्ती ऊर्जा साईक्लोट्रॉन केन्द्र	155.98	67.92	88.06	56
अनुदान सं. 6- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग					
4.	2852.04.800.01- केन्द्रीय प्लास्टिक आभियंत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (के.प्ला.अ.प्रौ.सं.)	110.00	21.70	88.30	80
अनुदान सं. 15-सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग					
5.	2852.07.202.03-सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नैनो इलेट्रॉनिक्स विकास कार्यक्रम	95.00	37.89	57.11	60
6.	2852.07.796.01-इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेस	92.42	20.43	71.99	78
अनुदान सं. 30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
7.	3435.60.800.11-खतरनाक पदार्थ प्रबंधन	89.85	24.65	65.20	73
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग					
8.	2235.60.800.10-वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजाना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान	182.25	99.55	82.70	45
अनुदान सं. 34-ब्याज भुगतान					
9.	2049.03.110.01 भारतीय श्रेणी के असंवितरण वेतन हेतु बोनस (प्रभारित)	84.67	18.30	66.37	78
अनुदान सं. 43-अप्रत्क्ष कर					
10.	4047.00.037.03- निवारक एवं अन्य कार्य	87.15	5.45	81.70	94
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
11.	2211.00.800.14-प्रबंधन सूचना प्रणाली	145.00	74.39	70.61	49
12.	3601.04.789.08- रोगों का पी.एच.-निवारण एवं नियंत्रण	99.68	32.20	67.48	68
13.	3601.04.796.06-प.क.-जनन एवं बाल स्वास्थ्य	158.32	91.75	66.57	42
14.	4210.01.110.06-सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	100.00	32.57	67.43	67
अनुदान सं. 54-पुलिस					
15.	3601.01.117.04- मादक द्रव्य यंत्रण ब्यूरो	83.00	1.72	81.28	98
16.	4055.00.210.01-राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	109.00	42.60	66.40	61

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)

17.	4055.00.214.05-भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	110.00	40.00	70.00	64
18.	4055.00.214.07- समेकित चैक-पोस्ट का संस्थापन	160.00	73.11	86.89	54
19.	4055.00.215.03- तटीय सुरक्षा हेतु राज्य/सं.शा.क्षे. को सहायता	170.00	79.97	90.03	53
20.	4055.00.216.04-केन्द्रीय न्यायालयिक -विज्ञान प्रयोगशाला	73.25	2.69	70.56	96
अनुदान सं. 59-उच्च शिक्षा विभाग					
21.	2202.80.789.05- आई.सी.टी. के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	114.75	28.47	86.28	75
22.	3601.04.175.01-सामुदायिक पॉलिटेक्नीक	83.68	29.39	54.29	65
23.	3601.04.789.02-तकनिकी शिक्षा पॉलिटेक्नीक	160.31	77.73	82.58	52
अनुदान सं. 68-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
24.	2810.00.104.01- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अ. एवं वि.	134.55	57.47	77.08	57
अनुदान सं. 75- ऊर्जा मंत्रालय					
25.	2801-80-800.26-त्वरित ऊर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (त्व.अ. वि.सु.का.)	117.00	17.04	99.96	85
अनुदान सं. 81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
26.	3055.00.004.24-निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र	90.00	10.00	80.00	89
अनुदान सं. 82-ग्रामीण विकास विभाग					
27.	2515.00.003.01-राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदानें	113.80	48.87	64.93	57
अनुदान सं. 88- नौ परिवहन मंत्रालय					
28.	5051.02.200.01-अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	99.86	45.88	53.98	54
अनुदान सं.89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
29.	2225.01.789.10- मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना	98.00	20.00	78.00	80
30.	3601.03.359.03-अपंग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्चयन हेतु योजना	75.00	8.37	66.63	89
31.	4225.80.190.16 कमजोर वर्ग हेतु राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	91.00	27.65	63.35	70
अनुदान सं.90-अंतरिक्ष विभाग					
32.	3252.00.053.06 इनसेट-4/जी सेट उपग्रहें	76.46	24.96	51.50	67
33.	3402.00.103.01-भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (भौ.अ.प्र.)	111.90	55.89	56.01	50
34.	5402.00.101.07-तरल प्रणोंदन प्रणाली केन्द्र (त.प्र.के.)	165.34	82.31	83.03	50
35.	5402.00.101.37-अर्द्ध निम्नतापी ईंजन विकास	106.59	56.22	50.37	47

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹50 करोड़ और उससे अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)

36.	5402.00.800.02-विशेष स्वदेशीकरण/उन्नत क्रमण	94.25	2.40	91.85	97
अनुदान सं. 93- कपड़ा मंत्रालय					
37.	2851.00.103.41-एकीकृत हस्त करधा विकास योजना	105.56	30.74	74.82	71
अनुदान सं. 95- जनजातीय मामलें मंत्रालय					
38.	2225.02.796.08-अनुसूचित जनजाति का कल्याण-शिक्षा	119.50	62.12	57.38	48
39.	2225.02.796.09-अनुसूचित जनजाति का कल्याण-अन्य व्यय	91.90	32.23	59.67	65
अनुदान सं. 99- दमन एवं दीव					
40.	5051.02.200.04 पत्तनों तथा प्रकाश गृहों का निर्माण एवं विकास	79.80	6.85	72.95	91
अनुदान सं. 101- शहरी विकास विभाग					
41.	2217-80.191.33 विश्व बैंक-शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण	65.17	1.58	63.59	98
अनुदान सं. 104- जल संसाधन मंत्रालय					
42.	2701.80.004.05-अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	92.00	31.37	60.63	66
43.	2701.80.800.19-सिंचाई प्रबधन कार्यक्रम	90.00	0.24	89.76	100
44.	3601.03.786.03-नदी प्रबंधन गतिविधियां तथ सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य	100.00	9.24	90.76	91
अनुदान सं. 105- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
45.	3601.04.358.02-विश्व बैंक स.बा.वि.यो.-परियोजना- IV (बाह्य सहायता प्राप्त संघटक)	64.00	5.58	58.42	91
46.	3601.04.789.16-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (इं.गां.मा.स.यो.) (पहले सशर्त मातृत्व लाभ योजना (स.मा.ला.यो.)	79.00	15.23	63.77	81
रक्षा सेवाएं अनुदान सं. 27 – रक्षा सेवाएओं पर पूंजीगत परिव्यय					
47.	4076.03.050-भूमि	90.00	19.78	70.22	78
48.	4076.04-052-मशीनरी एवं उपकरण	173.24	90.42	82.82	48

अनुबंध 4.1

(पैरा सं. 4.5.5 और तालिका सं. 4.8 के संदर्भ में)

विषय शीर्षों 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' में वृद्धि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा का शीर्ष	डी डी जी में बजट (मूल प्रावधान)	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि
	4-परमाणु उर्जा विभाग			
1.	4861.02.201.01.12.52- ए.एम.डी. सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण	0.35	0.56	0.21
2.	4861.60.105.15.00.52-अपशिष्ट निपटान सुविधा	1.30	1.84	0.54
3.	4861.60.202.13.00.52- एन.एफ.सी.	0.20	0.89	0.69
4.	4861.60.202.32.00.52- एन.एफ.सी.	2.67	3.18	0.51
5.	4861.60.202.46.00.52- एन.एफ.सी.	0.74	1.15	0.41
6.	4861.60.203.26.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	1.90	3.16	1.26
7.	4861.60.203.43.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	4.08	6.13	2.05
8.	5401.00.201.01.01.52- भा.प.अ.के.	6.96	9.38	2.42
9.	5401.00.201.01.03.52- भा.प.अ.के.	1.00	1.48	0.48
10.	5401.00.201.03.01.52- भा.प.अ.के.	4.99	6.87	1.88
11.	5401.00.201.09.02.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.25	0.24
12.	5401.00.201.03.04.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.11	0.10
13.	5401.00.201.04.13.52- भा.प.अ.के.	18.50	20.49	1.99
14.	5401.00.201.04.17.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.07	0.06
15.	5401.00.201.04.18.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.03	0.02
16.	5401.00.201.05.01.52- भा.प.अ.के.	6.39	8.22	1.83
17.	5401.00.201.07.01.52- भा.प.अ.के.	2.32	3.26	0.94
18.	5401.00.201.11.05.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.05	0.04
19.	5401.00.201.13.08.52- भा.प.अ.के.	0.01	0.02	0.01
20.	5401.00.201.19.01.52- भा.प.अ.के.	4.26	5.12	0.86
21.	5401.00.201.26.01.52- भा.प.अ.के.	1.08	2.00	0.92
22.	5401.00.201.26.02.52- भा.प.अ.के.	0.00	0.01	0.01
23.	5401.00.201.26.03.52- भा.प.अ.के.	1.60	3.02	1.42
24.	5401.00.201.49.00.52- भा.प.अ.के.	1.94	2.64	0.70
25.	5401.00.201.90.00.52- भा.प.अ.के.	8.00	9.00	1.00
26.	5401.00.202.57.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.83	1.50	0.67
27.	5401.00.202.62.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.68	1.12	0.44
28.	5401.00.202.81.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.25	0.31	0.06
29.	5401.00.202.82.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.01	0.36	0.35

30.	5401.00.202.86.00.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.01	0.57	0.56
31.	5401.00.202.93.06.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.15	0.24	0.09
32.	5401.00.202.94.06.52 आई.जी.सी.ए.आर.	0.10	1.60	1.50
33.	5401.00.206.36.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	4.50	5.80	1.30
34.	5401.00.206.37.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	3.50	3.92	0.42
35.	5401.00.206.49.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	0.27	2.00	1.73
36.	5401.00.206.67.00.52 आर.आर.सी.ए.टी.	0.14	0.20	0.06
37.	5401.00.400.02.35.52-अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.27	0.70	0.43
38.	5401.00.400.02.49.52- अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	4.30	4.86	0.56
39.	5401.00.400.03.07.52- अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.70	0.85	0.15
40.	5401.00.400.03.10.52- अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.02	0.08	0.06
41.	5401.00.800.17.00.52- अन्य व्यय	2.90	3.58	0.68
42.	5401.00.800.18.00.52- अन्य व्यय	2.40	2.79	0.39
43.	4861.60.105.16.00.52-अपशिष्ट निपटान सुविधा	9.30	15.94	6.64
44.	4861.60.203.58.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	9.00	12.88	3.88
45.	4861.60.203.59.00.52-ईंधन पुनर्संसाधन	13.00	64.03	51.03
46.	5401.00.201.01.06.52- भा.प.अ.के.	1.00	8.66	7.66
47.	5401.00.201.02.03.52- भा.प.अ.के.	5.00	9.41	4.41
48.	5401.00.201.04.12.52- भा.प.अ.के.	6.62	11.76	5.14
49.	5401.00.201.04.14.52- भा.प.अ.के.	3.87	14.28	10.41
50.	5401.00.201.10.01.52- भा.प.अ.के.	4.18	7.82	3.64
51.	5401.00.201.06.04.52- भा.प.अ.के.	5.45	8.96	3.51
52.	5401.00.201.09.01.52- भा.प.अ.के.	10.78	15.62	4.84
53.	5401.00.201.11.02.52- भा.प.अ.के.	7.67	18.10	10.43
54.	5401.00.201.13.01.52- भा.प.अ.के.	41.15	49.00	7.85
55.	5401.00.201.13.02.52- भा.प.अ.के.	9.67	19.09	9.42
56.	5401.00.201.18.01.52- भा.प.अ.के.	6.21	10.58	4.37
57.	5401.00.201.18.02.52- भा.प.अ.के.	10.85	16.00	5.15
58.	5401.00.201.25.01.52- भा.प.अ.के.	2.00	5.33	3.33
59.	5401.00.201.92.00.52- भा.प.अ.के.	8.63	15.41	6.78
60.	5401.00.202.52.00.52- आई.जी.सी.ए.आर.	1.70	14.98	13.28
61.	5401.00.206.40.00.52- आर.आर.सी.ए.टी.	7.92	12.08	4.16
62.	4861.60.203.46.00.53-ईंधन पुनर्संसाधन	2.80	3.19	0.39
63.	4861.60.203.48.00.53-ईंधन पुनर्संसाधन	3.71	6.32	2.61
64.	5401.00.201.10.01.53- भा.प.अ.के.	2.00	4.50	2.50
65.	5401.00.202.57.00.53- आई.जी.सी.ए.आर.	0.19	0.25	0.06
66.	5401.00.283.15.16.53-आवास के प्रबंध	10.00	11.20	1.20
67.	5401.00.283.15.21.53-आवास के प्रबंध	10.00	21.99	11.99
68.	5401.00.400.02.27.52-अन्य अनुसंधान सुविधाएँ	0.61	3.95	3.34
	योग			**218.06**

	90-अंतरिक्ष विभाग			
1.	3402.00.101.25.00.52 एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर. केन्द्र	0.12	0.14	0.02
2.	3402.00.101.33.00.52 जी.एस.एल.वी. परिचालन (जी.एस.एल.वी.-ओ) परियोजना	2.00	14.59	12.59
3.	3402.00.101.45.00.52 अर्द्ध निम्न तापिकी इंजन विकास	1.50	3.00	1.50
4.	5402.00.101.20.00.52 पी.एस.एल.वी. निरंतर परियोजना	3.75	6.33	2.58
5.	5402.00.103.04.00.52 मेघा-ट्रॉपिक्स	0.09	0.14	0.05
6.	5252.00.204.01.00.53 इनसैट-एम.सी.एफ.	1.23	3.43	2.20
7.	5402.00.101.02.00.53 आई.आई.एस.यू.	5.91	9.42	3.51
8.	5402.00.101.25.00.53 जी.एस.एल.वी. परिचालन (जी.एस.एल.वी.-ओ) परियोजना	0.74	1.86	1.12
9.	5402.00.283.02.00.53 एल.पी.एस.सी.	1.77	4.30	2.53
10.	5402.00.283.03.00.53 एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर. केन्द्र	2.78	3.56	0.78
11.	5402.00.283.05.00.53 एस.ए.सी.	3.84	5.19	1.35
12.	5402.00.283.07.00.53 केन्द्रीय प्रबंधन	7.20	8.12	0.92
	योग			**29.15**
	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
1.	4055.00.207.05.00.53 शहरी विकास-राज्य पुलिस-अन्य सिविल निर्माण कार्य	9.75	11.25	1.50
2.	4059.80.051.04.00.53 शहरी विकास-लोक निर्माण कार्य-सामान्य प्रशासन	11.95	14.40	2.45
3.	4059.80.796.01.00.53 शहरी विकास-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना निर्माण-भवन निर्माण	1.86	2.13	0.27
4.	4202.01.201.01.00.53 शहरी विकास- खेलकूद, कला तथा सामान्य एवं मौलिक शिक्षा-भवन निर्माण	3.34	5.75	2.41
5.	4202.01.202.05.00.53 शहरी विकास- खेलकूद, कला और सामान्य एवं द्वितीयक शिक्षा-भवन निर्माण	3.47	6.13	2.66
6.	4202.04.800.02.00.53 शहरी विकास-खेलकूद, कला एवं संस्कृति-भवन निर्माण	0.05	0.56	0.51
7.	4210.80.796.01.00.53 शहरी विकास-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -भवन निर्माण	1.10	1.40	0.30
8.	4210.80.800.01.00.53 शहरी विकास-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-अन्य व्यय-भवन निर्माण	7.91	10.36	2.45
9.	4215.01.102.03.00.53 ग्रामीण विकास-ग्रामीण जलापूर्ति	23.00	25.46	2.46
10.	4216.01.106.05.00.53 शहरी विकास-आवास प्रबंध-सरकारी आवासीय भवन-सामान्य पूल	9.41	13.86	4.45
11.	4217.60.051.01.00.53 शहरी विकास-गैर सड़क के किनारे अपवाहिका का निर्माण	1.23	1.45	0.22
12.	4250.00.201.02.00.53 शहरी विकास-अन्य सामाजिक सेवाएं-श्रमिक भवन	1.55	1.99	0.44

13.	4401.00.800.15.00.52 शहरी विकास-फसल कृषिकर्म-अन्य व्यय-भवन निर्माण	0.20	0.32	0.12
14.	4403.00.800.13.00.53 शहरी विकास-पशुपालन-अन्य व्यय-भवन निर्माण	1.70	2.58	0.88
15.	4406.01.105.01.00.53 पर्यावरण एवं वन-वन एवं वन्यजीव-वन संरक्षण-वन उत्पाद एवं अन्य योजनाएँ	2.00	3.33	1.33
16.	4408.02.800.01.00.53 शहरी विकास-खाद्य भण्डारण एवं गोदाम-अन्य व्यय-भवन निर्माण	0.63	1.45	0.82
17.	4801.05.800.06.00.53 शहरी विकास-बिजली परियोजनाएँ- प्रसारण एवं वितरण-भवन निर्माण	0.50	2.05	1.55
18.	4801.06.800.01.00.53 शहरी विकास-बिजली परियोजनाएँ-ग्रामीण विद्युतीकरण-अन्य व्यय	0.50	1.35	0.85
19.	4851.00.102.09.00.53 शहरी विकास-ग्रामीण एवं लघु उद्योग-भवन निर्माण	0.98	1.58	0.60
20.	5054.04.337.01.00.53 सड़क, परिवहन एवं राज मार्ग-सड़कें एवं पुलें-जिला एवं अन्य सड़क निर्माण कार्य	7.00	7.90	0.90
21.	5425.00.800.02.00.53 शहरी विकास-अन्य वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-अन्य व्यय-भवन निर्माण	0.05	0.15	0.10
	योग			**27.27**

अनुबंध 4.2

(पैरा 4.6.1 तथा 4.7.3 के संदर्भ में)

प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्षों तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
01- वेतन	यात्रा खर्चों (छुट्टी यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित इसमें कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण साकार भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें वर्तमान में आकस्मिकता से देय कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03-समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन की प्रभारें	इसमें सरकारी सेवकों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार के ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। फिर भी, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को योजनानुसार चुकता की गई राशि शामिल होगी, यदि कोई, मंत्रालय/विभाग में परिचालित हो।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए चुकता की गई राशि शामिल होगी।
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होगी।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों के भारत से बाहर के दौरे, वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।
13-कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चे शामिल होंगी जैसे कि कुर्सी, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं औजारों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकास्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दर एवं कर	इसमें किराये पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दर एवं करें आदि शामिल होंगी। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति नियम, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड के छपाई, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले छूट भी शामिल होंगे।
20- अन्य प्रशासनिक खर्चे	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्चे, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
21-आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22-शस्त्र और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों के शस्त्र और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
23-राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24-पी.ओ.एल	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते है ।
25- कपडा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों के कपड़े और टेंट पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रकाशन	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्त्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें की गई सेवाओं अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्चे के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
31-सहायता अनुदान-सामान्य	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33-आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
34- छात्रवृति/वृतिछात्र	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान-वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
41-गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
42-एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान रू.10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों मे व्यय के अन्य विषयों द्वारा अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचिंत	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45-ब्याज	इसमें पूंजीगत पर ब्याज तथा ऋण पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
50-अन्य प्रभारें	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
51-मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आनेवाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक के अलावा मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53 मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि तथा ढांचों के अधिग्रहण का लागत भी शामिल होगा।
54-निवेश	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।

विषय शीर्ष	विवरण
55-ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56-उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
61- मूल्यह्रास	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
62-आरक्षितें	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्यायोजन का विवरण उपलब्ध न होना।
63- अंतर-खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा को अंतरण शामिल होगा, इत्यादि, पूंजी से राजस्व को वापस लिखना।
64- बट्टे खाते/हानियां	बट्टे खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति नियमों, 1978 के प्रत्योजन का विवरण उपलब्ध न होना।

अनुबंध 4.3

(पैरा सं. 4.12 तालिका सं. 4.19 के संदर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग में पुनर्विनियोग जारी करने से पूर्व प्रावधान से अधिक किए गए व्यय के मामले

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
1.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.01 योजना	131.00	142.82	जनवरी-13	11.82
2.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.01 गैर-योजना	1739.00	1892.26	जनवरी-13	153.26
3.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.06 योजना	7.00	7.41	मार्च -13	0.41
4.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.06 गैर-योजना	85.00	85.47	मार्च -13	0.47
5.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.11 गैर-योजना	5.00	5.89	जनवरी -14	0.89
6.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.27 योजना	207.00	256.56	फरवरी-13	49.56
7.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.27 गैर-योजना	35.00	44.04	फरवरी -13	9.04
8.	01- एम.सी.एफ.	3252.00.053.01.00.31 गैर-योजना	1.00	1.06	मार्च -13	0.06
9.	04-इनसैट 3	3252.00.053.04.00.20 योजना	10.00	11.95	दिसम्बर-12	1.95
10.	04-इनसैट 3	3252.00.053.04.00.21 योजना	10.00	27.30	अगस्त-12	17.30
11.	04-इनसैट 3	3252.00.053.04.00.28 योजना	20.00	24.89	सितम्बर-12	4.89
12.	06-इनसैट 4	3252.00.053.06.00.11 योजना	151.00	174.53	फरवरी -13	23.53
13.	06-इनसैट 4	3252.00.053.06.00.21 योजना	12.00	249.70	मई-12	237.70
14.	07-इनसैट 4 एल.एस.	3252.00.053.07.00.50 योजना	10.00	11.20	जनवरी -13	1.20
15.	10- जी.एस.ए.टी. 7 एल.एस.	3402.00.001.01.00.06 गैर-योजना	351.50	451.90	फरवरी -13	100.40
16.	10- जी.एस.ए.टी. 7 एल.एस.	3402.00.001.01.00.27 गैर-योजना	660.00	887.80	जनवरी -13	227.80
17.	01-इसरो मुख्यालय	3402.00.001.01.00.28 गैर-योजना	18.00	30.33	नवम्बर-12	12.33
18.	01-इसरो मुख्यालय	3402.00.001.01.00.50 गैर-योजना	1280.00	1491.05	फरवरी -13	211.05
19.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.06 योजना	1625.00	1743.00	मार्च -13	118.00
20.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.06 गैर-योजना	325.00	357.00	दिसम्बर-12	32.00
21.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.20 गैर-योजना	250.00	270.00	फरवरी -13	20.00
22.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.26 गैर-योजना	20.00	30.00	जनवरी -13	10.00
23.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.50 गैर-योजना	6.00	11.87	मार्च -13	5.87
24.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.11 योजना	69.00	70.00	मार्च -13	1.00
25.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.13 योजना	256.00	352.03	दिसम्बर-12	96.03
26.	02आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.27 योजना	55.00	74.00	नवम्बर-12	19.00
27.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.52 योजना	457.00	499.00	मार्च -13	42.00
28.	04-पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.01 योजना	357.00	385.01	जनवरी -13	28.01
29.	04-पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.11 योजना	50.00	169.26	सितम्बर-12	119.26

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
30.	04पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.13 योजना	50.00	94.28	अक्तूबर-12	44.28
31.	04-पी.एस.एल.वी.सी.	3402.00.101.04.00.27 योजना	15.00	63.52	अप्रैल-12	48.52
32.	06 जी.एस.एल.वी. एम.के. III	3402.00.101.06.00.50 योजना	40.00	80.59	जनवरी -12	40.59
33.	09 एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.02 गैर-योजना	3.00	9.00	दिसम्बर-12	6.00
34.	09- एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.06 योजना	390.00	432.00	मार्च -13	42.00
35.	09- एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.27 योजना	820.00	898.00	मार्च -13	78.00
36.	09- एल.पी.एस.सी.	3402.00.101.09.00.28 योजना	910.00	1048.00	मार्च -13	138.00
37.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.06 योजना	800.00	990.00	जनवरी -13	190.00
38.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.20 गैर-योजना	124.00	129.07	फरवरी -13	5.07
39.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.21 योजना	1810.00	1939.54	नवम्बर-12	129.54
40.	10आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.21 गैर-योजना	190.00	229.97	मार्च -13	39.97
41.	10आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.27 योजना	216.00	219.56	मार्च -13	3.56
42.	10-आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.50 योजना	175.00	176.97	मार्च -13	1.97
43.	10आई.एस.ए.सी.	3402.00.101.10.00.50 गैर-योजना	50.00	55.58	फरवरी -13	5.58
44.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.06 योजना	14.00	15.15	मार्च -13	1.15
45.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.20 योजना	9.00	9.23	मार्च -13	0.23
46.	11 एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.26 योजना	5.00	5.35	जनवरी -13	0.35
47.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.27 योजना	210.30	232.34	फरवरी -13	22.04
48.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.50 योजना	65.00	144.10	सितम्बर-12	79.10
49.	11- एल.ई.ओ.एस.	3402.00.101.11.00.52 योजना	27.00	27.15	मार्च -13	0.15
50.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.02 गैर-योजना	16.00	43.71	अगस्त-12	27.71
51.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.06 योजना	282.00	590.70	मार्च -13	308.70
52.	25 एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.06 गैर-योजना	968.00	987.58	फरवरी -13	19.58
53.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.14 गैर-योजना	1.00	19.00	मार्च -13	18.00
54.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.20गैर-योजना	25.00	37.18	सितम्बर-12	12.18
55.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.50 गैर-योजना	1.00	4.62	जून-12	3.62
56.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.52 योजना	3.00	56.98	फरवरी -13	53.98
57.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.01 योजना	340.00	348.00	मार्च -13	8.00
58.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.01 गैर-योजना	3060.00	3149.23	फरवरी -13	89.23
59.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.06 योजना	60.00	69.66	जनवरी-13	9.66
60.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.06 गैर-योजना	105.00	120.33	मार्च -13	15.33
61.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.11 योजना	75.00	75.10	मार्च -13	0.10
62.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.11 गैर-योजना	25.00	25.65	मार्च -13	0.65
63.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.12 योजना	88.00	88.50	मार्च -13	0.50
64.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.12 गैर-योजना	13.00	17.77	मार्च -13	4.77

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
65.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.20 गैर-योजना	4.00	4.03	मार्च -13	0.03
66.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.26 गैर-योजना	6.00	8.78	मार्च -13	2.78
67.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.28 योजना	89.00	111.03	दिसम्बर-12	22.03
68.	26-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.28 गैर-योजना	231.00	288.52	दिसम्बर-12	57.52
69.	33-जी.एस.एल.वी.ओ.	3402.00.101.33.00.01 योजना	400.00	441.23	जनवरी-13	41.23
70.	35-आर.आई.एस.ए.टी. 1	3402.00.101.35.00.11 योजना	7.00	20.02	अप्रैल-12	13.02
71.	38-आई.आर.एन.एस.एस	3402.00.101.38.00.11 योजना	121.00	145.71	फरवरी -13	24.71
72.	38-आई.आर.एन.एस.एस	3402.00.101.38.00.28 योजना	120.00	143.70	फरवरी -13	23.70
73.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.11 योजना	32.00	34.69	फरवरी -13	2.69
74.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.21 योजना	10.00	65.21	अगस्त-12	55.21
75.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.27 योजना	25.00	44.00	फरवरी -13	19.00
76.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.28 योजना	5.00	12.06	मार्च -13	7.06
77.	41- जी.एस.ए.टी. 11	3402.00.101.41.00.50 योजना	6.00	17.00	अप्रैल-12	11.00
78.	45- एस.सी.ई.डी.	3402.00.101.45.00.52 योजना	150.00	300.00	दिसम्बर-12	150.00
79.	46-ई.ओ.एन.एम.	3402.00.101.46.00.13 योजना	60.00	82.41	फरवरी -13	22.41
80.	46-ई.ओ.एन.एम.	3402.00.101.46.00.28 योजना	15.00	22.00	फरवरी -13	7.00
81.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.13 योजना	53.00	54.80	मार्च -13	1.80
82.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.20 योजना	21.50	24.22	मार्च -13	2.72
83.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.28 योजना	10.00	18.12	दिसम्बर-12	8.12
84.	47-एस.ए.आर.ए.एल.	3402.00.101.47.00.50 योजना	7.00	10.54	मार्च -13	3.54
85.	49- जी.आई.एस.ए.टी.	3402.00.101.49.00.11 योजना	17.00	18.00	फरवरी -13	1.00
86.	49- जी.आई. एस.ए.टी.	3402.00.101.49.00.27 योजना	30.00	31.59	मार्च -13	1.59
87.	49 जी.आई. एस.ए.टी.	3402.00.101.49.00.28 योजना	5.00	8.60	फरवरी -13	3.60
88.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.01 योजना	5250.00	5300.00	फरवरी -13	50.00
89.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.01 गैर-योजना	9350.00	9599.64	फरवरी -13	249.64
90.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.06 योजना	400.00	499.94	फरवरी -13	99.94
91.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.11 योजना	200.00	219.95	फरवरी -13	19.95
92.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.14 गैर-योजना	5.00	15.00	फरवरी -13	10.00
93.	01- एस.ए.सी.	3402.00.102.01.00.50 योजना	950.00	1013.00	मार्च -13	63.00
94.	05- एन.एन.आर.एम.एस	3402.00.102.05.00.01 योजना	96.00	130.34	फरवरी -13	34.34
95.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.01 योजना	1173.00	1185.45	जनवरी -13	12.45
96.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.01 गैर-योजना	6447.00	6546.40	मार्च -13	99.40
97.	11 एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.06 योजना	294.00	442.12	दिसम्बर-12	148.12
98.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.11 गैर-योजना	14.00	16.02	जनवरी -13	2.02
99.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.12 गैर-योजना	5.00	5.68	जनवरी -13	0.68
100.	11 एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.14 गैर-योजना	15.00	30.56	अगस्त-12	15.56

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
101.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.20 गैर-योजना	84.00	182.82	अगस्त-12	98.82
102.	11- एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.26 गैर-योजना	30.00	120.15	सितम्बर-12	90.15
103.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.02 गैर-योजना	9.00	12.80	दिसम्बर-12	3.80
104.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.06 योजना	34.00	69.43	दिसम्बर-12	35.43
105.	12आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.06 गैर-योजना	20.00	40.84	दिसम्बर-12	20.84
106.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.11 योजना	20.00	27.22	दिसम्बर-12	7.22
107.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.11 गैर-योजना	16.00	21.77	दिसम्बर-12	5.77
108.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.13 योजना	40.00	50.15	फरवरी -13	10.15
109.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.13 गैर-योजना	25.00	31.34	फरवरी -13	6.34
110.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.20 योजना	4.00	18.29	नवम्बर-12	14.29
111.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.20 गैर-योजना	2.00	9.14	नवम्बर-12	7.14
112.	12- आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.26 गैर-योजना	12.50	17.31	दिसम्बर-12	4.81
113.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.27 योजना	230.00	276.30	मार्च -13	46.30
114.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.27 गैर-योजना	30.00	36.04	मार्च -13	6.04
115.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.28 योजना	10.00	11.91	फरवरी -13	1.91
116.	12-आई.आई.आर.एस.	3402.00.102.12.00.28 गैर-योजना	5.00	5.96	फरवरी -13	0.96
117.	12- ए.एस.पी.	3402.00.103.12.00.50 योजना	520.00	754.85	नवम्बर-12	234.85
118.	16- एम.ए.आर.एस.	3402.00.103.16.00.13 योजना	50.00	131.53	मार्च -13	81.53
119.	02-ओ.पी.	3402.00.798.02.00.32 योजना	20.00	22.50	फरवरी -13	2.50
120.	18 डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.11 गैर-योजना	80.00	117.91	दिसम्बर-12	37.91
121.	18- डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.14 गैर-योजना	1.00	1.59	मार्च -13	0.59
122.	18- डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.20 गैर-योजना	12.00	15.41	फरवरी -13	3.41
123.	18 डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.28 गैर-योजना	60.00	87.65	नवम्बर-12	27.65
124.	18 डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.31 गैर-योजना	30.00	50.51	मार्च -13	20.51
125.	18- डी.ओ.एस.	3451.00.090.18.00.50 गैर-योजना	6.50	61.35	जून-12	54.85
126.	01- एम.सी.एफ.	5252.00.204.01.00.53 योजना	123.00	342.70	सितम्बर-12	219.70
127.	01-वी.एस.एस.सी.	5402.00.101.01.00.53 योजना	4299.00	4393.98	मार्च -13	94.98
128.	02-आई.आई.एस.यू.	5402.00.101.02.00.53 योजना	591.00	941.99	जनवरी -13	350.99
129.	17- एस.एच.ए.आर.	5402.00.101.17.00.53 योजना	2492.00	2586.95	मार्च -13	94.95
130.	18-आई.एस.टी.आर.ए.सी.	5402.00.101.18.00.53 योजना	122.00	129.42	मार्च -13	7.42
131.	25- जी.एस.एल.वी.ओ.	5402.00.101.25.00.52 योजना	1416.00	1423.84	मार्च -13	7.84
132.	25- जी.एस.एल.वी.ओ.	5402.00.101.25.00.53 योजना	74.00	185.93	फरवरी -13	111.93
133.	27- आर.आई.एस.ए.टी.	5402.00.101.27.00.60 योजना	13.00	23.07	अगस्त-12	10.07
134.	04- एम.ई.जी.ए	5402.00.103.04.00.52 योजना	9.00	13.76	जुलाई-12	4.76
135.	06- एस. एस.	5402.00.103.06.00.60 योजना	136.00	159.51	मार्च -13	23.51
136.	02- एल.पी.एस.सी.	5402.00.283.02.00.53 योजना	177.00	430.00	अक्तूबर -12	253.00

क्र. सं.	उप-शीर्ष	लेखा वर्गीकरण	बजट प्रावधान	व्यय	ऐसे माह जिसमें उपलब्ध प्रावधानों से ज्यादा खर्च किए गये	पुनर्विनियोग से पूर्व के प्रावधान जिसमें अधिक व्यय किया गया
137.	03- एस.एच.ए.आर.	5402.00.283.03.00.53 योजना	278.00	355.97	दिसम्बर-12	77.97
138.	05- एस.ए.सी.	5402.00.283.05.00.53 योजना	384.00	519.00	नवम्बर-12	135.00
139.	07- सी.एम.	5402.00.283.07.00.53 योजना	720.00	811.95	फरवरी -13	91.95
140.	01- वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.01 योजना	7000.00	8060.00	मार्च -13	1060.00
141.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.01 गैर-योजना	21000.00	21151.61	जनवरी -13	151.61
142.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.13 योजना	1210.00	1602.00	दिसम्बर-12	392.00
143.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.13 गैर-योजना	152.00	190.99	दिसम्बर-12	38.99
144.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.27 योजना	1150.00	1620.00	दिसम्बर-12	470.00
145.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.27 गैर-योजना	125.00	180.00	दिसम्बर-12	55.00
146.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.50 योजना	1500.00	2224.04	जनवरी -13	724.04
147.	01-वी.एस.एस.सी.	3402.00.101.01.00.50 गैर-योजना	200.00	228.00	अक्तूबर-12	28.00
148.	02-आई.आई.एस.यू.	3402.00.101.02.00.21 योजना	1172.00	1621.00	जनवरी -13	449.00
149.	06- जी.एस.एल.वी. एम.के. III	3402.00.101.06.00.21 योजना	4874.00	6009.15	नवम्बर-12	1135.15
150.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.21 योजना	948.00	2893.78	सितम्बर-12	1945.78
151.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.21 गैर-योजना	902.00	1783.27	जून-12	881.27
152.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.27 योजना	509.00	1435.24	नवम्बर-12	926.24
153.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.27 गैर-योजना	591.00	1108.97	जुलाई-12	517.97
154.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.28 योजना	515.00	516.25	फरवरी -13	1.25
155.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.28 गैर-योजना	1735.00	2139.02	दिसम्बर-12	404.02
156.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.50 योजना	551.00	1537.85	दिसम्बर-12	986.85
157.	25- एस.एच.ए.आर.	3402.00.101.25.00.50 गैर-योजना	703.00	1095.60	अगस्त-12	392.60
158.	26- आई.एन.एस.टी.आर.ए.सी.	3402.00.101.26.00.50 योजना	855.00	2353.15	दिसम्बर-12	1498.15
159.	13- जी.एस.एल.वी.ओ.	3402.00.101.33.00.21 योजना	18484.00	21840.49	दिसम्बर-12	3356.49
160.	13- जी.एस.एल.वी.ओ.	3402.00.101.33.00.52 योजना	200.00	1458.83	जुलाई-12	1258.83
161.	11--एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.27 योजना	131.00	1003.68	मई-12	872.68
162.	11-एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.50 योजना	0.00	1134.80	मार्च -13	1134.80
163.	11- -एन.आर.एस.सी.	3402.00.102.11.00.50 गैर-योजना	32.00	182.79	मार्च -13	150.79
164.	06- जी एस.ए.टी. 7 एल.एस.	5252.00.203.06.00.60 योजना	15500.00	44850.79	दिसम्बर-12	29350.79
165.	31- एन.एस.एस.	5402.00.101.31.00.60 योजना	7299.00	8136.57	मार्च -13	837.57
166.	40- एस.ए.आर.ए.एल.	5402.00.101.40.00.60 योजना	1161.00	1700.00	जनवरी -13	539.00
167.	01- एस.ए.सी.	5402.00.102.01.00.60 योजना	100.00	1139.98	मार्च -13	1039.98
168.	09- एम.ए.आर.एस.	5402.00.103.09.00.60 योजना	10090.00	11564.10	मार्च -13	1474.10
		योग				**58,670.59**

अनुबंध 5.1

(पैरा सं. 5.6.8(घ) के संदर्भ में)

उन अग्रिमों को दर्शाती हुई विवरणी जिनका भुगतान निर्माण अभिकरणों, स्टाफ सदस्यों, आपूर्तिकर्ताओं आदि को किया गया लेकिन उ.प्र. में पृथक रूप से दर्शाया नहीं गया है

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष	वार्षिक खाते में दर्शाई गई संवितरित ऋणें एवं अग्रिमें
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर	2010-11	11.77
2.		2011-12	33.70
3.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	2010-11	78.65
4.		2011-12	77.07
5.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2011-12	1297.10
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरूचिरापल्ली	2011-12	427.54
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	2011-12	5326.93
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	2011-12	110.75
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	2011-12	324.55
10.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	2011-12	5989.01
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	2011-12	6504.04
		कुल	**20181.11**

अनुबंध 5.2

(पैरा सं. 5.6.9 (घ) के संदर्भ में)

हिन्दी के विकास एवं प्रोत्साहन की योजना के अंतर्गत व्यक्तियों/संगठनों/निजी संस्थानों को ₹ 10 लाख तथा अधिक की अनुमोदित सहायता अनुदान को दर्शाती हुई विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम	अनुमोदित राशि	
		2010-11	**2011-12**
1.	असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी	3121050	3121050
2.	असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	2842290	2842290
3.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर	3277762	3277762
4.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, जयनगर, बंगलौर	2393025	2393025
5.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	2498700	2498700
6.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, (कर्नाटक) धारवाड़	5878800	5878800
7.	मुंबई हिन्दी विद्यापीठ, मुंबई	2800350	2800350
8.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	4787070	4787070
9.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	1068750	1068750
10.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई शहर योजना	3263400	3263400
11.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई (पी.जी. केन्द्र के लिए)	6156320	6156320
12.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, त्रिची	7482200	7482200
13.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	1881000	1211000
14.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (केरल) एर्नाकुलम	3157575	3157575
15.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, तिरूअनन्तपुरम	3257175	3257175
	कुल	**5,38,65,467**	**5,31,95,467**

अनुबंध 5.3

(पैरा सं. 5.6.9 (ङ) के संदर्भ में)

उच्च शिक्षा विभाग में वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष	लंबित उ.प्र. की सं.	जारी किया गया कुल अनुदान (₹ लाख में)
1977-1978	1	3.50
1978-1979	23	29.26
1979-1980	16	18.32
1980-1981	9	17.20
1981-1982	11	21.10
1982-1983	32	67.65
1983-1984	19	36.31
1984-1985	15	28.56
1985-1986	77	382.02
1986-1987	26	94.96
1987-1988	91	491.51
1988-1989	76	359.36
1989-1990	75	515.23
1990-1991	12	11.75
1991-1992	40	297.96
1992-1993	45	427.15
1993-1994	57	553.33
1994-1995	17	122.33
1995-1996	20	180.59
1996-1997	20	270.76
1997-1998	29	337.27
1998-1999	32	169.99
1999-2000	90	382.05
2000-2001	80	648.53
2001-2002	85	736.64
2002-2003	161	1632.28
2003-2004	139	2052.71
2004-2005	145	4146.43
2005-2006	213	1313.90
2006-2007	68	6170.95
2007-2008	23	78.89
2008-2009	36	626.64
2009-2010	193	3095.29
2010-2011	372	11103.61
2011-2012	286	63765.17
	2634	**100189.20**

अनुबंध 5.4

(पैरा सं. 5.6.22 के संदर्भ में)

वस्त्र मंत्रालय में, 31 मार्च 2012 को वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लंबित उ.प्र. की संख्या	राशि
1.	1978-1979	10	44.83
2.	1979-1980	2	11
3.	1980-1981	3	3.87
4.	1981-1982	1	0.40
5.	1982-1983	4	2.02
6.	1984-1985	1	0.65
7.	1985-1986	3	2.15
8.	1988-1989	1	0.25
9.	1989-1990	2	1.50
10.	1991-1992	3	7.47
11.	1992-1993	7	8.85
12.	1993-1994	8	77.11
13.	1994-1995	31	26.26
14.	1995-1996	47	229.47
15.	1996-1997	15	41.11
16.	1997-1998	15	35.46
17.	1998-1999	9	26.20
18.	1999-2000	28	126.53
19.	2000-2001	28	72.44
20.	2001-2002	26	35.46
21.	2002-2003	34	74.38
22.	2003-2004	74	549.51
23.	2004-2005	111	576.98
24.	2005-2006	133	995.69
25.	2006-2007	122	1218.17
26.	2007-2008	290	2569.36
27.	2008-2009	409	3611.06
28.	2009-2010	653	13682.43
	योग	**2070**	**24030.61**

(स्रोतः परिणाम बजट 2013-14)

अनुबंध 5.5

(पैरा सं. 5.6.27 के संदर्भ में)

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा संसद को सूचित किए बिना, निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को ₹10 लाख से ₹ 25 लाख तक अवमुक्त की गई आवृत्ति अनुदान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	2010-11	2011-12
1.	बैरागी शिक्षा संस्थान, यू.पी.	19.17	18.82
2.	कला विद्या संकुल पॉलिटेक्निक, मुंबई	15.70	--
3.	गुरू अंगद देव सेवा सोसायटी, पंजाब	13.50	--
4.	भारतीय शिल्पकला एवं डिजाईन संस्थान, जयपुर	13.50	--
5.	लक्ष्य फाउंडेशन, छत्तीसगढ़	13.50	--
6.	महाशक्ति सेवा केन्द्र, भोपाल	13.50	--
7.	नारी चेतना संगठन, हरियाणा	13.50	--
8.	विकलांगों के लिए जे.एस.एस. पॉलिटेक्निक, मैसूर	12.64	12.75
9.	भारतीय मानव विकास शिक्षा समिति, नागपुर	--	18.98
10.	भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान, इलाहाबाद, यू.पी.	--	18.72
11.	ज्योति शिक्षा संस्थान, नागौर, राजस्थान	--	13.90
12.	सार्वभौमिक मूल्य रचना, नई दिल्ली	--	13.50
13.	आर्क शैक्षिक सोसायटी, जयपुर	--	13.30
14.	पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयम्बटूर	--	12.60
15.	सेंट जॉन डी ब्रिटूस औद्योगिक विद्यालय, माला	--	12.54
16.	फैशन प्रौद्योगिकी विद्यालय, भुवनेश्वर	--	12.00
17.	अखिल भारतीय अल्पसंख्यक कल्याण कार्य समूह, लखनऊ	--	10.04
	योग	**115.01**	**157.15**

स्रोतः अ.वि.मां. 2012-13 एवं 2013-14

अनुबंध 5.6

(पैरा सं. 5.6.31 (ख) के संदर्भ में)

एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना के अंतर्गत रद्द परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	एस.पी.वी.का नाम	अवमुक्त राशि (अवमुक्त का माह एवं वर्ष)	वसूल की गइ राशि (धन वापसी की तिथि)	मार्च 2013 को धन वापसी में विलंब (माह में)	लंबित अनुदान की रशि	धन वापसी की तिथि को बकाया ब्याज	ब्याज भुगतान	31 मार्च 2012 को लंबित ब्याज	कुल लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
1.	सोहम एकीकृत वस्त्र पार्क अहमदाबाद प्रा.लि., गुजरात	4.00 (10/2006)	4.00 (6/2007)	7	शून्य	0.23	0.07	0.16	0.16
2.	वाडा हाई-तक. बुनाई पार्क, थाने	4.00 (3/2006)	2.21 (7/2008)	27	1.79	0.50 1.25 (3/06 से 3/2013 पर ₹1.79 करोड़)	शून्य	1.75	3.54
3.	श्री लक्ष्मीनरायण औद्योगिक सहाकरी सेवा समिति, सूरत	4.00 (1/2007)	4.00 (6/2008)	16	शून्य	0.53	शून्य	0.53	0.53
4.	राजस्थान टेक्समार्ट (प्रा.) लि., राजस्थान	3.78 (6/2007)	3.78 (4/2008)	9	शून्य	0.28	शून्य	0.28	0.28
5.	कपिला अवसंरचना प्रा.लि., गुजरात	4.00 (7/2007)	4.00 (9/2008)	13	शून्य	0.43	शून्य	0.43	0.43
6.	तारापुर वस्त्र पार्क लि., मुंबई	4.00 (10/2006)	4.00 (6/2010)	43	शून्य	1.43	0.19	1.24	1.24
7.	हैदराबाद हाई-टेक वस्त्र पार्क, महबूब नगर, आ.प्र.	12.00 (4.00+8.00) (1/2007) (3/2008)	शून्य	74 60	4.00 8.00	2.47 4.00	शून्य	6.47	18.47
8.	श्री धैर्यशील माने वस्त्र पार्क, सहकारी समिति इच्छलकरंजी, महाराष्ट्र	8.67 (2.89+5.78) (2/2007) (2/2008)	शून्य	73 61	2.89 5.78	1.76 2.94	शून्य	4.70	13.37
9.	भारत फैबटेक्स एवं कार्पोरेट पार्क प्रा.लि., पाली, राजस्थान	4.00 (6/2009)	शून्य	45	4.00	1.50	शून्य	1.50	5.50
10.	वैगाई हाई-टेक बुनाई पार्क, तमिलनाडु	2.44 (3/2010)	शून्य	36	2.44	0.73	शून्य	0.73	3.17
	योग	**50.89**	**21.99**		**28.90**	**18.05**	**0.26**	**17.79**	**46.69**

शब्दावली

विनियोग	:	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
विनियोग अधिनियम	:	संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	:	इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	:	पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
प्रभारित विनियोग	:	संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)	:	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जो का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
भारत की आकस्मिकता निधि	:	विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।

के.यो.यो.मॉ.प्र.	:	केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मॉ.प्र.) योजना आयोग की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजनागत योजना है जो लेखा महानियंत्रक द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना ने भारत सरकार के योजनागत योजनाओं के लिए एक समान लेन-देन आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली एवं एम.आई.एस. को स्थापित किया है। मंच का विस्तार राज्य सरकारों तक, राज्य खजानों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योजनागत निधियों के प्रभावी भुगतान के लिए किया गया है।
ऋण सेवा	:	देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
अनुदानों की मांग	:	अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है। जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।
ई-लेखा	:	कोर लेखांकन समाधान (को.ले.स.) लेखांकन प्रक्रिया की दक्षता तथा यथार्थता को सुधारने के उद्देश्य के साथ सिविल लेखा संगठन हेतु एक इलेक्ट्रानिक भुगतान तथा लेखांकन साफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। वेतन एवं लेखा कार्यालयों में निर्मित तथा चालू कॉम्पेक्ट के आसपास तथा अन्य ऑफलाईन अतरापृष्ठों हेतु यह मूल्य वृद्धि रिपोर्टिंग तथा मानीटरिंग क्रियाविधि हेतु दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया सहित कोर लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करता है।
अधिक अनुदान	:	ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
बाह्य ऋण	:	सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
राजकोषीय घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।

उपादान लागत पर स.घ.उ.	:	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
बाजार मूल्य पर स.घ.उ.	:	बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
आन्तरिक ऋण	:	भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे "भारत में लिया गया ऋण" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
मुख्य शीर्ष	:	लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
लघु शीर्ष	:	लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होते हैं।
नई सेवा	:	अभिप्राय नई नीति निर्णय जो पूर्व में संसद के संज्ञान में न लाया गया हो, से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है, जिसमें एक नई गतिविधि या एक नए निवेश का तरीका शामिल है।
सेवा का नया साधन	:	वर्तमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक वृहत व्यय।
मूल अनुदान	:	किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
प्रारंभिक घाटा	:	राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
लोक लेखा	:	भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न 'ऋण' से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दतमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।

लोक ऋण (भारत का)	:	भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
पुनर्विनियोजन	:	इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
राजस्व घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
राजस्व व्यय	:	यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
राजस्व प्राप्तियां	:	इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
स्टॉक	:	स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।
अनुपूरक अनुदान	:	यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।
बचत का अभ्यर्पण	:	केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
बचत	:	जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।
दत्तमत्त अनुदान	:	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
वेबसाइटःएचटीटीपीः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन